राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या: 09

बुधवार,

03 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

खेद प्रकट

सदन में माननीय सदस्य श्री वासुदेव देवनानी द्वारा किये गये कृत्य के लिये खेद प्रकट

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहें तो, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सोमवार एक मार्च को यह सदन गतिरोध में स्थगित हुआ संसदीय कार्य मंत्री महोदय के एक प्रस्ताव के कारण। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर श्रीमान जितनी बार आये हैं, जितना समझते हैं, उतना शायद इस सदन में कोई नहीं समझता। कई बार तनाव के क्षण आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सबकी मान्यता है, दृढ़ मान्यता है, यह आसन सर्वोपरि है। आसन का सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है और यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा भी है और एक तरह से आवश्यकता भी है पर, अध्यक्ष महोदय, कई बार उत्तेजना के क्षणों के अन्दर जब माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, मौका नहीं मिलता तो इस तरह के दृष्टांत हो जाते हैं। इसी सदन के अन्दर भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अपना विरोध जिस प्रकार प्रकट किया, वह सारे सदन ने देखा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, Please, don’t give reference of

(श्री अध्यक्ष)

Hon'ble Governor. आप सीनियर हैं, लीडर हैं। गवर्नर जब हाउस में होते हैं तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। Please, don't quote it, because कल से मैं देख रहा हूं, कल से मैं देख रहा हूं कि गलत सूचना जनता के बीच में जा रही है। जब गवर्नर हाउस में आते हैं तो हाउस गवर्नर के पजेशन में होता है तो कोई भी व्यवहार क्या करता है, it's between the Governor and the respective member. सरकार यदि उसके पक्ष में समझती है तो प्रस्ताव लेकर आये अन्यथा उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं कर सकते इसलिये उसको कोट नहीं करें कृपया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया। संसदीय कार्य मंत्रीजी को उस बारे में संज्ञान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह आसन उदार है। ऐसी उदारता थोड़ी इधर भी होनी चाहिए। ये नजरें इधर भी इनायत होनी चाहिए। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन चले, हम चाहते हैं और माननीय सदस्य ने जो बात कही, और किसी प्रस्ताव के माध्यम से, जब आप अनुमति देंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी मान्यता है कि संसदीय कार्य मंत्री, आपका कर्तव्य सदन को चलाने में है, गतिरोध पैदा करने में नहीं। मैं भी इस पद पर, कुर्सी पर बैठा हूं। कृपया अपने आचरण को ठीक करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय नेता, व्यवहार के सम्बन्ध में तो कमेंट करना पड़ेगा। I'll not appreciate it until you feel कि जो व्यवहार था, वह डिजायरेबल नहीं था। उसमें आप अपनी कोई ओपीनियन तो रखें नहीं तो हाउस को अपने हिसाब से चलाएं हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर उत्तेजना के कारण से माननीय सदस्य ने.....जिस प्रकार का यहां वैल में आये, उस तरह की परम्परा नहीं है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, आप ही हमारे संरक्षणदाता हैं, हम जाएं तो जाएं कहां, आप आसन पर विराजे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please, come to the point. Do you have any regret on it or you don't want to regret on it? I think it's as simple as that.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिये हम पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह अपने दूसरे किसी प्रस्ताव के माध्यम से आएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: फिर मैं अंतिम बार बोल रहा हूं। (व्यवधान) प्लीज, मैं फिर अंतिम बार बोल रहा हूं। जो व्यवहार हुआ उसके सम्बन्ध में निश्चित तौर पर एक आइडियल, वरिष्ठ नेता हैं, पहले वाले होते तो मैं कभी कुछ नहीं करता, पर आसन जब पैरों पर है और सदन के सदस्य जानते हैं, सीनियर होते हुए, बैठने के बाद अपनी व्यथा व्यक्त करते तो ठीक है। मेरी और कोई अभिव्यक्ति नहीं है लेकिन एक गलत परम्परा चली जाएगी और उस परम्परा का, मैं समझता हूं कि आप जैसे पार्लियामेंटेरियन को खड़े होकर पहला सेन्टेंस यह बोलना चाहिए कि it was not desirable और हम अपनी पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करते हैं। It's something like, either your member should come out or the party should come out.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी ऐसे कृत्य से, तो हम उसके लिये क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की घोषणा का क्रियान्वयन

148. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट वर्ष 2019-20 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त निरीक्षक को गृह विभाग ने

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

वापस नौकरी पर ले लिया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में पैरा संख्या 180 पर राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी, वह जीरो टोलरेंस के बाबत थी।

पुलिस निरीक्षक एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये अभियोग संख्या 293/2014 में अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 22.11.2016 को चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस निरीक्षक का आचरण एक लोकसेवक की अपेक्षा में, अनुपयुक्त एवं अशोभनीय पाये जाने पर उन्हें अनुशासनिक अधिकारी द्वारा राज्य सेवा से दिनांक 29.01.2020 से बर्खास्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध निरीक्षक द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 23 के अंतर्गत अपीलाधिकारी (गृह विभाग) को अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड आदेश दिनांक 29.01.2020 को आदेश दिनांक 30.12.2020 द्वारा अपास्त किया गया।

अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक को राज्य सेवा में वापस नहीं लिया गया है तथा उक्त अपीलादेश के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 34 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गयी है, जो विचाराधीन है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोरोना काल में जब अपराधों में कमी आई पूरे प्रदेश में, उस समय भ्रष्टाचार के केसेज में कमी नहीं आई। मंत्रीजी, जिस सम्भाग से आप और हम आते हैं, 7 महीने में 32 केसेज भ्रष्टाचार के पकड़े गये। इस पृष्ठभूमि में मैं इस गम्भीर समस्या, जिसका उल्लेख जीरो टोलरेंस के रूप में सरकार ने किया है और उसकी मंशा पर मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार की

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
क्या मजबूरी होती है कि वह अधिकारी, जिनका ट्रैक रिकार्ड भ्रष्ट है, जो पहले आर.पी.एस. में थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, प्रश्न।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लेता हूं ताकि बहस नहीं हो। सरकार की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों, जिनका ट्रैक रिकार्ड भ्रष्ट है, उनको एस.पी., कलेक्टर और आई.जी. के पदों पर नियुक्त किया जाता है व पुन: भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर जेल में बंद करना पड़ता है? मैं चाहूंगा कि बारां, दौसा और उदयपुर के जो अधिकारी नियुक्त किये हैं, उनके बारे में आप सदन को जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न, please, be precise. आपने प्रश्न पूछा है निरीक्षक के सम्बन्ध में। आप डिबेट को इतना लम्बा कर देंगे तो ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): डिबेट नहीं कर रहा। जीरो टोलरेंस ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जीरो टोलरेंस।

श्री अध्यक्ष: आप, प्लीज, न, न, प्लीज। हां, जीरो टोलरेंस का मतलब उन्होंने स्पेसिफिक पढ़ा। आप क्वेश्चन पढ़िये। मैंने पूरा पढ़ा है। जीरो टोलरेंस के बाद एक निरीक्षक के बारे में पूछा है। इसलिये please, be specific to the question only ...(व्यवधान) No. Please, don't guide me. I'm not supposed to be guided by anybody. If you want to ask anything about the निरीक्षक, जिसके सम्बन्ध में आपने प्रश्न पूछा है, जिस प्रश्न पर, अपील अथोरिटी ने उसको रेस्टोर कर दिया, उसकी अपील पर गये हैं, उसके सम्बन्ध में यदि पूछना है तो पूछें। As simple as that. जो आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में बहुत सिम्पल है। जीरो टोलरेंस, एक निरीक्षक का आपने प्रश्न पूछा, निरीक्षक को अपील अथोरिटी ने रेस्टोर कर दिया। इन्होंने अपील कर दी। अपील करने के बाद अपील पैंडिंग है तो आज की डेट में वह सर्विस में तो है नहीं, so, be specific to the question. Why I say it is very simple, because Question Hour is specifically for one specific question and it cannot be for a general thing. Please understand. यह हम सदस्य, जो संसदीय परम्परा में इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन आवर केवल मात्र किसी एक स्पेसिफिक

(श्री अध्यक्ष)

घटना की जानकारी लेने के लिये है, जनरल पालिसी के डिस्कशन के लिये नहीं है। आपका जो इश्यू है, आप दूसरे ढंग से लेकर आएं, मैं आपको अलाउ करूंगा। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली निरीक्षक के बारे में कुछ पूछना है? आप पूछिये।

अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

पेयजल के काम में आने वाली विद्युत की दर का निर्धारण

149. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक, पेयजल, घरेलू, कृषि, बागवानी आदि विभिन्न श्रेणियों में विद्युत सम्बन्धों को बांटा जाकर उसी के अनुरूप विद्युत व्यय वसूला जाता है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी में? श्रेणीवार निर्धारित दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वयं के जल स्रोत से ट्यूबवैल के माध्यम से पेयजल प्राप्त करने के लिए घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करने वाले से किस दर से राशि वसूली जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पेयजल के लिए काम में आने वाली विद्युत व्यय की दर को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। विद्युत की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों को घरेलू, अघरेलू, कृषि, मिश्रित भार, विद्युत चलित वाहन एवं औद्योगिक श्रेणी में बांटा गया है। इन श्रेणियों के लिये विद्युत दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों की प्रस्तुत याचिका पर आपत्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापक जन सुनवाई के पश्चात् किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित श्रेणीवार विद्युत दरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) व्यक्तिगत स्तर पर ट्यूबवैल के जरिये पेयजल प्राप्त करने के लिये (केवल स्वयं के उपयोग हेतु) घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करने पर उपभोक्ता से घरेलू श्रेणी की दर से राशि वसूल की जाती है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह अर्ज कर रहा हूं कि, माननीय मंत्रीजी, प्रचार तो बहुत है कि उद्योगों से ज्यादा पैसा लिया जाता है लेकिन घरेलू कनेक्शन 50 यूनिट के बाद महंगा हो जाता है, आपने श्रेणी डाल रखी है। गरीब आदमी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): एक लाइन तो बीच में बोल दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल प्रश्न पूछिए। नहीं, यह बहुत गलत परम्परा है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके जिन-जिन अधिकारियों ने व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन से ट्यूबवैल के या पीने के पानी का काम लिया, जिनको आपने वी.सी.आर. भरी, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उनको वापस वी.सी.आर. का पैसा दिया जाएगा? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले एक प्रश्न का जवाब आने दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घरेलू उपयोग के लिए पेयजल अपने कुओं से प्राप्त करते हैं, उनसे घरेलू बिजली की दर वसूल की जाती है और इसमें यदि कोई वी.सी.आर. गलत भरी गयी है और स्पेसिफिक शिकायत यह करेंगे तो मैं उसका परीक्षण करवाकर उन्हें न्याय दूंगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत आदमी, जैसे मैं इटावा क्षेत्र से हूं, पीपल्दा से हूं, 90-100 किलोमीटर खातौली पड़ता है, आप एस.ई. के पास जाते हो, ए.ईएन. को अधिकार देंगे कि नहीं देंगे, इस तरह की शिकायत सुनने की बात करें?

दूसरी बात मेरी अर्ज करना यह है कि बाप मर गया, बेटी और कहीं रहती है, उसके नाम भी मेरे क्षेत्र में आपने पुराना बकाया डाल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत निवेदन किया, ऐसे केसेज में आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप मुझे समझाएं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। Please, be spe-

(श्री अध्यक्ष)

cific. आप सीनियर आदमी हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है आपको इंटरवीन करते हुए। Be specific. आपका कोई घरेलू कनेक्शन में किसी का दिया है तो आप पूछें, अपनी बात करें। आप जनरल बात पर आ जाते हैं। आप सीनियर आदमी हैं, प्लीज, ऐसे नहीं करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि क्या श्रेणीवाइज अलग-अलग हैं तो उद्योगों से पचास प्रतिशत गरीब के घरेलू कनेक्शन पर चार्जेज, कोई समाजवादी समाज की स्थापना करना आपका उद्देश्य है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इनको परिशिष्ट- 'ए' दिया है, उसमें खास तौर से बी.पी.एल. परिवारों को और घरेलू 50 यूनिट तक हम 1 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट राज्य सरकार से अनुदान दे रहे हैं और उसके बाद जो 50 यूनिट से ज्यादा उपयोग करते हैं, तो 50 यूनिट तक यह अनुदान देने के बाद जो-जो दरें, 50 से 150 यूनिट तक यदि करता है तो उसकी 6 रुपये 50 पैसे दर है और 150 से 300 यूनिट का उपभोग करता है तो उसकी अलग दरें हैं। यह इस तरह से अलग-अलग दरें हैं। जो छूट दी गयी है, वह 50 यूनिट तक दी गयी है और हम प्रति वर्ष जो बी.पी.एल. परिवार और जो लघु घरेलू परिवार हैं, स्मॉल डोमेस्टिक, लगभग 56 लाख लोगों को 528 करोड़ रुपये का अनुदान प्रति वर्ष दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अनुदान तब दे रहे हो जब आपने रेट ज्यादा बढ़ा दी। गरीबों की रेट कम करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बी.पी.एल. की दर कम कर रखी है न, पचास यूनिट तक दर कम कर रखी है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): पचास यूनिट क्या होती है? ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आप बैठें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): पचास यूनिट क्या होती है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अंकित नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और अपन क्या खड़े हो जाते हैं कहीं पर भी? कहीं समाजवाद आ जाता है, कभी यह आ जाता है। प्रश्न, be specific. I am very sorry. अगला प्रश्न,

(श्री अध्यक्ष)

श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान) आप अमीर हैं, आप बैठें। फिर वही बात हो गयी। एक को रोकें तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। क्या तकलीफ है? आप प्लीज, बैठें। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में एक साथ मिलो, दोनों एक जैसे करो फिर। क्षेत्र एक ही है तो फिर असर पड़ना चाहिए एक दूसरे का। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर नगर परिषद् में सीवरेज लाइन के कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच

150. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् क्षेत्र, बाड़मेर में कौन-कौनसे वार्डों में किन-किन फर्मों द्वारा सीवरेज लाइन डालने का कार्य कितनी-कितनी राशि से किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने वाली फर्मों द्वारा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना उक्त कार्य करने में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इतने बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता की कमेटी बनाकर जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीवरेज लाइन से वंचित वार्डों में सीवरेज लाइन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगर परिषद् क्षेत्र, बाड़मेर के विभिन्न वार्डों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य लगभग 30 करोड़ 93 लाख रुपये का व्यय किया जाकर पूर्ण किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कार्य अनुबंध की विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता से करवाया गया है। अनियमितता के सम्बन्ध में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) वंचित वार्डों में सीवरेज लाइन आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण के द्वितीय फेज में स्वीकृति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं एशियन विकास बैंक से स्वीकृति उपरांत कार्य संपादित किया जाना सम्बन्धित होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर में 3 फर्मों द्वारा करीबन 30 करोड़ रुपये से ज्यादा का कार्य हुआ है, सीवरेज का जो कार्य किया गया, मैनहोल सारे टूटे हुए हैं, उसकी पाइप लाइन्स चोक हैं और न ही उनको घरों से जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): प्रश्न मेरा यही है सर, कि एक तो 30 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुआ, आधा शहर तो छोड़ दिया और जो कार्य हुआ है, वह इतना घटिया स्तर का हुआ है कि उसके अंदर अब मैनहोल टूट गये, हौदियां, चोक हैं, ट्रंक सीवर लाइन, जिससे मेन बाहर जाना है, उससे इन्होंने जोड़ा नहीं है तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाकर, जो घटिया स्तर का कार्य हुआ है और आधा शहर इसमें छूटा है, एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और जो बाकी कार्य बचा हुआ है, इस कार्य को कब तक पूरा कराएंगे? उस कमेटी के अंदर आर.ए.एस. अफसर और इंजीनियरों की टीम... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो प्रश्नों का जवाब आने दो। कहां आगे जा रहे हो आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य 2012 में चालू हुआ था और 2012 में यह जो कार्य चालू हुआ था, वह करीब-करीब 28-30 वार्डों में एक साथ चालू हुआ था। अब जब कार्य 2012 में चालू होता है और 2019 में खतम होता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर टूट फूट तो होती ही है। अब सवाल यह है कि विभाग को तो कोई किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो आप बता दें कि किससे इन्क्वायरी करायें, हम उसी से इन्क्वायरी करवा लेंगे, एक बात।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा कि आधा शहर, आधा शहर नहीं, आपके कुल मिलाकर के चालीस वार्डों में से पच्चीस वार्डों में सीवर लाइन डल चुकी है, जो कि 2019 तक पूरी हो चुकी है और इसके अलावा जो 15 वार्ड शेष रहे हैं, जिनमें लाइन डालनी बाकी है, उनके बाबत भी यह तय कर दिया गया है कि 10 एम.एल.डी. का जो आपका एस.टी.पी. है, उसकी स्ट्रैन्थ बढ़ाई जाए और इसी के साथ-साथ, यह ही नहीं 75 किलोमीटर की सीवर लाइन और डाली जाए और 4.80 का एस.टी.पी. जो है वह और नया बनाया जाए। अब आप दूसरा सवाल पूछ लें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि 2012 से शुरू हुआ और 2019 तक इसको पूरा किया। मेरा यह निवेदन है कि यह जो कार्य किया गया है, यह 2019 तक जो कार्य किया गया है, मैंने इसकी शिकायत के बारे में पिछले बजट के अंदर विधान सभा में भी यह मुद्दा उठाया, बाड़मेर नगर परिषद् की बोर्ड में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपने यह बताया कि आपने कोई शिकायत नहीं की। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने विधान सभा में भी इसका मुद्दा उठाया था कि इसकी जांच कराई जाए, यह घटिया कार्य है और उसके बाद में न तो जांच हुई और मैं यह चाहूंगा कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप यह सीधा पूछें न कि आप जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, बात खतम हुई।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच कराई जाए और पैसे का जो इतना दुरुपयोग हुआ है, इसको सही कराया जाए और कमेटी बनाकर जो अधूरा कार्य रहा है, उसको जल्दी पूर्ण किया जाए, आप इसकी घोषणा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि आपके द्वारा मुझे कोई शिकायत मुझे या विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक सवाल इस बात का है कि आप यह कह रहे हैं कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मैंने विधान सभा में यह बात उठाई तो आप शिकायत ही कर देते, वैसे भी अपना तो रोज मिलना-जुलना रहता ही है, एक बात।

दूसरी बात यह है कि जिससे आप जांच करवाना चाहते हो, उसी से जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं।

तीसरी बात, जहां तक सवाल यह है कि बाकी कामों का क्या होगा? तो उसमें हम आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से एशियन बैंक से 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन रख रहे हैं। बाड़मेर में बाकी जितने भी 15 वार्ड बचे हैं और जितनी भी, 10 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. आलरेडी बना हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने के अलावा 4.80 एम.एल.डी. का नया एस.टी.पी. भी बनाएंगे और इसके अलावा 75 किलोमीटर की सीवरलाइन भी खोदेंगे। मेरा ख्याल है, आप संतुष्ट होंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्रीजी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। मैं सरकार को यह निर्देश देता हूं कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य इश्यू उठाता है, तो विभाग के अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वह मंत्रियों के नोटिस में वह चीज लाये। उससे कम से कम जो हमारी जन भावना है, उसके बारे में कोई निर्णय हो सके। मैं आशा करता हूं कि जो विभाग के अधिकारी यहां असेम्बली में बैठकर प्रोसिडिंग नोट करते हैं जिस विभाग के सम्बन्ध में जो भी कोई कम्प्लेंट आ रही है, उस कम्प्लेंट को उस विभाग के पास भेजें, जिससे समय पर सदन में उसके बारे में कमेंट किया जा सके। यह सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आदेश उचित है, यह होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक सदस्य कह रहे हैं कि मैंने उठाया, फिर भी हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो सदन में चर्चा की महत्ता नहीं रहेगी। इसलिए, मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चाहे 295 हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, जो भी जनता के मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों पर विभाग की जानकारी मंत्री स्तर पर जानी चाहिए, जिससे कम से कम वह रिप्लाई दें तो सरकार उन सब चीजों को लेकर आ सके।

अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल खराबे का भुगतान

151. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल खराबा होने पर कितनी अवधि में बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया जाता है?

(2) जिला पाली की तहसील रोहट में वर्ष 2019 में खरीफ फसल के लिए किस-किस पटवार हलके में गिरदावरी की गई एवं सम्बन्धित बीमा कंपनी द्वारा किस-किस जिंस में कितना-कितना प्रतिशत खराबा बताया गया एवं वास्तविक उपज कितनी बताई गई है? खरीफ वर्ष 2019 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खराबे के विरुद्ध किस-किस पटवार सर्किल के किस-किस बीमा धारक काश्तकार की कितनी-कितनी राशि क्लेम की बनती है?

(4) उक्त तहसील के किस-किस पटवार सर्कल में कितनी-कितनी राशि का क्लेम भुगतान बीमित काश्तकार को दिया जा चुका है एवं किस-किस को किन-किन कारणों से दिया जाना शेष है तथा बकाया क्लेम राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुसार बीमा कम्पनी को उपज परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त 21 दिन की अवधि में अविवादित बीमा क्लेमों का भुगतान करना होगा, बशर्ते बीमा कम्पनी को राज्यांश प्रीमियम तथा केन्द्रीयांश प्राप्त हो गया हो।

(2) पाली जिले के रोहट तहसील में खरीफ 2019 में कुल 33 पटवार मण्डलों के 80 राजस्व ग्रामों के लिये गिरदावरी की गई थी।

खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत तहसील रोहट में फसलवार उपज में हुई क्षति एवं वास्तविक उपज का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत तहसील रोहट में कृषकवार आंकलित बीमा क्लेम का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत तहसील

(कृषि मंत्री)
रोहट में कृषकवार भुगतान किये गये बीमा क्लेम का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। दो कृषकों को तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया था, इन दो शेष कृषकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 21 दिन में बीमा क्लेम की राशि मिल जानी चाहिए, बशर्ते कि राज्य सरकार और केन्द्र का आपका प्रीमियम पहुंच जाए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि यह प्रीमियम समय पर पहुंच जाएं उसके लिये सरकार कोई न कोई एक अवधि तय करेगी कि आपका प्रीमियम समय पर पहुंच गया। दूसरा यह कि जो फसल खराबा होता है तो बीमा कम्पनी ही आकलन करती है कि कितना क्लेम बनता है, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती। आप यह शीट देखेंगे, जो आपने दी है। दो भाइयों के पचास-पचास बीघा जमीन है, दोनों ने ही एक ही जिंस की बुवाई की। एक को क्लेम मिला 90 हजार और दूसरे को मिला मात्र 9 हजार रुपये, जबकि जमीन बराबर है, जिंस भी वही की वही है, प्रीमियम उतना ही भरा है, पर एक को 90 हजार और दूसरे को 9 हजार तो यह अपने स्तर पर भी कोई आकलन हो जाए ताकि बीमा कम्पनी कहीं पर गड़बड़ नहीं कर सके। माननीय मंत्री महोदय, आपको पता होगा, आपने खुद ने प्रयास करके, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने करोड़ों रुपये जो बीमा कम्पनी मना कर चुकी थी, आपने दिलवाया।

तीसरा मेरा प्रश्न है, जब राज्य सरकार आधा प्रीमियम भरती है तो आपका भी उस पर अंकुश होना चाहिए। आपका जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है, वह आर्बिट्रेटर के रूप में कोई फैसला देता है, उसे दो साल तक बीमा कम्पनी नहीं मानती। जब आधा प्रीमियम आपका होता है तो उसके लिये भी आप कोई व्यवस्था करेंगे? इसका जवाब आप मुझे दे दो।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा कि हमारा उस पर क्या अंकुश है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बीमा क्लेम चलता है और नोर्म्स बने हुए हैं, पर फिर भी राज्य सरकार उस पर पूरा अंकुश लगाकर रखती है और उसी का परिणाम है कि आपके यहां जो दो कृषक थे, जिनका मैं नाम कोट कर देता हूं, तुलसाराम निवासी खांडी पटवार हलका खांडी को मूंग की फसल के लिये 19,287 रुपये का क्लेम अभी दिलवाया गया। दूसरा नाम है श्रीमती गुलाब कंवर निवासी बस्सी पटवार हलका, मूंग की फसल के लिये 77,101 रुपये।

(श्री लालचन्द कटारिया)

भारत सरकार की गाइडलाइन के अलावा जो भी शिकायतें हमारे पास आती हैं, आपने जो कमिश्नर साहब की बात कही है, मैं आपको एक ताजा जानकारी और दे दूं कि आपका 2017 का भी मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन है। आज उसकी मीटिंग होनी थी, वह मीटिंग अब कल है। हम उम्मीद करते हैं कि वह पुराने फैसले भी, शायद उनका कल निस्तारण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के साथ-साथ विभाग सावचेत नहीं है और जैसा यह मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं इससे बढ़कर माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगातार यह खुद अपनी व्यक्तिगत मानिटरिंग करते हैं और हर किसान को मुआवजा दिलाने की बात हमेशा रखते हैं और उसी के तहत लगातार मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके जिले में अब ज्यादा कोई बकाया है नहीं, चाहे पूरा पाली जिला हो, चाहे रोहट तहसील हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जो मैंने आपको जानकारी दी कि एक ही परिवार के दो भाइयों के पचास-पचास बीघा जमीन, एक ही जिंस बोयी, उसके बाद में आपकी शीट इस बात को साबित कर रही है कि एक को 90 हजार और दूसरे के 9 हजार मिले। आप अपने स्तर पर या विभाग के स्तर पर एक कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बीमा कम्पनी कहीं पर भी क्लेम में गड़बड़ न करे। मंत्री महोदय, आपको खुद को पता है कि आपने करोड़ों रुपया दिलाया है। जब मैं यह विषय आपकी जानकारी में लेकर आया हूं तो हमारी व्यवस्था भी कुछ होनी चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, क्योंकि मेरे पास भी डेटा हैं कि 6,740 किसानों में पालिसी हुई है 11,479 तो जो बात आप कह रहे हैं, वही बात है। कहीं डबल हुई है, कहीं जोत का फर्क है, उसके लिये राज्य सरकार जल्दी ही डेटा एनालिसिस्ट की नियुक्ति कर रही है, ताकि वह समय के अनुसार उसको चैक करता रहे और जो डेटा भारत सरकार को जा रहे हैं, उससे मिलान होता रहे और जहां कोई कमी आये तो उसको हम दूर कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में क्वारी लाइसेंस का आबंटन

152. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मीना कंवर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिहांदा (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 1,117 क्वारी लाइसेंस एवं भोमिया जी का थान बालेसर विस्तार क्षेत्र में 180 क्वारी लाइसेंसों के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो कब? विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनिज क्षेत्र के लिये कितने आवेदन पत्र किस-किस श्रेणी के प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों से कुल कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खनिज क्षेत्र के लिये नियमानुसार लाटरी खोली गई? यदि हां, तो कब व कितने सफल आवेदकों का चयन हुआ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त लाटरी में सफल आवेदकों को क्वारी लाइसेंस आबंटित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यही सही है कि उक्त क्षेत्रों में उक्त क्वारी लाइसेंसों का विभाग की लापरवाही से क्वारी लाइसेंस फार्म 8 (स्वीकृति फॉर्म) जारी करने मे विलम्ब के कारण सफल आवेदकों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार सफल आवेदकों के पक्ष में क्वारी लाइसेंस आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिहांदा विस्तार क्षेत्र में 1,117 क्वारी लाइसेंस प्लाटों के लिए दिनांक 04.03.2009 को तथा भोमिया जी का थान (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 180 क्वारी लाइसेंस प्लाटों के लिए दिनांक 11.03.2010 को विज्ञप्ति जारी कर क्रमश: दिनांक 23.03.2009 से 27.03.2009 तक तथा दिनांक 28.03.2010 से 30.03.2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। विज्ञप्ति की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त दोनों क्षेत्रों पर श्रेणीवार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदन पत्रों से सिहांदा विस्तार क्षेत्र से रुपया 8.38 करोड़ एवं भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र से रुपया 1.94 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

(खान मंत्री)

(3) जी हां। सिहांदा विस्तार क्षेत्र की लाटरी दिनांक 16.09.2010 को तथा भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र की लाटरी नियमानुसार दिनांक 14.09.2012 व 19.12.2012 को खोली गई, जिसमें क्रमश: 1,088 तथा 180 सफल आवेदकों का चयन हुआ। सफल आवेदकों की श्रेणीवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र के लाटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में क्वारी लाइसेंस जारी करने हेतु मंशा पत्र जारी कर, मंशा पत्र के अनुसार आवश्यक अनुमोदित सरलीकृत माइनिंग स्कीम प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। सिहांदा विस्तार क्षेत्र की लाटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में क्वारी लाइसेंस आबंटन की प्रक्रिया के दौरान ही इस क्षेत्र की लाटरी प्रक्रिया के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जनहित याचिका संख्या 10304/2010 श्री दिनेश बोथरा विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर हुई। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19.08.2011 से क्षेत्र में पर्यावरण अनुमति प्राप्त किये बिना सफल आवेदकों को क्वारी लाइसेंस आबंटित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया गया। इस कारण क्वारी लाइसेंस का आबंटन नहीं हो सका। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 से तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन कर क्वारी लाइसेंस का आबंटन संशोधित नियमों के तहत करने एवं अधिसूचना दिनांक से पूर्व के सभी लम्बित आवेदन पत्रों को निरस्त करने के प्रावधानों के कारण सिहांदा एवं भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र के सभी सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों को दिनांक 16.04.2013 से अस्वीकृत किये गये।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 के विरुद्ध फैडरेशन आफ सैण्ड स्टोन माइनिंग इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 4241/2013 दायर की गई। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 के उस भाग को अपास्त किया गया, जिसके आधार पर पूर्व के लम्बित आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया। निर्णय में आवेदन पत्रों को पुनः बहाल कर उनका निस्तारण पुराने नियमों के तहत करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक

(खान मंत्री)

31.07.2013 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2014 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2013 के क्रियान्वयन पर स्थगन है। उक्त कारण से सफल आवेदकों को क्वारी लाइसेंस आबंटित नहीं किये गये।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न के भाग संख्या 4 के उत्तर में वर्णितानुसार अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 से पूर्व के निरस्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2013 के क्रियान्वयन पर स्थगन है, जिससे वर्तमान में उक्त क्वारी लाइसेंस का आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से खान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि 2008 में सिहांदा भोमिया जी का थान बालेसर में क्वारी लाइसेंस हेतु 1,117 क्वारी पर लगभग 1 लाख 45 हजार आवेदन किये गये थे व उनके 180 क्वारी पर लगभग 35 हजार आवेदन किये गये थे, जिनको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खान मालिकों के पक्ष में फैसला कर क्वारी लाइसेंस जारी करने के आदेश दिये गये थे। विगत भा.ज.पा. सरकार द्वारा उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार खान मालिकों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर उनको क्वारी लाइसेंस दिलवाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें स्टे भी है। अत: जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है कि कब तक, तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

साथ ही, जहां तक सरकार की मंशा का प्रश्न है तो हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार देने के लिए समर्पित है। मैं सदन को,

(श्री प्रमोद भाया)

माननीय सदस्या जी को आश्वस्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जाएगा और उसके निर्णय के अनुरूप शीघ्र पालना की जाएगी।

प्रश्न संख्या 153

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं

154. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कौन-कौन से विद्यालय विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित विद्यालयों में सुचारु अध्ययन व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए विद्युत कनेक्शन शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में समस्त राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं जैसे चारदीवारी, शौचालय, लैब व कक्षा-कक्ष आदि का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय नहीं है, उक्त विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित 218 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 88 विद्यालय विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित समस्त 76 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।

(2) जी हां। विद्युत विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को कार्ययोजना बनाकर कार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) जी हां। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों में से 71 विद्यालयों में चारदीवारी, 60 विद्यालयों में लैब तथा 33 विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' से 'घ' पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। वर्ष 2021-22 हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें बानसूर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आधारभूत सुविधाओं की कमी वाले विद्यालय भी सम्मिलित हैं। उक्त क्रम में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार के पास समग्र शिक्षा अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है।

(4) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 96 के अनुसार प्रदेश के 200 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की घोषणा के अन्तर्गत कुल 190 अतिरिक्त संकाय खोले जा चुके हैं, जिनमें से 78 राउमावि में अतिरिक्त संकाय के रूप में विज्ञान विषय खोले जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट में किया है कि सभी राजकीय स्कूलों को टीवी से जोड़ा जाएगा, सैट टाप बाक्स से जोड़ा जाएगा, तो यह कनेक्शन कब तक होंगे, कब तक जोड़ने की प्रक्रिया चालू होगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो बजट घोषणा की है यह बजट पास होने के बाद में तुरंत उसके बाद में चालू कर दिया जाएगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह दिया है कि सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है, तो आज तक कलेक्टर्स ने, जो यह प्रक्रिया, कमेटी बनाई गई है, मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया है, तो क्या किया गया, आज तक की क्या कार्यवाही की गई? भारत सरकार के द्वारा जो एकमुश्त पैसा दिया जाता है तो इसका क्या प्रावधान है, कमेटी किस तरह से खर्च करेगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, आप किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? जो विद्युतीकरण विद्यालय हैं उनके लिए सी.एस.आर. के माध्यम से प्रयास करने के लिए हमने जिला कलेक्टर्स को लिखा है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधायक कोष है उसमें भी इसका प्रावधान है, उससे भी आप लोग प्रयास करें कि विद्युतीकृत हो सकें लेकिन जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तमाम उनका विद्युतीकरण हो चुका।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न है, प्लीज एक मिनट। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर संकाय खोले गये हैं? हरसोरा बालिका में 480 बच्चियां हैं, ...(व्यवधान) अजबपुरा और रायली में विज्ञान संकाय कब तक खोलने की मंशा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य, यह अलग प्रश्न है, आप प्रश्न क्या लिख रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं।

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। कन्हैया लाल जी।

बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संरक्षण हेतु कमेटी का गठन

155. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु परामर्श देने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी का नवीनीकरण कितने समय में किया जाता है व कमेटी की बैठकें कब-कब बुलायी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (राज्य मंत्री, वन के स्थान पर): (1) जी हां। बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को परामर्श देने हेतु राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 13.10.2008 से कमेटी का गठन किया गया, जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट '1' के अनुसार है।

(2) राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 13.10.2008 से गठित उक्त समिति के पुनर्गठन का प्रावधान नहीं है।

उक्त समिति की बैठकें दिनांक 16.10.2008, 05.02.2009, 29.07.2010, 27.11.2010, 17.11.2011, 29.12.2011, 12.09.2012, 29.12.2012 तथा 04.09.2013 को आयोजित की गई हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो बैठकें आपने 04.09.2013 से पहले 2 साल में 8 बार ही कीं, उसके बाद में आपने कभी बैठक नहीं की और बैठक में जो निर्णय किये गये, उनमें अभी तक क्या-क्या किया और क्या-क्या सुझाव आये और अब तक क्यों नहीं किया? यह बताएं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बैठकें हुई यह सारी बैठकें 2013 तक की हुई थीं। 2013 के बाद में जब 2014 में आपकी सरकार आयी, सरकार आते ही उसके बाद में पांच साल तक एक भी बैठक नहीं हुई और आज तक नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो बैठकें, जो कमेटी है उसका मुख्य रूप से काम है कि वह अपने सुझाव यहां पर भिजवाए, जिससे कि वहां काम हो सके लेकिन मीटिंगें नहीं हुईं, यह निश्चित तौर पर अधिकारियों की लापरवाही है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में मीटिंग समय पर हो और वहां के लोगों की जो भी सिफारिशें हैं वे यहां पर तय समय पर आ सकें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही तो आप करेंगे, बाकी इसके साथ-साथ आगे इसके बजट की क्या व्यवस्था है और कन्जर्वेशन के तहत इनके जो वर्षों पुराने तालाब हैं, क्या उनकी मरम्मत कराने का विचार रखते हैं, जिससे उसमें पानी रुक सके और जो भी जंगली जानवर हैं, उनके

(श्री कन्हैया लाल)

संरक्षण के लिए उनको पूरे साल भर पानी मिल सके, क्या इसकी व्यवस्था करने की मंशा रखते हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो समिति है, यह मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए बनाई गई है। अब जो कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें जो सुझाव आएंगे, उनके आधार पर जो सुझाव वहां के लोगों के भले के लिए हो सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

जहां तक आपने बजट की बात पूछी है तो हर वर्ष के बजट के आधार पर ही तय होता है। उसमें सरकार के द्वारा जो तय गाइडलाइन हैं, उनके आधार पर बजट का निस्तारण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में नवीन खेल स्टेडियम की स्थापना

156. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम रघुनाथपुरा में खेल स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये पंचायत समिति मुख्यालय पर खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी पंचायत समिति व तहसील को खेल स्टेडियम बनाये जाने के लिए चिन्हित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम रघुनाथपुरा में खेल स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप खेल से जुड़े हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बहुत खिलाड़ी हैं, क्या आप वहां स्टेडियम निर्माण का विचार रखते हैं?

नंबर दो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोटे से 10 लाख रुपये मैं देने का विचार रखता हूं, क्या राज्य सरकार 90 लाख रुपये स्टेडियम हेतु खर्च करने का विचार रखती है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बजट घोषणा 2021-22 के तहत प्रदेश में युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार किये जाने के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में एक खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक, सांसद निधि, जन प्रतिनिधि, जन सहयोग, सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अत: विधान सभा में पारित होने के उपरांत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाएंगे। आप 10 देंगे और 90 हम देंगे, ऐसा सम्भव नहीं हो पायेगा। बराबर-बराबर का, आप 50 दें और 50 हम दे देंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

जोधपुर संभाग में ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

157. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ई-मित्र संचालकों द्वारा सरकारी सेवा के पात्र आवेदकों से अनियमितता करने व फर्जी दस्तावेजों के नाम पर धनार्जन करने सम्बन्धी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जोधपुर संभाग में जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपयों की लागत से विभिन्न राजकीय कार्यालयों में स्थापित ई-मित्र

(श्री जगसी राम)

प्लस मशीनों का उचित रखरखाव नहीं किये जाने से ई-मित्र प्लस मशीनें खराब हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मशीनों के सदुपयोग नहीं किये जाने पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के ई-मित्रों की कार्य प्रणाली में प्रभावी सुधार लाने एवं ई-मित्र प्लस मशीनों के अधिकतम उपयोग हेतु जिलेवार अधिकारियों को पाबंद करने एवं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक बैठकें आयोजित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) विभाग को ई-मित्र कियोस्कों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली एवं फर्जी दस्तावेजों की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जोधपुर संभाग में जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 तक निर्धारित राशि से अधिक राशि लिये जाने की 170 एवं फर्जी दस्तावेजों से सम्बन्धित 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 156 ई-मित्र कियोस्कों पर शास्ति लगाने एवं अस्थायी रूप से बंद करने की कार्यवाही की गई है तथा 17 ई-मित्र कियोस्कों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता और सरकार को टेक्नोलोजी के माध्यम से जोड़े जाकर ई-मित्र की सेवाएं सेल्फ सर्विस कियोस्क से प्रदान करने के उद्देश्य से 9891 ई-मित्र प्लस मशीनें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर तक राशि रुपये 198 करोड़ की लागत से स्थापित की गई एवं 5000 ई-मित्र प्लस मशीनें शहरी क्षेत्र में राशि रुपये 119 करोड़ की लागत से स्थापित की गई हैं। इस प्रकार कुल 14891 ई-मित्र प्लस मशीनें प्रदेश में राशि रुपये 317 करोड़ की लागत से स्थापित की गई हैं। साथ ही, इसी लागत में इन मशीनों के उचित रखरखाव हेतु तीन वर्ष तक के Operational and maintenance की व्यवस्था करके दो फर्मों के माध्यम से मशीनों का रखरखाव करवाया जा रहा है। (अनुलग्नक-अ)

ये मशीनें जहां आमजन की आवाजाही रहती हो, यथा-राजकीय परिसरों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय, तहसील एवं उप तहसील मुख्यालय/पी.एच.ई.डी. कार्यालय, सी.एच.सी./पी.एच.सी., राजकीय महाविद्यालय/विद्यालय, न्यायालय परिसर, बस स्टैण्डों आदि एवं निजी परिसरों जैसे ई-मित्र कियोस्कों एवं मुख्य बाजारों आदि में स्थापित की गई हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रदेश में स्थापित 14891 ई-मित्र प्लस मशीनों में से 14811 मशीनों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, शेष 80 मशीनों पर कार्य नवगठित ग्राम पंचायतों पर भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र भवन नहीं बनने एवं बिजली एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है। इसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कर भवन तैयार होने के पश्चात् मशीनों की स्थापना कर उनको क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। प्रदेश के ई-मित्र की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु विभाग द्वारा नई Expression of Interest (EOI) 1 जनवरी, 2021 से लागू कर दी गई है, जिसमें स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) तथा ई-मित्र कियोस्क धारक की जवाबदेही तय की गई है। Expression of Interest (EOI) के द्वारा ई-मित्र कियोस्क धारकों को प्रति तीन माह में प्रशिक्षण प्रदान नहीं करने, ई-मित्र कियोस्क द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाने, नागरिकों को सेवा देने से मना करने, माह में एक भी लेन-देन नहीं करने इत्यादि पर ई-मित्र कियोस्क पर शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है। (अनुलग्नक-ब)

जिला/ब्लाक कार्यालय अधिकारियों द्वारा ई-मित्र की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें की जाती रही हैं। उक्त सम्बन्ध में बैठकें आगे भी नियमित रूप से की जाती रहेंगी। ई-मित्र प्लस मशीनों की अधिकतम उपयोगिता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में स्थापित 14891 ई-मित्र प्लस मशीनों में से 14811 मशीनों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इन मशीनों के माध्यम से आमजन द्वारा उपयोग में ली गई ई-मित्र सेवाओं के लगभग 31 लाख से अधिक तथा जनसूचना पोर्टल-2019 की सूचनाओं के लगभग 1 लाख 58 हजार से अधिक ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।

ई-मित्र प्लस (ग्रामीण) मशीनों के माध्यम से उक्त कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशिक्षण आदि मशीनों के द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संवाद, वेबिनार इत्यादि का प्रसारण आमजन के लिए किया जा रहा है। ई-मित्र प्लस मशीन के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। (अनुलग्नक-स)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो ई-मित्र चल रहे हैं, इनमें

(श्री जगसी राम)

अनियमितता पायी गयी और इनकी जांच भी करवायी गयी। जांच के उपरांत जिस फर्म को बंद किया है उसी फर्म ने दूसरे नाम से चालू करके पब्लिक से पैसा वसूल कर रही है। इस तरह से पब्लिक के साथ कुठाराघात किया जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उन फर्मों की दोबारा जांच कराकर जो दोषी हैं, जो ई-मित्र चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जो फर्म दोषी पायी जाती है, पहली बार में 7 से 15 दिन तक उस कियोस्क को निलंबित कर दिया जाता है और 1 हजार से 5 हजार तक की पैनल्टी लगाई जाती है। दूसरी बार में दोषी पाये जाने पर 15 से 30 दिन तक उसको सस्पैंड कर दिया जाता है और 10 हजार से लेकर के 50 हजार तक की पैनल्टी लगाई जाती है। तीसरी बार में शिकायत प्राप्त करने पर उसको हटा दिया जाता है। यदि आप इस तरह की फर्म की कोई स्पेसिफिक सूचना मुझे देंगे कि उसने तीसरी बार गलती की है और उस फर्म को यदि पुन: ई-मित्र का काम दे दिया गया है तो मैं उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं दूसरे नम्बर के बिन्दु का जवाब चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो ई-मित्र मशीनें लगाई गई हैं, वहां पर कई मुख्यालय ऐसे हैं, पंचायत समितियां ऐसी हैं, कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं, कई सरकारी विभागों के दफ्तर ऐसे हैं, वहां की मशीनें धूल चाट रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उचित कार्यवाही कर उन मशीनों का ई-मित्र पर जाने वाली क्षेत्र की जनता को सीधा फायदा देने के लिए आप प्रयास करेंगे क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि केवल 80 मशीनें जहां पंचायतें नहीं बनी हैं, उनको दे दी गई है, जैसे ही वहां पर भवन बनेंगे, वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जायेगा। हर पंचायत समिति पर हमने एक व्यक्ति को, जिस फर्म से हमने ई-मित्र से कियोस्क सम्बन्धी उपकरण लिये थे, उनका एक-एक आदमी हर पंचायत समिति स्तर पर रहता है। जैसे ही शिकायत मिलती है कि मशीन खराब हो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

गई है और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो तुरंत जाकर उस ग्राम पंचायत में उसको ठीक करने का काम करते हैं। एसडीएम और कलेक्टर महोदय इस बारे में मोनिटरिंग करते रहते हैं। फिर भी मुझे आप बता दें कि फलां-फलां गांव में मशीनें काम नहीं कर रहीं हैं या उनमें डिफेक्ट है तो मैं उनको ठीक करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

श्री जगसी राम (रेवदर): एक इसी से सम्बन्धित और है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री अध्यक्ष: आप अलग से लिखकर दे दें। प्रश्न था, जनरल में कहां पहुंच गये आप?

भीनमाल एवं रानीवाड़ा में फ्लोराइड-मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

158. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल एवं रानीवाड़ा के गांवों एवं ढाणियों को फ्लोराइडमुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नर्मदा का ईआर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, 2020 तक भी ईआर प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? वर्तमान प्रगति रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नर्मदा ईआर परियोजना के लिए क्लस्टर बनाकर पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा डीपीआर तैयार की गई है? यदि हां, तो डीपीआर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट की क्लस्टर डीपीआर अनुसार

(श्री नारायण सिंह देवल)

राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के 77 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 24 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र सांचौर के 112 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र आहोर के 22 ग्राम एवं विधान सभा क्षेत्र जालौर के 21 ग्राम, इस प्रकार कुल 256 ग्राम एवं इनकी ढाणियों तथा भीनमाल शहर की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए, इनमें निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा नहर आधारित ईआर आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 455.16 करोड़ की जारी हुई थी।

उक्त परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु मैसर्स एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा) को दिनांक 24.09.2013 को राशि रुपये 372.70 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर, अनुबंधक फर्म द्वारा दिनांक 04.10.2013 को इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया।

उक्त पेयजल परियोजना की स्वीकृति का सार संक्षेप विवरण तथा अनुबंधक फर्म को जारी किये गये कार्यादेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त परियोजना के कार्य धीमी गति से करने एवं तदनुसार तय प्रोरेटा अनुसार प्रगति नहीं देने के कारण, इसका 67 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया गया है। स्वीकृत परियोजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप उक्त परियोजना का कार्य अनुबंधक फर्म द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया तथा अभी तक इसका कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अनुबंध के प्रावधान/शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्म की रुपये 20.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है।

परियोजना के कार्यों की निर्धारित प्रगति नहीं देने एवं उक्त दिनांक से कार्य बंद किये जाने के कारण, अनुबंध के क्लाज-2 एवं 3 के तहत कार्यवाही

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

करते हुए इसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु विभाग द्वारा क्रमश दिनांक 14.07.2020 एवं 13.11.2020 को अनुबंधक फर्म को नोटिस जारी किये गये हैं।

(3) ईआर क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत जालौर जिले के उक्तानुसार शेष रहे 256 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु पूर्व में वर्ष 2016 में राशि रुपये 449.82 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी परन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त डीपीआर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तत्समय जारी नहीं की जा सकी। वांछित प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

सतही जल स्रोत नर्मदा नहर आधारित ईआर क्लस्टर पेयजल परियोजना के अंतर्गत जिला जालौर के विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के 77 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 26 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र सांचौर के 160 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र आहोर के 22 ग्राम एवं विधान सभा क्षेत्र जालौर के 21 ग्राम, इस प्रकार वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 306 ग्राम एवं इनकी ढाणियों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जल सम्बन्ध द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 द्वारा राशि रुपये 233.64 लाख की जारी की गई है। उक्त कार्य हेतु सलाहकार फर्म नियुक्त की जाकर परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किये जाने बाबत दिनांक 24.02.2021 को की गई बजट घोषणा में, उक्त पेयजल परियोजना (लागत 1 हजार 94 करोड़ रुपये) को भी सम्मिलित किया गया है।

(4) उक्तानुसार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ईआर क्लस्टर परियोजना की डीपीआर बनने के उपरांत, इसकी वास्तविक लागत के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाएगा।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री नारायण सिंह देवल)

पहला सप्लीमेंट्री सवाल माननीय मंत्रीजी से है कि ईआर प्रोजेक्ट की मुख्य पाइपलाइन लगाने का काम, आपने जवाब में बताया है कि 67 प्रतिशत हो गया है जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इसमें लेबर काम अधिकांश हुआ है, टैक्निकल काम एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है। इसका फिजिकल वेरीफिकेशन आप करवाएं, पुनर्मूल्यांकन करवाएं और यह काम कब तक पूरा होगा, अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन जवाबदार है? मंत्री महोदय, इनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? मेरी जानकारी में आया है।

श्री अध्यक्ष: आप इसका पहले जवाब आ जाने दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिस ठेकेदारी फर्म ने काम किया उसकी 20 करोड़ 98 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है। उनको समय-समय पर नोटिस दिये गये हैं। इनको एक्स.ईएन. ने 12 नोटिस दिये हैं। एक नोटिस दिया 08.05.2018 को, दूसरा 05.06.2018 को, तीसरा 12.06.2018 को, इस तरह से 12 नोटिस दिये गये। एसई द्वारा 8 नोटिस दिये गये और मुख्य अभियंता द्वारा 2 नोटिस दिये गये, टोटल 22 नोटिस इनको वक्त न वक्त दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि 70 प्रतिशत काम पूरा हुआ है तो मैं इसका फिजिकल वेरीफिकेशन करवाकर, इसका पूरा परीक्षण करवाकर सही जानकारी जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, उनको दे दूंगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ईआर प्रोजेक्ट की क्लस्टर परियोजना की डीपीआर आप कब तक मंजूर करवा देंगे और यह पूरा काम आप कब तक पूरा करेंगे क्योंकि यह जालौर जिले की पांचों विधान सभा क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने का काम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, केवल प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल भी तो बहुत लम्बा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न लम्बा थोड़े हो सकता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया है, इसकी अभी डीपीआर बनाने के लिए 2 करोड़ 33 लाख 64 हजार की मंजूरी 11.02.2021 को जारी कर दी गई है और बजट में भी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

घोषणा जो की गई है, 1094 करोड़ रुपये की राशि इस पर खर्च होगी और चूंकि पहले तो यह योजना पनघट योजना के रूप में थी, एक पनघट बनाकर पानी उपलब्ध करवा दिया जाता था, अब जल जीवन मिशन में घर-घर कनेक्शन दिये जाएंगे, इसके कारण से वृहद् डीपीआर बनाकर इस योजना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपकी एसपीएमएल कम्पनी है, ये नागौर में भी पहले ब्लैक लिस्ट हुई तो फिर इसको टेंडर कैसे दिया? आपने अपने जवाब में बताया कि हमने कम्पनी से 20 करोड़ रुपये पैनल्टी के रूप में वसूल किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 7 साल और 4 महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बताएं कि यह काम कब तक पूरा करेंगे और इसके लिए ये 1094 आपने जल जीवन मिशन में बताया, एक तरफ आप कह रहे हो कि डीपीआर बनी नहीं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। प्रश्न पूछो, ये क्या पूछ रहे हो? (व्यवधान) यह कोई प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): डीपीआर के लिए मैंने राशि स्वीकृत करने की बात बतायी। डीपीआर 31 अगस्त से पहले-पहले बन जाएगी और उसके बाद उसकी स्वीकृति हो जाएगी। जहां तक आपने डिले का कहा है, 2013 में प्रोजेक्ट सलेक्ट हुआ, पिछली सरकार आपकी पार्टी की सरकार थी, उसने ही डिले किया, उसने ही उनको ठेका दिया, ठेका देने के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार, हमने तो कम से कम उनको अलग-अलग स्तर पर 33 नोटिस दिये हैं। उनकी 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आज भी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रोक रखी है और हर तरीके से जो भी दोषी फर्म्स होंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेस उप-कर पर भारी ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने से व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मेन्द कुमार एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में फूड सेफ्टी कमिश्नर के पद पर नियम विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारियों का पदस्थापन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अधूरे पड़े बाईपासों का निर्माण कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों की चल रही हड़ताल से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के उप-नगर पुर में से होते हुए रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप-निरीक्षक भर्ती, 2021 के लिए जारी की गयी विज्ञप्ति में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रही भर्तियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु एवं परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में आने वालों गांवों के किसानों को के.सी.सी. तथा अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जालौर जिले के भीनमाल उप-खण्ड के थूर गांव की नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

दर्ज नहीं किये जाने के फलस्वरूप उसकी मां द्वारा आत्मदाह किये जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(10) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा अतिरिक्त चार्ज वाली ग्राम पंचायतों में समय पर गिरदावरी नहीं किये जाने से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ (जोधपुर) में नशा मुक्ति का संदेश देने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतारने पर आमजन में व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा बैंक से लिये गये ऋणों को जमा नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) योजना में किसी तरह की स्वीकृति नहीं निकालने से खनन प्रभावित क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज लाइन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फीस वसूली के अंतरिम आदेश की अवहेलना कर अभिभावकों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से ग्राम मोरीजा की सैकड़ों बीघा भूमि को भू-माफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की ग्राम पंचायतों के अधीन बोरिंगों के विद्युत बिल जमा नहीं होने से कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से थाना बिलाड़ा के ग्राम बोयल में हुए हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों के खातों में राशि हस्तान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री रामलाल शर्मा, श्री राजकुमार रोत, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्री पुखराज एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में आवारा कुत्तों, बंदरों व सूअरों के आतंक से आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से रानी नगरपालिका से मुण्डारा तक सड़क व पुलिया निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से नव क्रमोन्नत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ के लिए भूमि आबंटन किया जाकर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के परिसर में उद्यान, आडिटोरियम एवं आर्ट गैलरी निर्माण के स्थान पर श्री दिगम्बर जैन संस्थान कोटा द्वारा धर्म के प्रचार का कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों में

जनता जल योजना के नलकूपों के बिजली के बिल वाणिज्यिक दर पर जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से नदबई के उच्चैन तहसील मुख्यालय पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (एसीजेएम) खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से जैतसागर झील के संरक्षण, रख-रखाव के अभाव में हो रही दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रूपा राम (मकराना), सदस्य की ओर से मकराना शहर में सीवरेज लाइन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जवाई बांध की जल वितरण समिति में जैतारण विधान सभा क्षेत्र के विधायक को शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा दक्षिण नगर निगम के 8 वार्डों में चयनित/पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने एवं भोजपुर व रानीपुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(13) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से प्रदेश में जोगी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से भादरा शहर में बरसात के पानी की निकासी किये जाने की कार्ययोजना नहीं बनाये जाने से स्थानीय नागरिकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(15) श्री गोविन्द राम, सदस्य की ओर से खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ एवं दन्तोर में आबादी भूमि के पट्टे काटने का अधिकार ग्राम पंचायतों के सरपंचों को न दिया जाकर मण्डी समितियों को दिये जाने से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(16) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आवारा पशुओं से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बरसात के पानी की निकासी हेतु सड़कों पर रपटों की जगह पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

(18) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित बंदी के कारण गेहूं, चने की फसल को समुचित पानी नहीं मिलने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालीचरण सराफ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

निजी विद्यालयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फीस वसूली के अंतरिम आदेश की अवहेलना

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निजी स्कूलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अभिभावकों को फीस वसूली के मामले में परेशान किये जाने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 और 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूलों में कोई नियमित पढ़ाई नहीं हुई और ऑनलाइन पढ़ाई की केवल खानापूर्ति की गयी। कोरोना की वजह से मध्यम वर्ग के लोग, खासकर छोटे व्यापारी और निजी संस्थानों में नौकरी करने वाले लोगों के सामने भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उसके कारण वे निजी स्कूलों में अपने बच्चों की फीस जमा करवाने में असमर्थ रहे।

इस कारण निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकगण हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने कहा कि केवल 60 से 70 परसेंट फीस वसूल की जा सकती है। उसके खिलाफ निजी स्कूलों के जो प्रबंधक थे, वे माननीय सुप्रीम कोर्ट में

(श्री कालीचरण सराफ)

गये और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश निकालकर यह व्यवस्था की कि 6 किस्तों में 5 मार्च, 2021 से 5 अगस्त, 2021 तक फीस वसूली की जा सकती है। इसमें भी उन्होंने यह कहा कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, वे यदि निजी स्तर पर स्कूल प्रबंधकों से बात करें तो उन्हें रिलीफ दिया जाए।

तीसरा आदेश यह दिया कि कोई भी अभिभावक यदि फीस न दे पाये तो विद्‌यार्थी को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों के जो मालिक हैं, उन्होंने अधूरी व्याख्या की और टेलीफोन करके और घरों पर अपने स्टाफ को भेजकर जिस प्रकार से अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है तथा ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को वंचित किया जा रहा है, इसके खिलाफ कई अभिभावकों ने हमारी राज्य सरकार के जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन्हें लिखित में शिकायत की, परंतु उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि प्रदेश के 70 लाख इस प्रकार के अभिभावक हैं जो इससे परेशान हैं, और जिस प्रकार से निजी स्कूलों के प्रबन्धक उन पर दबाव डाल रहे हैं, उससे वे मानसिक तनाव की स्थिति में हैं इसलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। यदि इसके लिए कोई विधेयक लाने की आवश्यकता हो, कानून बनाये जाने की आवश्यकता है तो अभी विधान सभा चल रही है, इसके लिए कानून भी बनाया जाए और जो प्रदेश के अभिभावक इससे त्रस्त हैं, उनको राहत दिलाने का काम राज्य सरकार करे। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और मंत्री जी बैठे हैं, यह बहुत बड़ा मामला है, 70 लाख लोगों का है।

अध्यक्ष द्‌वारा सम्बोधन

शून्य काल में मंत्रीगण को सदन में उपस्थित रहना चाहिए

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में कोई रिप्लाई नहीं आयेगी। श्री रामलाल शर्मा। एक मिनट।

संसदीय मंत्री जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जीरो आवर में सभी मंत्री बैठेंगे, जब तक जरूरी हो तब ही जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। जीरो आवर में, स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री को बोलने नहीं देते हैं, 295 में भी बोलने नहीं देते हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जीरो-आवर यानी विधायी कार्य के पहले सारे मंत्री हाउस में मौजूद रहें।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा मेरा निवेदन है कि यहां सब मंत्रियों के चैम्बर हैं, तो जिनको व्यक्तिगत काम करना है वे सदन का उपयोग नहीं लें, चैम्बर में जाकर मंत्री से बात करें। उससे एक व्यवस्था रहेगी, नहीं तो जीरो आवर में हम सब जिस तरह की बात करते हैं उससे परम्परा ठीक नहीं रहती है। इसलिए मेरा इस सदन की गम्भीरता को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि मंत्री जीरो आवर तक हाउस में रहें, उसके बाद विधायी कार्य के समय में जिनका काम है वे मंत्री रहें, 3-4 मंत्री रहें लेकिन बाकी मंत्री आवश्यक हो तो परमिशन लेकर जाएं, लेकिन यह परम्परा बन गई कि जीरो आवर शुरू होते ही हम चले जाते हैं, मैं समझता हूं कि सदन की इसमें गरिमा नहीं रहती। मैं चीफ व्हिप से अपेक्षा करूंगा कि सदन में जीरो आवर में जितने भी मंत्री हैं उनको यहां उपस्थित रहना डिजायरेबल है, नहीं तो स्थगन प्रस्ताव, 295 की महत्ता खतम हो जाएगी। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि इसका पालन किया जाए।

श्री रामलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मोरीजा (चौमूं) की भू-माफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द भूमि

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सरकार कहती है हम तो ट्रस्टीशिप हैं और ट्रस्टीशिप करने के लिए आये हैं लेकिन सरकार के अधिकारी, अगर बाड़ ही खेत को खाने लग जाए, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मोरीजा के अन्दर ठाकुर अमरसिंह के पास 585 बीघा जमीन थी। वे 585 बीघा जमीन में से 314 बीघा जमीन श्री करणी संयुक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति जो बिना रजिस्टर्ड थी, उसके नाम 1964 में रजिस्ट्री कराते हैं। 1964 में 314 बीघा की रजिस्ट्री कराने के उपरांत ग्राम पंचायत के पास नामान्तरण के लिए आते हैं तो ग्राम पंचायत ने मना कर दिया कि यह सीलिंग की जमीन है, यह सरकार की जमीन है, हम इसका नामान्तरण तस्दीक नहीं करेंगे। तत्कालीन एसडीएम, आमेर के पास ये व्यक्ति जाते हैं, 13 व्यक्ति होते हैं, 13 व्यक्तियों के नाम से इस जमीन की रजिस्ट्री करायी जाती है। ये एसडीएम, आमेर के पास जाकर एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारा नामान्तरण तस्दीक किया जाए। ग्राम पंचायत मोरीजा के इन्कार करने के बाद चीथवाड़ी ग्राम पंचायत में

(श्री रामलाल शर्मा)

नामान्तरण तस्दीक करते हैं 1025 बीघा और 1025 बीघा की जमीन का नामान्तरण तस्दीक होने के बाद तहसीलदार ने जांच करने के बाद पाया कि इस जमीन में 440 बीघा तो गोचर जमीन है, जिसका नामान्तरण गलत तस्दीक किया जाता है। इन 13 व्यक्तियों के अन्दर एक व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता है, स्टे होने की वजह से वह नामान्तरण जो 440 बीघा का, जिसके लिए तहसीलदार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, गोचर जमीन है, वह तस्दीक नहीं हो पाता क्योंकि उसके ऊपर था।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 2005 के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड से रिमांड होकर पत्रावली तहसीलदार, चौमूं के पास आती है। तहसीलदार, चौमूं ने 2005 में कहा कि यह सारी की सारी जमीन सीलिंग की है, सरकार की है और उस नामान्तरण को निरस्त करते हुए ठाकुर अमरसिंह के नाम से वह नामान्तरण खोलकर तत्काल एसडीएम, चौमूं के यहां एक सीलिंग का प्रकरण दर्ज कराया जाता है। 2005 में सीलिंग का प्रकरण दर्ज कराने के बाद एसडीएम की बदनीयती के उपरांत एक पुनीत नाम का व्यक्ति, जो पक्षकार नहीं होते हुए भी उसके प्रार्थना पत्र के ऊपर तत्कालीन एसडीएम, चौमूं ने तहसीलदार, चौमूं के आदेश पर स्टे देकर इस करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आज की तारीख के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर निगरानी विचाराधीन है, यथास्थिति के आदेश हैं, हाई कोर्ट से यथास्थिति के आदेश हैं, उसके बाद भी भू-माफिया 1025 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। वहां पर तारबंदी करने का काम कर रहे हैं, उस जमीन के ऊपर निर्माण करने का काम कर रहे हैं, ट्यूबवैल कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि यह जमीन आपकी है, यह जमीन सरकार की है, सीलिंग की जमीन है, इस जमीन को बचाने के लिए जो भी मौके के ऊपर यथास्थिति के बावजूद अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करायें और उस समय से लेकर अब तक जिन भी लोकसेवकों ने अपराध किया है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज कराकर उसकी जांच करायें ताकि निष्पक्ष जांच के आधार पर यह बेशकीमती जमीन बच सके और सरकार भी जनता को यह एहसास कराये कि सरकार ट्रस्टीशिप के रूप में काम कर रही है, बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री

(श्री रामलाल शर्मा)

महोदय, आप बहुत संवेदनशील हैं, आप ऐसे मामलों में बहुत गम्भीर रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जांच कराने के आदेश दें कि जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच भी कराएंगे और उस जमीन को बचाने का भी काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री राजकुमार रोत।

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को आवासीय पट्टे

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 50 पर बोलने का अवसर दिया। आज जो विषय है वह यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है। इस इलाके में बिलानाम की भूमि पर या फिर कृषि भूमि पर या हाल ही में वन विभाग की भूमि पर जो रह रहे हैं, उनका तो प्रोसेस चल रहा है लेकिन जो लोग कृषि भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, उन लोगों को अब तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। पिछली बार मैंने सदन में क्वेश्चन लगाकर जानकारी प्राप्त की थी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 84047 आदिवासी परिवार रह रहे हैं और इनमें से 1832 लोगों के पास ही मकान का पट्टा है। यही स्थिति पूरे उदयपुर सम्भाग में है। इससे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति सरकार से कोई लाभ लेना चाह रहा है या फिर लोन लेना चाह रहा है तो उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है और कभी भी इस इलाके में कोई फैक्टरी लग रही है, कोई सड़क बन रही है या कोई बड़ा उद्योग, कारखाना खुल रहा है तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास मकान का पट्टा नहीं है, तो उन लोगों को मुआवजे के बिना ही खाली करवा दिया जाता है। यही स्थिति नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में भी है। वहां पर डूंगरपुर नगर परिषद् है, वहां पेरीफेरी का इलाका आता है, वहां लोग लम्बे समय से डिमांड कर रहे हैं और वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है और उन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है। वैसी ही सेम स्थिति ग्रामीण इलाकों में भी है। मेरा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग कृषि भूमि में रह रहे हैं, उसमें राजस्व विभाग हस्तक्षेप कर उन सभी को आवासीय मकान का पट्टा दिया जाए और जो बिलानाम की भूमि पर लम्बे समय से रह रहे हैं, उनको भी अपने मकान का पट्टा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर के ग्रामीण इलाकों में बोरिंग के कटे विद्युत कनेक्शन

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी तो गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है और मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्दर पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस समस्या के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और इस विभाग के अधिकारियों से समय-समय पर मिलता रहा हूं। और तो और, अभी बजट आने से कुछ दिन पूर्व भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में मिला और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आने वाले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की इस समस्या का समाधान निकालकर कुछ न कुछ मुझे देंगे, परन्तु एक बार पुन: मेरे क्षेत्र की अनदेखी कर, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात कर उन्होंने पीने के पानी का कोई भी प्रावधान मेरे क्षेत्र के लिए नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या तो बनी हुई है और आगे बात करें ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली सभी योजनाओं से लगे हुए बोरिंगों की, तो इनके विद्युत के कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। जब समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग से बात की जाती है तो विद्युत विभाग के अधिकारी बोलते हैं कि उनके बिजली के कनेक्शन का बिल जमा नहीं हुआ और जब बात बीडीओ, सरपंच से की जाती है तो कहते हैं कि ग्राम पंचायतों के पीडी खाते में बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं और जलदाय मंत्री भी ये ही हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो वे ग्राम पंचायतों के पीडी खाते में पैसा जमा करें, जिससे उनके बिजली के बिल जमा हों और वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके अन्यथा इस समस्या का कोई और समाधान निकालकर उन बोरिंग के कनेक्शन वापस चालू करें जिससे वहां के लोगों को इस गर्मी में पीने का पानी मिल सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुन: आग्रह करूंगा कि आप उन्हें निर्देशित करें और इस समस्या का हल निकालकर आपकी तरफ से मुझे जवाब दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

बोयल (बिलाड़ा) हत्याकांड

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक नृशंस हत्या की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पीपाड़ पंचायत समिति के बोयल गांव के अंदर, गांव के सभी लोगों ने एक सामूहिक सभा करके, जो गांव के सरपंच जयसिंह चौहान हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग करके, गांव ने एक सामूहिक डिसीजन लिया कि गांव के अंदर अवैध दारू और अवैध स्मैक के व्यापार को पूरी तरह से रोका जाए। उस सामूहिक डिसीजन के अंदर उस गांव का श्रवण पुत्र श्री भगवानाराम भी उपस्थित था और श्रवण की अपनी एक कल्पना थी कि मेरा गांव नशामुक्त हो, मेरे गांव के युवा दिग्भ्रमित न हों, मेरे गांव का युवा सही दिशा में चले लेकिन अवैध कारोबार करने वाले, अवैध शराब और स्मैक बेचने वाले लोगों ने उस श्रवण को डराकर चेतावनी दी कि आप जो हमारा विरोध कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। इस अवैध धमकी की श्रवण ने सीओ, बिलाड़ा को सूचना दी लेकिन सीओ बिलाड़ा ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की और दूसरे दिन ही शाम को श्रवण की उन लोगों द्वारा उसी गांव के अंदर बुलाकर उसकी नृंशस हत्या कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि ऐसी नृशंस हत्या, जो व्यक्ति नशा मुक्ति जैसे संवदेनशील मामले में पैरोकारी करता हो, जो व्यक्ति अपने युवाओं को सही दिशा देने की बात करता हो, जिस व्यक्ति ने अपने गांव को नशा मुक्त कराने का संकल्प लिया हो, उसकी नृशंस हत्या हो जाना और 40 घंटे बाद भी हत्यारों का पकड़ा नहीं जाना, बड़ी शर्म की बात है। विशेषकर, उस सरकार से जो सरकार हमेशा गांधीवादी विचारों पर चलने की बात करती है और हमारे स्व. छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि देती है। उस सरकार के लिए और विशेषकर मुख्य मंत्री जी का गृह जिला है, आज भी उस श्रवण का परिवार और सम्पूर्ण गांव वहां बिलाड़ा के अंदर धरने पर बैठा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपये दें और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दें क्योंकि जो मृतक श्रवण है, उसके पिताजी भी मानसिक रोगी हैं और अन्य कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर वक्तव्य दे और शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार करे, परिवार को आर्थिक सहायता दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सरपंचों द्वारा पंचायत समितियों पर धरना-प्रदर्शन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में 11 हजार 344 निर्वाचित सरपंच पंचायत समितियों के सम्मुख धरना दे रहे हैं। 5 तारीख को पूरे राजस्थान में, सारे सरपंच जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 8 मार्च से विधान सभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रारम्भ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् आर्टिकल 243 में व्यापक संशोधन करके, एक युग प्रारम्भ हुआ था पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक रूप से स्वायत्तता का। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस आर्टिकल में जो संशोधन हुआ, उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार वित्त आयोगों के माध्यम से एक निश्चित अपने शुद्ध राजस्व के अंदर, ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे, उन पंचायतों की निश्चित प्रतिशत की राशि निक्षेप करेंगे, इस प्रकार का आदेश हुआ।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 243(आई) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि महामहिम राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे और राज्य वित्त आयोग, राज्य की शुद्ध राजस्व आय के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले पैसों के लिए एक प्रतिशत निर्धारित करेंगे। 5वां वित्त आयोग बना, 1 अप्रैल, 2015 को और उसका समय समाप्त हो गया 31 मार्च, 2020 को। दुर्भाग्य है राजस्थान में पहली बार संविधान में प्रदत्त जो प्रावधान किये गये हैं, उनको धता बताकर छठा वित्त आयोग नहीं बना और इसी कारण से 2020-21 और 2021-22 के अंदर एक फूटी कौड़ी भी राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के खाते में नहीं गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बात यहीं खतम नहीं हुई। जो 5वां वित्त आयोग है, अभी आर्थिक समीक्षा 2021-22, मैं सदन का ध्यान पृष्ठ 57 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें आपने कहा कि राज्य के कुल शुद्ध राजस्व में 7.18 परसेंट राशि पंचायती राज संस्थानों को और नगरीय स्थानीय निकायों को 75 परसेंट और 25 परसेंट के हिसाब से वितरित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है, 2019-20 के अंदर जो पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए था, वह 2020-21 में जारी किया गया, 2019-20 का पैसा है। 2020-21 का जारी हुआ नहीं, पर 2019-20 का पैसा जो 2020-21 में जारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया। यह मैं नहीं कह रहा, आपकी आर्थिक समीक्षा की वह पुस्तक कह रही है, जो आपने हमें दी। 2 हजार 267 करोड़ रुपये आपने जारी किये और उसमें से 31 दिसम्बर तक खर्च हुए 434 करोड़ रुपये, उसमें भी उन ग्राम पंचायतों को एक पैसा नहीं गया, 293 करोड़ रुपये पंचायतों के सहायकों को सीधा मानदेय आपने दिया और 49 करोड़ रुपये जो आपका कोविड-19 स्पेशल है, वहां गया। एक रुपया भी, दुर्भाग्य है कि दो वर्षों में राज्य वित्त आयोग से मिलने वाला, ग्राम पंचायतों में एक पैसा नहीं गया और उसी कारण से आज किसी भी गांव के अंदर एक भी काम अगर इस सरकार के आने के बाद का बता दो तो आप कहो मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। 15वें वित्त आयोग का जो केन्द्र सरकार का पैसा है, उसमें 2020-21 की जो किस्त थी 2 हजार करोड़ रुपये की, आपने जारी की 1931 करोड़ रुपये और उसमें व्यय हुआ 677 करोड़ रुपये, क्योंकि आपने पीडी खाते के अंदर, ट्रेजरी के पीडी खाते में सारी राशि जमा कराने का फैसला कर लिया। मैं समझता हूं जिन पंचायती राज संस्थानों का शुभारम्भ 1952 में जगादरी, नागौर से हुआ, उसका सत्यानाश आप कर रहे हो, उनकी वित्तीय स्वायत्तता को आप नष्ट कर रहे हो। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपने आज कहा कि जीरो आवर में मंत्री रहें और संज्ञान लें। आप जवाब मत दो, पर यहां से गूंजकर यह बात जाएगी, ग्राम पंचायतों के सरपंच 8 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना देंगे और आपको धता बताएंगे।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री संजय शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अलवर शहर में पार्कों की बदहाली एवं आवारा पशुओं का आतंक

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम-295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पार्कों की बदहाल स्थिति एवं आवारा कुत्तों, बंदरों व सूअरों के आतंक से आमजन को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में राजस्थान आवासन मंडल व नगर विकास

(श्री संजय शर्मा)

न्यास, अलवर द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों के पार्कों की विभाग द्वारा समय-समय पर देखभाल नहीं करने से उक्त पार्कों की दीवारें टूटी हुई हैं तो कहीं लाइटें खराब हैं तो कहीं पर पेड़-पौधों का नामोनिशान तक नहीं है। सिर्फ सूखी झाड़ियां ही दिखाई देती हैं तथा उक्त पार्कों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।

अलवर शहर की सड़कों व पार्कों में आवारा पशु, सूअर, बंदरों व कुत्तों का समूह दिखाई देता है, जिसके कारण क्षेत्र की आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्र में आवारा कुत्तों व बंदरों द्वारा आम जनता को काटने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उक्त समस्याओं के चलते अलवर शहर में रहने वाले आमजन को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर की जनता को आवारा कुत्तों, बंदरों व सूअरों के आतंक से निजात दिलाएं तथा पार्कों की उचित देखभाल की व्यवस्था किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

चाणोद से मुंडारा वाया केनपुरा रानी सड़क निर्माण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि चाणोद से मुंडारा वाया केनपुरा रानी 51 किलोमीटर रोड, एमडीआर, जिसके लिए पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने स्टेट रोड फंड के तहत लगभग 34 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे, यह रोड जिसकी चौड़ाई 3 मीटर थी, उसको 7 मीटर चौड़ा करना और रास्ते में जितने भी नाले थे, उस पर पुलिया निर्माण करवाने का कार्य स्वीकृत किया। यह कार्य जनवरी, 2018 में प्रारम्भ हुआ और मार्च, 2019 तक ठेकेदार को कार्य पूर्ण करना था परंतु आज तक वह 19 किलोमीटर का कार्य जो रानी नगरपालिका से मुंडारा तक अधूरा पड़ा हैं और दोनों तरफ रोड के किनारे खड्ढे खुदे पड़े हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और इस मार्ग पर कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाए व जो रोड निर्माण हो चुका है उसकी गुणवत्ता की भी जांच करवाई जाए

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और पुन: निविदा जारी कर निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके व दुर्घटनाओं का सिलसिला चला आ रहा है, वह समाप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कान्ति प्रसाद।

प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आबंटन

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत मुख्यालय प्रतापगढ़ कस्बे एवं आसपास के गांव जैसे पडाक, छापली, आमका, चौसला, लालपुरा, चावा का बास, भूरिया वास, टोडा, झिरी, सांवतसर, डुमोली, समरा, टिगरिया, हमीरपुर, नटाटा, कालेड, पिपलाई, काला पारा, निंझरा, कलसीकाला, पलासना, खोलाई, लोठावास आदि गांवों को मिलाकर कुल आबादी लगभग पचास हजार है। इतनी बड़ी आबादी के गरीब तबके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आमजन के इलाज उपचार हेतु हाल ही में नव क्रमोन्नत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ़ के पास पर्याप्त भवन सुविधा नहीं है। भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन पत्रावली सरकार के पास विचाराधीन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन औसतन 500 मरीजों की ओपीडी है। बड़ी संख्या में स्थानीय एवं आस पास के उक्त वर्णित गांव से डिलीवरी के लिए माता-बहनें स्वास्थ्य केन्द्र पहुंच रही हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान में रोगियों के बैठने, इलाज, उपचार के लिए तथा चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ के लिए पर्याप्त भवन सुविधा उपलब्ध नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नव क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के आवश्यकतानुसार पद उपलब्ध नहीं हैं। आवश्यक मेडिकल मशीनरी, जांच मशीनें, आपरेशन थिएटर एवं विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं हैं। सरकार से आग्रह है कि सर्वप्रथम स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आबंटन के विचाराधीन प्रकरण में आबंटन पत्र जारी करवाकर आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण, आवश्यक सुविधाओं सहित मेडिकल स्टाफ, विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत कर प्रतापगढ़ कस्बे एवं आस पास के उक्त वर्णित गांव की 50 हजार की आबादी को सरकारी क्षेत्र की सुलभ नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ देकर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर में श्री दिगम्बर जैन संस्थान, कोटा द्वारा धर्म का प्रचार

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 91वीं बैठक दिनांक 14.03.2015 के प्रस्ताव संख्या 91/6 में लिये गये निर्णय की पालना अनुसार विश्वविद्यालय के परिसर में उद्यान, आडिटोरियम एवं आर्ट गैलरी के निर्माण के स्थान पर श्री दिगंबर जैन संस्थान, कोटा द्वारा धर्म के प्रचार का कार्य करवाने बाबत निवेदन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी धर्म का प्रचार निषेध है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का नाम भगवान महावीर के नाम पर है मगर इस विश्वविद्यालय पर जैन धर्म का अधिकार नहीं है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के आब्जेक्ट अनुसार बिंदु संख्या (XII) पर उल्लेख है कि विश्वविद्यालय दानदाता से Donations, Grants, aid व gift प्राप्त कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल की 91वीं बैठक दिनांक 14.03.2015 के प्रस्ताव संख्या 91/6 के अनुसार श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान को उद्यान, आडिटोरियम व आर्ट गैलरी के निर्माण की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी।

श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान, कोटा एक धार्मिक संस्थान है, जो अपने धर्म का प्रचार करती है। नियम अनुसार धार्मिक प्रचार संस्थान को धर्म प्रचार हेतु विश्वविद्यालय का उपयोग निषेध है। दिनांक 14.03.2015 को स्वीकृति प्राप्त होने के 19 दिन बाद ही श्री दिगंबर जैन संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 02.04.2015 को विशाल धार्मिक कार्यक्रम व धर्म सभा कर धर्म का प्रचार किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। इस भूमि को प्राप्त करने का यही लक्ष्य था। श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान ने विश्वविद्यालय को आज तक न तो कोई डोनेशन दिया है और न ही प्राप्त स्वीकृति अनुसार उद्यान, आडिटोरियम व आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है।

धर्म प्रचार हेतु जो अधूरा सभागार बना हुआ दिखाई देता है उसकी सम्पूर्ण राशि 65 लाख रुपये मई, 2016 में विधायक व सांसद कोष से प्राप्त

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

की गई है। श्री दिगंबर जैन संस्थान तो कार्य के निर्माण की मात्र कार्यकारी संस्था ही थी। सांसद व विधायक कोष का पैसा धार्मिक संस्थान को नहीं दिया जा सकता था इसलिए इसे विकल्प के तौर पर विश्वविद्यालय को देना दिखाया गया है। इसी राशि को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने जानबूझकर डोनेशन का रूप प्रदान कर छल किया है।

विडम्बना तो यह है कि श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान ने दिनांक 10.03.2015 को विश्वविद्यालय के सामने अपनी मांग रखी थी व दिनांक 12.03.2015 को इस पर विचार किया गया व दिनांक 14.03.2015 को विश्वविद्यालय द्वारा सहमति व्यक्त कर दी गई। मात्र 5 दिन में ही सब कुछ कैसे सम्भव हो गया? सरकार से यह मांग है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय व श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान के बीच हुआ समझौता रद्द किया जाए। दोषी लोगों के खिलाफ सांसद व विधायक कोष की राशि का दुरुपयोग करने हेतु कार्यवाही की जाए व यह राशि उनसे वसूल की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

ग्राम पंचायतों में संचालित जनता जल योजना

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश के कई गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों की जिम्मेवारी जनता जल योजना के माध्यम से निर्धारित कर रखी है, जो ग्राम पंचायतों के लिए अभिशाप है। मेरे क्षेत्र की कई पंचायतें तो पूरे वर्ष का बजट बिजली का बिल भरने में खर्च कर देती हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है कि दोनों विभाग जलदाय और बिजली के आपस में सामंजस्य नहीं रखने से पंचायतों पर लाखों रुपये का व्यय भार अतिरिक्त पड़ता है। इसका एकमात्र कारण है कि यह जो बिजली कनेक्शन नलकूपों पर दिये गये हैं उनको वाणिज्यिक माना गया है, जबकि बिजली सप्लाई कृषि फीडरों से दी जाती है।

बिलिंग ऊर्जा विभाग द्वारा कामर्शियल उपयोग से की जा रही है, जो नियम अनुसार गलत है। बिजली का बिल उपयोग के अनुसार साधारण श्रेणी से ही जारी होना चाहिए। सभी पंचायतों में जनता जल योजना के जो नलकूप चल रहे हैं वह एग्रीकल्चर उपयोग बिजली तंत्र से चल रहे हैं जबकि ऊर्जा विभाग लाखों रुपये का बिल वर्षों से पंचायतों से वसूल रहा है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों से जनता जल योजना को वापस जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को सुपुर्द किया जाए अन्यथा जो गलत बिजली बिल जारी हो रहे हैं, उनको सही करवाकर राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन तहसील मुख्यालय पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन तहसील मुख्यालय पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (एसीजेएम) खोलने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन तहसील मुख्यालय पर कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को उनकी कोई भी न्यायिक समस्या के समाधान के लिए उनके निवास स्थान से दूर बयाना के एसीजेएम न्यायालय तथा रूपवास के मुंसिफ न्यायालय में जाना पड़ता है, जो कि क्रमश: 28 व 26 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण उनके आने-जाने में होने वाले खर्च से उनकी आर्थिक स्थिति जो पहले से ही खराब है, उस पर काफी प्रभाव पड़ता है तथा उच्चैन से पुलिस को मुलजिमों को जे.सी. के लिए रूपवास व बयाना जाना पड़ता है। राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर एसीजेएम न्यायालय स्थापित हैं परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र की उच्चैन तहसील मुख्यालय में एसीजेएम न्यायालय स्थापित नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को उक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन तहसील मुख्यालय पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की कृपा करें, जिसके लिए मैं व मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में आये दिन डकैती हो रही है, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। दिनांक 15.12.2020 को बदाराम मार्डर्न फैक्टरी से घर जा रहा था, तब चोरों ने ट्रोमा सेंटर के पीछे मारपीट करके हाथ तोड़ा। दिनांक 16.12.2020 को भंवर पुत्र श्री कालाजी मोरडू को भी उसी जगह पर लूटपाट और मारपीट की गई। दिनांक 23.12.2020 को अमृतलाल कैमला कालोनी में मारपीट की और हाथ की उंगलियां तोड़ दीं। तीन चोरों में से एक चोर को लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उसे पुलिस के हवाले किया गया लेकिन उस चोर से पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई और जो आपके साथ 2 भाग गये वह भागने वाले कौन थे, यह पुलिस वालों ने उससे क्यों नहीं पूछा?

दिनांक 12.02.2021 को रात 8 बजे गांव भारजा रोड पर हरजीराम अध्यापक को आंखों में मिर्ची डालकर मोटरसाइकिल, मोबाइल, रुपये लूट ले गये। इसी दिन 12 बजे नाबाराम गरासिया और गांव के निकट मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं रुपये लूट कर भाग गये। चोरों के 2 वर्ष में हौसले बढ़े हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार चोरों के प्रति गंभीर नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

जैतसागर झील की दुर्दशा

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के बूंदी शहर क्षेत्र में प्रसिद्ध ऐतिहासिक जैतसागर झील की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। इसके रखरखाव व संरक्षण के अभाव में आमजन इसमें कचरा डालते हैं। विगत कई वर्षों से इस झील में कमल गट्टों की भरमार होने से पूरी झील कमल गट्टों से सराबोर हो गई है। यह झील 4455 हैक्टेयर में फैली है और वाइल्डलाइफ के अधीन आती है। वर्ष 2008 में जैतसागर झील को विश्व झील संरक्षण योजना में शामिल कराने के प्रस्ताव बने थे परंतु यह सिर्फ कागजी कार्यवाही बनकर रह गई।

(श्री अशोक डोगरा)

इस झील पर मालिकाना हक सिंचाई विभाग का है और वर्तमान में यह झील सिंचाई विभाग के काम में नहीं आ रही है। सिंचाई विभाग ने इसे नगर परिषद् को सौंपने के बाद वर्तमान में यह 3 विभागों के अधीन आ रही है, जिसमें नगर परिषद्, जल संसाधन विभाग और वाइल्डलाइफ विभाग है।

राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को प्रस्ताव बनाकर जानकारी चाही थी परंतु तत्कालीन जिला कलेक्टर, बूंदी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे आज झील की यह दुर्दशा हो रही है। जैतसागर झील जो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसका संरक्षण किया जाता है तो यह पर्यटन नगरी बूंदी को विश्व पटल पर और आगे ले जा सकती है।

अतः जैतसागर झील बूंदी जो कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का हिस्सा भी है, को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शुमार कराने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाए ताकि पर्यटन नगरी बूंदी की इस ऐतिहासिक झील का सौंदर्यीकरण, रखरखाव हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपा राम (अनुपस्थित)। श्री अविनाश।

जवाई जल वितरण कमेटी में जैतारण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत जवाई बांध से पिछले वर्ष की तुलना में कम पेयजल की उपलब्धता के क्रम में एवं जवाई जल वितरण कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निवेदन है कि कल दिनांक 07.10.2020 को श्रीमान संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में बांध कमांड एरिया से सिंचाई व पेयजल के बंटवारे को लेकर वीसी (वीडियो कांफ्रेंस) के माध्यम से बैठक रखी गई। उक्त बैठक में संभागीय आयुक्त के द्वारा कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए 4000 एमसीएफटी व पेयजल के लिए 2192.51 एमसीएफटी पानी आरक्षित किया गया।

पिछले वर्ष तत्कालीन संभागीय आयुक्त श्रीमान बाबूलाल कोठारी की अध्यक्षता में सिंचाई हेतु 3400 एमसीएफटी व पेयजल हेतु 2586 एमसीएफटी पानी आरक्षित किया गया था, जिसमें से 2363 एमसीएफटी पानी का उपयोग पेयजल के लिए किया गया। पेयजल की उपलब्धता के उपरांत भी पाली शहर में वाटर ट्रेन के द्वारा पानी की आपूर्ति की गई। मेरी विधान सभा पाली जिले के अंतिम छोर पर स्थित है। विधान सभा क्षेत्र जैतारण की पंचायत समिति

(श्री अविनाश)

जैतारण व रायपुर के 125 गांवों को जवाई जल योजना से लाभान्वित करने की योजना स्वीकृत है, जिसमें से आज तक लगभग 50 गांव को जोड़ लिया गया है, जिसमें अभी तक 20 से 25 गांवों में ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही मार्च, 2021 तक लगभग 35 से 40 गांवों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें भी अतिरिक्त पेयजल की आवश्यकता होगी।

मेरे विधान सभा का क्षेत्र अंतिम छोर पर होने के कारण पंचायत समिति रायपुर की अधिकांश पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जवाई जल योजना से जुड़े 50 गांव में भी पानी की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। इसी क्रम में मेरा श्रीमान से निवेदन है कि पेयजल आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 393.49 एमसीएफटी पानी का आरक्षण कम किया गया, जबकि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही इस वर्ष 35 से 40 अतिरिक्त गांवों को जवाई जल योजना से जोड़ दिया जाएगा, इनके लिए भी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी।

अतः इस सम्बन्ध में श्रीमान से आग्रह है कि एक बार पुन: इस पर विचार करते हुए पेयजल हेतु अतिरिक्त पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुन: पूर्व की भांति पेयजल आरक्षण लागू कराएं एवं जवाई जल वितरण कमेटी में जैतारण क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए मुझे भी मनोनीत कर उपरोक्त कमेटी का पुनर्गठन करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

कोटा दक्षिण नगर निगम के आठ वार्डों में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोटा दक्षिण नगर निगम में आने वाले 8 वार्डों में चयनित/पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिन लोगों ने मकान बना लिए, उनकी भी राशि नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नहीं दी जा रही है। लोग चक्कर काट-काटकर परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं जिन लोगों को प्रथम किस्त की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई थी, यूआईटी द्वारा उस राशि की निकासी पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों ने पैसे उधार लेकर आवास का निर्माण करवाया और यह सोच

(श्री मदन दिलावर)

कर कि राशि मिलते ही उधार चुका दूंगा लेकिन उन लोगों के साथ नाइंसाफी की गई, अब लोग उधारी का भी तकाजा कर रहे हैं।

महोदय, नगर विकास न्यास में इन गरीबों के आवासों की स्वीकृति व निर्माण में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। जो लोग चयनित और पात्र थे, उनके नाम काटकर मोटी राशि लेकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिये गये और सरकार की ओर से अनुदान की राशि षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर बंदर बांट कर ली गई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन गरीब लोगों का क्या दोष है जो झोंपड़ी/कच्चे आवास में रह रहे हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की स्वीकृति दी गई? फिर ऐसे गरीब लोगों को यूआईटी आवास का भुगतान क्यों नहीं कर रही है और दी गई राशि पर क्यों रोक लगाई गई है? मुझे तो पूरी आशंका है कि यूआईटी के अधिकारी व कर्मचारी 000 गरीबों की अनुदान राशि पर डाका डालकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, जो लिखा है वह बोलें, यह गलत परम्परा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या हो गया, साहब?

श्री अध्यक्ष: आप जो लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक शब्द भूल गया था।

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नहीं है, यह गलत परम्परा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं आपके माध्यम से यह भी जानना उचित समझता हूं कि यूआईटी ऐसे सभी लाभार्थियों को कब तक बकाया राशि का भुगतान कर उनके आवास पूर्ण करवा देगी? साथ ही जिन लाभार्थियों के खातों से राशि की निकासी पर अकारण रोक लगाई गई है, उन्हें कब तक राशि निकासी के लिए आदेशित कर दिया जाएगा। यह काफी लोक महत्व का मामला है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन तथा भोजपुर व रानीपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के

(श्री गोविन्द प्रसाद)

माध्यम से निवेदन है कि मेरी विधान सभा में समय-समय पर विभिन्न सरकारों में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थान जैसे उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, परंतु उक्त संस्थाओं को खोलने के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मापदंड निर्धारित नहीं होने के कारण कई संस्थाएं ऐसे स्थानों पर खोली जाती हैं जहां उसकी आवश्यकता या तो नहीं होती है अथवा उस चिकित्सा संस्था के अनुरूप वहां पर निर्धारित जनसंख्या भी नहीं होती है तथा बिना किसी उचित प्रस्ताव अथवा मापदंड चिकित्सा संस्थान खोल दिया जाता है। भवन निर्माण एवं स्टाफ पर लाखों रुपये की राशि खर्च कर दी जाती है, जिसके लिए सरकार में कोई जिम्मेदार नहीं होता है, जबकि जिन स्थानों पर चिकित्सा संस्थान खोलने अथवा क्रमोन्नत करने की आवश्यकता होती है, वहां किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है।

अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि जब भी नये चिकित्सा संस्थान खोले जाएं, उसके लिए राजनैतिक घोषणा के साथ-साथ वहां की भौगोलिक एवं जनसंख्या का भी ध्यान रखा जाए, जिससे चिकित्सा संस्थानों एवं स्टाफ के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग न हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में निम्नलिखित उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि क्षेत्र की जनता को उचित स्वास्थ्य मिल सके:-

उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पीएचसी में क्रमोन्नत करें-

1. कोलूखेडी कलाकला, 2. ल्हास, 3. शोरती, 4. आमेठा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें-

1. जावर, 2. घाटोली, 3. सरड़ा, 4. चुरेलिया, 5. भालता।

नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु-

1. भोजपुर, 2. रानीपुरा।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

जोगी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल करना

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियम 295 के अंतर्गत

(श्री मदन प्रजापत)

प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कई जातियां पायी जाती हैं, जिसमें जोगी (कालबेलिया), नाथ व सपेरा भी कह दो, यह जाति भी प्रमुख है। इस जाति में आम लोगों में व आम प्रचलन में या आम बोलचाल में जोगी जाति से ज्यादा जाना जाता है, परंतु जोगी, नाथ, कालबेलिया व सपेरा चारों जातियां एक ही हैं, परंतु कालबेलिया व सपेरा को अनुसूचित जाति में रखा गया है व जोगी व नाथ को अन्य पिछड़ा जाति में रखा गया है, जिसके कारण इस अनुसूचित जाति की अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ घोर अन्याय है। इस जाति के लोग नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, जिसको स्वामी जाति के समान मानकर अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, परंतु अनुसूचित जाति में जो जातियां सम्मिलित की गई हैं उनसे भी कई गुना पिछड़ा जाति है। समाज कल्याण विभाग में भी 1964 में जो जातियों का विभाजन किया गया था, उसमें जोगी (कालबेलिया) के साथ दर्शाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा जोगी, कालबेलिया, नाथ, सपेरा को अलग-अलग जाति मानने के कारण जोगी जाति के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है। रेवेन्यू में कालबेलिया जाति के लोगों के पास जमीन जायदाद है ही नहीं व जिनके पास थोड़ी जमीन जायदाद है उसमें जाति जोगी लिखी हुई होने से इनके जाति प्रमाण पत्र में पटवारी रिपोर्ट जोगी जाति की करके अन्य पिछड़ा वर्ग की करते हैं। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के होते हुए भी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं। इस जोगी, कालबेलिया, नाथ, सपेरा को एक ही प्रकार के जाति के लोग मानकर, इस जाति के लोग मानकर जोगी जाति के साथ न्याय प्रदान कराएं। नाथ, कालबेलिया कहो या सपेरा कहो, ये चारों जातियां एक दूसरी जाति की पर्यायवाची हैं। यह जाति मरुस्थलीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर में ही पायी जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

भादरा में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से परेशानी

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियम 295 के अंतर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहर भादरा में वर्षा ऋतु में अंबेडकर चौक के आसपास व शहर की मुख्य सड़कों तथा मुख्य चिकित्सालय के सामने की रोड पर तथा शहर के 27, 28 नंबर वार्डों के साथ-साथ 8, 9 नंबर वार्ड में भी

(श्री बलवान पूनियां)

गहरे बरसाती नाले की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे बरसाती दिनों में दुकानदारों व आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसका सिर्फ पानी निकासी की कार्ययोजना बनाकर ही समाधान किया जा सकता है तथा डीपीआर बनाकर, बजट मंजूर कर राहत प्रदान करने का काम सरकार हाथ में ले तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविंद राम।

खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दन्तौर में सरपंचों द्वारा पट्टे काटने के अधिकार की मांग

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दन्तोर पंचायतों की आबादी के पट्टे सरपंचों को काटने का अधिकार देने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दन्तोर चारों पंचायतें मुख्य पंचायतें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ उक्त तीनों तहसील मुख्यालय हैं इनके साथ ही दन्तोर की पंचायत को आबादी के पट्टे सरपंचों द्वारा काटने का अधिकार नहीं देने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है तथा आबादी के पट्टे सरपंचों द्वारा नहीं काटने से आम जनता को बैंक लोन की सुविधा नहीं मिल रही है। यहां पट्टा काटने का अधिकार मंडी समिति को दे रखा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण यहां के ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश है, जबकि राजस्व गांव में सरपंच को आबादी का पट्टा देने का स्वत: ही अधिकार होता है, लेकिन उक्त पंचायतों में पट्टा देने का अधिकार नहीं होने से आबादी पट्टा देने का कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है। इस कारण यहां के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त चारों पंचायतों की रिकार्ड सम्बन्धी उच्च स्तरीय जांच करवाकर तुरंत प्रभाव से सरपंचों को पट्टा काटने का अधिकार देने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में आवारा पशुओं से परेशानी

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

(श्री जगदीश चन्द्र)

प्रस्ताव के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के सादुलशहर कस्बे में आवारा पशुओं के लिए नंदी शाला का निर्माण करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के सादुलशहर में आवारा पशुओं हेतु नंदीशाला के लिए नगरपालिका के पास भूमि है। आये दिन आवारा पशुओं के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं तथा जान-माल का नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं के जहां-तहां विचरण करने से शहर में आने वाले आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के कस्बा सादुलशहर में आवारा पशुओं के लिए नंदी शाला का निर्माण यथाशीघ्र करवाकर आम जनता को हो रही उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में बरसात के पानी की निकासी हेतु पुलिया निर्माण

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अत्यधिक बरसात होने की वजह से गांव में रोड होने के बावजूद भी रपटें होने की वजह से बरसात में बहुत दिनों तक रास्ता बंद हो जाता है, जिससे गांव वाले विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पिपलिया नग्गा ग्राम पंचायत, खेरिया, रतनपुरा ग्राम पंचायत नू.गाडरवाडा, मरायता, नया गांव, बंजारा, दुर्जनपुरा, ग्राम पंचायत सूमर में रपटों की जगह पुलिया बनाने की कृपा करें, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने, बीमार को अस्पताल पहुंचाने में आसानी हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित बंदी के कारण फसलों को समुचित पानी का अभाव

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 7 मार्च, 2021 से प्रस्तावित बंदी ली जा रही है, जिससे प्रथम एवं द्वितीय चरण के लगभग 3 लाख 30 हजार हैक्टेयर गेहूं, चना की फसल को अंतिम पानी नहीं मिलने के कारण फसल नष्ट हो जाएगी एवं सारे पशुधन के लिए तूड़ी व नीरे (चारे) की विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मच जाएगी, क्योंकि पकती हुई फसल को मार्च में दो पानी की बारी की आवश्यकता रहती है, जबकि इस वर्ष 3 में से एक ग्रुप में पानी चलने के कारण जो नहरें 9 से 18 फरवरी को बंद हुई थीं, उन्हें 7 मार्च को पानी मिला है। सरहिंद फीडर के निर्माण व आई.जी.एन.पी. से सीपेज बढ़ने के दौरान 'क' और 'ख' वाली नहरों के ग्रुप को सात दिवस के लिए आगे किया गया है। अब जो ग्रुप 'ग' 6 मार्च को पूरा होना था, वह अब 13 मार्च को पूरा होगा। ऐसे में जिन किसानों को 11 फरवरी को पानी मिला था, उन्हें 15 मार्च से पहले की कोई उम्मीद नहीं है। यदि किसानों को 35वें दिन मार्च में पानी मिलेगा तो गेहूं की फसल का 30-40 परसेंट नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि पंजाब सरकार से बात करके शेयर में बढ़ोतरी करवायी जाकर 7 मार्च से एक पानी बारी सभी क, ख एवं ग तीन ग्रुप के लिए चलाकर किसानों की गेहूं व चना की फसल को बचाया जाए। पानी की कमी के रहते यदि सात रोजा बारी साढ़े पच्चीस दिनों तक व्यवस्था नहीं हो पाती तो साढ़े तीन रोजा छोटी बारी से प्रति मुरब्बा 2 हैक्टेयर गेहूं व चने की फसल को बचाया जा सकता है अन्यथा किसानों के पशुधन के चारे एवं इलाके के दुग्ध उत्पादकों के लिए भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पोंग बांध का लेवल 1301 फीट से नीचे ले जाकर एक बारी की व्यवस्था करायी जाए, ताकि किसानों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री लालचन्द कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष: पहले ये रख दें, फिर।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का प्रतिवेदन रखे जाने में विलम्ब

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 के तहत जो प्रतिवेदन रखा है, वह 2019-20 का है। अध्यक्ष महोदय, जो नियम एवं प्रक्रियाओं का नियम है, इसमें पंचम अनुसूची आपने लगायी है, उसके क्रम संख्या 12 में राजकीय उपक्रमों की सूची में राज्य भण्डार व्यवस्था निगम भी लिखा है। यानी आपने हमें अधिकार दिया है कि जो प्रगति प्रतिवेदन रखे हैं, उस पर हम अपने विचार विमर्श कर सकें, सदन में उस पर चर्चा हो सके।

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, कई बार आप श्रीमान के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि कम से कम 2019-20 एक पूरा साल निकल गया, आज 2020-21 का प्रतिवेदन आना चाहिए था। 2021-22 में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक तरह से आदत बन गयी। आपके स्पष्ट निर्देश अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद एक वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ? इसके लिए मंत्री जी तो खेद प्रकट करें ही, परंतु विलम्ब कारक जो भी अधिकारी रहे, उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि इस विधान सभा की गरिमा बनी रहे।

व्यवस्था

प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत होने चाहिए

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट, माननीय सदस्य, ये काम मुझे करने दें। माननीय सदस्य, आपका पाइंट वेलिड है। सरकार से अपेक्षा करेंगे कि समय

(श्री अध्यक्ष)

पर दें लेकिन आपको स्वयं को मालूम है कि महामारी है, कोरोना है तो रिपोर्ट कहां से बनती, परंतु हम आशा करते हैं कि जो नियम है, परम्परा है, नियमों के अनुसार प्रतिवेदन प्रति वर्ष आ जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में विभाग के जितने भी अलग-अलग, जिनको रिपोर्ट सब्मिट करनी है, वह समय पर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे सदस्य उस पर डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें और सदन के सामने चर्चा कर सकें।

श्री उदयलाल अंजना, सहकारिता मंत्री, प्रतिवेदन रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पांच अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(1) दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(3) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

(श्री अंजना उदयलाल)

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(4) राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(5) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री राजेन्द्र पारीक।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 2)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दिये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क' 2020-21 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सामान्य वाद-विवाद।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय जो अलग-अलग पार्टी के व्हिप ने दिया है, उस समय सीमा को एड्हिअर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग ले सकें। श्रीमती अनिता भदेल।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया। चूंकि पिछला वर्ष पूरा का पूरा कोरोना काल में निकल गया। इस महामारी से न केवल देश-प्रदेश बल्कि पूरा विश्व पीड़ित था और ऐसी स्थिति में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस बात को लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और पूरे वर्ल्ड में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और उसी की वजह से आज हमारा पूरा देश

(श्रीमती अनिता भदेल)

वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि इस वैक्सीनेशन के कारण से, जो दो वैक्सीन आई हैं, उनके कारण से निडर होकर, आत्मनिर्भर बनकर हमारा देश आगे बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब हम प्रदेश की चिंता करते हैं तो प्रदेश में क्या हुआ? आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है और किस ओर बढ़ रहा है? मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगी कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गयी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आये दिन हमारा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वह बड़े-बड़े अधिकारियों को भी गिरफ्त में ले रहा है लेकिन सरकार क्या कर रही है, इस ओर हमें देखने की जरूरत है, इस ओर हमें चिंता करने की जरूरत है। बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत हैं और किसान कर्जमाफी की आस में पूरी तरह से टूट गया है और आत्महत्या करने की स्थिति में है। राजस्थान आज बदहाली की स्थिति जी रहा है।

राजस्थान में जब हम किसान कानूनों की बात करते हैं तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बढ़-चढ़कर बात करते हैं और किसान आंदोलन-किसान आंदोलन की बात करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि किसान आंदोलन के बारे में जो किसान बिल आये हैं, उन बिलों में अंदर क्या है? क्या ऐसी नकारात्मकता है, हम उस पर कभी चर्चा नहीं करते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, सत्ता पक्ष को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दस दिन में कर्ज माफी करने की घोषणा करने वाली सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वह दस दिन में आज तक भी हम कर्जा माफी नहीं कर पाये हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्जदार हैं, वे आज भी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इस शासनकाल में हमने आये दिन अखबारों में देखा है लगभग 4 दर्जन किसानों ने कर्जमाफी नहीं होने के कारण से आत्महत्याएं की हैं। दूसरी ओर हमारे किसान भाई, बिजली, सरकार ने वादा किया था, ये मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली दिन में देंगे लेकिन बिजली दिन में देना तो दूर, रात्रि में भी ठीक प्रकार से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं कि आप बिलों के लिए जो इतना आंदोलन कर रहे हैं तो आप पहले अपने स्तर पर जो चीजों का समाधान कर सकते हैं, वह अपने स्तर पर क्यों नहीं करते? प्रदेश में किसान रबी फसल की सिंचाई कड़ाके की ठंड में करने

(श्रीमती अनिता भदेल)

को मजबूर है। बिजली रात में आती है, दिन में नहीं आती। इसके अतिरिक्त अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में घोषणा की है, परंतु जब हम 2019-20 और 2020-21 का बजट उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 33 प्रतिशत घोषणाएं भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी नहीं की हैं। दो साल से किसानों को बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी, वह सब्सिडी इस सरकार ने बंद कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो सहकारी ऋण थे, वह सहकारी ऋण, मैं उदाहरण देती हूं अजमेर में राजूलाल पुत्र श्री हजारी लाल, घाटोल, पंचायत समिति विनायका, इस राजूलाल का कहना है कि मुझे फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। मैं और मेरी पत्नी पहले लगातार फसली ऋण लेते रहे हैं लेकिन जब से कर्ज माफी हुआ है तब से मेरी पत्नी गीता को ये फसली ऋण नहीं दे रहे हैं। इस तरह से फसली ऋण का वादा करके भी यह सरकार मुकर गई।

दूसरी ओर, राष्ट्रीयकृत कर्ज माफी की जो बात है, मैं एक आर्डर पढ़कर सुना रही हूं, 19/12/2018 का यह आर्डर है। इस आर्डर में लिखा है, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव का यह आर्डर है, डी.बी. गुप्ता जी के द्वारा निकाला गया है कि राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार पात्र पाये गये सभी ऋण कृषकों को दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं, जो अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफाल्टर, उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाये जाने पर दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में दो लाख रुपये की सीमा तक का कालातीत अवधि पार अल्पकालीन फसली त्रण माफ किया जाता है।

(13.07 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों की भी बात इसमें लिखी है। डी.बी. गुप्ता जी का आर्डर है मेरे पास। माननीय सभापति महोदय, जब मैं बात करती हूं अजमेर की तो मुझे ज्ञात होता है कि ये जो हमारा सांवरलाल है उसका बिल माफ नहीं हुआ और आर्डर मिलता है, हमारे मुख्य प्रबंधक यूनियन

(श्रीमती अनिता भदेल)

बैंक के द्वारा कि आप इसकी कुर्की कर दीजिए। आप इसकी जमीन की कुर्की कर दीजिए। वह दर-दर भटकने को मजबूर है। यहां से हमारे मुख्य सचिव जो आर्डर निकालते हैं, दूसरी ओर, जब व्यक्ति इस आर्डर के आधार पर सरकार की ओर जाता है तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, संयुक्त सचिव जो मुख्य मंत्री जी के हैं, वह कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि सांवरलाल पुत्र रामकरण खाती, निवासी चावंडिया, ग्राम पंचायत समिति सतवाड़िया, तहसील मसूदा, मुख्य मंत्री कार्यालय पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें। मुख्य मंत्री जी को जो बात करनी है, जो काम करना है, वह मुख्य मंत्री कलेक्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और आर्डर डी.बी. गुप्ता जी के हैं, यह किस प्रकार की व्यवस्था है? किसानों को किस प्रकार भ्रमित करने की आप बात करते हैं। किस तरह किसानों से आप छलावा करने की बात करते हैं? यह बहुत शर्म की बात है। ऐसी स्थिति में किसान आपको माफ करने वाला नहीं है, किसान आपको छोड़ने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम बात करते हैं किसानों की, आगे जब मैं बढ़ूंगी कि कोरोना काल में मजदूरों के लिए, सड़क पर चलने वाले जो हमारे मजदूर भाई थे, जो पलायन कर रहे थे, हमने उनके लिए व्यवस्थाएं की। बिजली के बिलों को हमने डेफर किया। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली को लेकर आज पूरे प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। न केवल परेशान है बल्कि आज उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा है।

माननीय सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगी कि बिजली, पूरे हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा बिजली की रेट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। उदय योजना के तहत जब हमारी पार्टी की सरकार थी, उस समय 62 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर बिजली कंपनियों का चुकाया गया था। सिर्फ 20 हजार रुपये का ही कर्ज बिजली कंपनियों के पास शेष था लेकिन अब पुन: इस सरकार के दो साल के कार्यकाल में ही 80 हजार 500 करोड़ रुपये का बिजली का कंपनियों पर जो कर्ज है, वह बढ़ गया है। 1 से लेकर 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 8 रुपये से लेकर 12 रुपये तक प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, जो सबसे महंगी बिजली है। सरकार ने इस कोरोना संकट में राहत देने की बजाय बिजली के फिक्स चार्ज और फ्यूल चार्ज को बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर और बोझ डालने का काम किया है। एक ओर तो यहां जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी की बहिन है, हमारी प्रियंका बहिन हैं, वह उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बिल माफ कर दे और यहां पर राजस्थान सरकार बिजली के बिलों को माफ करने के बजाय फ्यूल चार्ज और फिक्स चार्ज बढ़ाने के साथ बिजली के बोझ को और बढ़ाने का काम करती है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): इस तरह अपमान नहीं किया जाता है, वह आपकी बहन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट, अनिता जी। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखूंगा कि बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, जब भी मैं कुछ बोलती हूं तो सत्ता पक्ष के कुछ लोगों को पता नहीं अजीब सा लगता है। आप समझा देते बहन जी को कि चिट्ठी नहीं लिखे। (व्यवधान)

श्री सभापति: अनिता जी, एक तो आप इधर देखकर ...(व्यवधान) 39 माननीय सदस्यों को बोलना है, अगर आप इसी तरह से इंटरवीन करेंगे तो मुझे परेशानी होगी। समय निर्धारित किया गया है। जब मैं आपसे कहूं तो आप मुझे सहयोग करें, वरना कोई नहीं बोल पाएगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिलकुल, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आवास पर आना चाहूंगी। माननीय प्रधान मंत्री जी की जो आवास योजना है, जिसमें 15 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया, 13 लाख आवास स्वीकृत हुए जिसमें से 9 लाख आवास बनकर तैयार हो गये, लेकिन राजस्थान के लोगों को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान की

(श्रीमती अनिता भदेल)

किस्त समय पर नहीं पहुंच रही है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इंदिरा आवास है, जिसके लिए माननीय सदस्य बार-बार स्थगन के माध्यम से ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपना सवाल उठा रहे हैं। एक आम आदमी का पक्के मकान का सपना होता है, वह उसको इंदिरा आवास के रूप में मिले। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिले, ताकि इस आवास में रहकर वह अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सके।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं आवास की बात करती हूं तो आप देखिएगा कि राजस्थान में मुख्य मंत्री जन आवास योजना है, उस जन आवास योजना के तहत कितने समय से प्रोजेक्ट्स लंबित हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बीएसयूपी योजना के तहत, 2013 में यह आयी और उस योजना के तहत आने के बावजूद भी आज तक भगवान गंज के आवास पूरे नहीं हो रहे। उन आवासों की जर्जर स्थिति हो गई है। इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बीएसयूपी के तहत 21 मार्च, 2007 में जो आवास बने थे, जिसमें 64 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हुई थी, जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया, जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट 10 हजार रुपये का जमा करा दिया, जमा कराने के बावजूद भी भगवान गंज की योजना में उन आवासों को अभी तक आबंटित नहीं किया गया है। यह आवास आबंटन करने का काम शीघ्र करें।

साथ ही साथ, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अजमेर में लगभग 10-15 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं, उन स्वीकृत प्रोजेक्ट में जो बिल्डर है, उस बिल्डर ने अपने हिस्से की जमीन तो विकसित कर ली, लेकिन गरीब को जो फ्लैट बनाकर देने थे, वह आज तक नहीं दिये। रेरा में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी 2007, 2008, 2009, 2010 के प्रोजेक्ट आज तक लंबित हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर सरकार तुरंत समीक्षा करे, मोनिटरिंग करे और ऐसे गरीब लोगों को आवास देने की कोशिश करे, तब उसका अपने घर का सपना पूरा हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी की एक योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश निरोगी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, किसी को मिलावट का खाद्य पदार्थ नहीं मिले। जब से माननीय अशोक जी ने मुख्य मंत्री का पद सुशोभित किया है तब से उनका, हर कार्यकाल में उनका एक ध्येय होता है कि शुद्ध के विरुद्ध

(श्रीमती अनिता भदेल)

युद्ध, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, यह बार-बार करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी भावना है, लेकिन आपकी मोनिटरिंग ठीक नहीं है, कार्ययोजना ठीक नहीं है, आपकी कार्य पद्धति नहीं है, आपके स्टाफ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, 2010 में मिलावटियों पर कार्यवाही और रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल की घोषणा की।

श्री सभापति: कनक्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल बना तो दिया गया लेकिन रजिस्ट्रार के पद पर स्टेनो और दो चपरासी ही कार्यरत हैं, इसके अलावा कोई और कार्यरत नहीं है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि कानून विशेषज्ञ इस पद पर आसीन होता और यह काम करता। पूरे प्रदेश में प्रयोगशालाएं लगतीं, प्रयोगशालाएं अपग्रेड होतीं, प्रयोगशाला में इक्विपमेंट होते, प्रयोगशाला में जांच करने वाले इंस्पेक्टर होते और उन नमूनों की समय पर जांच होती तथा समय पर रिपोर्ट आती। 2010 का उनका जो लक्ष्य था, लेकिन आज 2021 चल रहा है, 2021 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करते हैं कि ट्रिब्यूनल के स्थान पर अथोरिटी बनाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जब आपने ट्रिब्यूनल बनाया था, आपको एक एडीजी या कानून विशेषज्ञों को तैनात करना था, आपने उस समय तैनात नहीं किया, अब अथोरिटी बनाकर क्या कर लेंगे? माननीय सभापति महोदय, ज़िलों में सिर्फ 13 प्रयोगशालाएं हैं। जो केन्द्रीय प्रयोगशालाएं हैं, उनमें पूरा स्टाफ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम शुद्ध के विरुद्ध युद्ध कैसे करेंगे, मुझे आप समझाइये। और तो और नमूने होते हैं वह अवधि पार हो जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अवधि पार होने के बाद इनका रिजल्ट आता है, वह भी डाउटफुल होता है कि रिजल्ट सही है या गलत है। ऐसी स्थिति में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध सिर्फ खोखला दिखावा है और कुछ भी नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मेरे दो विषय और हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करूंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोविन्द राम।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं दो विषय रखकर, सिर्फ दो मिनट में खतम कर रही हूं।

श्री सभापति: नहीं, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फर्स्ट वक्ता हैं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आपने लिस्ट दी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: माननीया सदस्या, आप विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए, सहयोग करिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है यह ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, नहरें, सिंचाई का पानी सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान देते

(श्री गोविंद राम)

हुए, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब चीजों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है।

आदरणीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, सब लोग, यह बड़ी-बड़ी बात तो कर रहे हैं लेकिन यह जब से, 6 साल से, राज में आये हैं, हमारा 14 हजार करोड़ रुपया जीएसटी का बकाया पड़ा है। पहली बार, केन्द्र की सरकार आने के बाद इन्होंने अभी तक किसी तरह की योजना नहीं दी, उलटे जितनी हमारी कम्पनियां थीं उनको बेचने का काम इन्होंने किया। आज मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा, जिसको इन्होंने कहा कि यह बोर करने वाला है, ऊहापोह की स्थिति है। अगर हम इस बजट पर टीका-टिप्पणी करेंगे तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि फिर अच्छा बजट कौनसा है?

सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1960-70 के बीच हमारी नहरें बनीं। आज मैं नेहरू जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने 1962 में भाखड़ा डैम बनाया, जिसके माध्यम से पवना डैम बना। उसके बाद हमारी नहरें बनीं, आज करीब 50 साल हो गये, लेकिन उनमें किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं हुई। सारी नहरों में पानी का रिसाव चलने लग गया। मैं पाकिस्तान की सीमा, खाजूवाला से आता हूं, वहां तक नहरें पहुंचते-पहुंचते हालत यह हो गई कि जो टेल का किसान है उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा था। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, दिसम्बर, 2018 में सरकार बनने के बाद, इन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री से मीटिंग की, इन्होंने नहर के बारे में योजना बनाई कि जो नहर इतने लंबे समय से बनी हुई है, मरम्मत नहीं होने के कारण किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ज़िले, शहर, पेयजल योजनाएं इस नहर से जुड़े हुए हैं। खाजूवाला के खालवा क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आज वहां पर अनाज का उत्पादन हो रहा है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं 1962 में नेहरू जी चाइना युद्ध के समय लाल गेहूं बाहर से लाए थे। आज हमारे गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं वह इन्हीं नहरों की मेहरबानी है। हमारे पूर्व नेताओं की मेहरबानी है। दुर्भाग्य की बात है कि मरम्मत नहीं होने के कारण, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें बजट लिया। आज इंदिरा गांधी नहर पर 3 हजार 290 करोड़ रुपये का बजट पास किया, जो पंजाब इलाक़े में नहर है, उसमें भी काम हुआ, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण उस नहर का काम रुक गया। मेरे खाजूवाला नहर की

(श्री गोविंद राम)

स्थिति है, आदरणीय सभापति जी, बीडी है जिसमें 1300 लाख रुपये, कुण्डल डिस्ट्रीब्यूटरी (केएलडी) 470 लाख रुपये, पीएचएम नहर 434, केडब्ल्यूएम कालूवाला माइनर 56 लाख, बीजीएम भागु माइनर में आप स्थिति देखेंगे तो वहां पीने के पानी की स्थिति नहीं है, लेकिन आज हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 462 लाख रुपये दिये हैं। एएलएम अल्लादीन माइनर 180 लाख, बीएलडी नहर जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जगह-जगह से टूटने के कारण, जब भी अच्छी बरसात आती है, पानी आता है, बार-बार नहर टूटती थी, वहां 712 लाख रुपये दिये। के.एच.एम., खुशानवाला माइनर 430 लाख, हमारे एस.एस.एम. सियासर माइनर में 93 लाख, पूगल ब्रांच का हैड है 17 का, वह काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, वहां 1100 लाख, PWM पावली माइनर, 340 लाख और इसके अलावा जो हमारी बीकानेर चीफ इंजीनियर के अंडर में आती है, वहां 40 करोड़ रुपये और बी.डी. और हमारा धोधा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें 135 करोड़ रुपये दिये हैं। करीब 200 करोड़ वहां, 300 करोड़ खाजूवाला में और पूरी नहर के लिये 3200 करोड़ रुपये दे करके आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां के किसानों को पूरा टेल तक पानी पहुंचे, उसकी व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिये इनको जितना धन्यवाद दें, उतना कम है। अगर हम दूसरी साइड में देखें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरनसर): पानी नहीं पहुंचा। पानी आ ही नहीं रहा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): पानी पहुंच रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में मत बोलिये। माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सुमितजी, सुनते रहें। देखिये, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वह टाइम देना मुझे।

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने तो पूगल गांव, जो बीकानेर से पहले बसा हुआ था, रियासत थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, पहले पंचायत समिति दी, आज वहां गौण मंडी देने का काम हुआ। खाजूवाला हमारा जो कि सीमा का इलाका है, खाजूवाला विधान सभा हैड-क्वार्टर है, वहां मुंसिफ कोर्ट था, आज उन्होंने उस न्यायालय को प्रमोशन दिया है और छतरगढ़ में एक न्यायालय और खोला है।

135 करोड़ रुपये धोधा डिस्ट्रीब्यूटरी और भूट्टोवाली वितरिका में दिया है। खाजूवाला जलप्रदाय, जो पेयजल की स्कीम है, सभापतिजी, मेरे क्षेत्र में घी

(श्री गोविंद राम)

मिलता था लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता था, आज वहां 488 करोड़ रुपये उन्होंने पेयजल स्कीम, जल मिशन योजना के तहत दे करके गांव-गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इसके अलावा छतरगढ़ तहसील में 165 करोड़ रुपये दिये हैं। उसके अलावा हमारे 33 के.वी. के जी.एस.एस., जो खाजूवाला में कम पड़ रहा था, उसको और विस्तार के लिये उन्होंने और सुविधा दी है। हमारी सत्तासर से बीकानेर सड़क, पिछले 20 साल से खराब पड़ी थी, उसको इन्होंने 200 करोड़ रुपये, रायसिंहनगर और पदमपुर तक और जाएगी, 206 करोड़ रुपये इन्होंने इस बजट में ले करके और वह जो टूटी-फूटी रोड है, जिसकी हालत खराब थी, पिछले 5 साल के बी.जे.पी. के राज में, आज पेचवर्क का काम चालू है और अब 206 करोड़ रुपये देने का काम किया है।

इसी प्रकार हमारी जो वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी है, उसके अन्दर इन्होंने डेयरी सांइस का महाविद्यालय खोलने का काम किया है। इसके अलावा PBM में 110 ICU बैड वाले में 70 नये बैड देने का काम हुआ है।

एक बहुत बड़ा काम हुआ है। चूंकि अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह आदमी आगे बढ़ेगा। इन लोगों ने क्या किया है, यह जामिया इस्लामिया हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली में, JNU में, वहां जा-जा करके इनके सम्बन्धित संगठनों के लोगों ने लाठी चार्ज किया, उनके साथ मारपीट की। जिस देश के अन्दर शिक्षण संस्थाओं में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट होती है, सभापति महोदय, आप अनुमान लगाइये, सियासत करने वाले लोग, और उनको देशद्रोही के नारे देते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में हमले होते हैं तो आप देखिये, कहां तो हमारे देश ने 1947 में आजादी प्राप्त की, डाक्टर अम्बेडकर ने कितना बड़ा संविधान बनाया। उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अनुसूचित जाति के लिये व्यवस्था की कि यह गरीब तबका है, जबकि अगर आप यह देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अन्दर, अपराध, अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में, धरती पर पैदा होता है। आपको विश्व में दूसरा कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। उन्हीं को मरवाने के लिये आज जगह-जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पार्क के अन्दर आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं का,

(श्री गोविंद राम)

लाठियों से, कोई दूसरों से, वहां झगड़ा हो गया, एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यहां सदन बंद कर दिया कि आर.एस.एस. के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई और, एक तरफ एक गरीब जाति के, नीच जाति कह कर पुकारते हैं, और उनके दूल्हों को उतार दिया जाता है। अगर वह मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वह नाम के आगे 'सिंह' लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधान सभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं।

सभापति महोदय, जो डाक्टर अम्बेडकर, नेहरूजी और महात्मा गांधीजी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, उसमें कमी आ रही है। पिछले छह साल में जितनी मॉब -लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पर हत्याएं हुई हैं, इतनी पहले कभी नहीं हुईं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत यह हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारे जो दिन पहले थे, वे ही रहने दो। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं, वे पिछड़े वर्ग से आते हैं।

श्री सभापति: कनक्लूड करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): वे ज्योतिबा फुले के विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थीं।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): पहली, प्रथम शिक्षिका थीं सावित्री देवी, जब वे बच्चों को, बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थीं, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पर कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पर चलकर, डाक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर, नेहरूजी के रास्ते पर चल करके जो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट दिया है, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले, 2014 से पहले, मैंने वीडियो देखा है, जो आज हमारे प्रधान मंत्रीजी हैं, इन्होंने कहा, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है, वह पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। आज हालत क्या हो रही है, पूरे

(श्री गोविंद राम)

देश में साढे बारह हजार किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश हैं, जिसके अन्दर भूख से लोग मरते हैं, उन 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अन्दर हमारे तीन स्टेट हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में है, जो हमारे यहां भूख से तीन लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बी.पी.एल. के नीचे आ रहे हैं। तीन देश ऐसे हैं जो मुर्दे बेचते हैं, विश्व में तीन ऐसे देश हैं जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है और कानून है, उसके अन्दर हमारे भारत का नाम आ रहा है, जिसके अन्दर इथोपिया, सोमानिया और भारत, जहां मुर्दे बेच करके और यहां अपना आदमी टाइम-पास करता है। आज यह विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु-महात्मा ही जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशु से टकरा करके उनकी डैथ हो गयी। हमारे सुरेशजी, भूतपूर्व एम.एल.ए., भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पर बात कर ली।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अभी जब अपना लॉकडाउन था, अनाज बांट रहे थे।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उनको ऊपर पटका।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): (व्यवधान) वे बैड पर हैं। यहां आदमी से ज्यादा पशु की पूजा हो रही है।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): और पशुओं के नाम पर ये लोग आये दिन दंगा करवाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं एक-दो बात और कह दूं, खतम कर देता हूं। मनमोहन सिंहजी जब हमारे प्रधान मंत्रीजी थे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): ए. राजा को जेल भेजा, कलमाड़ी को जेल भेजा, कनिमोझी को जेल भेजा, महाराजश्री को जेल भेजा। और अब क्या हो रहा है, विजय माल्या 9 हजार करोड़ लेकर फरार, ललित मोदी 5000 करोड़ लेकर फरार, मेहुल चौकसी 15 हजार करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी गुजराती, और ये सारे के सारे गुजराती हैं। ये ले करके फरार और सारे के सारे बैंकों से ले करके फरार हुए हैं। अभी देश की हालत क्या है, सभापतिजी, प्रधान मंत्री गुजराती।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): ...(व्यवधान) राष्ट्रीय चीफ गुजराती। आर.बी.आई. चीफ गुजराती, सी.बी.आई. चीफ गुजराती, सारे बड़े-बड़े ठेके ले गये गुजराती। अनिल अंबानी गुजराती।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: नहीं। विराजिये, प्लीज सहयोग करें। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिये ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: बिलकुल, विराजिये। नहीं, नहीं, अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। प्लीज, सहयोग करें, विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिये। महेन्द्रजी, यह लिस्ट दी है आपने मुझे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जी, यह लिस्ट दी है।

श्री सभापति: दी है तो इसका पालन करवायें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरा भी चैप्टर पूरा खतम होगा तब बैठूंगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मिनट, एक मिनट में समाप्त कर दें, गोविन्दजी।

श्री सभापति: अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: महेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये, आप। (व्यवधान) विराजिये आप, आसन पैरों पर, विराजिये आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: दोनों पक्षों के माननीय उप नेता महोदय ने और आपने मुझे लिस्ट दी है। इसमें आपने बाकायदा समय निर्धारित किया है, कौन सदस्य कितना मिनट बोलेगा। माननीय अध्यक्षजी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसकी अक्षरश: पालना करवाएं। इसके बावजूद भी जब आप मुझे यह कह रहे थे कि एक मिनट और बोलने दें तो मैं आपको और बोलने दे रहा हूं। 7 घंटे 30 मिनट बोलने के लिए होंगे और यदि आप लोग इस तरह से इंटरवीन करके बीच में करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे। यह आपको तय करना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है? यदि आपको इसी तरह से चलाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक मैं यहां पर बैठा हूं मैं अलाउ नहीं करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं, मैं फिर आपसे यह आग्रह कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई वह नहीं है, दोनों पक्षों के जो माननीय नेता हैं उन्होंने मुझे यह लिस्ट दी है, मैं उसका पालन करवा रहा हूं और

(श्री सभापति)

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश से पालन करवा रहा हूं। इधर के जो माननीय सदस्य हैं, उनको सबको दस मिनट का समय दिया गया है, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप पालन करेंगे। इधर जो माननीय सदस्य हैं उनके दो या तीन लोगों को पन्द्रह मिनट का समय माननीय अध्यक्षजी ने दिया है और माननीय उप नेता महोदय ने दिया है। मैं यह आग्रह करूंगा कि आप उसका पालन करें और यह आपकी वजह से ही है क्योंकि आप यदि नहीं बोल पाएंगे तो फिर उपयोगिता क्या है? इसलिए कृपया बीच में इंटरवीन नहीं करें, अब आप विराजिए। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं, आप पहली बार आये हैं, कुछ सीखिए। अब आप विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आसन पैरों पर है, विराजिए आप। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए कुछ। कुछ परंपराएं सीखिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मैं धीमी गति का समाचार हूं मुझे बोलने में पांच मिनट की छूट भी दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 24 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया है, पूरे बजट को पढ़ते-पढ़ते थक गया। पेज नम्बर 71 पर पैरा संख्या 198 पर सूरतगढ़ का एक स्थान पर नाम आया है और वह नाम कैसे आया? आठवीं इकाई 660 मेगावाट की बिजली पैदा करके जल्दी ही बेचने के लिए तैयार हो जाएगी बिजली बेचने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ थर्मल पावर के अंदर सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पचासों गांव उसके इर्दगिर्द हैं, वह लोग प्रदूषण झेल रहे हैं। उनको आज के दिन पूरी छह घंटे बिजली नहीं मिल रही है। मैं इस सदन के अंदर कई बार यह बात बोल चुका हूं। डेजर्ट एरिया के अंदर किसानों के ट्यूबवैल लगे हुए हैं। एक तरफ नहर की बंदी आ रही है और दूसरी तरफ छह घंटे लाइट नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि टिब्बा बैल्ट के अंदर कम से कम एक माह तक आप आठ घंटे बिजली देकर फसल पकाने का काम करें, तब मैं यह मानूंगा कि आप लोग किसानों के हितैषी हो। खाली घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों के हितैषी नहीं हो सकते।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस सरकार ने समय रहते हुए अपने हिस्से की बीमा की राशि नहीं भरी जिसके कारण से किसानों को आज दिन तक बीमा नहीं मिल रहा है वर्ष 2019-20 का।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि थर्मल स्टेशन के इर्दगिर्द जो गांव हैं, न तो उनको नौकरी दी जाती है और न ही बिजली दी जाती है, बल्कि प्रदूषण दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं इस सदन के अंदर तीसरी बार भूमि से सम्बन्धित यह विषय उठा रहा हूं। मंत्री महोदय ने दो बार सदन में खड़े होकर मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और राजस्व विभाग की डिमांड पर भी उत्तर दिया कि मौके पर जाकर गांवों में कैम्प लगाकर आपने जो समस्या उठाई है, उनका समाधान करेंगे। दो बार इस पवित्र सदन में यह आश्वासन दिया है। माननीय सभापति महोदय, टी.सी. से पुख्ता खातेदारी देने का काम पेंडिंग पड़ा है। शहरी क्षेत्र के इर्दगिर्द तरह-तरह के राइडर्स लगे हुए हैं। भूमाफियाओं को रात को ही खातेदारी मिल जाती है और किसान को नहीं मिलती है। बड़े-बड़े पूंजीपति लोग भूमि खरीदकर, एक ऐसा रास्ता है उसमें कि जन प्रतिनिधि को बिलकुल ही उस आबंटन के अंदर न तो प्रधान है, न विधायक है, कोई जन प्रतिनिधि सरपंच, नगरपालिका का चेयरमैन, कोई भी नहीं है, सिर्फ अधिकारी ही हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग क्षेत्र, वन विभाग प्रस्तावित, इस तरह के तरह-तरह के राइडर्स लगाकर किसानों को रोका हुआ है खातेदारी लेने से वंचित कर दिया। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जो ओरिजनल काश्तकार हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र खातेदारी देने का काम करे।

यह आपके स्माल पेच, मीडियम पेच, बालिग पुत्रों के प्रकरण हैं, हजारों की संख्या में यहां पर फाइल पेंडिंग पड़ी हैं, गजट में साया कर दी, काश्तकार भूमि आबंटन करवाने के पात्र हैं पर पटवारियों की गलती से भूमि गजट में प्रकाशित कर दी गयी, ऐसी भूमि को निकालकर पात्र काश्तकारों को भूमि आबंटन की जाए।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर नहर की चर्चा हो रही थी। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल की जो देन है वह गंगासिंहजी महाराज की है। पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और गजट जो है, ... (व्यवधान) गंग कैनाल नहीं, इंदिरा गांधी नहर का भी, पोंग डैम की भी उनके टाइम की स्कीम बनी हुई है, पता कर लेना।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने का सारा काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह निर्णय हुआ था, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सत्य बात सत्य ही रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनका संरक्षण करो, चाहे राठी गाय है, चाहे थारपारकर है, चाहे ऊंट है। किसान की बात करते हो लेकिन आपको यह पता नहीं है कि किसान कैसी जाति है, कैसे जिंदा रहता है? तारामीरा कितना होता है एक बीघा में, यह भी आपको पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले छह महीने से लगातार इस पवित्र सदन के अंदर मैं यह बराबर सुनता आया हूं कि केन्द्र सरकार यह जो तीन बिल लेकर आयी है, ये किसानों के गला घोंटने वाले हैं। मैं इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीनों बिल, मैं भी किसान हूं, अगर कोई भी क्लॉज इसका गलत है तो आप मुझे बोलकर बताएं कि इस बिल के अंदर यह बीमारी है। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन बिल हैं, तीनों में अलग-अलग दस क्लॉज हैं और यदि आपको दो नम्बर पसंद नहीं है तो सरकार यह कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है। दो की जगह पर आप क्या लिखवाना चाहते हो? चार, तो चार लिखने के लिए तैयार है। पैरा नम्बर छह पसंद नहीं है, सरकार यह कह रही है, आपको जो पसंद नहीं है, त्रुटि लग रही है तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं पर, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग यह कहते हैं कि इसको पूरे को ही जलाकर नष्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा, इसमें अच्छी बातें भी हैं। सिवाय व्यापारियों को नुकसान, सत्य कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर मंडियों के अन्दर, प्राइवेट मंडियों के अन्दर, कृषि उपज मंडी जो सरकारी है उसके समान टैक्स लग गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। स्टॉक सीमा की बात कही है। आज से पहले हमारे देश के अंदर हजारों-हजारों टन अनाज नष्ट हो रहा था। सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये देकर गोदाम निर्माण करने का जो काम शुरू किया है, उसमें मैंने अडाणी और अंबानी नहीं देखे हैं। हमारे इलाके के छोटे-छोटे लोग गोदाम बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि सरकार सब्सिडी दे रही है। मोदीजी ने पहली बार इस देश के किसान की चिंता करके जो हमारा अनाज नष्ट होता था, उसकी व्यवस्था की है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रहा सवाल, स्टॉक पर अंगुली उठा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने टमाटर का कारखाना लगा रखा है और उसको छह महीने चलाना है या बारह महीने, तो उसके लिये टमाटर स्टॉक नहीं करेगा? उसको स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक के बिना काम नहीं चलेगा। फिर इस बिल के अन्दर यह भी प्रोविजन है कि अकाल, युद्ध, अलग से ऐसी कोई महामारी या परिस्थिति आ जाए तो स्टॉक सीमा पर पाबंदी होगी, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल किसान हितैषियों का, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके समय किसानों पर अत्याचार हुए हैं। सर्वप्रथम तो 1969-70 में संगरिया के अन्दर आठ किसान शहीद हुए थे। अभी माननीय सदस्य विनोद जी बैठे थे, उनको एक-एक बात का पता है। आठ किसान शहीद हो गये, उनका अगर आप चाहो तो मैं नाम सहित बता सकता हूं।

इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंहजी के टाइम में मध्य प्रदेश के अन्दर सन् 1997 के अन्दर 24 किसानों को गोलियों से भून दिया, वह भूल गये, वह याद नहीं है।

एक माननीय सदस्य: अभी 250 किसान मर गये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, देखिए, भगवान किसी को बीमार कर दे, किसी की गोली-लाठी से नहीं मरे। मैं यह बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी बंदे के नाखून तक के भी हाथ नहीं लगाया है। यह आप अपने मन से कह रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं, आजकल इस तरह राजनेताओं की भाषा में क्या हो गया, हमारे शिवसेना ने क्या किया लोक सभा में, क्या किया राज्य सभा में? पता नहीं आपको? एन.सी.पी., शरद पवार, उनकी भी सहमति थी और राकेश जी टिकैत, प्रवक्ता, उन्होंने मुजफ्फरनगर के अन्दर कहा था कि हमारी वर्षों की जो मांग है, वह सरकार ने मानी है। हम बार-बार मांग कर रहे थे कि किसान को अपना माल बेचने की हर जगह छूट होनी चाहिए। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने पहली बार किसानों की बात सुनी है। माननीय सभापति महोदय, मुझे डर लग रहा है समय का, नहीं तो मैं एक-एक बात को कहता। आपने कभी भी किसानों का भला नहीं किया। आपने किसानों की बारियां काटीं पक्के खालों के लिये। एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये किसानों के एक मुरब्बे पर कर्जा, कांग्रेस ने मोगे बंद करवा दिये, बारी काटी। बीजेपी ने पैसा माफ करने का काम किया था। इतना

(श्री रामप्रताप कासनियां)

ही नहीं, 55 से पहले वाले दो मुरब्बा फ्री जमीन देने का काम किसी ने किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। फ्रेगमेंट दस्तबरदारी का कानून समाप्त किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरा समय ही नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं कांपने लग जाऊंगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ऊपर लाने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण देने का जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका प्रमाण पत्र जब एस.डी.एम. से बनवाते हैं तो कम से कम चार महीने लगते हैं और इसमें एक वर्ष की समय सीमा है, इसको बढ़ायी जाए और इसको पांच साल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत चुनाव के अंदर इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। समय का अंतर साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल का है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस चुनाव को इकजाई कैसे करोगे? आज भी चुनाव पैंडिंग पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका में वार्डों के गठन में तो बंटाढार कर दिया। एक वार्ड 1900 वोट का और एक वार्ड 300 वोट का। आपने कोई करामात करके चुनाव नहीं जीता है, आपने तो बेईमानी करके चुनाव जीता है। माननीय सभापति महोदय, पंचायत के अन्दर पांचवें वित्त आयोग की राशि इस सरकार ने आज दिन तक जारी नहीं की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, छठे वित्त आयोग की राशि भी अभी पैंडिंग पड़ी है। छठे वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया। पंचायतों को पंगु बनाने का काम इस सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, हरियाणा, पंजाब...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या हुआ, सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री रामनारायण मीना।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, देश में रेवड़ियां बांटने का जो काम है, चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मैं इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर देश के गरीब को ऊंचा उठाना है, अगर वाकई में गरीब की गरीबी खतम करनी है तो प्रथम काम तो इस देश में, राज्य में कानून व्यवस्था हो, और चाहे अन्य सारे काम सुधर जाएंगे, एक बच्चे का प्रोविजन कर दो और गरीब को पढ़ाओ-लिखाओ, उसको नौकरी लगाओ, परमानेंट साधन दो, यह रेवड़ियां बांटने का काम बंद कर दो। माननीय सभापति महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष से कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए। माननीय श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व मंत्री कासनियां जी से निवेदन करूंगा कि उनकी बात मैं पूरी कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, कासनियां जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अगर इस देश को बचाना है, इस प्रान्त को बचाना है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 का जो बजट भाषण है, उसके बारे में अपनी तरफ से बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे थे किसानों के बारे में, खालों के बारे में, नहरों के बारे में। माननीय सभापति महोदय, हर सरकार और विशेषत: गांवों में आज भी चर्चा है माननीय देवेगौड़ा जी की, उनके थोड़े समय के लिये प्रधान मंत्री बनने पर यूरिया की खाद का भाव कम हुआ था। देवेगौड़ा जी का नाम लेते ही आज भी गांवों के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता होती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने एक पम्फलेट भेजा है। यह हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। मैंने वोट दिया या नहीं लेकिन मेरे देश के प्रधान मंत्री हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में प्रधान मंत्री हैं, लेकिन सिर नीचे झुकता है या ऊंचा उठता है, वह बात अलग है। कासनियां जी, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आपके पास मोदीजी ने नहीं भेजा हो और हमारे पर कृपा कर दी हो तो आप पढ़ लीजिए।

(श्री रामनारायण मीना)

कमोडिटीवाइज भाव है, माननीय सभापति महोदय, एक तरफ राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी बजट भाषण पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष से कृषि का अलग बजट दिया जाएगा। यह किसानों के साथ पूरी तरह से सहयोग है, अपनत्व है और किसानों को आगे बढ़ाने की भावना दर्शित हो रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार किसानों को आगे बढ़ा रही है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत लंबा है, पर मैं शार्ट में पढ़ देता हूं। इसमें गेहूं का भाव 1975 रुपये है, आपको शंका है क्या? जब 1975 रुपये है, माननीय सभापति महोदय, यह नेता प्रतिपक्ष मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इनको थोड़ा डांटिए। आप डांट पिलाइए, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी बात को नहीं सुनने दे रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज शांत रहें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा 1975, कासनियां जी, मेरा गेहूं 1500 में क्यों बिका, गरीब का गेहूं 1400 में क्यों बिका और मिल-मालिक उस 1400 के गेहूं के भाव का 3 हजार में आटे का पैसा क्यों ले रहे हैं? यह कृपा करके भारत सरकार से कहिए, हम सहयोग देंगे। राजस्थान सरकार सहयोग देगी और सदन का बहुमत इसमें सहयोग देगा कि किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको न्याय में तब्दील किया जाए। सारी कमोडिटीज हैं, माननीय सभापति महोदय। पूंजीपतियों का पक्ष, दलालों का पक्ष, फिर, माननीय सभापति महोदय, हम तो देश में कहते हैं, राजस्थान भी कहती है, दिल्ली भी कहती है, सारा देश कहता है 'मेक इन इंडिया' शेर का चिहन, फिर 'मेक इन इंडिया' में डी.आई.डी.ओज. को, उद्योगों को खतम क्यों किया जा रहा है? इंजीनियरों को बेरोजगार किया जा रहा है और फ्रांस से हथियार क्यों मंगाये जा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, हम किसान हैं, मंडी में जाते हैं, मंडी में जाते हैं तो वहां आढ़तिया मिलता है, दो रुपये सैकड़ा, डेढ़ रुपये सैकड़ा की आढ़त लेता है, जब हम बेचेंगे कोई खरीदेगा तो आढ़त होगी, तो फिर माननीय राहुल गांधी ने कौनसा गलत कहा कि इस राफेल की जांच होनी चाहिए, दुगनी कीमत क्यों दी है, देश के हित में है? यह तो कोई देख ले, सोच ले।

माननीय सभापति महोदय, यह जो चीजें हो रही हैं और आज जिस तरह से क्रश किया जा रहा है, किसानों को क्रश क्यों किया जा रहा है? मैं याद दिलाऊंगा, आप तो भूल गये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को,

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की वह पंक्ति याद रखिये, हम तो याद रख रहे हैं, अटल जी को अच्छा इंसान मानते थे, वो गरीबों के पक्ष में थे, अटल जी गरीबों के खिलाफ नहीं थे। माननीय सभापति महोदय, पूंजीपति से नहीं डरते थे। आज देश का माहौल है कि गरीबों को क्रश किया जा रहा है, खतम किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से क्रश करने का श्रेय देश की सरकार ले रही है, उसका मुखिया कौन है, आप और हम सब जानते हैं। साहब, यह योजना बनायी, हमने यह किया, इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिया, राजीव गांधी की योजना को बदल दिया, नेहरू जी के बारे में यह कह दिया, महात्मा जी के बारे में यह कह दिया। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आज किसान जिस प्रकार से बैठा हुआ है, सौ दिन से ज्यादा टाइम हो गया, उनको क्यों क्रश किया जा रहा है, बात क्यों नहीं मानी जा रही? माननीय सभापति महोदय, वो यही तो कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी, आपने मुखारविंद से अर्ज किया था, यह बताया था, निर्देश दिया था, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं मान रही है, तुम्हारे को जलील क्यों किया जा रहा है? 1975 में गेहूं खरीदेंगे तो 1500 में मंडी में क्यों बिक रहा है? जब विरोधियों को क्रश किया जाता है तो प्रजातंत्र खत्म हो जाता है, एकात्मवाद पैदा हो जाता है। (व्यवधान) क्यों हो रहा है यह तो आप जानो लेकिन मैं आपको अटल जी की बात बता रहा हूं। जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय हो जाता है। आज तानाशाह कौन हैं? दो ही तो व्यक्ति हैं न। आप मुझे बता देना, सदन के बाहर बता देना। (व्यवधान) वो जो भी हैं, आप कृपा करिये, उनसे मिल लीजिए।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, आप इधर देखिए, आप उनको क्यों इन्वाइट कर रहे हैं?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, डांटना उनको चाहिए, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो डिस्टर्ब करते हैं।

श्री सभापति: नहीं, इधर बोलिये आप।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो किसान को क्रश कर रहे हैं।

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में क्या है कि एक तरफ तो राजस्थान की सरकार, मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम किसानों का अलग से बजट रखेंगे, एक तरफ मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कुंड खोदेंगे, किसानों का हित करेंगे, इतनी सब्सिडी देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, 25 कमोडिटी पर सौ फीसदी तक कृषि सेस लागू होगा। इन्होंने तो मटर तक को नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे लागू होगा तब देखना आप, पढ़ना आप। इसलिए मैं आपसे आज कह रहा हूं कि कम से कम कृपा करके यह जो टैक्स की परिपाटी आप पहली दफा डाल रहे हो, मैं नहीं कहता कि आप पूंजीवादी व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता आप ब्रिटेन की, अमेरिका की और फ्रांस की तरह पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम समाजवादी समाज की व्यवस्था में विश्वास करते हैं क्योंकि नेहरू जी जो हमसे कहकर गये हैं, माननीय सभापति महोदय, यही कारण था हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा था कि यह सहकारिता गांवों की रीढ़ की हड्डी है, पंचायती राज गांवों को आगे बढ़ाने वाला, गरीबों के हित में सुलभ न्याय उपलब्ध कराने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, यह आज क्या हो रहा है? सिखों के साथ विशेष सम्बन्ध, सबसे ज्यादा सिखों को पीटा है, मैं आथेंटिसिटी से कह सकता हूं, आप रिकार्ड उठाकर मंगा कर देख लीजियेगा। अन्नदाता को समर्पित मोदी सरकार, माननीय सभापति महोदय, यह किताबें बांट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बटन लगा रहा हूं इसका भी टैक्स है, बालों में तेल डाल कर आया हूं, इसका भी टैक्स है। ट्रस्टी कौन बन गया? पहले तो टैक्स यहां का यहां रहता था, वहां का वहां जाता था, कुछ एक्साइज जाती थी, अब सारा टैक्स वहां ले रहे हैं, राज्य सरकारों को खतम कर रहे हैं, संघीय ढांचे को खतम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह परिपाटी अच्छी नहीं है, देश के हित में नहीं है और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इस देश में यह जो गरीब विरोधी भावना पैदा हो रही है वो अच्छी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ सोचा जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो ज्ञान है, आप तो पुराने आदमी हैं, आपसे तो हम सीख रहे हैं, चेयर से आप डांटते हो तो इसलिए सुन लेते हैं कि

(श्री रामनारायण मीना)

आप कुछ ज्ञान की बात कहोगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पूछिये शिक्षा में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, पेयजल में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता था और केन्द्र सरकार कितना देती थी? आज तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ही 40:60 का ऐसा करने जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, एक सड़क नहीं बनेगी। यह ब्लॉक करने का तरीका है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिस प्रकार भी देश में यह परिस्थितियां बन रही हैं क्या यह देश के हित में हैं? इसलिए अधिक बात नहीं कहते हुए मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आप हमसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं, वहां से मुझे थोड़ा-सा इशारा कर देना, मुखारविंद से कम तकलीफ करना, मैं अपने आप बैठ जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें हो रही हैं। आज नगरपालिकाओं में जो यह छोड़ कर गये हैं...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो प्रारम्भ किया है। (व्यवधान) वो मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, वो पुराने आदमी हैं। वो सब के ऊपर कर देंगे, मुझ से तो बड़े प्रसन्न हैं इसलिए कृपा नहीं करेंगे, इसलिए दोबारा मत बोलना आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन दयालु है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): वो सामने आपको बैठा रखा है, मुझे तिरछा बैठा रखा है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए नोनेरा डैम बन रहा है, योजना कब बनी, बी.जे.पी. सरकार के टाइम पर। क्यों बनी, क्योंकि धौलपुर पानी ले जाना था। मेरे क्षेत्र में जहां नोनेरा डैम बना है, बूंदी जिले में जहां होकर पानी जाएगा, सवाई माधोपुर के गांव में जाएगा, वहां नाममात्र का पानी दिया जाएगा, इस योजना को बदला जाना चाहिए क्योंकि यहां पेयजल मंत्री जी नहीं हैं, घरेलू कनेक्शन की दर ज्यादा है, प्रचार किया जा रहा है, कृषि के फ्लैट रेट की बात छोड़िए, यूनिट के हिसाब से आप आगे जोड़ोगे तो पैसा ज्यादा आ रहा है, इसको ठीक करिये।

माननीय सभापति महोदय, आज बाल विकास परियोजनाएं हैं, इन योजनाओं में करप्शन बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैंने मंत्री जी को

(श्री रामनारायण मीना)

भी कहा है, मैंने अधिकारियों को भी कहा है। क्या कारण है कि बाल विकास परियोजनाओं का करप्शन खतम नहीं हो रहा? मेरे इलाके में कागजों में खानापूर्ति की जा रही है, बेईमानी से उस राशन को, गरीबों के राशन को, बच्चों के राशन को, गर्भवती महिलाओं के राशन का पैसा कहां जा रहा? मैं इसके बारे में अधिक अर्ज करने के बजाय वह सरकार के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन अंत में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

जिस प्रकार से वंचित वर्ग को खतम किया जा रहा है, किसान को कमजोर किया जा रहा है, बेरोजगारों को क्रश किया जा रहा है, पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है, यही कारण है कि कोरोना में गरीब को न्याय नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला और पूंजीपतियों की सम्पत्ति बढ़ी। पूंजीवाद देश के लिए अहितकारी है, नुकसानदायक है, गरीबों को क्रश करने वाला है, कृपा करके उस नीति को छोड़ने के लिए आप अपने नेताओं से कहिये और कांग्रेस की रीति-नीति पर विश्वास करिये ताकि देश आगे बढ़ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें वास्तविकता कम और उप चुनाव की छाया ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी बजट है। घोषणाओं में हवाई किले बना दिये, धरातल पर कब उतरेगा, यह कुछ कह नहीं सकते। पिछले दो साल में जो घोषणाएं की थीं वो घोषणाएं खाली घोषणाएं रह गयीं, मात्र 33 परसेंट इस बजट के ऊपर काम हुआ है और इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में जितनी भी योजनाएं थीं उनका बंद करने का एक रिकार्ड तय कर दिया है। देश के गरीब के लिए जो भामाशाह योजना थी उसको बंद किया, भामाशाह

(श्री नारायण सिंह देवल)

स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा रसोई, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना, ग्रामीण गौरव पथ और किसानों को जो 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, वो सारी योजनाएं इस सरकार ने बंद करने का एक रिकार्ड कायम किया।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार हम लोग वहां बैठते थे और यहां पर सत्ता पक्ष में जो हैं, वह इधर बैठा करते थे। वह एक ही बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया। 22200 स्कूलें बंद करने की बात की गई। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि हम इन स्कूलों को खोलेंगे, लेकिन अभी तक 978 स्कूलें ही आपने खोली हैं। यह जनता के साथ में बहुत ही कुठाराघात है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलने के लिए आपने वाहवाही खूब लूटी है। यह आज के युग की मांग भी है कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे गरीब बच्चे इंग्लिश की शिक्षा ले सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़े हुए अध्यापक हैं, वह कितने हैं? आप कोई नई भर्ती करेंगे? यह आप बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी इसी सत्र में सुन रहा था और सरकारी कालेज खोलने के लिए खूब वाहवाही लूटी जा रही है, हमने 88 कालेजें खोल दीं। मेरे रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय में हमारी सरकार के टाइम में कालेज स्वीकृत हुई थी, 6 करोड़ का एस्टीमेट भी दिया हुआ है, लेकिन इस सरकार की काम करने की मंशा नहीं है। 2017-18 में जसवंतपुरा में आईटीआई स्वीकृत हुई और 10 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार है। पिछली विधान सभा में मैंने सवाल लगाया था तो मंत्री जी ने कहा कि इसको बहुत ही जल्दी खोलेंगे लेकिन आज दिन तक न तो वहां कोई कर्मचारी लगा है और न ही कोई स्टाफ लगा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में और रानीवाड़ा में सड़क के नाम पर एक विकास पथ स्वीकृत हुआ है, वहां भी कोई काम नहीं हुआ है। बरसात के बाद में जो पैचवर्क होने चाहिए, वह भी यह सरकार नहीं कर रही है। 2019-20 में सरकार ने घोषणा की थी कि 500 से अधिक आबादी वाले 1900 गांवों को 4 साल में हम चरणबद्ध रूप से जोड़ेंगे, इसको 2 साल हो गये हैं, केवल 57 गांव जोड़े हैं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है कि 2 साल के अंदर आप 952 गांव कैसे जोड़ेंगे, यह सरकार स्पष्ट करे।

मेरे रानीवाड़ा विधान सभा में जसवंतपुरा और जालौर के बीच में टोल रोड है, यह बीओटी बेस पर है, लोगों से टोल ले रहे हैं। वह सड़क इतनी टूटी हुई है कि अगस्त में पूरी नई सड़क बनानी थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण आज भी जनता इसका खामियाजा भुगत रही है।

पेयजल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 2019-20 में एक सोलर डीफ्लोरिडेशन की घोषणा की। हमारे रानीवाड़ा विधान सभा में कई सोलर लगे। इन सोलर में से कइयों में सोलर पैनल नहीं हैं, कहीं फिल्टर नहीं हैं, कई जगह भूमि समर्पण नहीं हुई, फिर भी वहां लगा दिये। इसका भुगतान उठा लिया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा के रानीवाड़ा उपखंड पर ए.ईएन. और 3 जे.ईएन. की पोस्ट खाली है। जसवंतपुरा के अंदर 2 जे.ईएन. और एक ए.ईएन. की पोस्टें पिछले 7-8 महीने से खाली हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी नहीं है तो योजना का एस्टीमेट कौन बनाएगा? मेरा कहना है कि न तो नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी।

सभापति महोदय, इस सरकार ने तो जनता के साथ में भारी खिलवाड़ किया है। आज अगर गांवों में ट्यूबवैल जल जाए तो 2-2, 3-3 महीने से मोटर रिप्लेस नहीं की जाती है। टेंडर समय पर होते नहीं हैं। इनके आफिस में न वाल्व हैं, न 10 फीट का पाइप है। वहां कोई सुनने वाला नहीं है। यह राजस्थान की जनता के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा है। कर्मचारी हैं नहीं। रिटायर हो रहे हैं। नई भर्तियां यह कर नहीं रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय में जितने भी आर.ओ. प्लाट लगे थे, वह अधिकांश बंद हैं। मेरे यहां रानीवाड़ा विधान सभा में पिछले डेढ़-दो साल से सारे ही आर.ओ. प्लांट बंद हैं।

सुबह मैंने नर्मदा की बात कही। नर्मदा का जो डीआर मेन प्रोजेक्ट है और वहां क्लस्टर का काम हो रहा है, इससे गांवों में नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात कही गई है। मैं जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा के कई गांव छितराई हुई ढाणियों में रहते हैं। वहां या तो पानी है नहीं और है तो फ्लोराइड है। सबसे

(श्री नारायण सिंह देवल)

पहले उन गांवों को इस जल जीवन मिशन के तहत, जिनकी 500 करोड़ की डीपीआर बनी हुई है, आप इसको जुड़ाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में किसान बिजली जाने का इंतजार करता था, आज इस सरकार में किसान बिजली कब आयेगी, इसका इंतजार कर रहा है। किसानों को 6 घंटे बिजली देने का वादा किया था, उसमें भी भारी ट्रिपिंग है। जले हुए ट्रांसफार्मर महीने-महीने तक यह बदल नहीं पा रहे हैं। सरकार ने यह घोषणा की थी कि 16 जिलों में हम दिन में बिजली देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नैनोल, टीटोब और लूनियासर में प्रशासनिक स्वीकृति 5 जनवरी, 2021 को मिल गई लेकिन वित्तीय स्वीकृति आज दिन तक नहीं मिली। जसवंतपुरा के अंदर 132 केवी का सब-स्टेशन एक साल से चालू है।

श्री सभापति: अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक साल के अंदर खाली 100 फीट बाउंड्री बनी है। दीनदयाल के कनेक्शन बंद हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज दो साल से क्या हालत हुई है? संविदाकर्मी पिछले दो सालों से स्थाई होने का इंतजार कर रहे हैं। कमेटी बन गई, उसने सरकार को रिपोर्ट दे दी। यह पता नहीं कब स्थायी होंगे? यही हाल हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं, पंचायत सहायक हैं, पैरा टीचर्स हैं, लोक जुम्बिश है, शिक्षाकर्मी हैं, विद्यालय सहायक हैं, 1 लाख 50 हजार संविदाकर्मियों को दीपावली से पहले नियमित करने का सरकार ने वादा किया था। यह संविदाकर्मियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में पिछले डेढ़-दो महीने से पटवारी हड़ताल पर हैं। अतिरिक्त चार्ज जितना भी था, वह पटवारियों ने तहसील आफिस में जमा करा दिया। यह फरवरी का समय है, गिरदावरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा का उनको क्लेम कैसे मिलेगा? उनको केसीसी कैसे मिलेगी? इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विकास अधिकारी, एएनएम और बेरोजगार युवा साथी अपनी मांगों को लेकर बार-बार धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इनकी बात सुनकर इनकी समस्या का समाधान किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं आखिर में कहूंगा कि महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आपने लागू की। आपने केन्द्र की योजना आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया। हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे जालौर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, वहां गुजरात की सीमा लगती है, हमारे लोग राजस्थान में इलाज नहीं कराकर गुजरात में इलाज करवाते हैं। इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, इसको राजस्थान के अन्दर लागू किया जाए ताकि सीमावर्ती जिलों को यह लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पिछले एक वर्ष में कोरोना के कारण प्रदेश और देश की परिस्थितियां रही हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब रही। भारत सरकार ने भी जो हमारे स्टेट का बजट था उसमें कटौती की। ऐसी परिस्थितियों में भी जो बजट पेश हुआ, वह मैं समझता हूं कि उसकी न तो पक्ष और न विपक्ष को ही ऐसी उम्मीद थी, हमको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इतना अच्छा बजट पेश कर पाएंगे जिसमें उन्होंने जन कल्याण की सारी योजनाओं को छुआ, सड़क हो, हास्पिटल हो, स्वास्थ्य हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम हों, प्रत्येक साइड में पैसा दिया गया। मैं समझता हूं कि जिन-जिन विधायकों ने जो-जो डिमांड अपनी रखी, हमने स्वयं ने भी रखी, अधिकतर उन डिमांडों को पूरा किया गया है। चाहे किसी ने एसडीएम आफिस मांगा हो, चाहे किसी ने तहसील मांगी हो, चाहे किसी ने स्कूल मांगा हो, चाहे पीएचसी मांगी हो, चाहे हास्पिटल मांगा हो, चाहे सड़क मांगी, इन परिस्थितियों में भी मैं समझता हूं कि इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वाह!

श्री मुरारी लाल (दौसा): आप कह रहे हो वाह, मैं उस दिन सुन रहा था। आप यह कह रहे थे कि यह घोषणाओं का पिटारा है, घोषणाओं का पिटारा है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह तो आप मान रहे हो कि घोषणाएं हुई हैं और घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं का पिटारा है तो आपका पेट दर्द क्यों कर रहा

(श्री मुरारी लाल)

है? यह बताओ। अगली बार बजट पेश हो और हमारी घोषणाएं पूरी न हों, फिर कहना कि आपकी घोषणाएं पूरी नहीं हुईं। हमारी जो-जो घोषणाएं हुई हैं उनको पूरी करेंगे और इस बार प्रतिपक्ष को ऐसा कोई चांस नहीं मिला, आपको भी बिलकुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट आ सकता है, ऐसा बजट आया है इसलिए आप सबको भी मिलकर समर्थन करना चाहिए और हम सब भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दौसा में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी आपको मंत्री बनाने की। (व्यवधान) वह मंत्री बनाने की घोषणा की थी कि नहीं की थी? (व्यवधान) आपको मंत्री बनाने की घोषणा की थी कि नहीं की थी? वह पूरी की?

श्री मुरारी लाल (दौसा): दौसा को इतना कुछ दिया है, इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। यदि मैं बहुत लम्बी लिस्ट पकड़ाता, आज फिर मांग रखूंगा कि मैंने जो मांगा उससे ज्यादा दिया और सबको दिया। (व्यवधान) मान्यवर, अब आप मेरी बात सुन लो (व्यवधान)

मान्यवर, पिछले छह-सात साल से इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। जब से बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे-ऐसे फैसले आपने किये हैं, आपने नोटबंदी का फैसला किया, क्या हुआ उसमें? गरीबों का, मध्यम वर्ग का सारा पैसा, जमा पूंजी बाहर निकलवा ली। आपने जीएसटी का फैसला किया, आपने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। आपने निजीकरण का जो फैसला किया, उसको बढ़ावा दिया, उसका सबसे ज्यादा प्रहार हुआ, पब्लिक सैक्टर को बेचने का तो हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों पर हुआ। आपने हमारी नौकरियां छीन लीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये गरीब तबके के लोग, ये एससी, एसटी के लोग, ये जो पढ़ना सीखे हैं, खेती के बाद इनका एक ही उद्देश्य था, हम पढ़ें-लिखें और नौकरी करें लेकिन जिस तरह का माहौल आपने बना दिया, पब्लिक सैक्टर के सारे पीएसयू, कोल इंडिया, भेल इंडिया, रेलवे, हवाई जहाज, सबको धीरे-धीरे, सारे पब्लिक सैक्टर को, पचास-साठ पब्लिक सैक्टर इस देश के अन्दर थे, जो अपने लम्बे कार्यकाल के अंदर सरकारों ने बनाये थे, आप एक-एक को खतम करते जा रहे हो, आप हमारी नौकरियां खतम करते जा रहे हो, आप हमारे आरक्षण को खतम करते जा रहे हो, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री मुरारी लाल)

इनडाइरेक्ट आरक्षण, सीधा तो आपमें खतम करने की हिम्मत है नहीं, सीधी हिम्मत तो आप लोगों की है नहीं। अब आप हमारे इधर देखो, 50 हजार नौकरियां, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निकालीं इस परिस्थिति में भी, पिछली बार भी भर्तियां की हैं, इसका सबसे ज्यादा यदि फायदा होता है तो हम गरीबों को होता है।

माननीय सभापति महोदय, एक और बहुत बड़ी बात कर दी आप लोगों ने, कई साथियों को पता है और कई को नहीं है। बड़े पदों पर हमारे लोग नहीं पहुंचते हैं, हमारे लोग पहुंचे हैं केवल आरक्षण की वजह से, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे हैं, आपने अलग से एक सिस्टम चला दिया, लेटरल एंट्री, यह क्या है भाई? लेटरल एंट्री क्या है? चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, लेटरल एंट्री क्या है? सीधा जोइंट सेक्रेटरी के पद पर पोस्टिंग।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह लैटरल एंट्री वैसे ही है +++ यह लेटरल एंट्री वो ही है।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मान्यवर, लेटरल एंट्री में क्या हुआ ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ यह लैटरल एंट्री ही है।

श्री मुरारी लाल (दौसा): यह लेटरल एंट्री क्या है, (व्यवधान) आप बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मैं पहली बार तो बोला हूं, कृपा करके चुपचाप बैठ जाओ, पांच-सात मिनट के लिए।

माननीय सभापति महोदय, लेटरल एंट्री पिछली बार आपने जोइंट सेक्रेटरी के पद पर डाइरेक्ट पोस्टिंग दी, एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी नहीं था, इस बार हाल ही में आपने 30 आईएएस की जोइंट सेक्रेटरी, आईएएस के पद निकाले, आप देख लेना लेटरल एंट्री के माध्यम से एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एक तरह से आप हमारा आरक्षण खतम करते जा रहे हो और बात करते हो, हम एससी, एसटी और ओबीसी का भला करते हैं। यह बड़ी सोची-समझी नीति के तहत कुछ पूंजीपति लोग, गिने-चुने लोग हैं जिनके लिए आपकी सारी की सारी पालिसी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप हमारे पर रहम करो, ये बहुत-सी ऐसी बातें हैं।

(श्री मुरारी लाल)

मानननीय सभापति महोदय, आपने पहले व्यापारी को मार दिया, युवा की नौकरी छीन ली, आपने गरीब तबके को मार दिया, बचे थे किसान। अभी हाल ही में आपने क्या किया, किसान के ऊपर तीन काले कानून और आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ये राजद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं, ये फलाने हैं, ये पाकिस्तानी हैं, पता नहीं क्या-क्या आप बात करते हो। जब देश की 70 परसेंट जनसंख्या जो कृषि आधारित है, वो ही राष्ट्रदोही हो गये तो बचा क्या फिर इस देश में? इसलिए कृपा करके आप स्वयं आत्म मंथन करो।

माननीय सभापति महोदय, महंगाई के लिए आप देखो, एक रुपया बढ़ जाता था तो बीजेपी वाले पूरे देश को बंद करवा देते थे। इंटरनल मार्केट है वह क्रूड आयल का 50 परसेंट है, आपने कहां पहुंचा दिया? गैस का सिलेण्डर कहां पहुंचा दिया? डीजल, पेट्रोल 100 रुपये पहुंचा दिया। आप यह तो सोचो कि चाहते क्या हो? फिर भी आप कहते हो कि हम बहुत अच्छे हैं। इसलिए अब जनता जाग चुकी है और आने वाले टाइम में आपको सब पता लग जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कहां जागे हो, +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए इनको। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहां जागे हो आप? +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल (दौसा): मेरा निवेदन है आप विराजें क्योंकि फिर मेरी घंटी बज जाएगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहां जाग रहे हो आप? +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? विराजो आप, प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं सबको दोषी मानता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। (व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, परम्पराओं का पालन कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, राठौड़ साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, प्लीज सहयोग करें, विराजिये। (व्यवधान) आप उत्तेजना पैदा न करें।

आसन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी के खिलाफ यदि आपको कोई बात कहनी है तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सौ फीसदी सहमत हूं। जो भी कुछ कहा गया है उसको विलोपित कर दें। अर्थहीन उत्तेजना पैदा न करें सदन में, बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी यदि आपका यही आचरण रहेगा, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 39 माननीय सदस्यों को बोलना है। सदन यदि इसी तरह से चले तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। बार-बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आसन पैरों पर, आसन पैरों पर और आप खड़े हैं, जिसकी जो मर्जी आये उसी तरह से बोल रहे हैं। परम्पराओं से माननीय सदस्य जो नये हैं वो सीख लेंगे तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे यहां से। बार-बार कहना पड़ रहा है इस तरह से, क्या साबित करना चाहते हैं आप? सदन में उत्तेजना ही पैदा करनी है तो मैं आपको आधे घंटे की छूट देता हूं, आपको जितनी उत्तेजना पैदा करनी है करिये आप। शांत रहिये, उन्हें भी पता है और मुझे भी पता है। प्लीज शांत रहें। विराजिये। श्री मुरारी लाल जी।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये लोग भी सोची-समझी नीति के तहत हल्ला करते हैं, क्योंकि ये आरक्षण...

श्री सभापति: अब आप सीधे-सीधे अपनी बात कहें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): साहब, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: हां, अपनी बात कहें आप।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मैंने निवेदन किया था, भारत की सिविल सर्विसेज में इन्डायरेक्टली आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। लेटरल एंट्री के तहत ये डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की भर्ती कर रहे हैं, इसमें एससी-एसटी का कोई कोटा नहीं है। यह इस बात को सिद्ध करता है। हमारा आईएएस पंद्रह साल की नौकरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, ये सीधे प्राइवेट सैक्टर से ले रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि आपकी सरकार आरक्षण विरोधी है। हल्ला करने से पार नहीं पड़ेगी। आप वेकेंसीज निकालें।

दूसरा, हमने एक से एक अच्छे काम किये हैं। क्या पंचायती राज का पुनर्गठन कोई छोटी-मोटी बात थी? हमारे दौसा जैसी जगह पर पांच-पांच पंचायत समितियां हो गयीं, कितनी ग्राम पंचायतें बनीं।

एक बहुत बड़ा मुद्दा और है जिसके लिए हम भी दोषी हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में हमने स्वयं ने बचपन में देखा है, पूर्वी राजस्थान बिलकुल हरा-भरा था। पश्चिमी राजस्थान, मैंने सूरतगढ़ में 1983-84 में नौकरी की है, वहां रेगिस्तान हुआ करता था। आज इन सालों में इतना अंतर आया है, आज जो पूर्वी राजस्थान हरा-भरा था, वह रेगिस्तान हो गया। पश्चिमी राजस्थान जो कि रेगिस्तान था, वह हरा-भरा हो गया। इसके लिए हम दोनों ही पक्ष दोषी हैं। पूरे राजस्थान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री महोदय से मांग की। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए ताकि इन तेरह जिलों में पानी आ सके।

मान्यवर, इसके अलावा मेरी कुछ छोटी-छोटी मांगें हैं। जिला दौसा पानी के मामले में पूरे राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। पहले तो बहुत पानी था। पहले तो हम बाल्टी से पानी निकाल लेते थे कुओं में से। आज की स्थिति में दस दिन, पंद्रह दिन में पानी आता है। ईसरदा डैम 2013 में स्वीकृत हुआ था। बांध का काम दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जब तक बांध का काम पूरा हो, मेन पाइपलाइन के लिए 200-400 करोड़ रुपये मिल जाएं तो उसके पैरेलल काम हमारा चालू हो जाए।

मान्यवर, इसके अलावा हमारी कुछ छोटी-छोटी बातें और हैं। मान्यवर, हमारे एससी-एसटी के बहुत-से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हमारे लोग

(श्री मुरारी लाल)

लगातार मांग करते रहते हैं, लेकिन सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी भावना तो ज्यादातर ठीक है नहीं। हम यह चाहते हैं कि हमारा जो रोस्टर रजिस्टर है, वह सब जगह लागू हो और कार्मिक विभाग इसके लिए बीच-बीच में आर्डर भी जारी करता रहता है। हाल ही में 19.05.2020 को भी कार्मिक विभाग ने एक रोस्टर रजिस्टर के संधारण के लिए एक आदेश जारी किया था। यह शर्म की बात है कि कार्मिक विभाग उनके लिए तो आदेश जारी करता रहता है, लेकिन स्वयं का आज तक रजिस्टर है ही नहीं। पहले तो कार्मिक विभाग इसमें सुधार करे। कम से कम खुद का तो जारी कर दें।

इसके अलावा जब माननीय मुख्य मंत्री थे 2013 में, हमारे बच्चों के लिए 19 हजार पद निकाले थे एलडीसी के ग्राम पंचायतों में, उसमें 9 हजार की भर्ती तो हो गयी थी और 10 हजार की भर्ती आज तक बकाया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, वे बच्चे रोज सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी डिमाण्ड को भी पूरा किया जाए।

वैसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है लेकिन इसके अलावा फिर भी दो-चार चीजें और हैं, क्योंकि उद्योग के धंधे भी नहीं हैं। जिस तरह से दो क्लस्टर्स की अभी घोषणा की है, इसी प्रकार दौसा के आस-पास बड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके।

इसके अलावा हमारे लवाण में कालेज का मामला आया है, नांगल राजावतान में सीएचसी का मामला है, ये सारी की सारी मांगें वैसे मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दे दी हैं। पिछली बार जो मांगें दीं, उन्होंने सबकी सब कर दीं। मुझे उम्मीद है कि वे इस बार बजट पर जब रिप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों को शामिल करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। इस बजट में जो सबसे बड़ी खासियत है, वह यह है कि यह बहुत बिखरा हुआ बजट है और जब मुख्य मंत्री बजट का भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जादूगर हूं और जादू दिखा रहा हूं आपको। हम सबको पता है जादू की

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

क्या हालत होती है, जादू में कोई सच्चाई होती नहीं है, उन्होंने केवल घोषणाएं कीं और जादूगर जब अपना सब-कुछ समेट कर जाता है, उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता है। न तो कोई फूल मिलता है, न कोई दूध का ग्लास मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता और जादूगर जादू दिखाकर अपने घर चला गया।

आप भी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली बैंचों पर बैठे हुए माननीय सदस्यों को यह पता नहीं है कि वे सत्ता में हैं। उन्हें मोदी फोबिया हो चुका है और मोदी फोबिया के कारण इन्हें यह ही पता नहीं चल रहा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, सारी खामियां जो देश में चल रही हैं या जो नहीं चल रही हैं, वे देश की बातें कर रहे हैं। राजस्थान के बजट में क्या-क्या घोषणाएं हुईं, आपके दो सालों की पीछे की क्या घोषणाएं हैं, उन पर क्या अमल हुआ, इन विषयों पर माननीय सदस्यों के पास चर्चा करने का वक्त नहीं है। इन्हें मोदी, मोदी, मोदी, मोदी ने जो कुछ किया है, उस मोदी ने पांच साल तक राज किया और दूसरी बार जब सत्ता में आया तो सीटें बढ़ा करके जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आया है। उस मोदी के लिए आप चिल्ला रहे हैं, कोस रहे हैं, दण्ड-बैठक लगा रहे हैं, कोई नाच-कूद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपको फिर कहने वाला हूं कि तीसरी बार भी मोदी आयेगा और आने वाले 30-40 सालों तक हमारा योगी तैयार हो रहा है। हमारा योगी तैयार हो रहा है, आप जितना चिल्लाएंगे, उतना जनता को जल्दी समझ में आयेगा कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। सत्ता की जो भूख है आपको, इस भूख के कारण आपने जो किया है, मैं आपसे फिर आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, इस सदन का जो बजट का सैशन है उसमें बजट पर चर्चा करें, जिससे जनता की भलाई हो सके।

श्री सभापति: आप जो कुछ कह रहे हैं, स्वयं तो इस बात का पालन करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं स्वयं तो बजट की ही बात कर रहा हूं। अभी जो बातें चार दिनों में मैंने सुनी हैं उनका सार यही है कि इन्होंने बजट पर कोई चर्चा नहीं की, इन्होंने मोदी, मोदी, मोदी के नाम की ही चर्चा की है।

श्री सभापति: मैं दस मिनट में घंटी बजा दूंगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ऐसा न करें, साहब।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): पहली बार तो बोल रहे हैं, साहब, भूमिका बन रही है थोड़ी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इस सरकार के पिछले दो बजटों की जो घोषणा हुई है, उनका मैं हश्र बताता हूं आपको। प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला का निर्माण होगा, आज तक एक भी पंचायत समिति में नंदीशाला का कहीं निर्माण हुआ हो तो बताएं। ऋण माफी में 10 तक की गिनती सिखायी गयी थी हमें। हमें गिनती ही नहीं आती थी। 10 दिन की गिनती के बाद आपने सत्ता हासिल कर ली और 300-700 दिन निकल गये, अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए आपके। अभी तक किसानों का जो बैंकों का ऋण है वह माफ नहीं हुआ।

15 लाख बेरोजगारों का पंजीकरण इस राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में हुआ है। 85 हजार बेरोजगारों को वसुन्धरा जी के शासनकाल में जो भत्ता मिलता था, उसके अलावा इन्होंने आज तक भी एक्स्ट्रा बेरोजगार को पैसा नहीं दिया है। ये सोचने के विषय हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि 5 साल बाद जब हम वापस चुनाव में जाएंगे तो हमें जवाब देने होंगे। इस पर चिंता करें आप, मोदी की चिंता छोड़ें।

पिछले बजट में मेरे भीलवाड़ा शहर के लिए लिखा था कि कोठारी नदी में एक पुल का निर्माण किया जाएगा, जो शहर और सांगानेर को जोड़ती है। उस बजट का एक इंच काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 30 करोड़ की घोषणा थी वह। एक रुपया नहीं लगा है और आप जिस तरह से जादू दिखाकर ये घोषणाएं कर रहे हैं और उन्हें गिना रहे हैं, जो घोषणाएं हो चुकी हैं, उनके क्रियान्वयन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इस सदन की उपयोगिता साबित होगी।

अब नयी घोषणाएं हो गयीं, नर्सिंग कालेज ऑलरेडी मेरे भीलवाड़ा शहर में चल रहा है लेकिन एक नर्सिंग कालेज और चलाएंगे। अब कब चलेगा, बजट है कि नहीं है, पता नहीं। 88 कालेज खोलने की घोषणा कर दी इन्होंने। हमारे जो दिवंगत माननीय सदस्य हैं, उनके नाम पर इन्होंने चार कन्या महाविद्यालयों की घोषणा कर दी। बजट में कहां प्रावधान है, कुछ बताएं तो सही। उन मृत आत्माओं के प्रति तो हम कम से कम ईमानदारी का व्यवहार करें, केवल घोषणाओं पर कायम नहीं रहें।

पूर्व में पिछले वर्ष मेरे वहां मुख्य मंत्री ने स्वयं दौरा किया था जब मैं 50 दिनों के धरने पर बैठा था। चार हजार मकानों में दरारें आई थीं। सरकारी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

भवन, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सबमें दरारें आ चुकी हैं, रहने लायक परिस्थिति नहीं है और 40 हजार की आबादी का कस्बा है उपनगर पुर। उस कस्बे में जब मैं धरने पर बैठा तो मुख्य मंत्री जी स्वयं दौरा करने आये और दौरा करने के बाद उन्होंने कई तरह की घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि 4 हजार मकानों का मुआवजा दिया जाएगा, पर उस घोषणा पर एक पैसा आज तक किसी गरीब को नहीं मिला। यह मुख्य मंत्रीजी की घोषणाओं का हश्र है। इसलिए, मेरी चिन्ता है कि क्या बोलें क्योंकि जब बजट के नाम पर ही बोलना है, केवल घोषणाओं को ही सुनना है, क्रियान्विति तो होती नहीं है।

जब अपने विधान सभा अध्यक्ष महोदय 12 साल पहले हमारे एम.पी. हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने चम्बल के पानी की घोषणा की थी कि भीलवाड़ा जिले को चम्बल से जोड़ा जाएगा। आज 12 साल हो गये पर नहीं हुआ। हमारे पांच साल के शासनकाल में हमने दौड़-दौड़ कर मुख्य मंत्री को कहा था कि, मुख्य मंत्री महोदया, चाहे घोषणा कांग्रेस की है लेकिन यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उन्होंने हमारे निवेदन पर गौर फरमाया और गौर फरमाकर उन्होंने उस पर काम शुरू किया। भीलवाड़ा शहर, मांडल और आसींद को हमारे शासनकाल में उस चम्बल की योजना से जोड़ा गया है। जिले के चार विधान सभा क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां एक इंच भी काम नहीं चल रहा है। एक भी इंच काम नहीं चल रहा है और अब उप चुनाव देखते हुए इन्होंने कहा कि अब गंगापुर को पानी से जोड़ेंगे। 12-12 साल पहले की बजट घोषणाओं के बाद अगर यह स्थिति रहती है तो हमारे सदन के लिए बहुत सोचने का विषय है।

आज की तारीख में भीलवाड़ा शहर में जब पुर उपनगर कस्बे की बात करता हूं, 40 हजार से ज्यादा की आबादी है, चार वार्ड हैं जिनमें 5-5 हजार वोट हैं और उस कस्बे में मुख्य मंत्री जी जब दौरा करने पधारे थे, तब उन्होंने पीएचसी की बात की थी। जब गांव वालों ने मुद्दा उठाया था और जनता के सामने वादा किया था कि मैं यहां नया भवन बनाकर सीएचसी में क्रमोन्नत करूंगा। इस बजट में घोषणाएं की हैं लेकिन पुर उपनगर का नाम नहीं लिया, जबकि इनके स्वयं के श्रीमुख से निकले हुए ये शब्द हैं। इस तरह का जादू अगर आप दिखाते चले जाएंगे तो पांच साल बाद जनता क्या जवाब देगी, इसमें आप मोदी की छोड़ो, अपनी चिंता करो।

मेरे भीलवाड़ा शहर में रेलवे फाटक की एक बहुत बड़ी समस्या है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

वहां 50 यात्री ट्रेन और लगभग 60-70 मालगाड़ियां रोज निकलती हैं। शहर को विभाजित करने वाली रेलवे फाटक 24 घंटे बन्द रहती है और हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने कई बार निवेदन किया था...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लिखकर दिया, उसके बावजूद आज तक उस आरओबी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी बजट में जब रिप्लाई करें तो भीलवाड़ा में रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण की मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसकी घोषणा कर उसकी क्रियान्विति करें।

मेरे भीलवाड़ा शहर में एमएलवी टैक्सटाइल कालेज है। उस शहर में 35 साल पुराना यह इंजीनियरिंग कालेज है। पूरे देश में टैक्सटाइल के केवल 10 कालेज हैं और उसमें राजस्थान का यह एकमात्र टैक्सटाइल कालेज है। उस कालेज को स्वायत्तता के नाते चलाकर उसकी आर्थिक स्थिति बिलकुल बेकार है, सरकार से मेरा आग्रह है कि कृपा करके सरकार इसको अंडरटेक करें। जो गरीब बच्चे उस कालेज में पढ़ते हैं उनको 80-80 हजार रुपये फीस देनी पड़ती है। अगर सरकारी कालेज बनेगा तो एक हजार की फीस में उन गरीबों का कल्याण होगा। आपसे आग्रह है कि उस टैक्सटाइल कालेज को सरकार अपने अधीन लेकर संचालित करें।

ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में सवर्णों को हम आरक्षण देते हैं, उनको अन्य तरह के जो आरक्षण मिलते हैं उन आरक्षण में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उनको सारी छूट मिलती है, आयु सीमा में छूट मिलती है और जिस तरह के लाभ उनको दिये जाते हैं, वे सारे लाभ ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में भी लागू किए जाएं, यह हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया, मैं विपक्ष से आने वाले साथियों को देख रही थी तो एक दोहरा किरदार नजर आ रहा था क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

ने एक भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कोई काम न दिया हो। एक तरफ तो तारीफ करना और दूसरी तरफ संदेश गलत चला जाए, इसके लिए विरोध करना, यह दोहरा आचरण मैंने देखा। मैं बजट पर यह बोलना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हमेशा से, पिछले कार्यकाल को भी आप देखते हैं तो उसमें भी चिकित्सा के ऊपर उन्होंने काफी काम किया। वे समझते थे कि चिकित्सा के अभाव में किसी गरीब की मौत न हो, वे समझते थे कि महंगी जांच के कारण किसी गरीब को उपचार न मिले, ऐसा न हो और ठीक इसी तरीके से इस बजट में भी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपार घोषणाएं की हैं।

अगर मैं बजट की बात करूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में उसका असर देखती हूं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। 2013 का इलेक्शन मैं हारी थी, उस दौरान संघर्षरत थी और हमने देखा कि उस सीएचसी के अन्दर तीन से ज्यादा डाक्टर नहीं रहते थे पर आज सीएचसी, राजगढ़ की अगर बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि 69 पद हैं और आज एक भी पद खाली नहीं है। उसी सीएचसी की बात करूं तो जो सोनोग्राफी मशीन वर्षों तक बन्द रही, वह आज चालू है। आपरेशन थियेटर बन्द रहा वहां आज आपरेशन हो रहे हैं। नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था है, ब्लड स्टोरेज हमें दिया, ट्रोमा सेंटर हमें दिया। पिछले बीजेपी के कार्यकाल के अन्दर जहां पर 200 ओपीडी होती थी वहां आज 600 से 700 है। यह मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा के सीमावर्ती है और इसकी वजह से हिसार में जाकर महंगा इलाज जिन्हें कराना पड़ता था, वे सुविधाएं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिल रही हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं और आपके माध्यम से अपील भी करती हूं कि 30 प्रकार की नि:शुल्क जांचें अभी हो रही हैं, उन जांचों को भी बढ़ाया जाए और 50 बैड के इस हास्पिटल को 100 बैड में किया जाए।

शिक्षा की अगर बात की जाए तो ब्लाक स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हुई थी और उसी में मुझे भी पिछले बजट में एक स्कूल मिला। उसमें कम सीटें होने के कारण बहुत सारे मजदूर या किसान भाई कहते थे कि हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाये। ऐसे में 5 हजार की आबादी तक के गांवों में जब अंग्रेजी मीडियम स्कूल देने की बात की है तो उस वर्ग में एक नया उत्साह आया है कि आज उसका बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सकता है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

इसके साथ-साथ, मैं शिक्षा मंत्री जी को यह जरूर कहना चाहूंगी कि शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। जिस तरीके से पिछले वर्ष कोरोना आया और इस गम्भीर बीमारी ने मनुष्य की जो प्राथमिकता है या वैल्यू है, उसके बारे में हमने जाना और यह एक ऐसा संसाधन है जिसमें हमें आगे काम करना पड़ेगा।

ठीक इसी तरीके से पिछले बजट में खेल के विषय के ऊपर भी मैंने काफी बातें रखी थीं और मैं यहां पर जरूर बोलना चाहूंगी कि राजनीति के जादूगर ने हॉकी के जादूगर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेजर ध्यानचन्द जी के नाम से जो ब्लाक स्तर पर स्टेडियम देने की बात की है, आप तो खुद स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले ओलम्पिक में मैडल, राष्ट्रीय खेल जो हॉकी माना जाता है उसमें हमारे देश के लिए गोल्ड मैडल जीते, उस हॉकी के जादूगर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। 29 तारीख को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं।

मेरा मानना है कि निरोगी भारत, निरोगी राजस्थान, अगर यह सपना सच हो सकता है तो खेल मैदान के जरिये हो सकता है। जिस दिन कोरोना आया था तो हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुआ और वह अपने शरीर को समय देने लगा कि किस तरीके से मुझे बचाव करना चाहिए इस तरीके की गम्भीर बीमारियों से। इसी के द्वारा मैंने आपको बताया कि पिछले बजट में मैंने खिलाड़ियों से सम्बन्धित एक बात उठाई थी कि फिजियोथेरेपी री-हैब सेंटर हमारा होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने आवासीय स्कूल की घोषणा की और साथ में 40 करोड़ रुपये हाई-परफार्मेंस सेंटर के लिए जो आपने दिये हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते विभिन्न देशों में जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला और विशेष तौर पर जो फिजियोथेरेपी री-हैब सेंटर की बात करती हूं तो साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और यू.के. में काफी अच्छे ये सेंटर हैं और हाल ही के दिनों में हमारे भारत में काफी ऐसे सेंटर बने, जिनका माननीय खेल मंत्री जी ने भी जिक्र किया, अभिनव बिंद्रा जी, जो देश के लिए गोल्ड मैडल जीत चुके हैं, उन्होंने भी खोला है। साथ ही, बेल्लारी, बैंगलोर के पास में जिंदल ग्रुप ने भी खोला है, जिसमें मैंने खुद ने भी विजिट किया था। यह एक ऐसा री-हैब सेंटर बनने जा रहा है हमारे प्रदेश के अंदर, मैं माननीय मंत्री जी को जरूर यह कहना चाहूंगी कि एक कमेटी बनाकर, इसको जब हम बनाएं तो उसके ऊपर हमारी स्टडी होनी चाहिए, उन सेंटर पर हमें देखना

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)
चाहिए कि किस तरह की फैसिलिटीज हैं, जो आने वाले लम्बे समय तक हमारे खिलाड़ियों को फायदा दे सके।

माननीय सभापति महोदय, आपको मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि जो एसएमएस स्टेडियम है, इस प्रदेश की धुरी है, बिलकुल, हमारे सदन के बाहर वह स्टेडियम और सुबह जब इस स्टेडियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर लगभग 500 बच्चे सुबह प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 15 साल पुराना वह स्टेडियम है और उस सिंथेटिक ट्रैक की हालत काफी खस्ता है। उस पर प्रैक्टिस करने वाला बच्चा कहां से आता है, मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी का बच्चा है, अपने खेल पर ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकता। एक जूता तो खरीद सकता है, लेकिन ट्रैक नहीं बनवा सकता और उसी के जरिए हमारे खिलाड़ी चाहें वे आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, देश के लिए पदक जीतें, इतनी मेहनत करते हैं, तो उन बच्चों को इंजरी न आए, इसके लिए मैं अपील करती हूं कि उसे सिंथेटिक जरूर बनाना चाहिए।

मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, राजस्थान में कोई प्रोविजन नहीं था कि खिलाडि़यों का भविष्य कैसा रहेगा लेकिन आपके आशीर्वाद से, माननीय मुख्य मंत्रीजी की कार्यशैली का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सीधे तौर पर भर्ती करना, तीस खिलाडि़यों को जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए मैडल जीतकर आये थे, डीवाईएसपी का पद देना, वन विभाग में अधिकारी लगाना, इस तरीके से अलग अलग विभागों में जो नियुक्तियां दी गई हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में 153 खिलाड़ियों के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनकी रोजी-रोटी चले, खिलाडि़यों को सीधी भर्ती दी गई है, यह बहुत बड़ी बात है। ब्लाक स्तर पर हम खेलों को लेकर आना चाहते हैं, जब खिलाडि़यों को नौकरियां दी जाएंगी तो वह खेलों में आगे भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के लिए मैडल भी जीतेगा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, ठीक इसी तरीके से, मैं कृषि बजट पर आना चाहूंगी। कृषि प्रधान देश की जब बात होती है और जब कृषि बजट की बात आये तो राजस्थान के मुखिया ने जो कृषि बजट अलग से पेश करने की बात की है, उसमें मैं कहना चाहूंगी, चाहे मेरे दाईं तरफ बैठे हमारे विपक्ष के साथी हों, चाहे हम पक्ष के साथी हों, हमें दिल खोलकर इस बात का स्वागत करना चाहिए कि एक इस तरीके का बजट है, जो राजस्थान के किसान के लिए बना

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

है। मैं दो-तीन दिन से यह सुन रही थी कि इतनी ज्यादा आलोचना की जा रही थी कृषि बजट के ऊपर, मैं अपने विपक्ष के साथी विधायकों से कहना चाहूंगी कि अगर आप वास्तव में किसान का भला चाहते हैं, पूरे दिन बहस में मैं सुन रही थी, अगर वास्तव में आप किसान का भला चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष सत्र बुलाते हुए, तीनों काले कानूनों के पक्ष में एक बिल जो पास किया था, आज गवर्नर महोदय के पास पड़ा है। आप वास्तव में इनका भला चाहते हैं तो गवर्नर महोदय से अपील कीजिए की राष्ट्रपति महोदय को यह बिल भेजें।

साथ ही साथ आपको मैं यह याद दिलाना चाहूंगी, लगभग सौ दिन हो चुके हैं, जब दिल्ली की सरहद के ऊपर हमारे किसान डटे हुए हैं, सर्दी में वे डटे हुए हैं, गर्मी में वे डटे हुए हैं, आप इतनी बड़ाई उन तीनों काले कानूनों की कर रहे हैं परन्तु बड़े अफसोस की बात, आप ही की सरकार के द्वारा..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): कंक्रीट की दीवार बनाई गई, सड़क पर कीलें ठोंकी गईं। किस चीज का डर था? जब इतना अच्छा बजट आप बताते हैं, पानी बंद किया गया, उनके लिए शौचालय बंद किये गये। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर वास्तविकता में आप जीना चाहते हैं, आप समझिये, वह समय दूर नहीं है जब युवा, किसान, महिला और छोटा व्यापारी भी सड़क पर हों।

साथ-साथ, मैं आज यह भी कहना चाहूंगी कि महंगाई पर बात, आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, किस तरीके से सिलेंडर को लेकर सड़क के ऊपर रोटियां बनाई जाती थी और आज उस सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है? उज्ज्वला-उज्ज्वला तो करते हैं लेकिन उस सिलेंडर की कीमत नहीं बताते हैं कि उसकी कीमत कितनी हो चुकी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बताते हैं कि कितनी हो चुकी है, तो यह जिस तरीके से इस सदन में आप आये हैं, आपका यहां आना सार्थक हो, तो कृपा करके केन्द्र की सरकार को सचेत करें और उनसे आग्रह करें कि इस महंगाई पर लगाम लगाए।

साथ-साथ, आपने कई बार कहा कि किसानों का कृषि ऋण माफ, इसमें भी आप सबके योगदान की जरूरत है और बार-बार कृषि मंत्री जी ने भी आपसे एक आग्रह किया था कि केन्द्रीय बैंक जो हैं, उनकी सूची आप हमें दीजिए ताकि उन किसानों को, अपने आपको वे ठगा हुआ महसूस नहीं करें।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

राजस्थान की सरकार किसानों का भला करना चाहती है, जिसमें आपके भी सहयोग की जरूरत है, यह मैं आप सबसे चाहती थी।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि इस बजट के अंदर काफी घोषणाएं हुईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऊपर भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी। चूरू जिला आपको मालूम है, सभापति महोदय, कि हमारे पास ऐसा कोई खासकर ज्यादा खनिज पदार्थ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, रेतीला है, रेगिस्तान है, बारिश पर निर्भर है। ऐसे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करने की जो घोषणा की है, मैं समझती हूं कि ये आने वाले समय में राजगढ़ में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

साथ-साथ, बहुत लम्बे समय से झुंझुनूंराजगढ़, जो सड़क है, काफी टूटी हुई थी, 151.47 करोड़ का बजट इसके लिए दिया है। साथ ही, एसएच-106, जो राजगढ़ से भादरा को जोड़ता है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): 126.77 करोड़ की जो योजना दी है और साथ ही साथ पांच करोड़ हर विधायक को, इसका मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। साथ ही राजगढ़ को जिस तरीके से पेश किया जाता है क्राइम के क्षेत्र में, मैं यहां पर भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए एसओजी चौकी वहां पर देने की जो बात कही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इसके प्रभाव रहेंगे, वहां पर हम क्राइम कम करने में भी सफल रहेंगे।

साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से कृषि महाविद्यालय, चांदगोठी में और सिद्धमुख तहसील में मंडी खोलने की मांग करती हूं और सीएचसी राजगढ़ में जो कि 50 बैड की है, उसे 100 बैड किया जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक तो काबीना मंत्री विराजे यहां, दो कनिष्ठ मंत्री बैठे हैं, जिनकी खुद के विभाग में ही नहीं चलती, कोई तो हो।

श्री सभापति: काबीना मंत्री बैठे हुए हैं, यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप देखो तो सही, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, यह पहली बार देख रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिये। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, बजट 2021-22 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने तीसरा बजट पेश किया है और तीसरे बजट में पुराने बजट की, जो घोषणाएं हैं, जनता उसकी राह देख रही है कि कब पूरी होगी क्योंकि मुझे लगता है, पुरानी घोषणाएं भूलते चलो और आगे की घोषणाएं करते चलो। एक आदमी ने कहा कि मैं अमेरिका जाने का प्लान कर रहा हूं, कितने रुपये लगेंगे तो दूसरे ने कहा कि एक रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लान करने के कोई रुपये नहीं लगते, केवल प्लान करो।

सरकार का बजट जनता की आशा एवं आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में झूठे वादे और थोथे नारों से वोटों की ठगी का इतिहास पुराना है। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है, एकता-अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये वादे सब पुराने हैं। बेरोजगार युवा भत्ते की राह देख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला? मुझे आंकड़े दीजिए, बाकी मैं नहीं जानता। उदयपुर जिले में 2150 बेरोजगारों को भत्ता मिला और हमारे विधायक झाड़ोल के बैठे हैं, वहां कोटड़ा तहसील में 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, लसाड़िया में 10 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, यह इस सरकार की उपलब्धि है।

मुख्य मंत्री जी ने चार विधान सभा क्षेत्र में जहां उप चुनाव है, उनमें कालेज की घोषणा की है। मेरी पुरानी मांग है उदयपुर जिले में बाकोलिया की डीपीआर बनी हुई, मावली तहसील पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है, कोई घोषणा नहीं की है। मावली में आपने नगरपालिका की घोषणा की, ऋषभदेव में नगरपालिका, जो नगरपालिका बनाई उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लंबे समय से मेरी मावली तहसील नगरपालिका के लिए कोशिश कर रही है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। आपने इसमें भी अपने दल को नहीं छोड़ा है तो मैं मुख्य मंत्रीजी से न्याय की अपेक्षा करता हूं। पिछले 2 बजटों में

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। 13 फरवरी, 2019 को मुख्य मंत्री जी ने लेखानुदान के वक्तव्य में बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठन करने की घोषणा की बिंदु-35 के अनुसार, वह बोर्ड अब तक नहीं बना है, 26 महीने हो गये हैं। 2019-20 में बजट में घोषणा की नंदी शाला स्थापित करेंगे, अब इसके लिए 2020-21 के बजट में 111 करोड़ की घोषणा की है। इस विषय में 2019-20 से आज तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई? कुछ कहना नहीं है। जन घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हम विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ।

यहां अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं उधर आगे सीट पर। मेरा उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि कालेज की जो फीस है उसमें भी रिजर्वेशन है। जिन बच्चों से रिजर्वेशन के आधार पर फीस ली जाती है, उसका हमारा विरोध नहीं है, उनको देना चाहिए पर जनरल क्लास के बच्चे जिनको 10 परसेंट आपने आरक्षण दिया है, उन बच्चों के लिए भी करें। इसके लिए राजस्थान सरकार में केवल 5 या 6 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता है। माननीय कालेज शिक्षा मंत्रीजी, मेरी आपसे प्रार्थना है उन बच्चों की फीस तो कम से कम समान कर दीजिए ताकि उन बच्चों को उसका लाभ मिले।

आपने नंदी शाला में मार्च, 2019 तक का पैसा दे दिया है और मार्च, 2019 तक के मेरे पास आंकड़े हैं यह, उसके अनुसार मैंने डिटेल निकाली है। आपने कहा, हमने मार्च, 2019 तक 209 करोड़ 50 लाख रुपये होते हैं उसमें से 193 करोड़ रुपये दे दिये। सभापति महोदय, 2019 की बात कर रहा हूं उसमें भी अधिकारियों ने झूठबाजी की क्योंकि अभी भी नंदी शाला के 2019 तक के मार्च तक के 43 करोड़ रुपये बाकी हैं। आपने कहा था 2019-20 के बजट में, सभी ग्राम पंचायतों पर हम विकास पथ बनाएंगे। गौरव पथ का आपने नाम बदल दिया, कितने विकास पथ बन गये? 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें गली सहित वॉल टू वॉल बननी थी, क्या हुआ?

वर्ष 2019-20 के बजट के बिन्दु संख्या-134 में विभिन्न विभागों द्वारा 75000 भर्तियों की घोषणा की थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019-20 के बजट के बिन्दु संख्या-201 में कहा गया 34,682 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 82,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इस बजट में 53,000 भर्तियों की आप ने घोषणा की हैं। भर्तियां नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। हमारे सामने डॉक्टर्स की भर्ती नहीं है। परेशान हो रहे हैं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

विधान सभा चुनाव, 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र की भूमिका में पहले पेज पर लिखा था, यह हमारे संकल्प के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश की जनता की उम्मीदों के संकल्प का भी दस्तावेज है। यह जन घोषणा पत्र महज औपचारिक घोषणा का दस्तावेज नहीं बल्कि आपके विश्वास और हमारे संकल्प का साक्षी है। यह गहलोत सरकार का तीसरा बजट है। जन घोषणा पत्र के पृष्ठ-3 पर पहला वादा था 10 दिन में किसानों के ऋण माफ करेंगे। यह वादा थोथा और झूठा साबित हुआ। जन घोषणा पत्र में समस्त कृषि यंत्र और ट्रैक्टर को सर्विस टैक्स से मुक्त करने का वादा था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश की गौण मंडियों को पूर्ण मंडियों में विकसित करने का वादा किया कुछ नहीं हुआ।

2019-20 के बजट में आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टोलरेंस की घोषणा की थी। इसके बाद स्थिति क्या है? प्रदेश में आला अफसर घूसखोरी में लिप्त पाये गये हैं। रिश्वतखोरी में पकड़े गये अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति में भी विलंब हो रहा है। नाबार्ड ने रिपोर्ट दी है, सहकारी बैंक अपात्रों के हवाले कर दिये गये हैं। अफसर खुद चांदी के सिक्के ले रहे हैं। सरकार प्रदेश में 214 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही। यह क्या भ्रष्टाचार का जीरो टोलरेंस है?

जन घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अधिकार देने का वादा था, स्थिति हमारे सामने है। एक रुपया भी किसी पंचायत को आपने नहीं दिया। सरपंच कह रहे हैं कि राज्य सरकार से विकास मद का पैसा नहीं मिल रहा है। डीएमएफटी के लिए आपने पहले कहा था कि जिला प्रमुख अध्यक्ष होगा, फिर कहा कलेक्टर होगा, फिर कहा कि प्रभारी मंत्री होगा और अब उसकी बैठकें चालू हुई हैं।

हमारे कांग्रेस के बंधु आजकल किसानों के लिए बड़े चिंतित हैं, काला कानून, काला कानून, क्या काला कानून है? उसमें काला क्या है? यह तो बताओ।

पशुपालन विभाग में, यह किसानों से जुड़ा मुद्दा है, गांवों में पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर नहीं हैं। मेरे मावली क्षेत्र में 45 पशु चिकित्सालय हैं और केवल 15 कर्मचारी हैं डॉक्टर और सारे मिलाकर। जन घोषणा पत्र में पशुधन का मुफ्त बीमा कराने एवं पशुओं की मुफ्त दवा चिकित्सा का वादा था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

10 जुलाई, 2019 को वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में बिंदु-17 में 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष की घोषणा थी। क्या हुआ कृषक कल्याण कोष का? इसी बजट के बिंदु-32 में पीडब्ल्यूडी के लिए 6,037 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2008 से शुरू हुए काम आज भी बजट के अभाव में अधूरे पड़े हैं।

उदयसागर से पानी ले जाने के लिए आपको आश्चर्य होगा मानसी वाकल पानी के लिए हिंदुस्तान जिंक ने पैसा दिया था। दिसंबर में है, एग्रीमेंट खतम हो गया। मैंने सरकार से, मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की। उन्होंने शायद उसको स्वीकार कर लिया होगा। अभी इसकी मियाद बढ़ाई नहीं है परंतु मुझे लगता है सरकार पता नहीं क्या करे, पिछले दरवाजे से क्या करें, कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि राजसमंद का उप चुनाव है, वल्लभनगर का उप चुनाव है, जाखम का पानी यानी माही का पानी जाखम में आये और जाखम का पानी वल्लभनगर में मावली और राजसमंद जाकर भर सकता है। डीपीआर बनी हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पानी को लाने की व्यवस्था करें। 2019-20 के बजट में 121 पाइंट पर लिखा हुआ है अट्ठारह भवन विहीन महाविद्यालयों में भवन बनाने की घोषणा की थी। मावली में कालेज खुला लेकिन भवन नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि 18 कालेज के भवन बनाएंगे, एक की भी व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 2019-20 के बजट में आपने पहले कहा था कि 3 लाख संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। वह रो रहे हैं। आज जगह-जगह हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी की हड़ताल चल रही है। परिवहन विभाग की हड़ताल चल रही है। कोई उसका धणीधोरी नहीं है। आपने 2019-20 के बजट में उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ दिये लेकिन जमीन पर एक रुपया भी वहां पहुंचा नहीं है। जन घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हमने 22,000 स्कूल जो इन्होंने बंद कर दिये, उनको वापस चालू करेंगे। क्या हुआ उसका? कितने स्कूल वापस खोले आपने? कुछ भी नहीं खोले। राजस्थान में 17000 स्कूलों में स्कूल का भवन नहीं है उसकी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। बजट में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं है। आपने जो पेंशनर हैं उनके हॉस्पिटल अधिकांश बंद कर दिये, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना के लिए

(श्री धर्मनारायण जोशी)
2019-20 में 18 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 50-50 लाख रुपये का प्रावधान है। क्या हुआ बजट का 18 करोड़ का?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आपने बजट में घोषणा की थी कि पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे। जैसे अभी खेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल मैदान बनेंगे, पुलिस थानों का पैसा विधायकों से लेने के लिए एसपी फोन कर रहे हैं, आईजी फोन कर रहे हैं, सरकार ने कोई एक रुपया भी नहीं दिया वहां पर।

श्री सभापति: श्री रफीक खान। विराजिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मावली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय किराये पर, मेरा अंतिम एक निवेदन है, एक मिनट की मेरी बात है। एक मिनट की बात है, सभापति जी, प्लीज मेरी एक मिनट की बात है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया...

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आप उनको रोकिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, तीन विश्वविद्यालय खोले आपने, अंबेडकर विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय और तीसरा खोला जनजाति विश्वविद्यालय। उनकी हालत क्या है? हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय आपने वापस चालू किया। 2019-20 में 39 विद्यार्थी थे, 2020-21 में 84 विद्यार्थी थे, अभी 114 विद्यार्थी हैं और उसका महीने का पेमेंट 11 लाख का हो रहा है, कोई विज्ञापन नहीं, यह सारी स्थिति आपने खड़ी की है। आपका राजस्थान का पेट्रोल-डीजल का वैट सबसे ज्यादा है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री रफीक खान।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): बहुत-बहुत धन्यवाद, बोलने का अवसर दिया। मेरा बहुत सारा विषय बाकी रह गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मुख्य

(श्री रफीक खान)

मंत्री के बजट अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्री का यह बजट और बहुत सारी बातें पक्ष विपक्ष ने यहां उठाई हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से गुजरी, पूरा वर्ल्ड इकोनोमिक क्राइसिस में था। भारत इकोनोमिक क्राइसिस में था और राजस्थान स्टेट इकोनोमिक क्राइसिस में थी। ऐसी स्टेट जिसमें कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का काम नहीं है, मरु प्रदेश कहलाता है। उस स्टेट का बजट ऐसे समय पर दिया गया, जहां पिछले 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का लोन ले लिया गया और 3 लाख 9 हजार करोड़ रुपये पर लोन पहुंचा दिया। इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ही 40-45 हजार करोड़ की आ गयी।

(15.00 बजे)

60 हजार करोड़ रुपये का हिस्सा सैलरी में चला जाता है तो जिस स्टेट की रेवेन्यू डेढ़ लाख करोड़ की है, उस स्टेट के अंदर एक लाख करोड़ रुपये सिर्फ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में, जो इन्होंने पिछले 5 सालों में लोन ले लिये, उनको चुकाने में चला जाता है। ऐसे स्टेट में बजट दिया और ऐसा बजट दिया जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे। ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, जहां इसका फायदा नहीं दिया गया हो।

हमारे पक्ष विपक्ष के साथी अभी बहुत सारी बातें बोल रहे थे। सभापति महोदय, आज के समय में बेरोजगारी एक्स्ट्रीम पर है, मुख्य मंत्री जी ने इस बात को समझते हुए, आम आदमी की प्रॉब्लम समझते हुए, कोविड के साल को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया और उस आदमी को टच करने की कोशिश की जिसकी किचन के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता था।

(15.02 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

10 से 15 हजार सैलरी कमाने वाले एक आदमी की पॉकेट से उसके हजार से पन्द्रह सौ रुपये बिजली पानी में चले जाते हैं, हजार, पंद्रह सौ रुपये उसके बच्चों की पढ़ाई में चले जाते हैं, हजार, पंद्रह सौ रुपये उसके खुद के कन्वेंस में चले जाते हैं, हजार, पंद्रह सौ रुपये उसके स्वास्थ्य में चले जाते हैं। दस, पंद्रह हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास चार-पांच हजार रुपये उसकी रसोई के लिए बचते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने इस पर ध्यान दिया। हैल्थ का पूरा बेनिफिट आम आदमी को देने की कोशिश की। बहुत सारे इलाज के,

(श्री रफीक खान)

दवाइयों के सैक्टर इसमें जोड़े। कोविड महामारी से निकले और निकलने के बाद में इस बात पर जोर दिया, निरोगी राजस्थान की कल्पना की। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने निरोगी राजस्थान की कल्पना की और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश की। चाहे वह हैल्थ का मसला हो, चाहे वह एजुकेशन का मसला हो, चाहे वह बिजली पानी का मसला हो, चाहे कन्वेंस का मसला हो। हमने लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद डीजल-पेट्रोल प्राइस कम किये। केंद्र सरकार ने क्या किया, सिवाय महंगाई बढ़ाने के कोई काम नहीं किया। सभापति महोदय 60 डालर, 80 डालर क्रूड ऑयल होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब 2008-09 में 148 डालर क्रूड ऑयल था, तब हम 45 रुपये पेट्रोल बेचते थे, आज हम पेट्रोल 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आम आदमी की जेब से पैसा खींच रहे हैं। सिवाय देश को बर्बाद करने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने अपनी ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए एक जगजाहिर प्रशंसनीय बजट प्रस्तुत किया। विपक्ष सिर्फ निंदा, आलोचना और दो दिन से जहर उगल रहे हैं और उसी उसी बात पर कर रहे हैं। मैं एक दो पंक्ति में इसका जवाब देना चाहता हूं कि बजट देने वाला तो क्या काम कर रहा है और जहर उगलने वाले क्या काम कर रहे हैं। घास खाकर दूध देवे गाय की नीयत तो देखो, दूध पीकर जहर उगले सांप की फितरत तो देखो।

सभापति महोदय, किसान का मसला, जब-जब किसान पर आंच आई, हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हमने किसानों का ऋण माफ किया, किसानों के लिए जो बन सकता था वह किया, लेकिन इन्होंने किसानों के बिल पर किसी भी तरह की सुध नहीं ली। राम के नाम पर राजनीति करते हैं। यह भूल जाते हैं कि राम किसान के साथ में हैं, आप लोगों के साथ में नहीं है। भगवान राम ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, गरीब का साथ दिया है। किसान को मत सताना, किसान रो देगा। किसान के राम ने सुन ली तो जड़ मूल से खो देगा। तुलसीदास जी कहते हैं, ''तुलसी हाय किसान की कबहु ना निष्फल जाए, मरे ढोर की चाम सू लोह भस्म हो जाए।'' लोह भी भस्म हो जाता है, तुम लोग बचोगे नहीं, किसानों की निंदा करोगे तो भस्म हो जाओगे।

सभापति महोदय, पूरे तीन दिन से राजस्थान के बजट पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के जयपुर की लाइफ लाइन एक्सपोर्ट बिजनस है, ज्वैलरी बिजनस है, हैंडीक्राफ्ट बिजनस है, फल सब्जियों के निर्यात का बिजनस है।

(श्री रफीक खान)

इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया और एयरपोर्ट वाले क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट वाले कह रहे हैं कि यहां से निर्यात बंद कर दो। राजसिको जो यहां का लघु उद्योग कॉरपोरेशन है, उसको यह कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाओ, हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। सभापति महोदय, दो महीने से एक्सपोर्ट बंद है, एक भी साथी ने आवाज नहीं उठाई। इन्होंने इतनी सारी बातें कीं सिवाय क्रिटिसिज्म करने के, सिवाय उसमें नुक्ताचीनी निकालने के एक बार भी नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, क्योंकि अडाणी तो इनका खुद का आदमी है, किस पर क्रिटिसिज्म करें, क्या ऐब निकालें। जयपुर से दो महीने से एक्सपोर्ट बंद है, दिल्ली से शिपमेंट भेजनी पड़ रही है। पूरे राजस्थान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई ...(व्यवधान)... अभी दूंगा आपकी बात का जवाब, रुक जाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो इतने सीनियर हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सिवाय बेचने के और बेचने वालों को सपोर्ट करने के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दो महीने से एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट की एक शिपमेंट नहीं जा पा रही। जयपुर में ज्वैलरी बिज़नस जिसका निर्यात किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, 10 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है उसके बारे में इनको चिंता नहीं है। कह रहे हैं कि यह तो जादूगर का बजट है, वह भी बताता हूं कि क्या-क्या जादू है, अभी बताता हूं आपको। बेचने के अलावा कोई बात नहीं है। दो पंक्तियों से बात करूंगा, समय आप लिमिटेड दोगे इसलिए दो पंक्तियों से बोलूंगा।

''जो डलहौजी न कर सका वह यह हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दे दो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, गलियां बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अगर हम जो यूं ही सोते रहे तो यह फर्जी राष्ट्रवादी देश बेच देंगे, वतन बेच देंगे।''

न जॉब की बात, न बेरोजगारी की बात, न काले धन की बात, न किसान की बात, न महंगाई की बात, न डीजल-पेट्रोल की बात, खाली मन की बात और मन में कपट है। मन में किसानों के लिए कपट है। मन में गरीब लोगों के लिए कपट है, तो खाली मन की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है। मोदी जी जब सत्ता में आये तब स्लोगन था, कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कहां गये, 45 से 100 रुपये ले गये हो, कुछ बोलो। 400 रुपये के सिलेंडर को सवा आठ सौ रुपये ले गये हो, कुछ

(श्री रफीक खान)

जवाब तो दो। राजस्थान से आप 25 सांसद चुनकर गये हो। सभापति महोदय, जब कोरोना जैसी महामारी यहां आई, राजस्थान के एक भी सांसद ने अपने कोष से मुख्य मंत्री को सहायता नहीं की और एमएलए, एमएलए को चाहिए था, इनके क्षेत्र की जनता ने इनको चुन कर भेजा है, इनका दायित्व नहीं था प्रधान मंत्री को पैसे भेजने का? इनका दायित्व था कि मुख्य मंत्री की मदद करें, मुख्य मंत्री को अपने विधायक कोष से पैसा दें और आम जनता के लिए, जिन्होंने इनको चुन कर भेजा है, उनके लिए खड़े हों लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली ...(व्यवधान) रहने दो, रहने दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। प्रधान मंत्री को दे रहे थे। ...(व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें, विराजें। कासनियां साहब, विराजें। (व्यवधान) विराजें, विराजें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठ जाओ, बैठ जाओ, नाखून कटा कर शहीदों में नाम मत लिखाओ। जिससे बात कर रहे हो, उसने अपनी विधान सभा में 1 करोड़ 80 लाख रुपये दिये हैं, दो लाख रुपये देकर बात की है आप लोगों ने, शर्म करो आप लोग। नाखून कटा कर शहीदों में नाम मत लिखाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सारा अनाज रामगंज ले गये, हमने भी दिये हैं 70 लाख रुपये, आपकी तरह सारा अनाज रामगंज नहीं ले गये। पूरा जयपुर भूखा था और रामगंज में बंट रहा था, इसलिए सदन में तो सच बोलो, सदन में सच बोलो। सारा रामगंज में ले गये। अभी तक भी बकरियां खा रही हैं, हमारे आदमी भूखे मर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप की भी बारी आयेगी, जब इधर से बोलेंगे तब भी आप यही अपेक्षा रखेंगे?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, कोरोना टाइम में राजस्थान पहली स्टेट बनी जिन्होंने भीलवाड़ा और रामगंज को पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल बनाकर पेश किया। पूरी दुनिया में मास्क वितरण के नाम से अगर कोई स्टेट फेमस हुई तो राजस्थान स्टेट फेमस हुई।(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अमरीका में राजस्थान की तर्ज पर

(श्री रफीक खान)

हाईलाइट करते हुए यह मेंशन किया गया कि राजस्थान पूरी दुनिया में पहला ऐसा स्टेट बना जिन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया। नो मास्क नो एंट्री, पहला स्लोगन राजस्थान से आया। इनको गर्व करना चाहिए बजाय क्रिटिसिज्म करने के। इनको मुख्य मंत्री जी को शाबाशी देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बातों से नाम रोशन नहीं होते हैं। हाउडी मोदी से, ट्रम्प की चम्पी करने से नाम रोशन नहीं होते हैं। नाम रोशन होते हैं, जो काम अच्छा करे, उनकी हामी भरने से। नाम रोशन होता है आपको सपोर्ट करने में। मुख्य मंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम की 1200 स्कूलें खोली हैं। आपके किसी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? क्या कोई वे कांग्रेस के विधान सभा क्षेत्रों में ही खुलेंगी? क्या सिर्फ उसमें कांग्रेस के आदमी पढ़ेंगे? आप लोगों के मुंह से एक शब्द भी निकला? आप लोग एक बात नहीं कह सके। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) विराजिए, माननीय सदस्य विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये असत्य बोल रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने 1200 स्कूलें खोली हैं, आप सपोर्ट में आते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं-

''मंजिल समझकर बैठ गये चंद लोग,
मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया,
मुझको डुबोया गया, मैं उबरता चला गया।''

कोशिशें सब नाकामयाब होंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। यह पुड्डुचेरी नहीं है, यह कर्नाटक या मध्य प्रदेश नहीं है, यह राजस्थान है, यह वीरों की धरती है। सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कुछ नहीं कर पाओगे। (व्यवधान) बैठ जाओ।

श्री पब्बाराम (फलौदी): पंजाब का देखो ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठ जाओ, पंजाब देखा हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कहां गये? बोलो तो सही। कहां गये? कोई जवाब नहीं है। सब भूल गये, बातों के गुबार में खो गये। नया बजट आपने अनाउंस किया, आपने अल्पसंख्यकों का बजट कम कर दिया। आप धर्म के आधार पर,

(श्री रफीक खान)

सम्प्रदाय के आधार पर, पहले आप सीएए बिल लेकर आये, वह भी धर्म के आधार पर। अब आप बजट दे रहे हो, वह भी धर्म के आधार पर। आपको मारने के लिए अल्पसंख्यक ही मिलते हैं? आप दूसरी जगह नहीं बोल सकते? आप लोग सिवाय साम्प्रदायिकता को भड़काने के अलावा कोई राजनीति नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कोरोना के समय में मीटिंगें लीं। एक मुख्य मंत्री जी ने, सारे पक्ष विपक्ष और सब लीडर को बुलाया और ढाई सौ मीटिंग कॉल कीं। कोरोना से निपटने के लिए 600 वर्किंग ऑवर दिये। इन सबको उनको दुआएं देनी चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए। ये सब सही सलामत बैठे हैं, हम बैठे हैं। यह मुख्य मंत्री जी का काम करने का तरीका था, इसलिए आज हम सब यहां बैठे हैं।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, एक शेर पढ़ देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: हां, शेर पढ़ दो, शेर पढ़ दो जोर से।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।''

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री अभिनेश। कृपया सभी दोनों तरफ से खूब आनंद लो, खूब सुनो और सुनाओ। ऐसा क्यों करते हो?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजट के ऊपर बहस के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। यह जो तीसरा बजट पेश किया गया है, मैं इसको इसलिए कपोल-कल्पित, असत्य और एक असत्य का पुलिंदा कहूंगा क्योंकि दो बजट घोषणाओं को अभी मूर्त रूप में अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। मैंने तीनों बजट का अध्ययन किया है। तीनों बजट में बहुत सारी

(श्री अभिनेश महर्षि)

ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर हम सभी सदस्यों को विचार करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि कोई पक्ष के विधायक के क्षेत्र में यदि कुछ दे दिया हो, विपक्ष के नहीं दिया हो, ऐसा हालांकि सदन में सदन के नेता को नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हुआ है और मूर्त रूप में धरातल के ऊपर वे सारी की सारी योजनाएं नहीं उतर पायी हैं, जिनकी पिछले दो बजटों की घोषणा की गयी थी। तीसरा बजट उसी तर्ज पर बहुत सारी घोषणाओं का पुलिंदा, असत्य का पुलिंदा सदन के नेता जी ने यहां पर प्रस्तुत कर दिया।

जो जादूगर ने जादूगरी दिखायी। जादूगर ने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि मैं जादूगर हूं। उनका इशारा वहां सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ तो जरूर था लेकिन वह इशारा पूरे राजस्थान की तरफ था, दुर्भाग्यपूर्ण है। जादू के अंदर जो चीज दिखायी जाती है वह असत्य होती है। जादू के अंदर, कपड़े के अंदर कबूतर होता है और बाहर लड़की प्रस्तुत की जाती है। यह जादू है, जो जादूगर जी ने दिखा दिया है। इसलिए यह गरिमामय सदन, जिसके अंदर हमने सुना था कि जो यहां पर कहा जाता है उसके ऊपर पूरा अमलीजामा पहनाया जाता है।

मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज प्रश्न काल में उन्होंने सरकार और मंत्रियों को फटकार लगायी। उन्होंने कहा कि जो बोला जाता है, उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और अधिकारियों को ये निर्देश दे देने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिये हैं, वे बजट की पोल खोलते हैं। विधान सभा में कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है। हमने सुना था कि एक-एक शब्द को नोट करके उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे ही प्रश्न काल समाप्त होता है अधिकारी दीर्घा से सारा का सारा सदन खाली होता है। माननीय सभापति महोदय, अब तो हालात ये हैं कि यहां दो राज्य मंत्री महोदय विराज रहे हैं और पूरा सदन खाली पड़ा है। ये सरकार के हालात हैं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के दो वर्ष, राजस्थान बदहाल है। दो-तीन बिंदुओं पर बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि समय की पाबंदी है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों से किसान परेशान हैं और आमजन हलकान है। अपराध का ग्राफ इतना ऊपर चढ़ा है कि आम व्यक्ति घर में भी असुरक्षित है। युवा भटक रहे हैं, रोजगार धरातल से हवा-हवाई हो गया है। प्रदेश की बेटियां असहज और असुरक्षित हैं। 'करनी थी प्रदेश की सेवा और सरकार ने खाया फाइव स्टार होटलों में मेवा।'

(श्री अभिनेश महर्षि)

कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक-दूसरे की टांग-खिंचाई ने राज्य के विकास को हाशिये पर ला दिया है। आमजन और गरीब को राहत दे रही योजनाओं को, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चालू कर रखी थीं, उन सबको बंद करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि-

''चहुं ओर कुशासन की रेलमपेल है

राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है।''

माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री महोदय का धन्यवाद दूं, जिनके कारण से ये राजस्थान के लोग बच गये। कोरोना काल की बात कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। आप भूल गये कोरोना काल में देश के प्रधान मंत्रीजी ने आपको क्या दिया? 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया, आप एमएसएमई की बात कर रहे थे, ठेले वालों की बात कर रहे थे, गरीब आदमी की बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर यदि किसी ने सबसे ज्यादा काम किया, सामाजिक सरोकार की भूमिका निभायी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निभायी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र के अंदर भामाशाह लोगों से बात करके, अपने विधायक कोटे से भी आम आदमी को भूखा नहीं सोने दिया।

देश के प्रधान मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मेरे भारत का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा। मुख्य मंत्रीजी, धन्यवाद, आपने भी उनकी तर्ज पर घोषणा कर दी, क्योंकि आपको मालूम था कि देश के प्रधान मंत्री पैकेज देंगे। उस स्थिति के अंदर सवा दो साल से अकर्मण्य और अराजक राज्यों में राजस्थान शामिल हो गया। विकास ठप हो गया, कानून व्यवस्था चौपट हो गयी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बेरोजगार सड़कों के ऊपर आंदोलनरत हैं। बेरोजगारों के बारे में आप सब लोगों को मालूम है। लाख करोड़ रुपये देश की कुल जीडीपी का, साढ़े दस परसेंट का प्रावधान, बीस लाख करोड़ रुपये का दिया। आप लोग कह रहे थे कि देश के प्रधान मंत्रीजी ने क्या दिया? 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी और आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत तीसरा देश है, जिसमें वैक्सीन बन गयी। इसके लिए देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी और केंद्र की भारत सरकार को कम से कम धन्यवाद तो दो। कश्मीर में धारा 370 हटा दी, 35ए हटा दी, आपको दर्द हो गया और हालात ये हो गये.. मेरे दो साथी अभी बहुत बोल रहे थे, चले गये। देश के प्रधान

(श्री अभिनेश महर्षि)

मंत्री ने मुस्लिम बहिनों की तरफ भी ध्यान दिया। तीन तलाक का कानून था, यह अभिशाप था हर महिला के लिए क्योंकि चार-चार शादी कर ली और इसके अंदर किसी भी महिला बहिन को तलाक-तलाक-तलाक कह कर बाहर कर दिया जाता था। देश के अंदर अगर यह अधिकार किसी ने दिया, तीन तलाक का कानून समाप्त करने का काम किया तो देश के प्रधान मंत्रीजी ने किया और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, फाइव स्टार होटल के अंदर, सेवन स्टार होटल के अंदर तो चले गये लेकिन 11 महीने से मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री निवास से बाहर निकले और लोग-बाग़ जो यहां पर बाहर से आने वाले लोग थे, उनके पैरों के अंदर छाले ही नहीं पड़े, उनसे खून रिसने लगा, तब मुख्य मंत्री जी को चिंता नहीं हुई। इस बात की चिंता यदि किसी ने की तो हम लोगों ने की। चरण पादुका देकर उन लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया ...(व्यवधान) और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने...

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): असत्य तो मत बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाऊं, यह क्या बात है?

श्री सभापति: आप बोलते रहिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कोरोना के संकट में बढ़-चढ़ कर सेवा कार्य किया। मैं बताऊंगा क्या-क्या किया तो आपको फिर दर्द होगा। आमजन की जरूरत के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख 25 हजार 350 पैकेट, 57 लाख 33 हजार 150 सूखी राशन सामग्री के पैकेट, 91 लाख 75 हजार 450 मास्क वितरण करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप लोगों ने तो जो सरकारी कोटा था, उसके ऊपर अपनी फोटो लगाकर लोगों के बीच में जाने का असफल प्रयास किया। इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, दलितों की बात कर रहे हैं। दलितों के प्रति अत्याचारों में देश में राजस्थान का दूसरा नंबर है। दलित भाई-बहिनों पर पूरे देश में अपराधों में केवल राजस्थान में 14.81 प्रतिशत अपराध घटित हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति अपराध में देश में राजस्थान

(श्री अभिनेश महर्षि)

का दूसरा नंबर है। देश भर में घटित अपराधों में 21.8 प्रतिशत अपराध तो केवल राजस्थान में हुए हैं और महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, आप सब लोगों को मालूम है, बहुत लंबी बात है।

मैं आप लोगों का ध्यान सिर्फ कुछ बातों पर और करना चाहता हूं। बजट के अंदर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे। तीसरा बजट पेश कर दिया, विप्र कल्याण बोर्ड धरातल पर तो कहीं आया नहीं है। इसके अंदर EWS का जो आरक्षण दिया था, EWS का आरक्षण देश के प्रधान मंत्री जी ने दिया था। आप लोगों ने यहां पर जो एक महिला बहिन है EWS की, उसके लिए पति की आय और पिता की आय, दोनों की आय जोड़ दी जाती है। कैसे EWS में आयेगी? आपने उनको आरक्षण दिया लेकिन आरक्षण के लिए जो आयु सीमा में छूट दी जाती है, वह आयु सीमा की छूट भी आपने नहीं दी। रोडवेज के अंदर जब वह परीक्षा देने जाते हैं तो उनको छूट दी जाती है, उसको भी आप लोग भूल गये। इसके बाद में जो फीस ली जाती है, उसके अंदर भी आप लोगों ने किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। ये EWS के लोगों के प्रति आपके मन में जो भेदभावपूर्ण रवैया है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि देगा और इन सब कामों को करने के लिए सरकार को सद्बुद्धि आयेगी।

'निरोगी राजस्थान' की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़-चढ़ कर 'निरोगी राजस्थान' की बात की। मैं रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं, पूरे राजस्थान की बात सभी लोगों ने कर ली। रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 70 प्रतिशत अस्पताल चाहे वह सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, उप जिला अस्पताल हैं, चाहे डिस्पेंसरीज हैं, उसमें 70 परसेंट से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ताले लगने की स्थिति में हैं। मंत्री महोदय, वह दिन दूर नहीं जब रतनगढ़ की जनता रतनगढ़ के अस्पतालों में वहां जंग खा रही मशीनों के आगे ताला लगा देगी। मैंने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को कई बार इस बात के लिए आगाह कर दिया है लेकिन राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार, सोयी हुई सरकार कुछ नहीं कर रही है। निरोगी कहां से करेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि दवा फ्री देंगे। दवा फ्री देंगे कहां से, जब आपके कोई देने वाला ही नहीं है, लिखने वाला ही कोई नहीं है, नाड़ी पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, स्टेथोस्कोप लगाने वाला ही कोई नहीं है? रतनगढ़ के चिकित्सालय में 16 पद हैं, एक चिकित्सालय की बात करूं जो स्पेशियलिस्ट के हैं, 16 में 14 पद खाली पड़े हैं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): कब से खाली पड़े हैं?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये कब से खाली हैं? ये पिछले दो-ढ़ाई साल से, सवा दो साल से खाली हैं। जो थे उसमें से 6 डाक्टर्स को वहां से हटा दिया। पीडियाट्रिशियन था, उसको हटा दिया, गाइनी का एक बार आया था, माइनोकोलोजिस्ट चला गया, आर्थोपेडिक्स का सर्जन आपके पास है ही नहीं। आप कौन से 'निरोगी राजस्थान' की बात करेंगे? क्या 'निरोगी राजस्थान' इसलिए हो जाएगा कि जो देश के प्रधान मंत्री जी ने बजट भेजा है, उस बजट के अंदर कर देंगे? सड़कों के हालात बहुत खराब हैं।

मैं इससे पहले, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय चले गये, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की बानगी बताता हूं। मेरे यहां पीजी कालेज है, रतनगढ़ के अंदर बालिका महाविद्यालय पीजी। एक लेक्चरर है, सिर्फ एक लेक्चरर। पूरे कालेज में सिर्फ एक लेक्चरर है। आप बता दीजिए यदि सदन में मैं असत्य बोल रहा हूं। एक लेक्चरर है, मैं छठी बार बोल रहा हूं और पीजी कालेज चल रही है। उसके अंदर होम साइंस है। होम साइंस के प्रैक्टिकल कैसे होंगे? बालिकाएं कहां जाएंगी? हालात खराब हैं।

ग्राम पंचायतों में विकास पथ बना रहे थे, क्या हुआ? आपने तो कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर विकास पथ बनाएंगे। कहां चली गयी बजट की घोषणा? मुख्य मंत्री जी कह रहे थे फेरो कवर लगाएंगे, वे फेरो कवर ढूंढने पर नहीं मिल रहे हैं। कहां गया वह अधिकार, विधायकों को अधिकार दिया था माननीय वसुन्धरा राजे जी ने, 7 किलोमीटर व 10 किलोमीटर की मिसिंग लिंक, कहां चली गयी? जनता जवाब पूछ रही है। गांव के अंदर अभी गये थे, वहां सुजानगढ़ तो इसलिए नहीं किया कि वह इसमें आ जाएगा, सुजानगढ़ के पास के अंदर पिलानियों की ढाणी में वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को ले आये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तीन मिनट हैं।

श्री सभापति: टाइम जो दिया है, वह आपके वहीं से आया है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप कृपा कीजिए। ऐसी स्थिति के अंदर सड़कों की री-कारपेटिंग की बात मैं करता हूं। एक इंच भी सड़क के ऊपर री-कारपेटिंग नहीं किया गया है। बहुत सारी सड़कें हैं, माननीय सभापति महोदय, जिनको मैं आपकी इजाजत से टेबल कर दूंगा, जिनका नाम लेना

(श्री अभिनेश महर्षि)

सम्भव नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। नर्सिंग भर्ती, पंचायती राज एलडीसी भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, रेडियोग्राफर लैब-टेक्निशियन परिणाम, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, एईएन भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सैकण्ड, एलडीसी भर्ती, रीट, ये सारे के सारे मामले आपके संज्ञान में होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बहुत गहरी नींद में सो गई है, इसको जगाने की आवश्यकता है। एक बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अभी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, सीएचसी बनाएंगे और उसके अंदर विधायक को अधिकार दिया गया है कि वह विधायक एक सीएचसी का, आप सब लोगों को भी सुनने की आवश्यकता है, एक सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाएंगे। हमने पिछले दो बार लगातार मुख्य मंत्री जी को कहा कि छापर के अंदर सीएचसी बनाओ, बड़ा कस्बा है, सीएचसी नहीं बनाई। अब हमको अधिकार मिला है तो मैं यह कहता हूं कि छापर में सीएचसी बनाओ, उसको मॉडल सीएचसी बनाओ और छापर देवाड़ी रोड से जो हाई-वे को जुड़ती है, उस सड़क को बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी, आप आगे बढ़कर उसको करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री मदन प्रजापत।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बिजली की बात रह गयी। घर-घर पानी लेने की बात के अंदर सरकार अपना राज्यांश नहीं दे पा रही है। शिक्षा के अंदर..

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, महामारी कोरोना के बावजूद जो शानदार और जानदार बजट पेश किया है, यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शानदार बजट आयेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने शानदार बजट पेश करके विपक्ष की बोलती बंद कर दी। विपक्ष की बोलती बंद करके माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने यह साबित कर दिया कि 60 इंच का सीना अगर किसी का है तो अशोक गहलोत जी का है।

माननीय सभापति महोदय, शानदार बजट के बावजूद विपक्ष का विरोध, उनकी मजबूरी है, दिल में अलग है, वह जानते हैं कि शानदार घोषणा हुई है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं नम्बर न कट जाएं। नम्बर कटने के डर से ऊपर से मजबूरी में बोल रहे हैं। वास्तव में इनकी मजबूरी भी है। ऐसे शब्द यूज आ रहे हैं, शर्म आ रही है। कोई आंदोलनजीवी बता रहा है, कल माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने घोषणाजीवी कह दिया। ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अगर वह घोषणाजीवी कह रहे हैं, तो मैं उनको भाषणजीवी कह दूं, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आपको भी मैं कह दूं भाषणजीवी। घोषणा है पर धरातल पर कैसे आयेगी, यह पूरी कैसे होगी, यह चिंता जननायक अशोक गहलोत जी को है, आपको नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन जादूगर की जादूगरी समझने में आपको और समय लगेगा। वास्तव में राजस्थान में महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज देश के क्या हालात हैं, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? सात साल पहले 300 रुपये की गैस की टंकी, आज 800-900 रुपये है। आये दिन टंकी ऊपर उठाकर स्मृति ईरानी जी, बहुत महंगी हुई, आज लोग ढूंढ रहे हैं कि वह टंकी और ईरानी जी कहां हैं।

माननीय सभापति महोदय, कच्चे तेल के भाव मनमोहन सिंह जी के टाइम 140 रुपये थे, तेल 60 रुपये था। आज 40, 50 रुपये भाव है और आंकड़ा 100 रुपये के पार हो गया और इनके लोग, चेले चपाटे कह रहे है कि यह तो देश हित में है, यह राष्ट्रवाद के हित में है तो, भाई, 200 रुपये कर दो। आम आदमी है, वह जानता है कि महंगाई क्या है। अभी वक्ता भाई कह रहे थे 20 लाख करोड़ का पैकेज, भई हमने तो फूटी कौड़ी नहीं देखी। ईमान से अगर कोई कह दे, किसी को कोई अगर मिला है, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभिनेश जी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज देश की चिंता नहीं है। उन दो चेलों की चिंता है। हम दो हमारे दो। एक भाई ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल

(श्री मदन प्रजापत)

में किया क्या। एक समझदार बोला, भाई बताना मत, मोदी जी बेच देंगे। किसी को मत बताना। आज बड़ा दु:ख होता है कि चार महीने से किसान सड़कों पर हैं। उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है। सैकड़ों शहीद हो गये। किसानों से मिलने का प्रधान मंत्रीजी को समय नहीं है और अंबानी जी के पोते से मिलने का समय मिल जाता है। जो व्यक्ति आज जन्म लेता है वह प्रधान मंत्री के बेटे और पोते के समान है, एक अंबानी जी के पोते से मिलने जाना और किसानों की सुनवाई नहीं करना, दूसरी तरफ कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। एम.पी. कोटा ही खतम कर दिया +++ क्या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो? हमारे एक सांसद मित्र, मैंने कहा कि आपकी तो मौज है, आप दिल्ली में हो, तो कहने लगे कि भाई, क्या बात करें, दु:खी हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह। एम.पी. कोटा हाथ में नहीं, मिलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, हम तो हाज़िरी लगाते हैं, आना और जाना यह हमारा काम रहा है। भाई, किसी को कहना मत। भाई, तू मेरा मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आज भोजन के पैकेट का विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार अकाल पड़ा, गेहूं से घर भर दिये। आज किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आप कह रहे हो पैरों में छाले पड़ गये। आनन-फानन में लॉकडाउन लगाया, मजदूर सड़कों पर भूखे मरे, पैदल आये, पूरे देश की क्या व्यवस्था थी, रेल भेज कहां रहे हैं और रेल जा कहां रही है, यह मैनेजमेंट इनका सामने आया।

माननीय सभापति महोदय, आज कई बातें हुईं। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी। यही आज देश के हालात हो रहे हैं। बड़ी खुशी कि देश में अगर +++ गौरवशाली, परमभक्त और शिष्य होने का सौभाग्य किसी को मिला, तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी को मिला। बहुत बड़ी खुशी होती है कि परम श्रद्धेय गुरु देव +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आनंद देवाय:, वासु देवाय: ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अपना भी बताओ ...(व्यवधान)... अमीन खां जी ने क्या कहा था ...(व्यवधान) +++

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): चेले नहीं हैं?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): +++ ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक्सपंज कर दो। विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): +++ चेले नहीं हैं। (व्यवधान) किस बात का डर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह एक्सपंज ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। कर दिया, विराजें। (व्यवधान)... बैठ जाओ, एक्सपंज कर दिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह नशा करके आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। इनका नशा तो कम कराओ। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, सरदार पटेल साहब का झूठा गुणगान और वाहवाही लेने वालों की असलियत सामने आ गई। उनका नाम हटाकर खुद के नाम से स्टेडियम। उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बदौलत आज यह भारत देश है। वह नहीं होते तो न कोई आप होते न हम होते। उनका नाम हटना। कभी मौलाना अबुल कलाम साहब का विरोध करना। कल एक भाई कह रहा था चंद्रशेखर जी को गोली नेहरू जी ने धोखा करके, मेहरबानी करके इतना तो झूठ मत बोलो। (व्यवधान) इतना मत बोलो, ऊपर वाला देख रहा है। कौन नेहरू जी थे, कौन पटेल साहब थे, उनके जूतों का मुकाबला अपन नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, आज पटेल साहब का नाम हटाना, मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मायावती जी के बाद में किसी ने जीते जी खुद का नाम लगाने की हिम्मत की है तो मोदी जी ने की है। डाटा और नेट जिसको दिया गया, आप देखते है, आये दिन नेट बंद हो जाता है। (व्यवधान) डाटा दे दिया और नेट बंद हो जाता है। अगर उनके हाथ में आटा दे दिया तो क्या हालात होंगे, गरीब कहां जाएगा?

सभापति महोदय, भाषण और राज बनाना और सरकार चलाने में अंतर है। मैं तारीफ करता हूं, सरकार बनाने में, सरकार तोड़ने में, भाषण देने में माहिर हैं लेकिन सरकार चलाने में माहिर कोई था तो मनमोहन सिंह जी थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस की चिंता विपक्ष को है। यह तो एकता दिखावा है। मेरे नाम राशि वाले बोल रहे थे, स्वर्गीय भैरोंसिंह जी को बार-बार याद कर रहे थे। उसके बाद दस साल मैडम मुख्य मंत्री रहीं, एक बार भी मुंह से नाम नहीं आया। लेकिन आपके नाम लेने और नहीं लेने से, इतनी बड़ी आंख, कई-कई तो डर जाते हैं, जैसे कोई बर्फ डाल दी हो। मैंने कहा, राठौड़ साहब नरम क्यों पड़ते हैं, जब मैडम आती है। आज +++ मैडल अगर किसी को मिलना चाहिए तो यह मदन प्रजापत को नहीं, मदन दिलावर साहब को मिलना चाहिए।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में दस साल महिला सीएम रही, लेकिन अगर महिलाओं की चिंता और पीड़ा किसी ने समझी, सैनेटरी नैपकिन देकर आम महिला, पूरे प्रदेश में, चाहे करोड़ों रुपये का बजट लगे लेकिन हमारी बहन और महिला को तकलीफ नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ आप सरकार में थे, स्कूलें बंद कीं। जब-जब हमारी सरकार आई, जवाहर नवोदय विद्यालय किसकी देन है? कांग्रेस की। मॉडल स्कूल किसकी देन है? गरीब का बेटा, आम आदमी का बेटा, उसके मन में है कि मेरा बेटा भी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। आज हर पांच हजार की आबादी में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जितने भी बड़े संस्थान हैं, वह किस की देन हैं, दुनिया जानती है।

सभापति महोदय, ज्यादा नहीं, दो मिनट में, मुझे टोकना मत, डर लगता है। बजट में इतनी घोषणाएं हैं, इतना शानदार, हर जिला, हर विधान सभा। आज किसानों की बात करें, किसानों का अलग बजट पेश करने की हिम्मत किसी ने की है, अशोक गहलोत जी ने की है। यह साबित कर दिया कि किसान का कोई भला कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम अशोक गहलोत है।

युवाओं के लिये ध्यानचंद स्टेडियम, और यह साबित कर दिया कि युवाओं का हितैषी कोई है, कांग्रेस सरकार है, लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं। बेरोजगारों के लिये 50 लाख भर्तियां, यह साबित कर दिया, बेरोजगारों के साथ में अशोक गहलोतजी हमेशा खड़े रहे।

महिलाओं के लिये हो चाहे गरीब के भोजन के लिये हो, चाहे आम आदमी के फ्लेट खरीदने के लिये, और एक भगवान और धर्म का ठेका लेते हैं, पुजारी, जो मन्दिर में पुजारी है, उसकी तरफ किसी ने देखा है, उनका नाम अशोक गहलोतजी हैं कि उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी, जो मन्दिर में सेवा करते हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज गऊ माता के लिये, गोशाला का बिल और 102, 108 की तर्ज पर, गऊ की पीड़ा कौन जानता है अशोक गहलोतजी से ज्यादा, माननीय सभापति महोदय, कोई नहीं जानता है। तमाम चाहे, एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी, शिक्षा, खेल के अलावा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं कहता हूं। मैंने और भी माध्यम से उठाया और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, पचपदरा क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। और भी जो हैं, समय कम है इसलिये मैं लिखित में दे दूंगा, लेकिन रावणा राजपूत जाति के अन्य शब्द हटाने के लिये मैंने जो निवेदन किया और जोगी, कालबेलिया, नाथ और सपेरा, ये एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, जोगी से ज्यादा गरीब कौन होता है, उनको ओ.बी.सी. में लेना, अपन सभी गहराई से समझें, कि वास्तव में जोगी, कालबेलिया, सपेरा, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। इनको एस.सी. का समान दर्जा मिले। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अंत में, कभी आत्म निर्भर हो, चाहे मन की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे शाइनिंग इंडिया हो, चाहे फीलगुड, दो साल बाद में, ये जो कीलें लगाई हैं, ये कीलें और दीवारें जो खड़ी की हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में किसान दे देंगे। जो नमस्ते ट्रम्प, अगली बार ट्रम्प सरकार, ये इनसे बुरे हालात हो जाएंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलालजी विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार के तीसरे बजट पर आपने डिबेट में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

मुझ से पूर्व वक्ताओं ने अभी तारीफ की कि कृषि का अलग से बजट पेश होगा, इस घोषणा के लिये बहुत धन्यवाद, मैं भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन किसान के लिए, किसान के हित में असली काम किन्होंने किये, उनकी आलोचना और सिर्फ मात्र घोषणा से किसी को शाबाशी, तो यह तुलना, यह संतुलन सही नहीं है। किसान हितैषी फैसले अगर किसी ने, सरकारों ने किये, किसानों की बातें तो सबने कीं, आज किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग भी किसान की हर बार बात करते हैं। नेता भी चुनाव में जाता है तो किसान के हित की बात करता है, स्वामीनाथन कमेटी की बात करता है, उनको लागू करने की बात करता है, लेकिन किसानों के हित में, किसान स्वयं के पैरों पर खड़ा हो, किसान मजबूत हो, किसान को साहूकार के चंगुल से

(श्री बिहारीलाल)

निकालने का भागीरथी प्रयास किसी ने किया तो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर किया।

किसान को यूरिया के लिये लाइन में लगना पड़ता था, पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। नीम कोटेड यूरिया का प्रावधान किसी ने किया, वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया। हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, निरोगी राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी, हमारी धरती जिसमें किसान बीज बोता है, फसल आती है और अन्नदाता अन्न उपजाता है, प्रदेश का और देश का पेट भरता है, उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उस मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किसी ने किया तो सोइल हैल्थ कार्ड देकर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और खराबा, जो 50 प्रतिशत की सीमा थी, उस सीमा को 33 प्रतिशत पर लाने का काम, इकाई जो तहसील मानी जाती थी, इकाई को गांव तक लाये, खेत तक लाये, ओलावृष्टि को इसमें शामिल किया, अतिवृष्टि को इसमें शामिल किया। ऐसे अनेकों क्रान्तिकारी फैसले अगर किसी ने किये तो देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्रियों ने किये।

वर्तमान में जो कांग्रेस के साथी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार और दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, किसान के हित में, देश का 86 प्रतिशत किसान जो छोटी जोत का किसान है, उसके हित में एग्रीकल्चर रिफोर्म्स के नाम से केन्द्र ने तीन बिल पास किये हैं, उन बिलों पर लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी कभी सरकार में थे। वे चाहे केन्द्र की सरकार में थे, चाहे प्रदेशों की सरकार में थे, इन रिफोर्म्स की वे वकालत किया करते थे। APMC एक्ट में संशोधन होना चाहिए, इसकी वकालत वे किया करते थे और किसानों के जितने सुधार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाकर होने चाहिए, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने सिर्फ बात नहीं की, उनको लागू करने का काम किया। डाक्टर स्वामीनाथन की 102 अनुशंसाओं में से एग्रीकल्चर रिफोर्म्स के माध्यम से 101 लागू कर दीं। उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। विरोध करने का जो इनका तरीका है, ये उसी बात का विरोध कर रहे हैं जो ये खुद सत्ता में रहते हुए कहा करते थे। अपने घोषणा पत्र में जिनको ये लेकर आते थे, चुनाव चाहे लोक सभा का लड़ते हों, चाहे प्रदेश की असेम्बली का लड़ते हों, अपने घोषणा पत्र में इन्हीं बातों को लेकर आते थे, ये वकालत करते थे। माननीय

(श्री बिहारीलाल)

सभापतिजी, यह तो वह बात हुई, जब दो टीमें खेलती हैं, और जब हाफ टाइम में, मध्यांतर में जब पाला-बदल हो जाता है तो खिलाड़ी इधर का गोल उधर करता है, उधर का इधर करता है। यह तो राजनीति में भी इसी तरह खेल रहे हैं। राजनीति में जो इनके डायलाग हुआ करते थे, जो बातें हुआ करती थीं उनको भी बदल दिया है। इसलिये इनके चाल, चरित्र, चेहरे को सब पहचान चुके हैं।

किसान हित में कितना काम हुआ, मैं आपको छोटा-सा उदाहरण दे दूं। माननीय सभापतिजी, पूरे राजस्थान के पटवारी हड़ताल पर हैं। मेरे नोखा में 57 पटवार मण्डल हैं, 23 खाली हैं। 147 गांवों में से 62 गांवों की गिरदावरी नहीं हुई है। ये पूरे प्रदेश की समस्या है। 45 हजार गांव गिरदावरी से वंचित रह गये हैं। गिरदावरी से वंचित रहने का मतलब के.सी.सी. का लोन नहीं मिलेगा और पी.एम. सम्मान निधि नहीं मिलेगी। एम.एस.पी. पर फसल बेचने जाएगा तो गिरदावरी की पर्ची साथ चाहिएगी। किसान की चिंता करने वाले ये लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें। पूरे प्रदेश के 45 हजार गांवों में गिरदावरी नहीं हुई है। रबी की फसल और पीछे खरीफ की फसल में भी पटवारियों ने, खराबा हुआ, उसका सही आकलन नहीं किया। प्रदेश के मंत्री को, कलेक्टर को, सबको अवगत कराया गया लेकिन किसान की थोथी चिंता करने वाले लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

नहरी तंत्र में पानी नहीं मिल रहा है। किसान जगह-जगह आंदोलन कर रहा है। चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे आगे द्वितीय फेज का नहरी बैल्ट हो, किसान अपने पानी की चिंता कर रहा है। डिग्गियां, जो किसान का प्राण है, नहरी तंत्र में डिग्गियों का राज्यांश नहीं मिला, केन्द्र का पैसा मिल गया। पिछले दो सालों में तो डिग्गियों का टार्गेट भी नहीं मिला। नई डिग्गियों के निर्माण का कोई अता-पता ही नहीं है, माननीय सभापतिजी।

यह जो बिजली की बात है, बिजली दिन में देंगे, दिन की छोड़िये, रात में भी समय पर पूरी मिल जाए। किसान पर वी.सी.आर. का खतरा, किसान का 50 हजार भी बकाया है तो तुरन्त ट्रांसफार्मर उतार लिया जाएगा। एक महीने का इंतजार भी नहीं किया जाएगा कि उसकी फसल पक जाए और किसान अपनी फसल बेचकर बिजली कम्पनियों का पैसा चुका दे, यह भी इंतजार नहीं किया जाएगा।

(श्री बिहारीलाल)

एम.एस.पी. पर खरीद करने वाले लोग, पंजाब और हरियाणा में किसान को बरगलाने वाले लोग, पंजाब और हरियाणा का एक-एक दाना एम.एस.पी. पर खरीदा जाता है। यू.पी.ए. की सरकार का अंतिम बजट 2013-14 का, आदरणीय मनमोहन सिंहजी का, एम.एस.पी. पर खरीद के लिये प्रावधान कितना, 20 हजार करोड़ का। इस साल का केन्द्र की सरकार का, मोदीजी की सरकार का बजट, एम.एस.पी. पर प्रावधान कितना, एक लाख 23 हजार करोड़ का। कहां 20 हजार करोड़, कहां एक लाख 23 हजार करोड़। इसलिए तुलना कर लीजिए कि कौन किसान हितैषी है।

ग्रामीण विकास की स्थितियां देखिये। ग्रामीण विकास, पंचायती राज नागौर में लागू हुआ। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लागू किया, उनकी वकालत करने वाली सरकार, उनके नाम पर पीठ थपथपाने वाली सरकार, अपने पंचायती राज की स्थिति देखिये। पंचायती राज के चुनावों का क्या हश्र किया? अभी भी 12 जिलों में चुनाव बाकी हैं और पंचायती राज चुनाव के टुकड़े कर दिये। सरपंच अलग, पंचायत समिति डाइरेक्टर का कभी ये कितना तारतम्य हुआ करता था पंचायती राज में, वह सारा तारतम्य तहस-नहस कर दिया। दो साल से फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के पैसे की किस्तें पंचायतों को नहीं मिलीं। केन्द्र ने जो पैसा दिया, उस पैसे को भी पंचायतों में नहीं पहुंचाया। सरपंच भी 8 तारीख से पटवारियों के साथ हड़ताल पर आ रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास को लागू करने की जो की-पोस्ट है, बी.डी.ओ. तो हड़ताल पर हैं, राजस्थान के 200 बी.डी.ओ. हड़ताल पर सरकार से इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रहे हैं, छूट मांग रहे हैं कि उनकी पदोन्नतियों की विसंगतियों को सरकार दूर करे। राजस्थान रुरल डवलपमेंट सर्विस में नियम, कायदे-कानून बनाकर उनके प्रमोशन की व्यवस्था करें तो जब आपकी एजेंसी, आपका बी.डी.ओ. हड़ताल पर, आपका पटवारी हड़ताल पर, ग्रामीण विकास की व्यवस्था से त्रस्त सरपंच हड़ताल पर, तो आप किस बात की वकालत करते हैं, किस किसान के हित की बात करते हैं? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह आपणो राजस्थान है या आपणो हड़तालिस्तान है, इसकी भी कल्पना कर लीजिए।

लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति, अभी यहां पर खाजूवाला से आने वाले मेरे बड़े भाई दलित साथी यह कह रहे थे कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, दलित सिंह नाम रख ले तो उसकी पिटाई हो जाती है, दलित की

(श्री बिहारीलाल)

मूंछ काट दी जाती है लेकिन एन.सी.आर.बी. का रिकार्ड उठाकर देखिए, वह क्या कहता है? दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरे पायदान पर खड़ा है और यह लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करने का जिम्मा किसका है? आपका है, इसलिए अपने खुद के गिरेबान में झांककर देखिए। घोषणाओं का अंबार, अभी मेरे साथी पचपदरा से आने वाले श्री मदन प्रजापतजी कह रहे थे कि यह बी.जे.पी. के विधायक शंका करते हैं, उनके क्षेत्र में घोषणा हुई उनके लिए। कल्लाजी सामने बैठे हैं मैं कल्लाजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे नोखा में मेरी जल की स्कीम को लागू किया, घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद भी दूंगा लेकिन साथ में ही यह मांग भी करूंगा कि यह घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं रहे, अमलीजामा पहने, समय पर पहने।

मेरे अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया, उसका भी धन्यवाद दूंगा लेकिन मेरे शहर में दानदाता गट्टानी परिवार ने एक आयुर्वेद हास्पिटल करोड़ों रुपये लगाकर बनाया है, उसको 'ए' ग्रेड का दर्जा मात्र देना है, वह देने का काम भी करें।

कालेजों की बात आयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा पढ़ते हुए जब चारों स्वर्गीय साथियों के नाम पर कन्या महाविद्यालय की बात की तो, माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी विधायक ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी यह क्या घोषणा कर रहे हैं? मैंने कहा कि कन्या महाविद्यालय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्या महाविद्यालय तो मेरे यहां पर भी चाहिए, तो मैंने कहा कि घोषणाएं हो रही हैं लेकिन घोषणाओं की कीमत बहुत महंगी है। अगर यह धरातल पर लागू हो जाए तो ठीक है लेकिन, शिक्षा मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, मेरे क्षेत्र में भी कन्या महाविद्यालय की जरूरत है, मुझे तो इतनी बड़ी कीमत देने की भी जरूरत नहीं है। मेरे यहां पर तो दानदाता तैयार है पूरा भवन और बिल्डिंग बनाने के लिए क्योंकि अब तक की पिछली दो घोषणाओं में एक भी कालेज की ईंट नहीं लगी अभी तक।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): इसलिए वहां पर दानदाता तैयार है और सरकार कालेज, कन्या कालेज देने की बात करे। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया और बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, तारीख 24 को राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का जो बजट पेश किया, उसका सहर्ष खुशी से मैं समर्थन करता हूं। इस बजट का समर्थन हम इसलिए करते हैं कि मुख्य मंत्री ने कृषकों को, पशुपालकों को, गरीब बच्चों, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और गरीब इंसान, जिनकी पेंशन के बारे में इन्होंने हर जगह राशि बढ़ाई है और किसी को महरूम नहीं छोड़ा है। इससे यह साफ साबित होता है कि मुख्य मंत्री की नीयत साफ और गरीब पर रहम करने का इरादा जाहिर हुआ, इसलिए राजस्थान के मुख्य मंत्री को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

यह पूरा साल कुदरती अपन सभी पर संकट का गुजरा है और इस संकट के दौर में आप और हम सभी लोगों के सहयोग से मुख्य मंत्री ने सतर्कता और ईमानदारी से इस कोरोना की बीमारी के बचाव की खूब कोशिश की, जिससे इस राज्य में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ और इसका प्रमाण आपको भी मानना चाहिए कि देश के प्रधान मंत्री ने भी तारीफ की, इसलिए आप आलोचना के हकदार नहीं रहे क्योंकि देश के प्रधान मंत्री के पास स्टेट्स की जितनी जानकारी होती है उतनी अपने पास नहीं होती है और वह कोई अनजान आदमी नहीं है, उसने यह तारीफ ईमानदारी से की है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि सच्चाई नहीं छुपाई।

इसके साथ में, इन आंकड़ों को बताना, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे की तारीफ करना, इस आदत का मैं नहीं हूं। मैं अपने आप में यह समझता हूं कि हम इस हाउस में जनता की नुमाइंदगी करने के लिए आये हैं और जनता की नुमाइंदगी में इस सदन में और सरकार में उनका ध्यान सच्चाई के तौर पर आकर्षित करने का हमारा कर्तव्य है।

मैं अब यह बी.जे.पी. वालों को कहना चाहता हूं और सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपने पिछले टाइम में पचास बच्चों पर एक मास्टर की पोस्ट का क्राइटेरिया तय किया है, जिससे राजस्थान के पिछड़े इलाकों में हजारों की तादाद में स्कूलें बनीं। मैं यह कहता हूं कि पचास की तादाद पर नहीं, साठ की तादाद पर आप एक मास्टर की पोस्ट रखो तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। देश की, इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी, सरकार कोई भी चलाएगा उनको हिसाब रखना चाहिए।

मैं बाड़मेर जिले का आपको हिसाब बताता हूं। शिव विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका 9057 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसी जिले

(श्री अमीन खां)

का बायतू कांस्टीट्यूएंसी का एरिया है, जो 3957 का है, बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र का 2900 का है, पचपदरा का 2680 का है, सिवाना का 3100 है, गुढ़ामालानी का 3048 है और चौहटन का 3642 है, तो क्या देश की और प्रदेश की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जिस जगह पर पन्द्रह घर की बस्ती है, उस पन्द्रह घर की बस्ती में बीस बच्चे होंगे और उस बस्ती से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर कोई किस्म की प्राइवेट या सरकारी स्कूल नहीं है तो क्या उन गरीबों के बच्चे बीस किलोमीटर पैदल स्कूल में जाकर वापस घर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यह आप और हम सबको ईमानदारी से महसूस करना पड़ेगा। ऐसे एरिया के लिए बीस बच्चों पर भी एक मास्टर की पोस्ट सैंक्शन कर दी जाए तो भी कोई जुर्म नहीं। अनाप-शनाप दुनिया में अपन सब बेकार खर्चों में पैसे गुजार देते हैं, जिनकी कोई फिक्र नहीं है लेकिन गरीब बच्चे, जिनको बीस को एक मास्टर पढ़ाता है, उसको मास्टर की तनख्वाह दे दी जाए तो यह कोई जुर्म नहीं है, न्याय है। अगर मान लीजिए कि ऐसा अपन नहीं करते हैं तो देश में गरीब का जो मूलभूत अधिकार है, वह अपन खतम कर रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनरल सिस्टम तय किया है कि 900 से 1200 तक का वोट होगा, उसमें एक मतदान केन्द्र कायम किया जाएगा लेकिन साथ में यह भी है, उसी भारत निर्वाचन आयोग का सर्कुलर कि किसी भी मतदाता को तीन किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाने देंगे। आज मान लीजिए कि किसी मतदाता केन्द्र से बीस किलोमीटर दूर पच्चीस मतदाता हैं तो वह तो मत नहीं डाल सकते। जब ईमानदारी से चुनाव कमीशन चुनाव करवाता है तो कोई भी पार्टी अपने साधन से उन मतदाताओं को नहीं ला सकती। सरकार अपने खर्चे से उन मतदाताओं को बूथ पर नहीं ला सकती, तो सीधी बात यह है कि उन मतदाताओं को वोट देने का हक अपन खतम करते हैं। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बाड़मेर में एक एस.डी.ओ. शुरू में ईमानदार आया था, उस एस.डी.ओ. को मैंने यह सर्कूलर बताया और चार बूथ ऐसे बताये जिनमें 20, 25 और 30-30 मतदाता थे।

(16.00 बजे)

कलेक्टर ने उस एस.डी.ओ. को कहा तुम पागल हो, कोई 20 वोटों के लिये पोलिंग बूथ बनता है? इसमें 20 कर्मचारी ड्यूटी पर लगते हैं, जितने कर्मचारी

(श्री अमीन खां)

उतने ही मतदाता हैं, यह हो सकता है क्या? एस.डी.ओ. ने सर्कुलर बताया कि मैं इस सर्कुलर के तहत सुझाव लाया हूं, यह आपकी मर्जी पर है तो खारिज कर दो, मर्जी हो तो पास कर दो। अंत में कलेक्टर ने पास किया। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 ऐसे बूथ हैं जिनके 20 से 25 तक वोट हैं और वह पोलिंग स्टेशन हैं तो यह कोई अन्याय थोड़े ही है।

अब मैं बाड़मेर जिले की पापुलेशन के बारे में बताऊंगा। शिव में पापुलेशन है 4 लाख 7 हजार 701, बायतू में पापुलेशन है 3 लाख 39 हजार, बाड़मेर में पापुलेशन है 3 लाख 70 हजार, पचपदरा में 3 लाख 36 हजार, सिवाना में 3 लाख 64 हजार, गुढ़ामालानी में 3 लाख 24 हजार, चौहटन में 4 लाख 22 हजार है। अब आप और हम सब फैसला करते हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच स्कूलें खोल दो बस बराबर हर क्षेत्र में। अब एक क्षेत्र ऐसा है जिसका 9 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें बहुत दूरी पर इंसान बसे हुए हैं और उनकी पापुलेशन जहां अच्छे कालेजों और स्कूलों की सुविधा है, जहां अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, उनसे ज्यादा उनकी पापुलेशन और ज्यादा एरिया और पांच-पांच स्कूलें दे दीं, न्याय कर दिया। यह न्याय नहीं है, गैर-इंसाफ है और एक मारवाड़ी की कहावत है 'अंधी पीसे, कुत्ता खाये'। आप न्याय वहां की पापुलेशन के आधार पर करो और दूरी के आधार पर करो।

दूसरी बात मैं पीने के पानी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसलमेर से मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर जिले को पीने का पानी आता है। सबसे पहले तहसील शिव का बड़ियाला गांव, सैकण्ड राजदाल, गोंघा और शिव में आता है, उसके बाद में बाड़मेर सिटी और बाड़मेर बी.एस.एफ. और आर्मी को भी पानी दिया जाता है लेकिन इस पानी की व्यवस्था पी.एच.ई.डी. ने किस प्रकार की है, जहां इनका हैडवर्क्स नीमला होना चाहिए था, उसका इन्होंने चोखला गांव में जाकर बनाया और वहां पानी का हैडवर्क्स होने से वहां पानी को भी डाइवर्ट कर दिया और शिव तहसील के सिर्फ तीन गांवों को पानी मिलता है और सरकार की तरफ से शिव तहसील के तमाम गांव स्वीकृत हैं परन्तु पानी जाता है सिर्फ तीन-चार गांवों में। यह विभाग की लापरवाही, कमजोरी और अव्यवस्था है। मैं मंत्रीजी को कहता हूं आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। गलती कौन कर रहा है, उसको सज़ा देनी चाहिए।

(श्री अमीन खां)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज से आठ साल पहले नर्मदा प्रोजेक्ट शिफ्ट हुआ, जिसमें 601 का बजट रखा और जिन गांवों में नहर से नजदीक कहीं पानी नहीं मिलता और अंडरग्राउंड जल की कोई सुविधा नहीं है, उस जगह के लिये तहसील चौहटन, रामसर और गडरारोड के लिये किया और उसमें आधे से ज्यादा मेरे ख्याल में पैसे खर्च भी हो गये, लेकिन पानी आज की तारीख में एक भी गांव में नहीं गया। यह विभाग किस प्रकार चलता है? इस पर सभी को विचार करना चाहिए और इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था होना और पैसा मिलने के बाद भी एक भी गांव तक पानी का नहीं जाना, अधिकारी पनिशमेंट के लायक हैं, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए।

इसके साथ मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपसे और हमारी सरकार से और हमारे विपक्षी साथियों से, छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों की भर्ती पर जो पाबन्दी की है, यह जनहित में नहीं है। जलदाय विभाग में फिटर होता है, एक बेलदार होता है, एक लाइनमैन होता है, यह क्लास फोर्थ की नौकरी में आते हैं। इनकी भर्तियां बंद की हैं राज के खजाने की बचत के लिये। बड़े-बड़े अधिकारी जहां लाखों रुपया तनख्वाह उठाते हैं, सरकार का लाखों रुपया व्यय होता है, उसको रोकने से तो बचत नहीं होगी और एक फोर्थ क्लास के आदमी की तनख्वाह रोककर या भर्ती न करके अपन स्टेट की बचत करते हैं, तो अपन सब जनता के गुनहगार हैं और इंसाफ नहीं कर रहे हैं। शासन का असली काम है कमजोर को ऊपर उठाओ। निर्बल को सबल के बराबर लाओ, यह शासन की ड्यूटी है।

अब पुलिस में ही भर्ती होती है। पुराने जमाने में जो सिस्टम था वह अच्छा था। उस कमेटी का चेयरमैन जिले का एस.पी. होता था, एक दो डीवाई.एस.पी. उस कमेटी के मैम्बर होते थे। एम.एल.ए., एम.पी. अपने-अपने आदमियों के लिये सिफारिश करते हैं तो एक-एक आदमी उनके कहने के लिहाज से रखता था, तो यह कौनसा गुनाह करता था? अनफिट आदमी को तो वह सलेक्ट करते नहीं थे। फिजिकली जो फिट आता था, पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना वह होता था। उनमें से किसी का नाम आता तो वह अपना कहना मानते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि उससे लोकल फोर्स भर्ती होती थी। आज बाड़मेर में अलवर, भरतपुर का सिपाही कामयाब नहीं रह सकता, बाड़मेर जैसलमेर का सिपाही कामयाब रह सकता है और स्थानीय लोगों के लिये रोजी का भी बंदोबस्त होता है।

श्री सभापति: माननीय, अब समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): अब इन आधुनिक परीक्षाओं में बड़े-बड़े टैक्नोलोजी के लड़के भर्ती कर देते हैं। वह न तो सिपाही में समझते हैं, न सी.आर.पी.एफ. में समझते हैं, न आई.पी.सी. में समझते हैं, तो यह राष्ट्र और राज्य की हानि है, कोई फायदा नहीं है। ऐसी सारी चीजों पर अपन सबको एक जुबान पर होना चाहिए और यह जनहित का काम है। किसी जाति या किसी पार्टी का सवाल इसमें नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा बोलने की यूं भी मेरी आदत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार भौगोलिक क्षेत्रफल के एरिये पर विकास इकाइयों को भी तय करने में सोचे। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र का 28 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया है और उसमें एक ढाणी से दूसरी ढाणी में 30 किलोमीटर का फासला है। क्या आप वहां 50 बच्चों पर एक मास्टर भेजोगे? हर एम.एल.ए. को कितनी सड़क दी है, 5 करोड़ की। अब जैसलमेर के एम.एल.ए. को, शिव के एम.एल.ए. को 5 करोड़ दोगे तो यह ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। भरतपुर, अलवर में पांच करोड़ रुपये दोगे, तो उस एम.एल.ए. की वाहवाही हो जाएगी। यह न्याय नहीं होकर अन्याय है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दूरी के हिसाब से अमाउंट रखना चाहिए। क्षेत्रफल की दूरी के हिसाब से स्कूलों में बच्चों की संख्या पर मास्टर की पोस्ट तय करनी चाहिए। हमारे जिले में तो मैं सच कहता हूं सारे लोकल मास्टर नेतागीरी करते हैं और यह भरतपुर, सीकर, अलवर, जयपुर, नागौर और झुन्झुनूं के मास्टर हमारे गांवों में लगे हुए रहते थे, इन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया। आपकी सरकार ने आते ही 11 पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में कांग्रेस की सरकार ने जो पाबंदी रखी थी, वह पाबंदी आपने हटा दी। आपके सारे मास्टर वहां से हट गये और अब सारी स्कूलें बंद पड़ी हैं।

सभापति महोदय, आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारा चौहटन और शिव एरिया है, इसमें 85 परसेंट जनसंख्या रिजर्व क्लास की है, ओ.बी.सी. और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की और सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर उस एरिया में सबसे नीचा है और आज की तारीख में आप जांच करा लो, वहां की हर सैकण्डरी स्कूल में न तो अंग्रेजी का मास्टर है, न गणित का मास्टर है, न भूगोल का मास्टर है, न हिन्दी का मास्टर है।

श्री सभापति: धन्यवाद, साहब।

श्री अमीन खां (शिव): और फिर उन पर इल्जाम आयेगा कि आप लोग पढ़ते ही नहीं। पढ़ें क्या, मेन विषय का मास्टर उस स्कूल में नहीं है। मेरे गांव में मॉडल स्कूल है, उसमें दूसरी मॉडल स्कूलों से बच्चे कम थे लेकिन हमारी उस स्कूल का रिजल्ट जिले में सबसे अच्छा आया और उसमें तीन विषयों के टीचर हमेशा नहीं रहे। मैं शिक्षा मंत्री जी से दस बार मिला हूं, यह शिकायत की तो डायरेक्टर, एजुकेशन ने बतौर सजा के एक प्रिंसिपल भेजा। उसने जाकर क्या धंधा किया कि, भाई, यह स्कूल चलेगी नहीं, खतम होने वाली है, बाहर चले जाओ, सौ टीसी काट दी। सौ बच्चों की टीसी काटने का मतलब वो प्रिंसिपल उस मॉडल स्कूल को बंद करना चाहता है। मैं शिक्षा मंत्री के घर गया तो कुछ लोगों ने कहा, साहब, दफ्तर वाले लोगों से टाइम का पूछो। दफ्तर वालों को पूछा, साहब की तबीयत नरम है, दूसरे दिन गया तो भी साहब की तबीयत नरम है। सभापति महोदय, यह देश गरीब है और यह देश गांधीवादी देश है, इन मंत्रियों के पास भी बहुत ज्यादा फर्नीचर, आराम मौज करने का नहीं होना चाहिए, इनको भी सादगी से रहना चाहिए। एक एम.एल.ए. को मंत्री दो दिन मुगालता करता है कि मेरी तबीयत नरम है तो क्या यह मंत्री इस गरीब अवाम को निहाल करेंगे?

श्री सभापति: साहब, अब समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री अमीन खां (शिव): आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पंचायत पुनर्गठन में कुल 31 नई पंचायत बनीं, जिसमें चार ऐसी स्कूलें हैं जो आज प्राइमरी स्कूलों में हैं, कम से कम इन चार को मिडल स्कूल बनाया जाए और सात सैकण्डरी स्कूल हैं, इनको हायर सैकण्डरी कराया जाए, 19 मिडल स्कूल हैं इनको सैकण्डरी किया जाए और एक स्कूल ऐसी है, पंचायत ऐसी है जिसमें पहले से ही हायर सैकण्डरी थी। यही निवेदन करता हुआ सभी को धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह जी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने पन्द्रहवीं विधान सभा में तीसरा बजट पेश किया लेकिन पिछले दो बजट को देखें, उनका विश्लेषण किया जाए तो यह काल्पनिक बजट है। पहले बजट में और दूसरे बजट में जो घोषणाएं करीं उनकी धरातल पर कोई पालना नहीं हो पायी, नीचे काम नहीं हो पाये और कुल जो घोषणाएं हुई उससे 20 से

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)
25 परसेंट काम हो पाये। मेरा तो मुख्य मंत्री जी से कहना है की बजट की घोषणा वो ही करो जो आप क्रियान्वित करवा सको।

अभी जो बजट की घोषणाएं करी हैं, उन्होंने केवल राजस्थान में जो चार उप चुनाव हैं, उसके बारे में घोषणा करी है, चुनावी घोषणा टाइप घोषणा करी है। मेरे को लगता है, पिछले दो बजट काल्पनिक हुए हैं उनका यह बजट भी काल्पनिक होगा।

यह सरकार किसानों के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में चर्चा करती है, किसानों को गुमराह करती है। मैं बिजली की बात करूं, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री जी, आपने जिस प्रकार बिजली के बिल बढ़ाये हैं, जिस प्रकार आपने वी.सी.आर. भरी हैं, वहां जनता तैयार है आप लोगों का स्वागत करने के लिए, बात करने के लिए। आपने घर की वी.सी.आर., सभापति महोदय, हमारे वहां एस.टी. बस्ती है और उनके एक-एक लाख, दो-दो लाख के टापरे नहीं हैं, 20-20, 25-25 हजार की झोपड़ियां हैं, एक-एक, दो-दो लाख की वी.सी.आर. भर दी, सवा लाख की वी.सी.आर. भर दी। इस प्रकार की वी.सी.आर. इन्होंने भरी हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली कटौती, जो यह आठ घंटे की घोषणा करी थी, वह 4 या 5 घंटे भी बिजली नहीं आ पा रही है। किसानों की सब्सिडी खतम कर दी, दरों में वृद्धि कर दी। कृषि कनेक्शन ये 2012-13 के बाद में कोई नये दे नहीं पाये, लोग उससे भी दु:खी हैं। किसान बिजली की चोरी करता है वो कोई कारणवश करता है। इस कारण करता है कि क्योंकि उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है और उसके बच्चे-बच्ची खाने के लिए क्या करें, उसके लिए छोटी-मोटी बिजली की करते हैं पर ये वी.सी.आर. पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा भरी हैं, उससे किसान काफी दुखी हैं।

इन्होंने किसान कर्ज माफी की बात करी, कर्ज माफी तो वसुन्धरा जी ने करी थी और पूरे राजस्थान में 50-50 हजार रुपये माफ किये थे, सभापति महोदय, वो जनता आज भी याद कर रही है पर इन्होंने किसान कर्ज माफी की जो बात करी और किसान का कर्ज माफ किया है, अभी भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कृषि ऋण, एम.टी. लोन इन्होंने माफ किया है, मध्य कालीन ऋण माफ किया है, सरकार की घोषणा के अंतर्गत माफी प्रविष्टियां बैंकों द्वारा एक मार्च, 2020 को पूरी की जा चुकी हैं। लगभग एक वर्ष बीत जाने के उपरांत

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

भी राजस्थान सरकार द्वारा बैंकों को उक्त राशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके अभाव में बैंक द्वारा उन काश्तकारों को न अदेय प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं न उन्हें पुनः नवीन ऋण वितरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के कार्यकाल में 413 पात्र कृषकों को राज्य सरकार की कुल 9 करोड़ 13 लाख ऋण माफी के रूप में प्रदान किये गये हैं। राज्य व अन्य सहकारी बैंकों की उक्त योजना अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मध्यकालीन ऋण 200 करोड़ के आसपास माफ किया है, वो किसान दु:खी हैं, उनको ऋण वापस नहीं मिल पाया, दूसरे बैंकों में नोड्यूज नही मिल रहा है, इस कारण कर्ज माफी नहीं हो पायी है। यह किसानों के बारे में है।

माननीय सभापति महोदय, कर्ज की बात तो सरकार ने चुनावी घोषणा, किसानों को सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात करी थी लेकिन बड़े दु:ख के साथ निवेदन है अपने आपको किसानों की मसीहा कहने वाली यह सरकार बिल्कुल ही प्रयासरत नहीं है और मात्र केन्द्र सरकार पर निर्भर होकर किसानों के चूल्हे पर अपनी रोटियां सेक रही है। प्रदेश में 18 लाख किसान कर्ज माफी की ओर देख रहे हैं लेकिन सिर्फ किसानों को काल्पनिक वादे कर गुमराह करने में व्यस्त हैं। पिछले बजट में सरकार ने किसान कल्याण कोष बनाया और उसकी घोषणा करी पर अभी तक उसका अमल नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी करी, चुनाव में काफी बढ़-चढ़कर उनके पर्चे भी भरे। जब चुनाव चल रहा था तब इन्होंने जगह-जगह टेबल-कुर्सी लगाकर यह कहा कि हम युवा बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने वहां एक भी रुपया नहीं दिया। उसके अलावा एक लाख से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया।

नई स्कूलों में व्याख्याता भर्ती, कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक इन दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, 5 मार्च, 2019 को मुख्य मंत्री द्वारा पंचायत एल.डी.सी. भर्ती, 2013, 10029 पदों पर नियुक्ति का कैलेंडर जारी किया लेकिन अभी तक बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं मिली। पिछले बजट में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

75 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की, जिसमें छह हजार ऊर्जा विभाग की भर्ती की घोषणा की, एक पद भी नहीं निकला। अपनी गलत मानिटरिंग, लापरवाही के कारण लाइब्रेरियन भर्तियां, सभापति महोदय, बेरोजगारों और युवाओं के लिए राजस्थान में भर्तियां, बाहर के राज्यों का कोटा भी समाप्त करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किया है, उस प्रकार राजस्थान में भी करना चाहिए। बाहर से, एम.पी., गुजरात से जो भी आएं उनको यहां नौकरी नहीं मिले। यहां के युवाओं को नौकरी मिले, राजस्थान वासियों को नौकरी मिले, ऐसी मैं मांग करता हूं।

हमारी भाजपा सरकार के कार्यकाल में हमने जो भर्तियां निकाली थीं, उन्हें या तो रद्द कर दी या फिर किसी प्रकार की अड़चन पैदा करके उनको साकार नहीं होने दिया। रेडियोग्राफर, टैक्निशियंस, फार्मासिस्ट, पटवारी भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी। आज पटवारी हड़ताल पर हैं। पूरे राजस्थान में काम बंद है। किसान परेशान हो रहे हैं। अभी गेहूं की तुलाई के लिए, दूसरे कामों के लिए भी वह काफी दुःखी हो रहे हैं। पटवारी की भर्ती भी चालू कराएं। उनकी मांगों की पूर्ति भी करें।

माननीय सभापति महोदय, संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग है लेकिन सरकार नहीं मान रही। महानरेगा में 60 हजार, विद्यार्थी मित्र 24 हजार, पंचायत सहायक 27 हजार, पैराटीचर्स 15 हजार, फार्मेसिस्ट 1500, एनआरएचएम 4500, प्रेरक 17500, जनता जल 10 हजार, 58 हजार आशा सहयोगिनी, 62 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको स्थायी करने की बात थी, उनको भी हम नहीं कर पाये। पटवारियों की जो विसंगति की बात है, उनको दूर करना चाहिए। उस आंदोलन को भी खतम करना चाहिए। पटवारियों के कारण नीचे काफी दिक्कतें आ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य विभाग की बात करूं, सरकार ने यह बात कही थी कि हम 100 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे, लेकिन पिछले एक साल से पोर्टल बंद है, एक भी गरीब आदमी का खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया। लाखों की तादाद में उनके नाम काट दिये गये। नामों को पार्टी पोलिटिक्स करके कि यह कांग्रेस का है, यह बीजेपी का है, इस तरह से करके काटा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करूं, पीडब्ल्यूडी की बात करूं, हमारी भाजपा सरकार में मुख्य मंत्री वसुन्धरा

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जी ने जो घोषणा की थी, उनको भी अटका दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी काफी इस तरह की रोड थीं, उनको भी बंद कर दी। पायलट साहब, उप मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उनको भी अटका दिया। उनको अटकाने की बात तो स्वाभाविक थी कि उप मुख्य मंत्री की घोषणा को कैसे करें, अगर करें तो हम करें। उनको भी डाउटफुल देखा जा रहा है। यह तो इनका आपस का झगड़ा है। हम तो चाहते नहीं हैं। हम तो यह चाहते हैं कि हमारी जो रोड हैं, उनको वापस कर दें।

माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ.टी. फंड की बात करूं, माइनिंग फंड की बात करूं। पिछले दो, ढाई साल से रोड बन गईं, काम हो गया, लेकिन उन ठेकेदारों को अभी तक पैसा नहीं दिया। उनके आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। उनका डी.एम.एफ.टी. फंड भी जारी करवाएं। इस तरह की मेरी मांग है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं 16.13 पर बोलने लगा हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग में भी सरकार ने यह कहा था कि हम नन्दी शाला खोलेंगे, एक भी पंचायत हैडक्वार्टर पर नन्दी शाला नहीं खोली है।

माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा मैं मांग करता हूं कि मेवाड़ में अफीम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, अफीम को तो केन्द्र सरकार तौल लेती है, डोडे, चूरे की दिक्कत है, उसको सरकार तौल नहीं रही है। उससे वहां वास्तव में वातावरण खराब है। मेरी मांग है कि सरकार कोर्ट का आदेश होने के कारण तौल नहीं पा रही है तो सरकार अपने लेवल पर उस डोडे, चूरे को हजार रुपये किलो में तौले और उसको नष्ट करे। कहीं पर भी नष्ट करे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस डोडे, चूरे के कारण किसान परेशान हैं, उनका आजीविका का नुकसान है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 2-3 मांगें हैं। एक तो पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ में काफी डवलपमेंट हो सकता है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें। एक मेडिकल कालेज की घोषणा की और केन्द्र सरकार से 50 परसेंट पैसा भी आया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक रुपया भी चित्तौड़गढ़ मेडिकल कालेज को नहीं दिया है, इसके लिए बजट में घोषणा करें।

चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल, पानी की जो दिक्कत हो रही है, उसको भी करें। डी.एम.एफ.टी. फंड की व्यवस्था करें। यह सरपंचों की जो हड़ताल चल रही है, उनकी 2 साल से एक भी किस्त राजस्थान सरकार ने नहीं डाली है, उस पैसे को भी सरकार डाले। गांवों में जो छोटे-छोटे खर्चे हैं, कहीं मोटर जल रही हैं, छोटे-मोटे कामों के लिए भी दिक्कत हो रही है। वह सरपंच काफी दु:खी हैं, वह धरना दे रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। उसका भी ध्यान रखें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): बीडीओ का धरना हो रहा है। पटवारियों का धरना हो रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक सैकण्ड। मेरे यहां भदेसर में उपखंड है, वहां आप कालेज भी खोलें। मेरे वहां रोड्स की काफी दिक्कतें हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरह की रोड्स दी हैं। पहले भी बस्सी, कनेरा जो रोड थी, उसकी पालना भी नहीं हुई है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री खिलाड़ी लाल जी बैरवा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, नई रोड भी दें और नई घोषणा भी करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजें। विराजें। श्री खिलाड़ी लाल जी बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, बजट

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

भाषण 2021-22 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट पर बहस चल रही है। इससे पूर्व जब बजट पेश हो रहा था, जब बजट पूर्ण नहीं हुआ, तभी कोरोना का संदेश आ गया। पूरा एक साल हो गया। कोरोना का जो रूप है, वह हमने सभी ने देखा है। कोरोना का जो प्रबंधन था, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने जितनी भी विषम परिस्थिति थीं, उसमें तय किया कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोयेगा। उसके तहत सरकार ने, भामाशाहों ने, हमारे एमएलएज ने, एमपीज ने और जितने भी लोग थे, सबने सहयोग किया। इस साल को निकालते हुए यहां तक बढ़े हैं।

मेरे विपक्ष के साथी बजट की आलोचना करते हैं। उन्हें करना भी चाहिए, उनका धर्म भी है लेकिन जो बातें सत्य होती हैं वह छिपती नहीं हैं। अभी कई साथियों ने, जिनमें हमारे विपक्ष के कई बड़े नेता हैं, उन्होंने यह कहा कि यह बजट तो मध्यावधि चुनाव की ओर संकेत देता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना तो समझा। जब चुनाव होते हैं तब सियासी पार्टियां बजट कुछ अच्छा पेश करती हैं लेकिन यह ऐसा बजट नहीं था कि यह चुनाव का बजट हो, लेकिन यह बजट को इस तरह से बता रहे हैं। उनके मन में जो मंशा है, मध्यावधि चुनाव की जो बात करते हैं, यह मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। यह सरकार पूरे 5 साल बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से चलेगी। बजट का अच्छा होना यह संकेत नहीं देता है कि मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो अच्छा बजट दिया है वह यह संकेत दे रहा है कि उन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए, चाहे शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 5 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया।

माननीय सभापति महोदय, चाहे सहरिया समाज हो, दूसरा समाज हो, जनजाति के लोग हों, निःशक्तजन हों, उनको 100 दिन के बजाय 200 दिन रोजगार के दिवस मुख्य मंत्री जी ने किये हैं।

मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोई भी जिला ऐसा नहीं छोड़ा है जहां मेडिकल कालेज नहीं हैं। 25 जिला मुख्यालयों पर

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

नर्सिंग कालेज खोले गये। उसमें हमारा धौलपुर भी शामिल है। उसके लिए तो मैं और भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि नर्सिंग कालेज खुलने से हमारे पूरे जिले को फायदा होगा। 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात मुख्य मंत्री जी ने की है। अभी यह तय होगा कि वह कहां-कहां खुलेंगे। मेरे इलाके में भी एक की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि महु गुलावली में भी अगर स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 58 ब्लाक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक औषधालय खोलने की बात कही है। एक जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं इंगित करना चाहता हूं। पहले कभी एक्सीडेंट होता था तो आदमी निकल जाता था। वह देखता था कि पता नहीं क्यों लफड़े में पड़ें, हाथ तक नहीं लगाते थे। अगर उनके मन में मानवता भी जागती थी तो वह कहते थे कि पता नहीं जाएंगे तो पुलिस, थाना हो जाएगा और अननैसेसरी चार चक्कर लगाने पड़ेंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए यह बात कही कि कोई भी घायल व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को हास्पिटल पहुंचाएगा, उसको 5 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। इससे एक मानवता जाग्रत होगी। कोई भी व्यक्ति मदद करना चाहता है, वह कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगा। जितनी भी परेशानी और तकलीफें थीं, थाने की और बाकी की जो फार्मेलिटी थी, उनको खतम करके यह जो तय किया है, यह बहुत बड़ी बात है।

(16.30 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5 हजार से अधिक आबादी के हमारे समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले दो वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1,200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हम यह जानते हैं, यह चर्चा थी बाजार में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन जिस तरह से ये स्कूल खोलने की बात कही है, वह निश्चित रूप से उनको एक साहस मिलेगा और गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई होगी तो एक गरीब का बच्चा, एससी, एसटी का बच्चा भी उसमें पढ़ सकता है।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, कृषि महाविद्यालय की बात हुई। विज्ञान के 600 विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इसी सदन में पिछले बजट में मेरे बसेड़ी के खेमरी में कृषि विद्यालय खोला था। कृषि विद्यालय खोलने के बाद में मात्र दो महीने में उसको चालू कर दिया गया, 60 बच्चों का एडमिशन हुआ और आज वहां लगातार दूसरी बार 60 बच्चे और आ गये और 120 बच्चे उसी कृषि विद्यालय जो खेमरी, बसेड़ी में खोला है, उसमें लगातार अध्ययनरत हैं। मेरे साथी जो चार्ज लगाते हैं और इस तरह का लगाते हैं कि जो घोषणाएं हुई थीं, उनको कुछ भी अमलीजामा नहीं पहनाया गया। हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो। कोरोना काल की वजह से ऐसी परिस्थितियां रह गई हों लेकिन सरकार की मंशा में खोट नहीं है, सरकार काम करना चाहती है, हर वह काम करना चाहती है जो आपको बताया गया है, इसमें पीछे रहने की बात नहीं है। परिस्थितियां थीं, कोरोना काल था, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं थी, इस तरह से व्यवस्थाएं की गईं वे अछूती नहीं हैं हमसे, इसके बावजूद भी पूरे तंत्र को पूरे साल खींचकर ले जाना और ले जाने के बाद लगातार काम करना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि वही स्कूल जो पिछले बजट में घोषित हुई थी, कृषि विद्यालय की घोषणा हुई थी, आज उस स्कूल में 120 बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बजट में केवल घोषणाएं की जाती हैं।

विपक्ष का काम है, साथी चार्ज लगाते हैं, आलोचना करनी भी चाहिए, टोकना एक अच्छी बात है लेकिन जहां अच्छी और सच्ची बात हो, उसको यस भी करना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए क्योंकि इस सदन में जब हम आते हैं तो सब लोग देख रहे हैं, पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है। अगर यही बात हम कहते रहेंगे कि मैं केवल अच्छी बात कहूं और आप केवल बुरी बात ही करते रहेंगे तो लोगों को आदत हो जाएगी कि दो पक्ष हो गये, एक इधर वाला हो गया, एक उधर वाला हो गया, इन लोगों के आपस में यही तर्क-वितर्क होते हैं। अगर कहीं अच्छी बात होती है और उसका कोई सपोर्ट होता है तो निश्चित रूप से उसकी बात आगे तक जाती है। यह तय किया जाता है कि विधान सभा में ऐसा ही नहीं है कि वहां पर लोग बिलकुल ही एक साइड के हैं कि एक पक्ष को हां करना है दूसरे को न करना है। जब बहस हो, बहस किसी भी

मुद्दे पर हो, बहस में यह बात रखना कि सत्य क्या है, वह हमारा धर्म होना चाहिए, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी तो एक मिनट हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि नया विद्यालय खुला, कोरोना की मार थी, कुछ बजट आया, कुछ नहीं आया, लेकिन वहां पर बिल्डिंग नहीं बन पाई है। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि विद्यालय की बिल्डिंग के लिए बजट हो जाए तो अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़ी, जिला धौलपुर में सरकार ने राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, जिनके पास पैसे की बहुत कमी होती है और बार-बार उनको परीक्षा देने जाना पड़ता है, उनके लिए राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा का जो प्रावधान किया है, वह बहुत ही साधुवाद का विषय है बहुत ही अच्छी बात है। मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने बीच में टोककर मेरा फ्लो खराब कर दिया। मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दो मिनट और दे दीजिए। दो वर्षों में 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है, यह सरकार की बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी मंशा की बात है। विरोध होते रहते हैं, तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी भर्तियां हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह कृषि और पशुपालन में जो ब्याज मुक्त फसली ऋण 16 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित करने की जो बात की है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले से सम्बन्धित सब्जेक्ट है, जिसमें फूड पार्क खोलने की बात आई है। मेरे बसेड़ी में बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। जिले में एक-एक फूड पार्क खोलने की बात आती है, अगर मेरे बसेड़ी का इसके लिए चयन होता है तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और जिले में अच्छा संदेश जाएगा।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार हमारी थी तो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का चयन हुआ था। जनता के आशीर्वाद से मैं एमपी था तो उसका मैंने उद्घाटन किया था। आज उसी में सरकार ने जो एक हजार किसान सेवा केन्द्रों को खोलने का काम किया है, उससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, बात किसानों की आ रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए जो अलग से बजट लाने की बात की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत ही साधुवाद देता हूं यह उनकी अच्छी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार तीन काले कानून लेकर आई है जिसके लिए पूरा देश जल रहा है, पूरा किसान जल रहा है, क्योंकि यहां इस राजस्थान ने 25 एमपी दिये हैं केन्द्र को, वो लोग उनकी व्यथा सुनें और इन काले कानूनों को वापस लें तो बहुत बढ़िया होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 2021-22 के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसमें प्रदेश में होने वाले विधान सभा उप चुनावों की छाया दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनावी बजट पेश किया है, घोषणओं का अंबार लगा दिया लेकिन ये घोषणाएं धरातल पर कितनी उतरेंगी, ये प्रदेश की जनता जानती है क्योंकि दो साल में केवल घोषणाएं ही हो रही हैं। पिछले दो वर्षों के बजट देखे जाएं तो उनमें से अब तक केवल 30 प्रतिशत घोषणाएं ही धरातल पर उतरी हैं, बाकी 70 प्रतिशत धरातल पर नहीं आई हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम पुरानी योजनाओं को बंद करने का धंधा नहीं करते हैं लेकिन आप ऐसा ही करते हो। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने 60 इंच का सीना होने पर भी हमारी सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई सबसे अच्छी भामाशाह योजना को क्यों बंद कर दिया? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को क्यों बंद कर दिया? स्कूली बच्चों को भरपूर पोषण देने के लिए चलाई गई मुफ्त दूध योजना को क्यों बंद कर दिया? अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही

(श्री हमीर सिंह भायल)

थी, उसको बंद करके नए नाम से शुरू करने की क्या जरूरत थी? क्यों मां अन्नपूर्णा के नाम से आपको चिढ़ थी? जल स्वावलम्बन योजना को बंद कर दिया। आपने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बंद कर दी। ग्रामीण गौरव पथ का नाम बदलकर बंद कर दिया। प्रशासन शहरों के संग जो राजस्व शिविर चल रहे थे, उनको क्यों बंद कर दिया? किसानों के हितैषी बनते हो, हमारी सरकार ने किसानों के बिल में 10 हजार रुपये की सब्सिडी देना शुरू किया था, उसको क्यों बंद कर दिया? इस बजट में आपने किसानों के एक बार सम्पूर्ण कर्ज माफी की स्टाइल में भरमाने का काम किया था, अलग से कृषि बजट, 16 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज वगैरह, वगैरह। अभी चल रहे किसान आंदोलन की आंच में आप अपनी रोटियां सेंकना चाहते हो पर राजस्थान का किसान आपको अच्छी तरह से जानता है कि आपने किसानों के लिए किया क्या है, दोबारा आपके झांसे में आने वाला नहीं है।

किसान, महिला, युवा, गरीब, दलित, वंचित और शोषित के लिए अगर किसी में सोच है तो वह हैं नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने न केवल आपकी बल्कि पूरे विपक्ष की भी सोच बदली है, आपकी राजनीति बदल दी। 6 साल में मोदी सरकार ने ऐसी-ऐसी योजनाएं शुरू कीं जो आम आदमी को सीधा टच करती हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, स्वस्थ भारत अभियान हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाते हो, हर घर को बिजली कनेक्शन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना हो, हर घर को नल से जोड़ना, और भी ऐसी कई योजनाएं जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के एक भी मंत्री पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जबकि आपके राज में टूजी, थ्रीजी, कोलगेट आदि न जाने कितने घोटाले हुए। आपको केवल एक ही परिवार की भक्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में मोदी जी का नाम लेने पर रात को भी आपको नींद नहीं आती। किसानों की आप चिंता कर रहे हैं पर किसानों का अगर किसी ने भला किया है तो पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। फसल बीमा योजना से लेकर, क्रेडिट कार्ड से लेकर आज दिन तक किसानों का किसी ने भला किया है तो इन्होंने किया है। आपको ध्यान होगा 2013 से 2018 के

(श्री हमीर सिंह भायल)

बीच में एक बार अतिवृष्टि हुई थी, उस समय राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने फसल बीमा योजना के तहत जो 50 परसेंट से ज्यादा खराबे पर मिलता था, तीन तरह की कैटेगरी बनाकर भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी ने गये पांच सालों में किसानों की जेब में पैसा दिया, चाहे अनुदान के रूप में हो, चाहे फसल बीमा योजना के रूप में हो। किसानों के लिए कर्ज माफी की आपने घोषणा करके यह हालत कर दी कि कर्ज माफी तो अलग रही, जिसे एक लाख रुपये सोसाइटी से मिल रहा था, किसी जगह 15 हजार, किसी जगह 10 हजार, यह स्थिति कर ली कि सहकार राजस्थान के किसान के लिए एक वरदान था, उसे राजस्थान से समाप्त करने का कार्य आपने किसानों के लिए जरूर किया है।

ऊर्जा विभाग में मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं कि चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, उसे बढ़ाने का कार्य जरूर किया है। ऊर्जा मंत्री जी विराज रहे हैं। आज यह स्थिति बन गयी है कि तार ढीले हों, वह ठीक है परंतु बिजली समय पर नहीं देना और इसके अलावा पीने के पानी के लिए जहां मैंने आपको सुबह 295 में बताया था कि बिलों की भरमार आ रही है और आपने पेयजल के लिए तो अति कर दी है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद तो करें।

श्री सभापति: बीच में नहीं बोलें आप।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अबार देऊं, साब। मैं निवेदन करूंगा, पेयजल के लिए आपने बजट का प्रावधान 580 करोड़ का किया है। 2003 में योजना बनी, 2017 में पानी पहुंचना था, 2018 तक एक साल बढ़ा दी, पर इसका मैंने आकलन करके आपके चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर से बात की। यह तो आपने सिर्फ इसका प्रावधान किया है पर 12 किलोमीटर लाइन नहीं आयेगी तो इसका उपयोग कहां होगा? आज की सर्दी में पीने के लिए पानी नहीं है, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

मेरे सिवाना को अधिकारी विहीन कर दिया। एक भी अधिकारी नहीं है। तीन पंचायत समिति, तीन तहसील, दो उप-खण्ड, एक जेईएन पीएचईडी का नहीं है, एक एईएन है जो डेपुटेशन पर लगा हुआ है। यह काम कैसे चलेगा? माननीय मंत्री जी, इस पर आप थोड़ा विचार करें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि चिकित्सा विभाग में मुझे दो पीएचसी दिये। मैं धन्यवाद करूंगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। बालोतरा को बड़ा हास्पिटल देने का भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन भी करूंगा, गये 2013 से 2018 के बीच में तीन पीएचसी मुख्य मंत्री जी ने दिये थे। दो-दो करोड़ का बजट भी साथ में दिया। भवन बनकर तैयार हो गये हैं तो मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनके लिए बजट भी दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): शिक्षा विभाग में, सिवाना में एक कालेज बनी। 6 करोड़ का बजट मिला। अभी आपने दो कालेज दे दिये, पर 2018 में सिणधरी में आईटीआई बनी पंद्रह करोड़ की लागत से, मंत्री जी से निवेदन करने के बाद भी आज दिन तक वह चालू नहीं हुई है। उसका भवन जर्जर होता जा रहा है और आपने समदड़ी में और आईटीआई दे दी है, पर भवन कहां से निर्मित करेंगे? बजट का प्रावधान इसमें नहीं किया है। जब तक बजट नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं होगा।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): हुकम।

श्री सभापति: सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): एक निवेदन और करूंगा। हमारे बाड़मेर के विधायक मेवाराम जी ने नंदी गौशाला खोली थी, उसका उद्घाटन मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी ने किया था और इन्होंने प्रश्न लगाया है प्रश्न संख्या 176...

श्री सभापति: विराजें। इनका अंकित नहीं होगा। विराजें। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 24 फरवरी, 2021 को जो बजट प्रस्तुत किया है वह एक जादूगर के रूप में किया है। जादूगर का जब हम खेल देखते हैं तो होता कुछ और है और हकीकत कुछ और होती है। वही जादूगर है जो वास्तव में जो दिखाता है, वह होता नहीं। वास्तव में बड़ी चतुराई से पिछले दो बजटों में जिस प्रकार से घोषणाएं हुईं, यह तीसरा बजट है। पहले बजट की जो घोषणाएं थीं, वे भी अभी जमीन पर नहीं हैं। पिछले बजट में मेरे यहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है, मैं जहां तक समझता हूं अभी तक सरकार का उस पर कोई विचार है नहीं।

अभी वर्तमान में दो घोषणाएं हुईं। सिंचाई विभाग की कालीसिंध पर एक एनिकट बनाने की। जब मैं पिछली बार भी एमएलए था, तत्कालीन मंत्री श्री रामप्रताप जी ने भी घोषणा की थी कि हम कालीसिंध पर राजपुरा के पास में छह-साढ़े छह करोड़ का एनिकट बनाएंगे, वही घोषणा अब कालीसिंध पर पुलिया के पास उसकी जगह बढ़ाकर कर दी गयी। सभापति महोदय, एक रोड की घोषणा हुई, वह उस समय भी घोषणा थी, उसके टेण्डर वगैरह सब हो गये थे, वह दो साल से हो नहीं रही थी, फिर उसकी घोषणा हो गयी। जो हो रहा है, वह पिछली घोषणा है, वास्तव में अभी तक भी वह काम जमीन पर नहीं है। कुछ घोषणा पिछली सरकार ने की थी, वर्क आर्डर हो गया, टेण्डर हो गया, काम चल गया। जो रोड बनना था, वहां मिट्टी हो गयी, ग्रेवल हो गया, उसके बाद में अभी वैसी की वैसी स्थिति पड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ रोड्स बता रहा हूं जो वास्तव में सवा दो साल से पिछली सरकार की घोषणाओं के समय से वैसी की वैसी पड़ी हैं। पहले तो फिर भी अच्छी तरह से उन पर आना-जाना होता था, रोड अच्छा था, कम से कम डब्ल्यूबीएम था पर उसके बाद मिट्टी डाल दी। बरसात में तो वहां से निकलने में ही बड़ी परेशानी आने लग गयी। कुछ रोड्स हैं, मैं बताना चाह रहा हूं- राजपुरा-रिछवा पंचायत, गणेशपुरा-आगरा पंचायत,

(श्री नरेन्द्र नागर)

गोपालपुरा-रझोन पंचायत, पाटल्या कुल्मी खुद पंचायत हैडक्वार्टर है, खेड़ली हरिपुरा-गुराड़खेड़ा पंचायत। रटलाई से बालदा रोड अधूरा पड़ा है। खानपुर में जो पुलियाएं बननी चाहिए थीं रोड के साथ, रोड बन गये पर पुलियाएं अभी भी अधूरी हैं। उसके अलावा करनवास से मालनवासा का रोड अधूरा है। पीपल्दा से राजपुरा अधूरा पड़ा है। बिसनखेड़ी में अधूरा पड़ा है। इसमें गौरव पथ भी हैं तीन-चार।

सभापति महोदय, गौरव पथ की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने घोषणा की थी, पर जो उनकी घोषणा थी, उसमें उन्होंने जो कार्ययोजना बनायी थी कि पांच साल में हम गौरव पथ बनाएंगे और पांच साल में पूरी पंचायत विधान सभा क्षेत्र में जितनी पंचायतें आती हैं, उन्हें पांच भागों में डिवाइड करके हर साल लगभग 12-15 गौरव पथ देने का काम हर साल किया था, पर मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पिछली बार बजट भाषण में विकास पथ की घोषणा की थी, मैं मान रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक एक विकास पथ बना है, उस विकास पथ का पैसा अभी तक भी उस ठेकेदार को नहीं मिला है। दो विकास पथ की स्वीकृति के लिए अभी और अधिकारियों ने कहा है, आगे क्या पता क्या होगा, पर जो घोषणा सरकार की है, क्योंकि आपका आधा कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, यदि एक गौरव पथ बना है तो आगे ढाई साल में ज्यादा से ज्यादा एक और बना देंगे, तो ऐसी क्या घोषणा है कि नाम बदलकर उसको आपने करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार का दुर्भाग्य है यह।

बिजली के क्षेत्र में मैं जमीनी हकीकत बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आप विराज रहे हैं। पिछली सरकार ने घोषणा की कि 10 हजार रुपये तक का 833 रुपया उसका आयेगा, सरकार ने देने का काम किया, आपने कहा, यह जाते-जाते घोषणा हुई थी। आपने 6-8 महीने दिये, उसके बाद बंद कर दी। फिर मुख्य मंत्री जी ने इसे 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया। 12 हजार में उन्होंने उसमें एक राइडर डाला कि जिनका मीटर चालू होगा, हम उन्हीं उपभोक्ताओं को लाभ देंगे। मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता मीटर इस प्रकार के आज-कल आते हैं कि किसान ट्रांसफार्मर ले गया, लेते ही उसकी ओसीबी भी इतनी कमजोर होती है, वह ओसीबी जल जाती है, उसका मीटर भी जल जाता है। फिर आप उसमें राइडर डालेंगे कि इसका तो मीटर चालू नहीं था, इसलिए इसको उसकी रियायत नहीं दी जाएगी।

(श्री नरेन्द्र नागर)

एक दूसरा यह डाला कि किसान के खाते में आप पैसा दोगे। अभी मेरे दादा, परदादा के नाम से बिल आ रहे हैं, एक मेरे पांच-पांच भाई हैं, उनके नाम से सामूहिक बिल आ रहे हैं तो अब उनके पांच में से किसके खाते में डालोगे? इसमें ही आप उलझे रहोगे या फिर आप लड़ाने का काम करोगे? वे पांचों भाई लड़ेंगे कि किसके खाते में आये, किसके में नहीं आये। जमीन के हिसाब से इंतकाल खुलता है, ऐसा आपके यहां पर कोई इंतकाल तो खुलता ही नहीं कि उसका खुल गया। एक पिताजी के पांच बेटे हैं, पांच का खुल गया, फिर पांच में भी उस एक हजार को पांच भागों में 200-200 रुपये करके डालोगे, तो इसमें कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि इसमें आप कोई नई तकनीक निकालो। मैं तो समझता हूं कि जिसका भी है, जो जमा कराता है उसमें आप एक हजार रुपये की छूट दे दो ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी और आम उपभोक्ता को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी।

साथ ही, मंत्री महोदय, इस बार तो फिर भी ठीक है पर पिछले साल का आपको भी जानकारी में है कि वास्तव में ट्रांसफार्मर एक-एक महीने तक नहीं मिले। इस बार व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा में ठीक है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 4-5 दिन में जरूर मिले हैं पर पिछले साल बहुत दिक्कत आई थी और एक-एक महीने तक ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं मिले थे। जो पिछली वसुन्धरा जी की सरकार थी उसमें 80 हजार करोड़ का बिजली का घाटा चुकाया था।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): उसके बाद में फिर वापस वही हो गया। मंत्री जी, जो अधिकारी लगे हुए हैं, वे सिर्फ और सिर्फ वीसीआर भरने में लगे हुए हैं और उनका टार्गेट पर ध्यान है। मंत्री महोदय, वीसीआर की स्थिति यह है कि किसी के घर में न फ्रिज है, न टीवी है, न कुछ है, उसके बाद भी उनका फ्रिज, टीवी, सबका वीसीआर भर दिया जबकि उसके घर में देखो तो उसके घर में ये हैं ही नहीं। वह उपभोक्ता हमारे पास आता है कि मेरे घर में यदि फ्रिज, टीवी हो तो, एमएलए साहब, आप कहो जैसे तैयार हूं पर वीसीआर 40 हजार की भरी और हम कहते हैं तो कहते हैं कि चलो, आपके कहने से इसको 20 हजार कर देते हैं, पर उसके तो 20 हजार की भी वीसीआर नहीं बनती है, उसके बाद भी इनकी वीसीआर भर देते हैं। मैं जल्दी ही इनको निपटाता हूं क्योंकि आपने कह दिया।

(श्री नरेन्द्र नागर)

सिंचाई के लिए परवन डैम पर एनिकट के लिए आपने लगभग 885 करोड़ का बजट दिया है, तो इतना तो पहले से बकाया है और अभी तो बहुत से लोगों को पुराना जमीन का मुआवजा देना है, तो यह योजना आगे कैसे बढ़ेगी और जो 2023 में पूरी होनी है वह पूरी नहीं हो पाएगी। परवन में हर घर नल योजना के माध्यम से आप डीपीआर बना रहे हो। पिछली बार भी मैंने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दिया था कि अभी तो इसकी डीपीआर बना रहे हैं, जबकि पिछली सरकार में 267 सैंक्शन कर दिये थे। अब मैं चाह रहा हूं कि उसकी तुरन्त डीपीआर बने ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिले। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट 2021-22 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, 24 तारीख को प्रदेश के मुख्य मंत्री जननायक माननीय अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया उसमें चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों चाहे दूसरे हों, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इस कोरोना की एक वर्ष की महामारी के बावजूद ऐसा शानदार और क्रांतिकारी बजट आयेगा। लेकिन ऐसा बजट आया, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री के पूरे जेहन में था कि प्रदेश के सभी वर्ग इस महामारी की वजह से परेशान हैं इसलिए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक शानदार और जानदार बजट प्रदेश को दिया और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं।

यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों को नई दिशा देगा और नई दिशा ही नहीं देगा, बल्कि एक आधारभूत और ढांचागत विकास इस प्रदेश का होगा। कोरोना की व्यवस्था का सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा और शानदार व्यवस्था राजस्थान की रही। इस व्यवस्था के बाद प्रदेश का तीसरा शानदार बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया। उसमें विशेषकर मैं आपका ध्यान चिकित्सा की तरफ दिलाना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक शानदार व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी की पहले भी रही है, चाहे वह नि:शुल्क दवा हो, नि:शुल्क जांच हो...

श्री सभापति: कृपया शांति रखें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): इस कोरोना की हो। इस प्रदेश के

(श्री किसनाराम विश्नोई)

अन्दर मेडिकल कालेज खोलने की बात हो, जगह-जगह पीएचसी और सीएचसी खोलने की बात हो, हैल्थ के सैक्टर में हमेशा माननीय मुख्य मंत्री के मरीजों, गरीबों के प्रति दयालु भाव रहे हैं और इनकी विशेष व्यवस्था इन्होंने की है। जैसे इन्होंने इस बजट में नये कालेज भी खोले हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू की है, निरोगी राजस्थान का ऐलान किया है, नये मेडिकल कालेज खोले हैं।

इसके साथ-साथ जो ऐतिहासिक घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है कि पहले रोड पर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो घायल को उठाने के लिए हर आदमी के मन में एक भय सा होता था कि पता नहीं कैसे दुर्घटना घटी है, इसको कैसे हास्पिटल ले जाएं, अपने खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो जाए। उस भय को मिटाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को 5 हजार रुपये की इनामी राशि देने की घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही साथ, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की हैं।

इसके अलावा कृषि बजट भी अलग से लाने की घोषणा की है। देश में पहले रेल बजट अलग हुआ करता था पर भारत सरकार ने तो रेल बजट को मर्ज किया है और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की, पार्टी की और हमारे नेताओं की सोच किसान के प्रति रहती है और किसान के प्रति हमारी हमदर्दी रहती है। प्रतिपक्ष के साथी अभी कह रहे थे पर किसानों के बारे में चाहे ऋण माफी की योजना हो, उसमें 72 हजार करोड़ की ऋण माफी की है, उसका रिकार्ड आज तक के इतिहास में कोई तोड़ नहीं पाया है। आप किसी एक्सपर्ट से आपकी और हमारी योजनाओं का मिलान कर लीजिये और उसमें हमारी आपसे दुगुनी नहीं हो जाए तब आप हमारे से बात करना। आपको उद्योगपतियों की बात करने की चिंता रहती है और किसानों के प्रति आपकी चिंता न कभी रही है और न कभी रहेगी। इसलिए यह ऐतिहासिक घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है कि अगले वर्ष से अलग से कृषि बजट पेश करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि विद्युत वितरण कम्पनी की अलग से करने की घोषणा की है ताकि किसानों को ढंग से बिजली की आपूर्ति हो सके, उनकी बिजली की समस्याओं को ढंग से दुरुस्त किया जा सके। यह भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में पशुपालन भी बहुत होता है और बहुत पशुपालक प्रदेश में रहते हैं, तो इनके लिए 102 वेटरिनरी मोबाइल वैन की घोषणा की है। ये लोग गायों की बात करते हैं और पिछली बार प्रत्येक ब्लाक में नन्दी गौशाला खोलने की घोषणा की, जिसके लिए बजट का माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ 102 डायल करने से वेटरिनरी मोबाइल वैन आ जाती है, चाहे वह गौशाला में जरूरत हो चाहे दूसरी जगह उसकी जरूरत हो, इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसके साथ ही दूसरे अस्पतालों में, मनुष्यों के अस्पतालों में होती है उसी प्रकार से पशु चिकित्सालयों में भी राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी बनाने की घोषणा की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के जेहन में है, उनके ध्यान में है कि आज पूरे प्रदेश में, गांव में, ढाणियों में कम पढ़े-लिखे बच्चे नशे की चपेट में, नाना प्रकार के व्यसन की चपेट में आ जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए, ज्ञान देने के लिए और बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए नेहरू बाल संरक्षण योजना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की ताकि बच्चों में इस नशे की प्रवृत्ति को छुड़ाया जाए, व्यसन करने की आदत को छुड़ाया जाए। इस तरह के बड़े-बड़े फैसले माननीय मुख्य मंत्री जी ने किये हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि महानरेगा में भी गरीब मजदूरों, विकलांगों को मजदूरी देने के लिए जो 100 दिन का रोजगार मिलता था उसको 200 दिन का रोजगार देने का किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में पैसे वाले लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते थे और एक गरीब आदमी का सपना होता था कि आज मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी मेरे बच्चे को, पोते को अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा दे सकूं...

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मैं मेरे क्षेत्र पर ही आ रहा हूं। साथ ही साथ पेयजल की जो बात थी, पेयजल की मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने मेरी पीलवा-सदरी-जम्भेश्वर नगर योजना की डीपीआर की घोषणा की थी। बेड़लाई पार्ट सैकण्ड के डीपीआर की घोषणा की थी, अवमोरई योजना की घोषणा की थी और सेतरवा-देचू योजना की घोषणा की थी, जिसकी इस बजट

(श्री किसनाराम विश्नोई)
में वित्तीय स्वीकृति जारी कर काम शुरू करने की घोषणा की है जिससे मेरे

(17.00 बजे)

विधान सभा क्षेत्र की करीब 85 पंचायतों की गांव-ढाणियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि मुख्य मंत्री जी को यह ध्यान है कि मारवाड़ के अंदर लोग गांव-ढाणियों में रहते हैं, भारी लू चलती है, आंधी चलती है, इसलिए वहां गांव -ढाणी में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जहां कोई दूसरी योजना नहीं है, इसलिए थर्ड फेज के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1458 करोड़ की योजना का काम शुरू करने की घोषणा की है, ताकि पूरे जिले के अंदर गांव-ढाणियों में लोगों को मीठा पानी मिलेगा। विशेषकर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 85 पंचायतें इन तीन योजनाओं से लाभान्वित होंगी और शेष पंचायतों के लिए थर्ड फेज के बाद काम शुरू करने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है।

मेरे आऊ को तहसील का दर्जा दिया है। लोहावट में मुख्यालय पर डिप्टी आफिस खोलने का एलान किया और लोगों को रोजगार देने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मेरे वहां रीको को भी चालू करने की घोषणा की है। मेरे तिंवरी में सीएचसी करने की घोषणा की है।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): ऐतिहासिक फैसला, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही साथ मेरे लोहावट में मुंसिफ़ कोर्ट खोलने की बात है, चाहे ट्रैजरी खोलने की बात है, क्योंकि एसडीओ हैड-क्वार्टर है, यह भी मैं आपके माध्यम से मांग रखूंगा। पीएचईडी मंत्री जी विराजे हैं, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सहायक अभियन्ता का कार्यालय नहीं है, चाहे वह लोहावट हो, देचू हो और बापिणी में सहायक अभियन्ता का कार्यालय माननीय मंत्री जी खोलें, ताकि योजना भी सही ढंग से समय पर पूरी हो सके और पेयजल की मोनिटरिंग भी सही ढंग से हो सके। मेरा नया विधान सभा क्षेत्र है, यह तीसरा चुनाव है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): कई नये कार्यालय भी स्थापित करने हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा, मेरे मुख्यालय पर सारे कार्यालय खोले जाएं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से 2021-22 के बजट पर अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, पिछले साल कोविड की वजह से, इस महामारी से निजात पाना एक चुनौती थी तो दूसरी तरफ चुनौती यह थी कि सारे उद्योग धंधे बंद हो गये थे, लोग बेरोजगार हो गये थे, कइयों की खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी, दूसरा चैलेंज यह था। दोनों को मैनेज करने के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल यहां राजस्व में 23 परसेंट की कमी आई, 14 हजार करोड़ रुपये, जो भारत सरकार से मिलने थे इसके हिस्से के, वे नहीं मिले हैं। अभी वैट में 2 परसेंट की कमी है, उसकी वजह से एक हजार करोड़ का घाटा राज्य को होगा।

इसके अलावा, तेल और डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो हिस्सा मिलता था, उसमें भी निरन्तर कमी आ रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा इतना शानदार बजट पेश किया है, जिसने प्रदेश के सभी हिस्सों, सभी वर्गों और सभी जितने भी महत्वपूर्ण सैक्टर्स थे, उनको संतुलित रूप से बजट दिया, जिससे प्रदेश का समग्र विकास होगा, लोगों की सामाजिक सुरक्षा होगी।

माननीय सभापति महोदय, अगर इसको सैक्टर वाइज लें तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, हैल्थ एंड मेडिकल की, 'राइट टू हैल्थ' बिल लाने की, जो इन्होंने घोषणा की है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि, इस तरीके से पहले भी 'राइट टू एजुकेशन', 'राइट टू फूड' आये हैं, जिनका भी समाज को बहुत ज्यादा लाभ मिला है।

इसी तरीके से 3500 करोड़ की, जो यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज है, उससे 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। इससे बहुत सारे गरीब लोग, पैसों की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उनकी जिंदगी बच सकेगी।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

इसी तरीके से हैल्थ एंड मेडिकल सैक्टर में 25 जिलों में नर्सिंग कालेज खोलना, हरेक जिले पर मेडिकल कालेज खोलना, जो जांचें होती थीं, उनको 133 पीएचसी, सीएचसी, सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में की है, इससे गरीब लोगों को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने पिछले एक साल के कोराना काल में जो चुनौतियां देखीं, उसे देखते हुए बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया और इससे राजस्थान की गरीब जनता को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से कृषक एवं पशुपालकों के लिए जो घोषणा की गई, पहली तो यही है, जो सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, एक अलग से कृषि बजट, अलग से कृषि बजट आने का फायदा यह होगा कि इस सैक्टर पर एक विशेष फोकस होगा, इस पर ज्यादा खर्चा होगा और किसानों की ज्यादा मदद की जा सकेगी। इसका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह तो सत्य है कि पिछली कांग्रेस सरकार में भी, जब अशोक गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, एक लाख तक का किसानों को बिना ब्याज का ऋण दिया गया था और अबकी बार भी इन्होंने 16 हजार करोड़ रखे हैं। इसमें किसी को शक-शुबहा नहीं होना चाहिए।

इसी तरीके से अभी हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि साहब, सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन 12 हजार प्रत्येक उपभोक्ता को, जो टोटल 13 लाख हैं, उनको यह सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। 01 अप्रैल से बजट पास हो जाएगा, उसके बाद मिलना चालू हो जाएगा।

इसी तरीके से बिजली के बिल किसान हर मंथ पे नहीं कर सकता तो उसका दो महीने में आयेगा, यह भी किसानों की मांग थी। पांच लाख किसानों को उन्नत बीज, नई टेक्नोलोजी है खेती की, उसके लिए भी प्रयास किया गया। माइक्रो इर्रिगेशन है, उसके लिए स्प्रिंकलर है, आपकी ड्रिप इर्रिगेशन का भी प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत भारी फायदा होगा।

सड़क सुरक्षा, अबकी बार यह सबसे यूनिक, जो किसी ने नहीं सोचा था। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल फैक्ट है, हम जानते हैं कि जब रोड पर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होता है, परिवार के परिवार,

(श्री लक्ष्मण मीणा)

पांच-पांच, सात-सात लोग सड़क पर पड़े रहते थे और उनको बाईपासर्स होते थे, कोई हाथ भी नहीं लगाता था। उनका यह कहना था कि पुलिस उनको बाद में परेशान करती है और यह सत्य भी है कि पुलिस उनको परेशान करती है, उनको एविडेंस में आना पड़ता था। इस चीज को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से सोच-समझकर, जो एक तरीके का पुण्य का काम, जो उस घायल आदमी को उठाकर ले जाएगा, हास्पिटल में भर्ती कराएगा, चाहे वह प्राइवेट हास्पिटल हों, चाहे सरकारी हों, उसको 5 हजार रुपये दिये जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इससे जो अभी हमारे प्रतिवर्ष 10 हजार लोग है, जिनकी रोड एक्सीडेंट में डैथ्स होती हैं, बहुत सारे घायल होते हैं, उनकी जान बचाई जा सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने, कोई कर नहीं लगाया गया, 910 करोड़ रुपये की राहत दी है। यह सत्य है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो झूठी घोषणा हो। आपके मण्डी शुल्क हैं, कृषक कल्याण शुल्क हैं, आढ़त है, फल और सब्जी में, कई कृषि जिंसों में है, उसमें बहुत भारी कमी की है। इससे एक तो हमारी मंडियां मजबूत होंगी...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): और जो हमारे यहां से सामान जाता है, वह बाहर नहीं जाएगा।

युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा में इंग्लिश स्कूल खोलना, जिसमें एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 5-5, 6-6 स्कूलें मिल जाएंगी। 600 कृषि विद्यालय खोलना और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में एक हजार की बढ़ोतरी करना। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको भी जो 40 और 50 रुपये हर माह मिलता था, उसमें भी बढ़ोतरी करके 500 और 600 किया गया है। इस तरीके से सारे समाजों का इसमें ध्यान रखा गया है।

पहली बार सामाजिक सुरक्षा निवेश का एक कान्सेप्ट लाया गया है, जिससे निश्चित रूप से एक अच्छा सामाजिक सुरक्षा ढांचा विकसित होगा। डी-नोटिफाइड जो कम्युनिटीज होती हैं, उनका समाज में कोई सम्मान नहीं है, घूमते-फिरते रहते हैं। जैसे- गाड़िया लुहार हैं, नट हैं, बहुरूपिया हैं, सपेरे हैं, जोगी हैं तो उनके विकास के लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिससे लोगों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी राजस्थान में पहली बार और पहला डेयरी टेक्नोलोजी एंड फूड टेक्नोलोजी का एक महाविद्‌यालय बस्सी में खोलने की घोषणा की है। यह पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी देन है। आजकल जमाना इसी चीज का है, क्योंकि सरकारी नौकरियां रही नहीं हैं। सारे जो पब्लिक सैक्टर हैं उनको बंद किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): ...कि यह जो बजट दिया है केवल मात्र घोषणा है, अभी तो एक साल है, जब बजट पास हो जाएगा, 01 अप्रैल से लागू होगा तो निश्चित रूप से धरातल पर आयेगी और सब लोगों का फायदा होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरक बजट में बस्सी में एक सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कर दें और तूंगा को उप तहसील बना दें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बहस में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट 2021-22 सदन में प्रस्तुत किया और माननीय सभापति महोदय, यह उनका तीसरा बजट था। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 का बजट, यह सारे बजट प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले साबित हुए हैं और यह बड़ी घोषणाएं और यह बड़े वादे सिर्फ बजट तक ही सीमित नहीं हैं, जो चुनाव पूर्व की घोषणाएं थीं, वह भी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी उन सारे वादों को, उन सारी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाये। आज जिस तरीके से कानून-व्यवस्था को लेकर और बजट घोषणाओं को लेकर पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है और जो इंतजार कर रही है कि कब बजट घोषणाएं पूरी होंगी, कब चुनाव घोषणाएं पूरी होंगी। आज राजस्थान जो 2018 से पूर्व पूरे राज्य में विकास के तीसरे पायदान पर आ गया था, इन 26 माह में सरकार ने अपने कामकाज से आज आखिरी के पायदानों में राजस्थान को लाकर खड़ा कर दिया।

किसानों के कर्ज माफी की बात, चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आये और घोषणा करके चले गये 10 दिन की गिनती गिनाकर, मुख्य मंत्री जी

(श्री संदीप शर्मा)

भी उनके साथ थे और किसानों से वादा किया कि आपका सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा और अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 14,000 करोड़ रुपये 19 लाख किसानों के उन्होंने माफ किये और उसमें भी वह राशि सम्मिलित है जो पूर्ववर्ती सरकार ने 50 हजार किसानों के ऋण माफ किये थे, वह भी राशि इन 14,000 करोड़ रुपये में सम्मिलित की गई है। लेकिन जो वादा था वह 59 लाख किसानों से था और 99 हजार करोड़ रुपये सरकार को माफ करना था, जो उनका चुनाव पूर्व घोषणा में वादा था लेकिन सरकार ने बड़ी अदा के साथ उस गेंद को केन्द्र सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से आपने वादा किया था, वह वादा आपको पूरा करना होगा। यह तय है, नहीं तो इस सरकार को परिणाम भुगतने होंगे। आपके वादे रहे थे किसानों के साथ। आप किसानों की हिमायत करने की बात करते हैं। आपने इस कृषि बजट में उनका 5.5 हिस्सा तय किया है जबकि अन्य प्रदेश की सरकारें 7% कृषि बजट को देती हैं और आपने 5.5% दिया है और आप अब बात करते हैं कि हमने 600 संकायों में कृषि को प्रारम्भ कर दिया है, हमने दो कृषि महाविद्यालय दे दिये। जब आपने पुराने बजट में जो कालेजों की घोषणा की थी उनमें एक भी शिक्षक काम नहीं कर रहा है, उनमें एक भी शिक्षक आप लगा नहीं सके, आप स्टाफ नहीं लगा सके। आप आवश्यक संसाधन नहीं लगा सके, और तो और वहां पर बिल्डिंग भी आप निर्माण नहीं कर सके और बात किसान हित की होती है और गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी जाती है। आपने वादा किया था लेकिन 30 लाख किसान अभी शेष हैं, वह इंतजार कर रहे हैं आपके वादे का जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उनका कर्जा भी आपको माफ करना है।

आप जिस तरीके से अपनी योजनाओं की बात करते हैं, कोई धरातल पर नहीं हैं। धरातल पर सब नदारद हैं। आपकी घोषणाएं डीपीआर की स्टेज पर भी नहीं आई हैं। आपके पास सिर्फ लोकलुभावन घोषणाएं करने का काम है लेकिन आपके पास न तो उसके इंप्लीमेंटेशन करने की, न स्ट्रैटेजी प्लान करने की कोई योजनाएं हैं।

आपने बेरोजगार युवकों के साथ दगा किया। बेरोजगार युवकों से आपने कहा कि हम आप सभी को 3,500 रुपये बेरोजगार भत्ते के रूप में देंगे और आज 15 लाख युवा बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और आप

(श्री संदीप शर्मा)

1,60,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, जिसमें से भी 85,000 पुरानी सरकार के समय के थे। पुरानी सरकार उन युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रही थी और साथ ही साथ जो 1,60,000 युवा बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है उनमें से भी अधिकांश की शिकायत है कि विभाग हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जाता है? आप उन 12-13 लाख जो नवयुवक हैं उनके वादे का क्या करेंगे? आपने संविदाकर्मियों से कहा कि हम आपको चुनाव जीतने के तुरंत बाद नियमित कर देंगे। वह संविदा वाला व्यक्ति जो 6-7 हजार में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह आज बड़ी दया के साथ आपकी तरफ देख रहा है परंतु आपकी संवेदनशीलता जैसे खतम हो गई है। वह ऐसा व्यक्ति है जो 6-7 हजार में अपने परिवार का गुजारा करके अपने परिवार का पेट पालता है। आपके वादे से उसकी आशा बंधी थी और आपने अपने झूठ से, आपके वादे जो आपके निराधार वादे निकले, उस संविदाकर्मी को आपने आज मजबूर कर दिया कि वह आंदोलनरत हो। आपने सरकारी भर्तियों के लिए कहा कि 5 लाख सरकारी भर्तियां कांग्रेस की सरकार देगी, चुनाव जीतने के बाद 5 लाख सरकारी भर्तियों की बात तो दूर...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 1,28,000 भर्तियां अभी तक दी गई हैं, जिसमें से अधिकांश प्रक्रियाधीन हैं। माननीय सभापति महोदय, अधिकांश के परिणाम नहीं आये। आपके 5500 कांस्टेबल्स के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए, 6632 पद कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों में कैद हैं, 4421 पटवारी पदों की परीक्षा आपने रद्द कर दी, 1289 अभियंता परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे हैं।

उद्योग आप एक भी लगा नहीं पाये राजस्थान में। राजस्थान में स्थिति यह है कि आपकी उद्योग नीति के कारण कोई उद्योगपति आना पसंद नहीं करता है। आप उद्योगपतियों को राजस्थान की धरती पर आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। मैं कोटा शहर की बात करूं तो हमारे मंत्री जी भी यही बैठे हुए हैं। नगर न्यास मंत्री जी स्मार्ट शहर के पैसे से बहुत सारे फ्लाईओवर, अंडरपास, बाईपास बना रहे हैं परंतु इस कोरोना के काल में उन्होंने स्वयं शहर की स्थिति को देखा है। शिक्षण संस्थान बंद होने के बाद जिस तरीके से कोटा की आर्थिक धुरी बिल्कुल जैसे ठप हो गई थी और कोटावासी किस तरीके से

(श्री संदीप शर्मा)

दर-दर भटका था। क्या यह आवश्यकता नहीं थी कि आप कोई उद्योग-धंधा कोटा की धरती पर लाते? कोटा के उन नवयुवकों को आप रोजगार देते? किस प्रकार से आपके इस सौंदर्यीकरण को वह देखेगा? आपके सौंदर्यीकरण को तभी देख पाता जब उसकी जेब में तनख्वाह होती लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं। सभापति महोदय, कसमें, वादे, प्यार, वफ़ा सब झूठे हैं, झूठों का क्या, आज राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार के लिए यह भावना लेकर चल रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में है और मथुराधीश जी का मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लगेगा, वह वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, यदि उसके परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जाए, उसका उद्धार किया जाए तो निश्चित रूप से कोटा शहर पर्यटन में धार्मिक स्थली बन सकता है और वहां पर लाखों तीर्थयात्री मथुराधीश जी के दर्शन करने आ सकते हैं। श्रीनाथजी और बांके बिहारी जी के समानांतर यह मथुराधीश जी का मंदिर है परंतु माननीय मंत्री जी का उस ओर ध्यान नहीं है, 2 वर्ष से पूरी मूलभूत सुविधाएं बंद हैं, शहर तरस रहा है। माननीय सभापति महोदय, मिनी सचिवालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज सहयोग करें। समय की कमी है। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें प्लीज। श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदी के सबसे खराब दौर में और आज तक की सबसे खतरनाक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक इच्छा शक्ति से मुकाबला करते हुए उसका शानदार प्रबंधन करने के बाद जिस तरह से एक अच्छे कुशल वित्तीय प्रबंधन करके एक जन कल्याणकारी बजट दिया है, उसके लिए उन्हें व उनकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूं। इस बजट से पूर्व भी दो बजट हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने पेश किये थे, उन दोनों बजटों

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

में और इस बजट में भी किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया है और इस कठिन दौर में भी 910 करोड़ की एक बड़ी कर राहत आमजन को दी है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ जरूर मिला है। कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से सरकार ने जटिल परिस्थितियों के बावजूद अच्छे तरीके से इतना शानदार बजट दिया, मेरे विपक्ष के साथी भी अंतरात्मा से तो निश्चित तौर पर मानते होंगे परंतु शायद पार्टी लाइन के चलते हुए उसकी खुलकर सराहना नहीं कर पा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को कोरोना के अच्छे तरीके से संचालन और उसका मुकाबला और प्रबंधन करने की बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, भीम देवगढ़ विधान सभा क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां कई वर्षों से पेयजल की बहुत भारी समस्या थी और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट में तमाम 275 गांवों और 828 ढाणियों और देवगढ़ नगरपालिका के लिए 1032 करोड़ की चंबल के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की और बजट में प्रावधान किया, उसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके इस भागीरथ प्रयास के लिए आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र जहां गरीब, ओबीसी बहुल और सर्वाधिक भूतपूर्व सैनिक और सैनिक भीम देवगढ़ में निवास करते हैं, जिनकी संख्या हजारों में हैं, उन सबकी ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजटों में भी चाहे भीलवाड़ा की चंबल परियोजना हो, चाहे ब्यावर में बीसलपुर का पानी देना हो, चाहे नाथद्वारा में बाघेरी का नाका, जिस इलाके से मैं आता हूं, उसके आस पास चारों तरफ जितनी भी जल योजनाएं आई हैं, चाहे इस शासनकाल में हो, चाहे पिछले शासनकाल में हो, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दी गई, उसके लिए हमारे इलाके में इन्हें नए युग का भागीरथ कहा जाता है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मेरे ख्याल से इस सदन में ज्यादातर लोगों के विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या एक गम्भीर समस्या है और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुल 25 सांसद आपकी पार्टी के जनता ने जिताए हैं, उनका और हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि केन्द्र से हम जल जीवन मिशन में अच्छी धनराशि राज्य सरकार के खाते में दिलवाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

में तो निश्चित तौर पर राजस्थान को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला और जोधपुर के माननीय सांसद को जल शक्ति मंत्रालय भी मिला, परंतु इस मंत्रालय से और मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व से कुछ नहीं होगा, जब तक वहां राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करके और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जल जीवन मिशन में हम नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए बड़ी तकलीफ का विषय रहेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में आपने देखा है कि नोर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स और यूनियन टैरेटरीज में 90 प्रतिशत तक केन्द्र का सहयोग रहा है। राजस्थान के सारे इलाके से आप सब लोग वाकिफ हैं। हिन्दुस्तान का सर्वाधिक भूभाग 10.4 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है। माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद हमारे यहां पर किसी तरह का सतही जल स्रोत भी बहुत कम है और जल स्रोतों की दूरी बहुत ज्यादा है ग्राउंड वॉटर ओवर एक्सप्लोइटेड है और खराब क्वालिटी का है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर केन्द्र सरकार से इस बात की मांग करें कि जल जीवन मिशन में हमें भी 90:10 का रेशो मिले, अदरवाइज जल जीवन मिशन से हम लोगों के सभी इलाक़े लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसमें एक FHTC रेशो की भी बात आती है (Functional Household Tap connection), वह जैसलमेर और राजसमंद, जिस इलाके से मैं आता हूं, उन दोनों जगहों पर करीबन लाख रुपया प्रति हाउसहोल्ड से ज्यादा है, जो कि नेशनल एवरेज 30 हजार से भी ज्यादा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अगर गांव-गांव में जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाना चाहें तो बहुत कठिन होगा। जल जीवन मिशन की एक और समस्या माननीय पीएचईडी मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में एक टैक्निकल फाल्ट है कि यह जो इंटरनल पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जल जीवन मिशन में होगा, उसके लिए विलेज कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है और चाहे वह सोर्स से आगमेंट करना हो, टंकी बनाना हो और दूसरे काम हो, तो निश्चित तौर पर सेंटर और स्टेट के रेशो में जाएगा। परंतु जहां इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, गांव-गांव में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसमें 45 परसेंट स्टेट का है, 45 परसेंट सेंटर का है और 10 परसेंट विलेज कंट्रीब्यूशन है, यह मेरे ख्याल में एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा काम्प्लीकेटेड हो जाएगा। आने वाले समय में योजनाएं बन जाएंगी। जब घर-घर पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन लगाने की बात आयेगी तो हम गांव के लोगों से कहेंगे कि इस पाइपलाइन में इतना

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)
हिस्सा आप लोगों को देना है। मसलन मेरे यहां पर एक जल योजना है जिसमें 46 लाख रुपये इस डिस्ट्रीब्यूशन में लगेंगे, तो उसका 10 परसेंट, अर्थात 4 लाख 60 हजार रुपये गांव के लोगों को इकट्ठा करके देने होंगे। एक तरह से यह एक टैक्निकल विसंगति है। इसके कारण हमारी कई सारी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। आज तक चाहे जयपुर में बीसलपुर का पानी आया हो, चाहे कहीं पर भी आया हो, इस तरह का पूर्व में पहले भी कहीं नहीं हुआ है कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा हमने जनता से कहीं अलग से मांगा हो। ओ एण्ड एम का इश्यू भी है, विलेज सैनिटेशन कमेटी को भी इस जल जीवन मिशन में ओ एण्ड एम की पूरी जिम्मेदारी देंगे। इन दोनों बातों के लिए पीएचईडी मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह इसका खुलासा करके केन्द्र सरकार से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन लें।

महाराणा प्रताप की विजय स्थली दिवेर है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिवेर को उप तहसील बनाने का जो गौरव दिया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेवाड़ के तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई, युद्ध, संघर्ष मेवाड़ की आन-बान-शान के लिए बहुत किया, पर विजय उन्हें दिवेर में मिली थी और दिवेर को यह गौरव दिलाने के लिए गांधीवादी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र 150 किलोमीटर लंबा है। एक छोर से दूसरी तरफ दिवेर में तहसील बनाने के लिए और दूसरी तरफ शेखावास/बार में पुलिस थाना बनाने के लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं और भीम देवगढ़ में आरटीडीसी के जीर्णोद्धार के लिए जो इन्होंने प्रावधान किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं।

धर्म की राजनीति करने वाले दलों को आईना दिखाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। चारभुजा और नाथद्वारा को धार्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। उनका और मुख्य मंत्री जी दोनों का धन्यवाद देता हूं कि राजसमंद डेयरी को-आपरेटिव का जो गठन कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक बजट के आंकड़ों का सवाल है, विपक्ष के माननीय सदस्य, हमारे माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता, सब लोग यही बोल रहे हैं कि यह आंकड़ों की जादूगरी है, एक मकड़जाल है। परंतु आप अतीत में

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

जाएंगे तो 2013 में हमने रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आपको दिया था और उसके बाद 2018 में आपने 29 हजार का रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हमको हैंडओवर किया और जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा था कि बजटरी एस्टीमेट में 12378 करोड़ का हम लोगों ने एस्टीमेट दिया था, रिवाइज्ड एस्टीमेट में 41721 करोड़ रुपया हो गया। मैं आपको देखता हूं कि निश्चित तौर पर आप बहुत विद्वान हैं, बहुत स्टडी करके आते हैं परंतु जो यह डेफिसिट है पिछले एक साल में निश्चित तौर पर कोरोना के कारण रेवेन्यू रिसीट हमारी कम हुई है, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके कारण आपका यह डेफिसिट बढ़ा है। 1 लाख 73 हजार करोड़ का हम मानकर चल रहे थे, उसके सामने 1 लाख 47 हजार करोड़ की हमको रिसीट हुई। इन रिसीट्स में जो 26 हजार करोड़ की कमी आई, वह भी एक बड़ा रीजन रहा है, जिससे कि हमारा यह रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो तमाम चीजें, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो और जो भी हमारे आय के साधन थे, उनमें गिरावट आई है, मैंने सबको स्प्लिट करके देखा था। इसी को देखने के लिए जब केन्द्र सरकार के बजट पर नजर डाली तो हमने देखा कि केन्द्र सरकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। केन्द्र में हमने 20 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसीट सोची थी, उसके सामने 15 लाख 55 हजार करोड़ की हमको रेवेन्यू रिसीट हुई, इसलिए वहां भी हमने जो रेवेन्यू डेफिसिट प्रोजेक्ट किया था कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 6 लाख 9 हजार करोड़ होगा, उसकी जगह वह 14 लाख 55 हजार करोड़ हुआ है..

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): यह सभी चीजें राजस्थान की राजनीति और केन्द्र की राजनीति में हुई हैं। केन्द्र के बजट के बारे में कहूंगा कि सभी रेवेन्यू रिसीट में तो घटत आई परंतु जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है, वह हमारी प्रोजेक्टेड से भी ज्यादा हुई। 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपये हमको मिला, यानी पेट्रोल और डीजल पर कोरोना के दौर में भी हमने दबाकर भारत की जनता से पूरी तरह से पैसा वसूल किया। पेट्रोल को तो हम 3 अंकों में ले ही गये, 100 रुपया आ गया। 100 रुपया अब एक न्यू नोर्मल हो गया है। माननीय सभापति महोदय, अब शायद गैस को भी हमारे विपक्ष के साथी दिल्ली में बैठकर 1000 रुपया ले जाने की तैयारी में है, आज 823 रुपया है। इसको भी आप चार डिजीट में ले जाना चाहते दिख रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

बधाई। इस तरह से जो आपने प्राइस राइज किया है, उसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद। मैं चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार से कम से कम इतना तो कहें कि रेवेन्यू डेफिसिट और इन सब चीजों के बावजूद एम.पी. फंड को तो रिलीज करें, ताकि हमारे 25 के 25 एम.पीज. को राजस्थान की जनता देख पाये कि वे लोग कहां हैं?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी तरफ से साधुवाद देता हूं कि आपने 4 दिवंगत सदस्यों के नाम से गर्ल्स कालेज के नामकरण किये हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एग्रीकल्चर पर एक अलग से बजट देने की घोषणा की गयी है। किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। बिजली को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम देवगढ़ में छोटी खेती को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। थ्री फेज का एग्रीकल्चर कनेक्शन लेना हमारे यहां उपयोगी नहीं है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमें सिंगल फेज एग्रीकल्चर कनेक्शन दें, ताकि हमारे किसान लाभान्वित हो सकें। देवगढ़ कालेज में साइंस फैकल्टी और भीम में आई.टी.आई. खोलने की कृपा करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बजट पर हो रहे विचार में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह तीसरा बजट है। तीनों बजट में बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच पिछले दो बजट की कई घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं। मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में घोषणा करें और वे दो वर्षों तक पूरी न हों, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बजट घोषणाओं का पूर्ण न होना राजस्थान सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को प्रकट करता है। बिना वित्तीय प्रबंधन की घोषणाएं जनता के साथ छलावा है। बजट में सरकारी व्ययों में कमी, गुणवत्ता बढ़ाने, मंडी कर कम करने, पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी करने की घोषणा नहीं करके जनता की आशाओं पर कुठाराघात किया है। इस बजट में नयी भर्तियों की घोषणा की है। पिछले दो बजट में भी 53 हजार

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

और 75 हजार भर्तियों की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी। उनमें से कितनी हुई, यह विचारणीय विषय है। बार-बार भर्तियों और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है।

बजट में प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियम की घोषणा की गयी है, परंतु इसके लिए सांसद/विधायक मद से पैसा स्वीकृत होगा। राज्य सरकार घोषणा करती है और पैसा सांसद/विधायक फंड से जारी होगा। माडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेंगे, पैसा विधायक मद से स्वीकृत होगा। थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे, पैसा विधायक मद से स्वीकृत होगा। ये सब घोषणाएं बजट में मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां पर की गयी हैं। हर विकास के लिए यह सरकार विधायक मद पर निर्भर दिख रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा था कि पहले थानों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती थी, 2019 में थानों में निर्बाध रूप से एफ.आई.आर. दर्ज कराना सुनिश्चित किया है। यह कैसी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि किसी नागरिक को थाने में प्राथमिकी लिखवाने का मूल अधिकार का विषय भी मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में है। 1947 में हम आजाद हो गये, नागरिक बिना दिक्कत के थाने में जाकर एफ.आई.आर. लिखवा सके, यह 2021 में विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का विषय है। इसके कारणों पर अलग से चर्चा की जा सकती है। राजस्थान के सत्ताधारी दल में जो आपसी खींचतान व अंतर्विरोध है, उससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। पिछले समय के स्वीकृत काम अधूरे पड़े हैं, फिर नयी घोषणाएं कर दीं।

इस बजट में भी जोधपुर को प्राथमिकता मिली है। इस बजट में चारों सीटों के उप चुनाव के प्रति मुख्य मंत्री जी की चिंता प्रकट हुई है। चारों क्षेत्रों की घोषणाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जनता सब जानती है। उप चुनाव में लुभावने वादे करके काम तो करने नहीं हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी अभी घोषणाएं कर रहे हैं।

अभी कुछ दिनों पूर्व उप चुनाव वाले क्षेत्रों में डाक्टरों का बड़ी संख्या में पदस्थापन किया है। क्या सरकार केवल उप चुनाव वाले क्षेत्रों की चिंता करेंगी? मेरा भी क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में है, मेरे यहां हास्पिटल खाली पड़े हैं, परंतु इसकी मुख्य मंत्री जी को चिंता नहीं है। इस सदन में पहले भी कई

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

माननीय सदस्यों ने कहा है कि विकास में दलगत व राजनीतिक भेदभाव न हो। भाजपा सरकार ने हमेशा बिना भेदभाव के विकास किया है और चाहे सैकेण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो या गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम हो, भाजपा सरकार ने निश्चित मापदंडों के अनुसार बिना राजनीतिक भेदभाव के काम किया है।

मेरे यहां एक गांव है, मानपुरा ग्राम पंचायत में गणेशपुरा, वहां पर 1200-1300 की पापुलेशन है, वहां पर दो कमरों में स्कूल चल रही है और वहां पर कोई सुविधा नहीं है। वहां 116 बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव वाले और मैं भी यहां विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए और विद्यालय की बिल्डिंग के लिए कहता हूं, पर सरकार के बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। गांव के सभी निवासियों ने अभी 35 लाख रुपये इकट्ठे किये हैं, तो सरकार द्वारा उनको जो खेल मैदान है, जो खेल मैदान की भूमि है, उसमें निर्माण करने की स्वीकृति तक प्रदान नहीं कर रहे हैं। वहां से सवा सौ बच्चे राजमार्ग से होते हुए मानपुरा या दामड़िया पढ़ने के लिए जाते हैं। आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए वे बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। यह सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है।

भीलवाड़ा जिले में चंबल की पानी की योजना है परंतु 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अब तक, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सबसे पहले पाइपलाइन होकर निकलती है, पहले माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र आता है, परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे वहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। कहते हैं कि काम चालू है, चालू हो रहा है और इसमें भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायतें करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि विकास का आधार राजनीतिक न होकर क्षेत्र की आवश्यकता व निर्धारित मापदंडों से हो। पिछले दो बजट की अधूरी घोषणाएं, इस बजट की घोषणाओं पर शत-प्रतिशत अमल का संकल्प सरकार व्यक्त करे, तभी बजट की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

मुख्य मंत्री जी ने दो वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण काम किये हैं। जैसे भामाशाह कार्ड को जन आधार कार्ड कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इन्दिरा रसोई कर दिया। पंचायत व पालिका चुनाव में प्रत्याशियों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता समाप्त की और अंगूठा छाप को वापस चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र और मीसा बंदियों की पेंशन तक इस सरकार ने

(श्री गोपाल लाल शर्मा)
बंद कर दी है। आपकी गांधी परिवार के प्रति श्रद्धा है, उन्हीं के नाम पर अधिकांश योजनाएं लागू होती हैं। आपने भामाशाह तक का नाम हटा दिया है। योजना वही है, केवल नाम बदला है। स्वतंत्रता के प्रेरणा पुंज, महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम की योजना को बंद करना पूरे देश का अपमान है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी अवैध बजरी व सैंड स्टोन का कारोबार धड़ल्ले से व खुले में चल रहा है, परंतु इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। इससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है व आम जनता को बजरी का चार गुना दाम चुकाना पड़ रहा है। इस अवैध कारोबार से माफिया पनप रहा है। आने वाले दिनों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैंड स्टोन का व्यवसाय है। इसमें खनिज विभाग द्वारा पहले आम जनता को खनिज का व्यवसाय देने के लिए लाटरी सिस्टम द्वारा, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन लेने के बाद लाटरी निकाली जाती है, परंतु आज वे सब बंद कर दी हैं। आम आदमी सोचता था कि मैं भी खान का मालिक बनूं और खान चलाऊं। यह सपना था, इस सरकार ने इस सपने को पूरी तरह खतम कर दिया है। अब केवल पूंजीपति ही यह व्यवसाय कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक ही खनिज नीति बनाकर माइनिंग लीज जारी करने की घोषणा करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि आम जनता को इस व्यवसाय में जोड़ने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए वापस लाटरी सिस्टम को चालू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आम आदमी को उससे रोजगार मिलेगा।

खातेदारी सिंचित क्षेत्र में, हमारे वहां पर खातेदारी में आबंटन के जो नियम हैं, उसमें सिंचित क्षेत्र है, 20 बीघा जमीन होती है, उसके बीच में 5 बीघा सिंचित होती है तो वह आबंटित नहीं होती है जबकि नियमों में आबंटन होना बंद नहीं है, परंतु राज्य सरकार द्वारा वह एग्रीमेंट नहीं होता है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि सिंचित क्षेत्र में जो आबंटन नहीं हो रहा है, उसको लागू करें।

मेरा विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। भीलवाड़ा से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। खनिज क्षेत्र है। वहां पर परिवहन कार्यालय नहीं है। वहां पर आने-जाने में, सुबह आते हैं, शाम तक भी भीलवाड़ा पहुंचने

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

में समय लगता है। आजकल ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से माण्डलगढ़ में परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2019 में अतिवृष्टि हुई थी...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो नदी के पुल बह गये थे। 2020 में मैं मंत्री जी से मिला, पहले बजट में मैंने तारांकित प्रश्न भी लगाए।

श्री सभापति: बैठिए। श्री अमित चाचाण।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 295 में भी बोला किंतु अभी तक उसका कोई निदान नहीं हुआ।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में महाविद्यालय है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट। उसमें 1350 विद्यार्थी पढ़ते हैं 22 व्याख्याता के पद हैं परंतु केवल 5 पद पर व्याख्याता कार्यरत हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): लेखाधिकारी, लिपिक का पद, पुस्तकालयाध्यक्ष का पद, शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त है, इनको भरने का आदेश करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 संस्कृत स्कूल हैं जिसमें 38 अध्यापक स्वीकृत हैं परंतु कुल 9 अध्यापक अभी काम कर रहे हैं। एक-दो विद्यालय में तो एक भी शिक्षक नहीं है। ये सरकार की नीति आपके सामने हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नेशनल हाईवे हैं। माण्डलगढ़, बीगोद, बिजौलिया दो बहुत बड़े कस्बे हैं। पूर्व बजट में 2020-21 के बजट में मुख्य मंत्री जी द्वारा ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी, बिजौलिया में। एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री अमित चाचाण।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बजट बहस में बोलने का अवसर दिया।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं आभार प्रकट करता हूं, हमारे राजस्थान के गांधी, एक जननायक, सादगी और सरलता की पहचान आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत का कि इन्होंने इस बार एक ऐसा बजट दिया। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति और तरक्की के लिए, विकट और विषम परिस्थितियों में एक शानदार बजट पेश किया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं:-

"क्या मारेगी मौत उसे, जो औरों के लिए जीता है,

इस जहां का प्यार मिलता है उसे, जो दूसरों के आंसू पीता है।"

चूंकि गत वर्ष हम सबने देखा कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश और विश्व उसकी चपेट में आया। राज्य की सरकारें हों, चाहे केन्द्र की सरकार, एक आर्थिक संकट गहराया। पूरा देश का पहिया थम चुका था। हर व्यापार और कारोबार ठप हो चुका था। सरकार पर एक बड़े आर्थिक संकट के साथ-साथ केन्द्र में बैठी हमारी मोदी सरकार ने एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया लेकिन हमें गर्व है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक शानदार बजट पेश किया। जहां हमारे पक्ष के लोग अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं प्रतिपक्ष के लोग दांतों तले अंगुली दबा रहे थे कि ऐसा बजट कैसे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया? चूंकि मुख्य मंत्री जी की सोच सदैव आमजन, किसान के हितैषी की रही, मुख्य मंत्री जी की लगन सदैव पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने की रही। मुख्य मंत्री जी की चिंता सदैव यही रही कि किस तरह से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को हम दु:ख-सुख में आगे लाने का काम करें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सभी 200 के 200 विधायकों को अपना मानते हुए बगैर किसी भेदभाव के साथ एक शानदार बजट पेश किया है। मुख्य मंत्री जी का जब-जब भी कार्यकाल आया, उन्होंने सदैव भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और मरीज को दवा, सबसे बड़ी सेवा होती है, यह मानकर कार्य किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में चाहे जरूरतमंदों को दवा के लिए नि:शुल्क दवा योजना की बात करें, चाहे नि:शुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, उन्होंने सदैव गरीबों के दर्द को मिटाने के लिए ऐसी-ऐसी योजनाएं चलाईं। आज हमें गर्व होता है कि जब पूरे देश में और विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना वैश्विक महामारी को

(श्री अमित चाचाण)

लेकर, वहीं मुख्य मंत्री जी के अच्छे प्रबंधन की वजह से उन्होंने प्रदेश की 7 करोड़ जनता का जीवन बचाने के साथ-साथ राजस्थान का नाम विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखाने का काम किया। उनके प्रबन्धन की वजह से इस कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, इस संकल्प के साथ उन्होंने कार्य करने का काम किया।

आज चिकित्सा व्यवस्था है, मुख्य मंत्री जी ने अपने हर कार्यकाल में उस ढांचे को मजबूत करने का काम किया। आज इस कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो हमें उन चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता पड़ी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा संस्थानों को बढ़ाने के लिए, चाहे वह जिले के अस्पतालों में आईसीयू बढ़ाने की बात करें, चाहे बैड बढ़ाने की बात करें, चाहे पीएचसी, सीएचसी को खोलने की बात करें, उनका सपना सदैव यही रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जरूरतमंद को नि:शुल्क दवा देने का काम करें।

इसके साथ ही मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षा में भी नवाचार किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था 'शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीयेगा, वह उतना दहाड़ेगा'। उन्होंने लगातार नवाचार करते हुए इस बार तो एक इतिहास ही लिखा कि आज राजस्थान का गरीब परिवार का बच्चा, जिसका एक सपना था कि वह भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाएगा, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई, बढ़ती फीस को देखते हुए उसका एक सपना था कि वह भी प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जायेगा, मुख्य मंत्री जी ने उनके सपने को पूरा करते हुए पहले जिला स्तर पर अंग्रेजी माध्यम खोला, फिर प्रत्येक ब्लाक में खोले गये और इस बार तो उन्होंने 5000 से अधिक आबादी वाले राजस्थान के प्रत्येक गांव में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की है, इससे राजस्थान का जो हमारा उज्ज्वल भविष्य है, जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, उसका भी सपना साकार हो रहा है। आने वाले दिनों में वह भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

आज वक्त की मांग है कि ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल स्मार्ट टीवी और सैटअप बाक्स लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों में 3500, चाहे वह क्लास रूम हो, चाहे वह लायब्रेरी हो, चाहे वह कम्प्यूटर रूम

(श्री अमित चाचाण)

हो, उन्होंने आने वाले समय में खोलने की बात की। चूंकि अभी दो वर्ष का समय बीता, एक वर्ष तो कोरोना काल में गया, विभिन्न आचार संहिताओं का वर्ष रहा फिर भी मुख्य मंत्री जी सदैव विकास के लिए चिंतित रहे। मुख्य मंत्री जी ने चार कन्या महाविद्यालय खोलने की जो बात की, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जो हमारे सदन के साथी थे, जो कोरोना काल की वजह से हमें छोड़कर चले गये, आज उनकी याद सदैव व्यक्ति के मन में रहे, इसके लिए उन्होंने चार कन्या महाविद्यालय हमारे साथियों के नाम से खोलने की घोषणा की।

मैं आपसे कहना चाहता हूं चाहे हम सड़कों की बात करें, मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 200 के 200 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये की सड़कों की बात की। नगरपालिका, नगर निकाय और नगर परिषद् में भी विभिन्न तरह की सड़कों के निर्माण कार्य की बात की। हर जिले में तीन मेजर सड़कें बनायी जाएंगी, राष्ट्रीय राज्य मार्गों का विस्तार किया जायेगा। इस तरह के विकास कार्य उन्होंने बताये। मुख्य मंत्री जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था की।

मुख्य मंत्री जी की सोच यही है कि वह प्रत्येक वर्ग को चाहे वह छोटा व्यापारी हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह बेरोजगार हो, उन्होंने इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्य मंत्री जी की सोच उस तानाशाह व्यक्ति की तरह नहीं है कि वह 15 लाख का सूट पहने, 20-20 लाख के चश्मे लगाए, हर दिन रंग-रूप बदले या विदेशों की यात्रा करें। मुख्य मंत्री जी हमारे सदैव गरीब जनता के दिल में रहते हैं। मुख्य मंत्री जी आमजन के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं।

केन्द्र में बैठी मोदी सरकार, जिन्होंने हद कर दी, तीन महीने से ज्यादा हमारा अन्नदाता राजधानी दिल्ली को घेरे बैठा है लेकिन उनको एक दिन भी चिंता नहीं हुई। आज हमारे देश का प्रधान मंत्री जब विदेशों में गया तब उनका मान-सम्मान हुआ। उनको भी घमंड व गुरूर हो गया लेकिन वह यह भूल गये कि वह नरेन्द्र मोदी का सम्मान नहीं, वह सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश का सम्मान हुआ था, भारत की इस मिट्टी का सम्मान हुआ था, पूर्व में जो-जो भी प्रधान मंत्री रहे, जो विदेशों में गये, उनका सम्मान

(श्री अमित चाचाण)

हुआ था। उन्होंने तो हद कर दी विदेश नीति की खिलाफत करते हुए चाहे वह 'नमस्ते ट्रम्प' या 'हाउडी मोदी' की बात करें, तो उसका हश्र भी हमने देखा कि किस तरह से देश की जनता ने उसका हश्र देखा।

हम चाहते हैं कि देश में बैठी वह तानाशाह सरकार होश में आये, अपनी नींद से जागे, सपने से बाहर आये कि जिस तरह से उन्होंने गत चुनाव में देश की जनता को गुमराह किया, युवाओं को गुमराह किया, झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे देकर केन्द्र की गद्दी पर तो बैठे लेकिन 6 वर्षों में उन्होंने विकास की एक भी बात नहीं की। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर, सेना के नाम पर सत्ता हथियाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं हमें गर्व है हमारे देश की सेना पर, देश की सेना आज ही मजबूत नहीं हुई, देश की सेना आजादी के साथ ही मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। शायद वह यह दिन भूल गये जब हमारी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने 90 हजार पाकिस्तान के सैनिकों का आत्म समर्पण करवाया था। हमारा देश सोने की चिड़िया था। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी भाई चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हों, एक धागे में पिरोकर एक साथ रहें। किसी भी तरह का जातिवाद का जहर घोलकर जो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, भाईचारे को खतम करना चाहते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी के नेता कभी कामयाब नहीं होने देंगे।

मैं मुख्य मंत्री जी का व नोहर विधान सभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं जिसने 30 वर्ष बाद, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण भांभू के बाद अपने इस स्थानीय बेटे को विधायक चुनकर राजस्थान की विधान सभा में भेजा। 30 वर्षों तक जो हमारे नोहर के जनप्रतिनिधि बनकर आये, नोहर के साथ शोषण किया, नोहर के साथ भेदभाव किया, उसका बेटा विधायक बनने के बाद, 30 वर्षों का जो भी शोषण था, दो वर्षों में पूरा करने का किया। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में तो इन्होंने ऐसी-ऐसी घोषणाएं कीं कि 35 वर्ष पूर्व हमारे नोहर में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, जो स्वर्गीय नर्मदा देवी बिहाणी जी के नाम पर था, 35 वर्ष बाद नोहर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई।

हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का फेफाना गांव, जो सबसे बड़ा गांव है, उसमें 12 हजार वोट हैं। वर्षों पूर्व उप तहसील बननी चाहिए थी लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से नहीं बन पाई। हमारे मुख्य मंत्री जी

(श्री अमित चाचाण)

ने इस बार उसको उप तहसील बनाने का काम किया। हमारे 27 गांव टेल के, जो वर्षों से पानी के लिए तरस रहे थे लेकिन नोहर के जनप्रतिनिधियों ने चिंता नहीं की, जब मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने बात रखी कि हमारे क्षेत्र का पानी भादरा क्षेत्र में चोरी किया जाता है, उसकी रखवाली नहीं की जाती, 27 गांव टेल एंड पर रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, तो मुख्य मंत्री जी ने जिला प्रशासन को लगाया, पानी पहुंचाने का काम किया। इस बार उन्होंने नया थाना देकर पानी चोरी रोकने वालों पर लगाम कसने का काम किया।

नोहर से सरदारशहर सड़क, जो लंबे समय से मांग चल रही थी, इस बार उनको पूरा करने का काम किया। नोहर से चूरू हाईवे, हर कार्यकाल में वहां से मंत्री बनते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी सुध नहीं ली। केन्द्र में बैठी मोदी सरकार ने बार-बार अपने बजट में, घोषणा की रैलियों में कि नोहर से चूरू तक का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं 258 करोड़ रुपये पास करके नोहर से चूरू हाईवे बनाने का कहकर गये हैं। आप कह रहे हो कि क्या किया? मुख्य मंत्री जी ने पक्ष और विपक्ष, सब को कुछ न कुछ दिया, लेकिन आप तो कुछ बोलिए, कुछ तो मुंह खोलिए। उन 25 सांसदों से पूछिए, केन्द्र का बजट पेश किया था, 25 सांसद इस राजस्थान की मिट्टी के लिए, राजस्थान की धरा के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्या लेकर आये? जब संसद चल रही थी, एक ने भी उठकर आवाज नहीं उठाई कि हमारे राजस्थान के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जबकि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद, भाजपा को जिताकर केन्द्र में भेजा था। वहां एक भी सांसद राजस्थान की जनता के लिए नहीं बोल रहा है।

सभापति महोदय, जब परिवार का मुखिया कुछ न कुछ बांटता है, अपने सदस्यों की हर चाहत को पूरा करता है तो हमारी भी डिमांड बढ़ जाती है कि हमें जो मिला वह तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन जो वंचित रह गया, वह भी हमें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नोहर व भादरा के 28 गांव, जिनके चारों तरफ पानी पहुंच गया, लेकिन आज भी 28 गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। 2019 में मुख्य मंत्री जी ने डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की, 306 करोड़ रुपये की डीपीआर बनकर आई। मैं चाहता हूं कि रिप्लाई के समय नोहरवासियों को सौगात दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): नोहर में अम्बेडकर कन्या छात्रावास की काफी समय से मांग उठ रही है। हमारी बहनें सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए अम्बेडकर कन्या महाविद्यालय खोला जाए।

सूई ब्रांच, 2003 व 2004 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने कुठाराघात करते हुए सूई ब्रांच निर्माणाधीन थी, उसको वहीं रोक दिया था। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उसको भी पूरा किया जाए।

पल्लू क्षेत्र जो नोहर विधान सभा से 70 किलोमीटर दूर है और रावतसर तहसील मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है, जहां एईएन आफिस है, थाना है, वहां ब्रह्माणी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए।

एटा सिंगरासर के, विभिन्न तहसीलों के लोग जो आंदोलनरत थे, एटा सिंगरासर का भी निर्माण करवाया जाए।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं हमारे संविदाकर्मी हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनकी तरफ भी आप संवेदनशील रास्ता उठाते हुए, सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए, जो-जो भी भर्तियां वंचित हैं, उनको एक रास्ता दिखाएं। आज हमारे युवा एक तरफ तो बेरोजगार है, ओवर एज का डर है, दूसरी तरफ घर से पैसा लगाकर, जगह-जगह कोर्ट में घूम रहे हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, चाहे नर्सिंग 2013 भर्ती हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक की बात हो, जो-जो भी विसंगति है, उनको दूर करने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। 2-3 दिन से पक्ष-विपक्ष व निर्दलीय साथियों द्वारा इस बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। इस बजट में राजस्थान के मुखिया द्वारा हमारे विधान सभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला, उसके लिए हमारे क्षेत्र की तरफ से, हम सबकी तरफ से माननीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहते हैं। लंबे समय से उस इलाक़े से डिमांड थी कि कृषि प्रधान आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहां एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए, उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय खोला, उसके लिए भी धन्यवाद।

लंबे समय से हम सबकी एक मांग थी कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति का अलग से कानून बनाया जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान पैटर्न लागू किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से जो कानून बनाने का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जो यह अलग से कानून बनाने की व्यवस्था हुई है, इसमें मैं सुझाव देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में जो व्यवस्था है, वहां की सारी स्टडी करें और इसके बाद राजस्थान में अनूसूचित जाति और जनजाति के लिए एक मजबूत कानून बनाया जाए। केन्द्र और राज्य से जो बजट आ रहा है वह बजट वास्तविक धरातल पर पहुंचे, लोगों के हित में पहुंचे। शिक्षा व स्वास्थ्य पर इसका विशेष उपयोग हो क्योंकि आज तक जो होता आया है, सिर्फ कार्यालयों में उपयोग हुआ है, बड़े-बड़े शहरों में उपयोग हुआ है, बड़े-बड़े शहरों में जो सड़कें हैं, वहां उपयोग हुआ है। संविधान के अनुरूप जो बजट केन्द्र या राज्य से आता है, उसका उद्देश्य यह होता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में, टीएडी का उद्देश्य यह होता है कि आदिवासी लोगों का उद्धार किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका ध्यान रखा और अलग से राजस्थान पैटर्न लागू किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।

साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, इस देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले दो वर्षों से जो स्थिति बन रही है, हर भर्ती कोर्ट में जाकर अटक रही है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए,

(श्री राजकुमार रोत)

हम एग्जाम इस तरह करायें, हर बार एग्जाम हो रहे हैं, कहीं न कही लीकेज हो रहा है, कही न कहीं पेपर आउट हो रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, बेरोजगारी जिस हद तक मार रही है। अभी इस बजट में 50 हजार नई भर्ती की घोषणा हुई है। मैं सदन की ओर से आशा करूंगा इन बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। राजस्थान में स्केल एक से नौ तक भर्ती होती है, उसमें दो विज्ञप्ति जारी होती हैं। एक विज्ञप्ति सामान्य एरिया के लिए और दूसरी विज्ञप्ति शिड्यूल्ड एरिया के लिए। शिड्यूल्ड एरिया के साथ, चाहे उधर की सत्ता बैठी हो, इधर की सत्ता बैठी हो, हमेशा अन्याय हुआ है। आज उस इलाक़े में राष्ट्रपति महोदय द्वारा शिड्यूल्ड एरिया की वृद्धि हुई, उस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बड़ा इलाका है, उस इलाक़े को इसके बाद वाली जो भर्ती आयेगी, उन भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

2018 की शिक्षक भर्ती थी, लेवल फर्स्ट और टू में, वहां पर भी यही चीज हुई। सैकण्ड ग्रेड की भर्ती थी, वहां पर भी बच्चों के साथ कहीं न कही अन्याय हुआ। एलडीसी भर्ती में भी उस इलाक़े के बच्चों के साथ अन्याय हुआ। आज तक इस इलाक़े को गुमराह किया हुआ है। 2013 में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी हुई, उसको 2016 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। एज इट इज कुछ शब्द संशोधन करके 2016 में वापस जारी कर दी गई। उसका आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि वास्तविक आरक्षण किस तरह से मिलना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि संविधान में जो प्रावधान है, 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण है, वह आरक्षण शिड्यूल्ड एरिया में लागू किया जाए।

कांकरी डूंगरी घटना हुई, वह बेरोजगारी को लेकर हुई, भर्ती को लेकर हुई, नौकरी को लेकर हुई। क्यों हुई? क्योंकि 2018 से बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे। कई लोगों ने उनको लालच दिया, यह करा देंगे, वह करा देंगे, लड़कों को गुमराह किया गया और लास्ट में इस स्थिति की ओर बढ़े। इसलिए आपके माध्यम से मैं सदन को, सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड एरिया में 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण व्यवस्था है, वह आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए।

अभी हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसी का बंगला ले लिया, किसी का वहां खाली करा दिया तो डूंगरपुर ज़िले में

(श्री राजकुमार रोत)

हमारी जो स्थिति बनी, वहां राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो सिद्घांत है, वह सिद्घांत उन लोगों ने खो दिया। मैं तो आपके माध्यम से, इस सदन के

(18.00 बजे)

माध्यम से यह मांग करता हूं कि पक्ष वालों को और विपक्ष वालों को, वहां पर जो सिद्घांत विहीन पार्टियां बना दीं, दोनों पार्टियों का मिलन कर दिया, उन लोगों को, ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए क्योंकि पार्टियां इस देश को चला रही हैं। दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों की दोनों एकजुट हो गयीं। यही स्थिति आज भी बनी हुई है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से आगे की कड़ी में, हमारे इलाके में संत सुरमाल करके एक संत हुआ करते थे, उन्होंने पूरे आदिवासी समाज में जन जागरण किया। ये गोविन्द गुरू के पहले से थे तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है, उसमें उनकी जीवनी और उनके इतिहास को सम्मिलित किया जाए। डूंगरपुर जो शहर है वह राजा डूंगर बरण्डा के नाम से था, लेकिन आज उनका कहीं उल्लेख नहीं है तो मैं यह भी मांग करूंगा कि उनकी जो जीवनी है, उनका जो इतिहास है, वह राजस्थान के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सदन में एक मांग उठी थी। वह सदन स्टार्ट ही था, उसी समय न्यूज पेपर्स में छपा था कि झाड़ोल फलासिया से बच्चे गायब हुए, उधर घाटोल से बच्चे गिरवी रख दिये। यह घटना हुई, उस समय और पिछली बार जो सदन था, उस सदन में इस बात को लेकर बहुत हंगामे हुए। लेकिन आज एक साल गुजर गया, सरकार ने ऐसी कौनसी व्यवस्था की वहां पर? वे घटनाएं रुक गयीं क्या? जो गिरवी रखे जा रहे थे वे बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिये बाहर जा रहे थे, मैंने पिछली बार आंकड़ा निकलवाया। उदयपुर सम्भाग से 37296 बच्चे स्कूल से ड्राप आउट हुए। यह सरकार का रिकार्ड है। क्यों? उदयपुर पूरे सम्भाग से, ये 6 जिले, 6 जिलों में से 37296 बच्चों ने स्कूल से ड्राप आउट किया। इसमें सबसे अधिक उदयपुर जिला, 20945 बच्चों ने स्कूल से ड्राप आउट किया। वे बच्चे आज कहां हैं? किसी के पास, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। मान लो प्राइवेट स्कूल में गये होंगे, 50 प्रतिशत बच्चे गये होंगे। आज भी वह स्थिति बनी हुई है। इसका रीजन क्या है? कई रीजन हैं। इसका रीजन गरीबी

(श्री राजकुमार रोत)

है। इसके अलावा वहां जो भाषा है, जिस तरह से आज हम कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में है कि मातृ भाषा में स्टडी कराई जाए लेकिन किसी स्कूल में पहली से पांचवीं तक बच्चा पढ़ रहा है, किसी स्कूल में मातृ भाषा में स्टडी नहीं कराई जा रही है। बच्चे को वहां डराया जा रहा है। कोई भी अध्यापक हो, इंग्लिश बोल रहा है, हिन्दी बोल रहा है, तो वहां बच्चा कहीं न कहीं डर रहा है। आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करेंगे कि उदयपुर सम्भाग में हमारी जो मातृ भाषा बोली जाती है, भीली भाषा, उस भीली भाषा में बच्चों को अध्ययन कराया जाए क्योंकि वहां के एजुकेशन स्तर पर बढ़ा करने के लिये TAD के मार्फत मां-बाड़ियां चल रही हैं, आंगनबाड़ियां चल रही हैं लेकिन वे नाममात्र की चल रही हैं। वास्तविक एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, बच्चों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह कहीं न कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो ड्राप आउट की स्थिति बनी हुई है, इसको कहीं न कहीं कंट्रोल किया जाए।

एक बात यह चल रही है, लम्बे समय से डिमांड हो रही है कि सामान्य एरिये के बहुत सारे अध्यापक प्रथम ग्रेड से थर्ड ग्रेड हैं, एल.डी.सी. हैं, जो बाबू लगे हुए हैं, वे उदयपुर सम्भाग में लगे हुए हैं। वे लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे गृह जिले में भेज दिया जाए, लेकिन सरकार यह तर्क दे रही है कि वहां पर स्टाफ खाली हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कौन। दूसरी तरफ जो स्कूल में व्याख्याता हैं, कालेज में जो व्याख्याता हैं, उन लोगों को नियुक्ति के तीन दिन बाद ही डेपुटेशन पर कार्य-व्यवस्था में इधर लगाया जा रहा है। यह कौनसी दोहरी नीति है? पांचवीं पढ़ाने वाले, आठवीं तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, उनको इस बात के लिये रोका जा रहा है कि आप रुको, वहां पर कार्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उच्च शिक्षा में वहां के जो व्याख्याता लगे हुए हैं, उनको नियुक्ति के 3-4 दिन बाद ही यहां पर डेपुटेशन पर लगाया जा रहा है तो वे लोग लम्बे समय से मांग कर रहे हैं, उदयपुर सम्भाग में जो लगे हुए हैं, स्केल एक से नौ तक के जो कर्मचारी हैं, उनको उदयपुर जिले से बाहर किया जाए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): साथ ही, अभी जो बात चल रही थी, मेरे यहां एक सीमलवाड़ा कालेज है, यह 2016 में सेंक्शन हुआ था, अभी तक उसका भवन नहीं बना है। इधर से आरोप लगाते हैं कि हमारे कार्यकाल में यह

(श्री राजकुमार रोत)

हुआ, वह हुआ, उधर से आरोप लगाते हैं। दोनों की स्थिति सेम बनी हुई है। इधर से सेंक्शन हो रही है तो वे नहीं निकाल रहे हैं, उधर से सेंक्शन हो रही है तो ये नहीं निकाल रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि 2016 से जो सेंक्शन हुई है, उसके भवन का निर्माण कराया जाए।

सीमलवाड़ा में TAD के मार्फत एक बालिका छात्रावास संचालित हो रहा है। यह छात्रावास 2018 में विभाग ने नाकारा घोषित कर दिया। आज भी, विभाग ने कह दिया कि वह रहने लायक नहीं है, वह नाकारा है, कभी भी गिर सकता है, फिर भी बच्चियां, यह जो छात्रावास है, उसी में पढ़ रही हैं तो, माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि मंत्रीजी विशेष ध्यान देंगे और इस बजट में भी यह जो सामुदायिक दावे, फोरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो किये गये हैं, तो हमारे आदिवासी समाज के अन्दर जितने जो पूर्वज हुआ करते हैं, जो माताएं हैं, कुलदेवियां हैं, सारी की सारी फोरेस्ट विभाग में हैं, तो उनको सामुदायिक दावे के पट्टे के तहत उनके जाने के लिये रास्ता और वहां भवन के लिये व्यवस्था कराई जाए।

साथ ही लम्बे समय से एक डिमांड कर रहे हैं, 2013 में जो एल.डी.सी. लगे हुए हैं, उन लोगों को आज तक अपन ने सचिव का चार्ज दे रखा है और उन लोगों से काम करवाया है। नरेगा का काम वे लोग ही सम्भालते हैं। नरेगा के नाम से हम सब मिलकर मेज थपथपाते हैं, तो उन एल.डी.सी. लोगों को सचिव में कहीं न कहीं प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि लम्बे समय से वे उसका काम सम्भाल रहे हैं।

एक जलशक्ति योजना, अभी बजट घोषणा में भी बहुत सारी घोषणाएं हमारे घाटोल के लिये हुईं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, दो मिनट में मैं समाप्त कर लूंगा।

पिछले बजट में कडाणा बैक वाटर से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना के लिये डी.पी.आर. की घोषणा हुई थी, लेकिन इसमें टेक्निकल दिक्कत हुई कि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। कडाणा जो बांध बना हुआ है, वह बांध गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया और समझौता हुआ है। इसमें हम यह चाहेंगे कि समझौते के अनुरूप जिस दिन वार्ता होगी, हो जाएगी लेकिन गुजरात में जो कडाणा बांध बना हुआ है, उससे हमें 700 MCFT पानी की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं सालाना उससे क्रय किया जाए या माही नदी में

(श्री राजकुमार रोत)

जो पानी है, वह 10 TMC रिजर्व पड़ा रहता है, उसमें से एक या दो TMC यहां पर छोड़कर उसकी व्यवस्था कराई जाए।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर जो अभी स्थिति बनी हुई है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, एक मिनट, लास्ट में।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): लास्ट, एक मिनट में।

कानून-व्यवस्था के लिये अभी ये बता रहे थे कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हर कोई व्यक्ति जाए, वहां परिवाद से उसको जल्दी सुलटारा मिल जाएगा। अभी दो दिन पहले न्यूज पेपर में आया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 फरवरी के दिन व्यक्ति गायब हुआ और 24 फरवरी को उसकी लाश मिलती है। बिलकुल कंकाल है वह, उसको कोई पहचाना नहीं, उसके कपड़ों से पहचानने में आया। उसके परिजनों ने 14 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया है गुमशुदगी का, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके परिजन खुद जाकर CCTV की फुटेज लाकर प्रशासन को दिखा रहे हैं कि CCTV फुटेज में ये इस दिन यहां है लेकिन उस अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा। प्लीज, सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): और वास्तविक जो मुलजिम हैं उनको पकड़ा जाए। धन्यवाद। जोहार।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने का अवसर दिया, इस हेतु धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का यह तीसरा बजट है लेकिन विगत 2019-20 और 2020-21 के बजट में प्रदेश के बेरोजगार

(श्री गोपी चन्द मीणा)
युवाओं के लिये, किसानों के लिये सिर्फ मात्र छलावा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2019-20 के बजट में जिन कामों की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की पेयजल के सम्बन्ध में, सोलर पम्प एक भी नहीं लगा, कालेज के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की, लेकिन अभी भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत अवगत कराना चाहूंगा कि निरोगी राजस्थान की अवधारणा को धरातल पर उतारने हेतु 7 मेडिकल कालेज राजस्थान में सरकार ने खोले हैं, लेकिन पूर्ववर्ती वसुन्धरा सरकार के मेडिकल कालेजों में ही इन्होंने उसी में घोषणा करते हुए, जोड़ते हुए नर्सिंग कालेज खोला, जो थोथी घोषणा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाई-वे 148 जहाजपुर से निकल रहा है, भीलवाड़ा जिले से सौ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ट्रोमा सेंटर खोला जाए, वहां डाक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं। मेरे क्षेत्र में अमरगढ़, जो सड़क के अंतर्गत भी आता है और आये दिन घटनाएं होती रहती हैं, के सब-सेंटर को क्रमोन्नत किया जाए। सी.एच.सी. में, जहाजपुर में ही पी.एच.सी. स्वीकृत किया गया है लेकिन पूर्व में वहां जमीन आबंटित हो चुकी है, बजट आबंटन किया जाए। जहाजपुर में ही टिटोड़ी ग्राम में सब-सेंटर, धुवाला में सब-सेंटर भवन 3-4 साल से जर्जर अवस्था में हैं, वहां भवन के लिये राशि स्वीकृत की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेरे वहां जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़क है एम.डी.आर. 56, वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एम.डी.आर. 56 में मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा भी की लेकिन अभी तक कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। यह 14 किलोमीटर की सड़क है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अत: मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस सड़क के कार्यादेश की स्वीकृति जारी कराएं।

डी.एम.एफ.टी. फंड जो भीलवाड़ा जिले का है, हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे सरकार के समय के स्वीकृत काम इस सरकार ने निरस्त करने का काम किया और नये काम कोई भी स्वीकृत नहीं किये जबकि

(श्री गोपी चन्द मीणा)

हमारा पैसा, हमारे क्षेत्र का पैसा वहां पर खर्च होना चाहिए, वहां पर खर्च नहीं किया। 350 करोड़ रुपये भीलवाड़ा जिले से राज्य सरकार द्वारा राशि स्थानांतरित कर ली गयी। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति जारी कराएं।

माननीय सभापति महोदय, सड़क के लिए मैं मेरे क्षेत्र की बताना चाहता हूं, प्रमुख सड़कें हैं, जो गांव वंचित हैं- बड़ला से सवाईपुर सड़क, खेमा का खेड़ा से देवरी माताजी तक सड़क, मुख्य सड़क महादेव बाबा के स्थान से सोराम मास्टर का झोंपड़ा सड़क, भारत खेड़ा से जहाजपुर तक सड़क, बिजेठा से बिजेठी तक सड़क, एन.एच. 148 से वाया लक्ष्मणपुरा से बरोदा सड़क, बिन्ध्याभाटा से छाजेला खेड़ा वाया पांच का बाड़ा, आगरिया से आसोप कोटड़ी सड़क, मुख्य सड़क ग्राम देवा की झोंपड़िया पंचायत टीटोड़ा जागीर सड़क, गुढ़ा से देवपुरा सड़क। अत: मेरा अनुरोध है कि जिले की इन सड़कों को जोड़ने का प्रावधान किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। पूरे जिले में चम्बल पेयजल परियोजना का शुभारंभ हुए 12 वर्ष हो गये लेकिन जहाजपुर, माण्डलगढ़ बिलकुल नजदीक होते हुए भी अभी तक पेयजल के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वहां पर सरकार और अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक द्वेषता के कारण कार्य नहीं किया जा रहा है और जो कार्य किया जा रहा है वह भी सड़क को, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के बीच में लाइन डाली जा रही है, सड़क की पटरी पर लाइन डाली जा रही है, जिससे वह सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगी। गांव के अंदर सी.सी. सड़क को तोड़कर लाइन डाली जा रही है। मेरा अनुरोध है कि उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिए और तुरंत हमारे को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ काम बंद करने का काम किया है। भारत सरकार ने जनजाति मंत्रालय के माध्यम से हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय की घोषणा की थी और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं लागू की थीं लेकिन इस सरकार ने दो वर्ष पहले सत्ता में आते ही मेरे जहाजपुर का एक आदिम जनजाति संघ द्वारा संचालित

(श्री गोपी चन्द मीणा)

अनुदानित छात्रावास, राज्य सरकार एवं आदिम जनजाति संघ के अनुदान द्वारा संचालित छात्रावास चल रहा था, वह उप-खंड मुख्यालय जहाजपुर में 1958 से संचालित था। इस आवासीय छात्रावास को सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया। यह विद्यालय क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद कर दिया गया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अत: मेरा पुन: इस छात्रावास को संचालित किये जाने का आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि जहाजपुर में विगत तीन वर्षों से भी अधिक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय शाहपुरा कोर्ट से संचालित हो रहा है। शाहपुरा कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में लगभग 60 प्रतिशत प्रकरण जहाजपुर क्षेत्र के हैं तथा कार्य हेतु वांछित प्रकरणों से भी ज्यादा विचाराधीन हैं, इसलिए जहाजपुर में ए.डी.जे. कोर्ट को स्थायी कोर्ट में परिवर्तन कराये जाने हेतु उचित बजट राशि जारी कराएं।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर में कोटड़ी उपखंड मुख्यालय पर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन निर्माण के लिए बजट में राशि स्वीकृत की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सभी उपखंड मुख्यालयों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कालेज खोलने की घोषणा की है तो मैं कोटड़ी उपखंड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोटड़ी उपखंड मुख्यालय है, वहां पर नामांकन के आधार पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी खोला जाए, ताकि हमारे बच्चों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि जहाजपुर को, बीसलपुर के बैक-वाटर में हमारा पूरा एरिया आता है लेकिन हमारे किसानों को जल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरा यह अनुरोध है कि बीसलपुर का जल स्तर भी बढ़ेगा, बनास नदी पर एक एनिकट बनाया जाए, जिससे एनिकट के रिसाव से, सीपेज से जलस्तर बढ़ाया जा सके, एनिकट निर्माण किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री वीरेंदर सिंह।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के पर्यटन के सर्किट में सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): घाटारानी माताजी, चवंलेश्वर जैन मंदिर, गाडोली महादेव मंदिर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: सहयोग करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): इनको विकसित किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग की एक-दो मेरी समस्याएं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से पैसा मिल रहा है लेकिन राज्य सरकार की दुर्भावना, हमारे नेताओं की वजह से, वहां पर दुर्भावना से कुछ गांवों को हमारे उस सिस्टम में गांवों को छोड़ रखा है। मेरी प्रार्थना है कि उन गांवों को भी सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। हाल ही में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, सहयोग करें। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने जो बजट में मुझे बोलने का अवसर दिया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय वीरेंदरजी। समय की अपनी सीमा है। बार-बार आग्रह नहीं करना पड़े, जब मैं आपसे कह दूं तो प्लीज, आप मुझे सहयोग करें ताकि सारे माननीय सदस्य बोल सकें वरना बोल नहीं पाएंगे माननीय सदस्य। श्री वीरेंदर सिंह।

श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने जो बजट में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट, जिसमें केन्द्र सरकार की उदासीनता तथा जी.एस.टी. का पैसा भी समय पर राजस्थान को नहीं मिल रहा है और साथ ही कोरोना महामारी के कारण पूरे बारह महीने वित्तीय

(श्री वीरेंदर सिंह)

स्थिति बिलकुल पटरी से उतर गयी, इस सबके बावजूद इस वर्ष हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिपक्ष भी मात्र यही कह पा रहा है कि बजट धरातल पर कब उतरेगा? इसका साफ मतलब यही है कि एक शानदार बजट पेश किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, विशेष तौर से मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में अगले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है जो कि एक सराहनीय कार्य होगा। किसान समुदाय किसान बजट की वाहवाही कर रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र दांता रामगढ़ में इस वर्ष में जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं, दांता रामगढ़ की जनता की ओर से मैं मुख्य मंत्रीजी का अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूं।

दांता रामगढ़ क्षेत्रवासियों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वह पानी की थी। मेरे द्वारा चुनावी समय में इस समस्या को दूर करने का जनता से वादा किया था, उस समय से हजारों लोगों की यह उम्मीद थी कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारा यह काम आप पूरा करेंगे, तो उसी आशा और उम्मीद पर मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा और मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं अपितु नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, धोद और सीकर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को भी शामिल करके 7700 करोड़ रुपये की कुम्भाराम कैनाल परियोजना के नाम से जो घोषणा की, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक अभिनंदन और आभार।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी समस्या जो निरंतर चली आ रही थी और यह मांग थी कि कन्या महाविद्यालय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 12वीं तक की शिक्षा हेतु कई सरकारी और निजी विद्यालय हैं, जिनमें 12वीं तक की शिक्षा की कोई समस्या नहीं आती किंतु 12वीं के बाद जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो 70 से 80 किलोमीटर दूर झुंझुनूं जाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत बेटियों की होती है और अभिभावक कई कारणों से बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर देते थे, किंतु माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, उससे उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों और मेरी तरफ से मुख्य मंत्रीजी का बार-बार धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही में इस वर्तमान युग में गांव के

(श्री वीरेंदर सिंह)

बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। इस बार पांच हजार से ज्यादा आबादी के राजस्व गांवों में मुख्य मंत्रीजी ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। उस घोषणा में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई राजस्व गांव आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने से निश्चित ही अंग्रेजी पर गांव के विद्यार्थियों की पकड़ होगी, इस हेतु भी मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. रानोली और पी.एच.सी. धींगपुर में खोली गयी है, इससे निश्चित रूप से चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों में सम्बल प्रदान होगा।

मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये सड़कों के लिए अलग से देने की घोषणा की है, कृषि बिल में हजार रुपये सब्सिडी दी और पेयजल के लिए दस ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प दिये हैं। पलसाना से खाटू श्यामजी सड़क के लिए नवीनीकरण की घोषणा की है, इस हेतु मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बजट के दौरान कई बार दांता रामगढ़ का नाम लेकर दांता रामगढ़ का मान बढ़ाया है।

मुख्य मंत्री महोदय ने कोरोना काल के समय कर्मचारियों का 15 दिन का वेतन सरकार चलाने के लिए काटा था, आपके वित्तीय प्रबन्धन से आपने वापस सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन देने की घोषणा की है, उससे सरकारी कर्मचारी सरकार से काफी खुश हुए हैं। कोरोना के कारण पूरे 12 महीने में वित्तीय स्थिति पटरी से नीचे उतर आयी थी, उसके बावजूद नई भर्तियां निकाली हैं। युवा इससे काफी खुश हैं। लोग चर्चा करते थे कि सरकार चुनावी समय में नई भर्तियों की घोषणा करती है, लेकिन आपने कोरोना के संकट के बावजूद जो भर्तियों की घोषणा की है, वह बजट में जो पेश किया, वह काबिले तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारतवर्ष के दो बड़े धार्मिक स्थल आते हैं - खाटूश्याम जी और जीण माताजी। इनको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की है, इसके लिये उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि खाटूश्यामजी का मंदिर पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहां पर लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, मन में

(श्री वीरेंदर सिंह)

धार्मिक आस्था लेकर आते हैं परंतु वी.आई.पी. दर्शन के नाम पर लूटखसोट की जा रही है। लोग आस्था के साथ आते हैं परन्तु जाते समय लूटखसोट की भावना लेकर जाते हैं, जो बहुत दुख की बात है। माननीय सभापति महोदय, मंदिर में वी.आई.पी. दर्शन और दान द्वारा जो राशि एकत्रित होती है, उसमें भी बहुत बड़ा घपला सामने आया है। गत दिनों से समाचार पत्रों में आने से सामने आया है कि मंदिर में रखे दान-पात्र देवस्थान विभाग और मंदिर कमेटी द्वारा सील किये जाते हैं, परंतु 14 और 15 नंबर के दान-पात्रों में कोई सील नहीं पायी गयी तथा उनमें रखी धनराशि का कोई हिसाब नहीं है। इस हेतु मेरा अनुरोध है कि इस मामले में जल्दी ही कार्यवाही की जाए। मेले का समय शुरू हो गया है। मेरा अनुरोध है कि जांच के साथ ही जल्दी ही सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के मार्फत कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, जो आने वाले सम्पूर्ण दान का हिसाब रखें और इस लूट को रोका जा सके। मेरी मांग है कि इस मंदिर को राज्य सरकार के अधिग्रहण में लिया जाए तथा वर्तमान में होने वाले मंदिर विस्तार के समस्त कार्य सरकारी देखरेख में किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में चल रहे रिक्त पदों के कारण आमजन को विभागीय संबंधी कार्यों हेतु जो परेशानी उठानी पड़ती है, उन पदों को भरने हेतु निवेदन करना चाहूंगा। वर्तमान में तहसीलदार संवर्ग के 670 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 63 प्रतिशत वर्तमान में खाली हैं। इसका कारण नायब तहसीलदार पद से तहसीलदार पद पर पदोन्नति पांच वर्ष में होनी जरूरी है, जिसके कारण यह पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियम में संशोधन कर अनुभव को दो वर्ष किया जाए। वर्तमान में नायब तहसीलदार संवर्ग वर्ग में 1971 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 50 प्रतिशत वर्तमान में खाली हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा पदोन्नति पर रोक के कारण यह पद खाली रहे हैं। इन पदों को भर कर आमजन को राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजस्व मामलों के आधे मामले सीकर में जाते हैं, इसलिए अनुरोध है कि पलसाना में ए.सी.जे.एम. कार्यालय खोला जाए। शानदार बजट के लिये मुख्य मंत्री महोदय का बारम्बार अभिवादन और धन्यवाद। पुन: आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, 26 महीनों की सरकार ने यह तीसरा बजट पेश किया है। 2019-20 का बजट 10 फरवरी को, 2020-21 का बजट 20 फरवरी को और 2021-22 का बजट 24 फरवरी को पेश किया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों का जो बजट है उसमें मात्र 33 प्रतिशत ही जमीन पर उतरा है, चाहे वह सड़कों का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो। हर विभाग की 33 प्रतिशत से कम राशि जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सत्ता से निवेदन करूंगा कि चिकित्सा विभाग में बजट की जो रूपरेखा रखी है वह बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी दिशा तय नहीं है। नर्सिंग कालेज खोलने की घोषणा की है, लेकिन किसी प्रकार का बजट आबंटन नहीं किया गया है। अस्पतालों में क्या विस्तार होगा, यह भी तय नहीं है। परिवहन विभाग में कौनसे रूट पर गाड़ियां चलेंगी, यह भी बजट में बिलकुल भी नहीं दर्शाया गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। झूठ और लूट की सरकार है। इस सरकार में अपराधीकरण बहुत ज्यादा हुए हैं। पिछला जो जल स्वावलंबन अभियान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको आपने बंद कर दिया। स्टेट हाईवे की जो सड़कें हैं, उन पर जो टोल नाके थे, आपने उनको पुन: चालू कर दिया। दो साल से ग्राम पंचायत बजट के अभाव में जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। विकास के लिये जो पैसा है, उसको कब भेजेंगे, इस बात को लेकर सरपंच जिला मुख्यालय से 8 तारीख को आपके यहां आने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जो नाम उपखण्ड कार्यालय पर है, उसमें सबसे बड़ी उपेक्षा आदिवासी क्षेत्रों की की गयी है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के लिये बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। मारवाड़ संभाग को देख लीजिए, जहां ट्राइबल का भू-भाग है, उसमें 50 हजार युवाओं के लिये सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। चाहे वह ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, मंत्रालयिक कर्मचारी के समान पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और बजट में समग्र औद्योगिक विकास की भी बात कही गयी है। 64 नये उपखण्डों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, परंतु जनजाति क्षेत्रों को इससे वंचित रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पूरे देश में महाराणा प्रताप का गुणगान किया जाता है। उनके बताये मार्ग पर अपन

(श्री अमृतलाल मीणा)

चलते हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में चावंड एक ऐसा क्षेत्र है, जो अंतिम राजधानी भी रहा और जहां पर महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी, उस क्षेत्र के लिये इस बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं रखा गया है। चावंड आज भी अपने विकास की राह देख रहा है। जयसमंद से चावंड रोड के जीर्णोद्धार की बात कही गयी, हाड़ारानी की भूमि की बात कह रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि स्टेट हाईवे 32 - उदयपुर से सलूम्बर, पिछले दो साल से पी.डब्ल्यू.डी. और वन विभाग की लापरवाही के कारण, यह मेगा हाईवे रोड भी है, जो उदयपुर से बांसवाड़ा-रतलाम-इंदौर को जोड़ता है, वहां आज 15 किलोमीटर की एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वहां कार्य बंद पड़ा है। मैं चाहूंगा कि उस कार्य को पुनः चालू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक बड़ा निवेदन आपसे है, आप भी इस बात से परिचित होंगे इंटर डिस्काम में स्थानांतरण आज तक नहीं हुआ। 2000 में जब विद्युत बोर्ड से कम्पनियां बनीं, अजमेर डिस्काम, जयपुर डिस्काम, जोधपुर डिस्काम प्रसारण और वितरण की, इसमें जो भी कर्मचारी थे, कोई गंगानगर का होगा, कोई उदयपुर का होगा, बांसवाड़ा का होगा, वह आज भी स्थानांतरण होकर अपने गृह जिले में नहीं जा रहा है। अभी हमारे बीच में ऊर्जा मंत्रीजी भी नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी भी नहीं हैं, इसको ध्यान में रखकर उन अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जब डिस्काम बना, 2020 में उसकी समयावधि पूरी हो गयी। अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बारे में कोई किसी तरह का प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में 12 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिसमें सरकार द्वारा 47 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वह कार्य किस क्षेत्र में होगा? कहां इन परियोजनाओं को लागू किया जाना प्रस्तावित है? यह भी स्पष्ट नहीं है। केवल एक लालसा दिखाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार को आप अवश्य बतायें, संविदाकर्मी पूरे राजस्थान में परेशान हैं। दो साल से स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिये कल्ला साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और कमेटी ने सरकार को निर्णय भी दे दिया। इनमें विद्यार्थी मित्र भी हैं, पंचायत सहायक भी हैं, पैराटीचर्स भी हैं, लोक

(श्री अमृतलाल मीणा)

जुम्बिशकर्मी भी हैं, शिक्षाकर्मी भी हैं, विद्यालय सहायक भी हैं। ये करीब डेढ़ लाख के करीब संविदाकर्मी हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): बस दो मिनट।

आज सरकार के सामने जो बहुत बड़ी स्थिति है, जो जमीनी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर हैं, एएनएम हड़ताल पर हैं, बेरोजगार युवा भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मेरा यही निवेदन है कि सलूम्बर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां जिला चिकित्सालय खोलने के लिए आपने कहा था लेकिन अभी तक नहीं खोला। सलूम्बर में हमारी पेयजल की पचास साल पुरानी पाइप लाइन है, उसको चेंज किया जाए। सामुदायिक चिकित्सालय चावंड और जावद में खोला जाए। हमारे सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय भी खोला जाए।

इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भू-माफिया हुआ, बजरी माफिया हुआ, किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पाये, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाये, आयुष्मान भारत का नाम चेंज कर दिया। चोरी, डकैती, अपहरण अधिक हुए कानून व्यवस्था बिलकुल डगमगा गई और बिजली की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ-सौ बार बिजली ट्रिप होती है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में कमरे बिलकुल सही नहीं हैं। तो मेरा यही निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। एक यह भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार में, ऐसी सरकार अपन ने पहले कभी नहीं देखी जो प्रश्न लीक हो जाना, भर्तियां समय पर नहीं होना, बजटीय घोषणा 33 परसेंट नहीं हो और दागी अधिकारियों को पुनः सही जगह पोस्टिंग करना, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना, वी.सी.आर. बनाना...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती निर्मला सहरिया।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सही तरीके से किसानों को नहीं करना। यह सारा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने पेश किया, वह सराहनीय है। हर वर्ग, युवा, महिला, कर्मचारी, उद्योग आदि सभी, समान रूप से सबके लिए बजट बहुत अच्छा पेश किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जो हमारी सहरिया जाति की मांग थी, सौ दिवस के स्थान पर दो सौ दिवस किया जाए, उसके लिए भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं जो उन्होंने दो सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया।

मेरे क्षेत्र में जो मांगें थीं सड़क की, वह ब्रिज भी मुझे मिला। साथ ही परानिया और खुशियारा में आवासीय विद्यालय बारहवीं तक किया, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं।

मेरी किशनगंज विधान सभा में औद्योगिक क्षेत्र किशनगंज में खोलने की घोषणा की, इसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं तीन दिन से बार-बार एक ही बात सुन रही हूं कि क्या किया? हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबका सम्मान रखते हुए जो सराहनीय बजट दिया, विपक्ष वाले बार-बार एक ही बात कह रहे थे, क्योंकि जो बजट इन्होंने दिया इनको बोलने का अवसर ही नहीं है, ये इस बजट पर क्या बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है। इनकी आदत में आ गया है इनको झूठ बोलने की, झूठ का पुलिंदा बनाने की।

आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिस एरिया से, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं जीतकर आई हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली बार, 1994 से लेकर आज तक सहरिया जातियों को टी.ए.डी. के तहत जो आवास मिलते थे वह आवास पिछली सरकार ने बंद कर दिये, पी.एम. आवास में ले लिये। आप कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं कहती हूं कि कांग्रेस ने हमारे लिए वह किया है जो आज हम उन्हीं की वजह से यहां हैं। हमारा शोषण हुआ है। आज मैं उसी के लिए आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि जो सहरिया आवास बंद हुए थे, यहां पर टी.ए.डी. मंत्री भी विराजमान हैं, उनको वापस चालू करें

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

ताकि सहरिया भी पक्के मकानों में रह सकें। वे उन झोपड़ियों में निवास करते हैं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में चित्तौड़ सादड़ी से कुछ भील गये थे, उस टाइम में वहां पर तालाब बना था। या तो उन भीलों को यहां उदयपुर में ला दिया जाए या फिर उनके लिए मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, उनके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में भी उनको कोई प्रावधान नहीं मिलता। मेरा मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि या तो उनको उच्च नौकरी में या छोटी नौकरियों में लिया जाए। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में उनके लिए एक-एक होस्टल खोलने का प्रावधान रखा जाए। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं भीलों के लिए भी एक होस्टल की मांग रखती हूं।

मेरा एरिया सहरिया बहुल क्षेत्र होने के नाते सहरिया बालिकाएं बारां कालेज नहीं आ सकतीं इसलिए मैं कन्या महाविद्यालय की मांग करती हूं। मेरे लिए कन्या महाविद्यालय केलवाड़ा में खोला जाए।

साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में एक कृषि कालेज की भी मांग करती हूं क्योंकि हमारे एरिया की भी मांग है कि वहां कृषि कालेज खोला जाए।

मैं एक मांग और रखती हूं कि हमारे क्षेत्र में मेरे गांव परानिया में, जहां मैं रहती हूं, पी.एच.सी. से उसको सी.एच.सी. किया जाए ताकि वहां के आसपास के 20-25 गांव लगते हैं, उनको अधिक लाभ मिले। इसी के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2021-22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के बोलने के दौरान कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा आमजन के हितार्थ जो कदम उठाये गये या जिन-जिन लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया और एक लाइन बोलते हुए कि मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में हमारा संकल्प था कि कोई भी भूखा न सोये इस बात

(श्री संजय शर्मा)

का भी विशेष उल्लेख किया। इस बात को लेकर के विज्ञापन भी छापे गये। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी भारतवर्ष की जनता से आह्वान किया था कि कोई भी भूखा न सोये, इसके लिए हमको आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी भामाशाहों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, युवा साथियों को और जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने आगे बढ़ करके अपने-अपने क्षेत्र में कोई भी भूखा न सोये, उसकी चिंता ही नहीं की अपितु कार्य करके भी दिखाया। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने आह्वान तो किया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान सरकार की तरफ से अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र में कोई भी भूखा न सोये, उसके लिए कोई बजट का आबंटन किया है क्या? इसको लेकर जब मैंने प्रश्न लगाया और जब प्रश्न का जवाब आया, मेरा प्रश्न था कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राशन किट वितरण हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। जवाब आया, विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में राज्य सरकार द्वारा राशन किट वितरण हेतु राशि आबंटित नहीं की गई।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि सम्भवत: यह 200 विधान सभाओं में ही हुआ होगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी तो गांधीवादी छवि वाले व्यक्ति हैं, वह निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। उसके साथ-साथ जब अलवर में राशन किट का वितरण हो रहा था, हमारे माननीय सांसद महोदय ने यह मानकर कि किट का वितरण निष्पक्ष भाव से होगा, उन्होंने तमाम राशन किट तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय को सौंप दिये। जब वह राशन किट वितरित हुए तो पहली बात तो वह कचरा उठाने वाली गाड़ी में, जिसमें घर-घर जाकर कचरा उठाया जाता है, उनके माध्यम से राशन किट का वितरण हुआ। बालकनाथ जी के द्वारा दिये गये किट के नीचे 'कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ' का यह बैनर लगाकर शहर में किट बांटे गये। उस वक्त राजस्थान सरकार किस प्रकार के निष्पक्ष भाव से काम कर रही थी?

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं बात करूं 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में अलवर शहर के लिए, अलवर जिले के लिए चंबल अलवर परियोजना की घोषणा की थी। उसके निमित्त 4718 करोड़

(श्री संजय शर्मा)
की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की थी लेकिन आज दो, सवा दो वर्ष पूरे होते आये, इन सवा दो वर्षों में डीपीआर बनी, टैक्निकल स्वीकृति जारी हुई लेकिन उसके बाद वह चंबल परियोजना का काम कहां गया, यह किसी को पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, गर्मियां अभी शुरू ही हुई हैं लेकिन अलवर शहर में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है। अभी सवा साल पहले नगर परिषद् के चुनाव हुए थे। वार्ड नंबर 25 से एक निर्दलीय पार्षद लोचन यादव जी जीतकर आये थे और इस भाव से कि कांग्रेस की सरकार है, काम होंगे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि एक साल से उनके वार्ड में, विशेष रूप से तंवर कॉलोनी, राजाजी का बास, हरदेव विहार, लाल डिग्गी में पानी की समस्या है। 2 बार बोरिंग भी कराई, बोरिंग सूखी निकली। प्रशासन का यह कहना था कि उनके वार्ड में पानी की सप्लाई टंकी से जोड़कर की जाएगी लेकिन एक वर्ष तक कोई काम नहीं किया। आज बड़ा दु:खद विषय है कि वह पार्षद पिछले 3 दिन से पानी की समस्या को दूर करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसके साथ-साथ वार्ड नंबर 22, जिसमें लिसोड़ा का कुआ, सूर्य बास, गायत्री मंदिर रोड, वहां भी पिछले एक वर्ष से पानी की विशेष समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अलवर शहर में मेडिकल कालेज की सौगात दी गई थी। 2016 में यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने इसी मेडिकल कालेज के लिए अलवर शहर में भूमि का आबंटन कर दिया था। 2018 में यही मेडिकल कालेज आपके अपने सीकर जिले में चला गया था। 2019-20 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में घोषणा की गई कि केन्द्र सरकार की 60:40 स्कीम के तहत 325 करोड़ का बजट दे दिया गया है लेकिन आज तक यह मेडिकल कालेज अमलीजामा नहीं पहन पाया। यह मैं आपके बीच कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बानसूर, रामगढ़, मालाखेड़ा और रैणी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की बात की गई है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान हैं। हम उद्योग लगाने के लिए जमीन तो ले लेते हैं, उस किसान की जमीन

(श्री संजय शर्मा)

अधिकारपूर्वक ले लेते हैं लेकिन उद्योग लगने के बाद उस किसान के बेटे को उस फैक्टरी में घुसने की अनुमति नहीं होती है। कल ही मैं टीवी पर देख रहा था कि हरियाणा सरकार ने उद्योगों में 75 परसेंट आरक्षण केवल हरियाणा के उस किसान के बेटे के लिए लागू किया है जो कि उस उद्योग में काम कर सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आप उद्योग लगाइए, किसान की जमीन ले रहे हैं, लेकिन उस किसान के बेटे को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी जमीन पर लगने वाला जो उद्योग है, उसमें उसको रोजगार मिले।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर अलवर सहित 5 जिलों में नये उद्यान गुरु नानक जयंती पार्क की घोषणा की गई थी लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी गुरु नानक जयंती पार्क का कहीं अता-पता नहीं है।

इसी प्रकार से वर्ष 2019-20 में विकास पथ की घोषणा की गई थी। अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में एक विकास पथ बना है, 2 के प्रपोजल मांगे गये हैं, लेकिन अब तक तीसरा विकास पथ शुरू हो जाना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शीघ्रातिशीघ्र विकास पथ बनवाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी। अलवर शहर की जनता सहित राजस्थान के समस्त जिलों की, जयपुर की तो मैं बात करता नहीं, जनता क्लिनिक को लैंस लगाकर ढूंढ रही है।

इसके साथ-साथ आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 2019-20 में नंदी शाला स्थापित करने की घोषणा की गई थी, यह घोषणा भी अमलीजामा नहीं पहन पाई है।

माननीय सभापति महोदय, यह बातें मैं आपके और सदन के ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2021-22 में समस्त विधायकों के लिए 5 करोड़ की नोन पेचेबल व मिसिंग लिंक की घोषणा की गई है। नगर परिषद् क्षेत्र में 20 किलोमीटर की मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य की घोषणा की गई है।

यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो शालीमार योजना में सीवर

(श्री संजय शर्मा)

लाइन व एसटीपी निर्माण की घोषणा की गई है। वैशाली नगर से एमआईए तक फोर लेन सड़क के नाला निर्माण की घोषणा की गई है। शहर के बड़े हिस्से जो कि सीवरेज लाइन से दूर रहे हैं, उनमें भी इसकी घोषणा की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। हीराबास कालोनी में काली मोरी से 200 फीट बाई पास तक, रूपबास आरओबी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण के लिए 30 करोड़ की विशेष योजना दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से चाहे 2019-20 हो, चाहे 2020-21 हो, उस बजट घोषणा को भी अब तक अमलीजामा नहीं पहना पाए हैं, वह धरातल पर नहीं आ पाई है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये घोषणाएं सार्थक रूप से धरातल पर आ जाएंगी? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक ऐसी एजेंसी बनाएं जो मोनिटरिंग करें, जो काम शुरू नहीं हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अलवर बहुत बड़ा क्षेत्र है और लगभग 5 लाख से अधिक उसकी आबादी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अलवर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट में करें। जो शिशु वार्ड है, उसको शिशु चिकित्सालय के रूप में घोषणा करें। थानों की बहुत आवश्यकता है। अलवर शहर में 2 थाने, विशेष रूप से वैशाली नगर में और एक जो अखैपुरा चौकी है, उसको थाने के रूप में क्रमोन्नत करने की माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारा मत्स्य विश्वविद्यालय है, उसके साथ-साथ जो मिनी सचिवालय है, उसके कारण बहुत सारी सरकारी सम्पत्तियों को यूआईटी द्वारा बेचा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस मिनी सचिवालय के लिए, मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष बजट की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आपने मंडी शुल्क में कमी की, उसका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने कृषक कल्याण टैक्स में कटौती की, उसका भी स्वागत है। हमारा व्यापारी वर्ग जो विशेष रूप से मंडी में काम करता है, उसने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है कि मंडी

(श्री संजय शर्मा)

शुल्क 50 पैसे प्रति सैकड़े से वसूला जाए, तो उससे किसान को भी राहत मिलेगी और व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): उसके साथ-साथ पेट्रोल, डीजल में वैट की कमी आप करेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा के सीमावर्ती जिले जिससे मैं आता हूं, वहां के पेट्रोल पंप मालिकों को राहत मिलेगी। उसके साथ-साथ चूंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान की सरकार वसूल रही है, पेट्रोल-डीजल भी सस्ता होगा, आम जनता को भी राहत मिलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस शानदार व जानदार बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मेरे कुछ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हंस रहे हैं साथ में धन्यवाद भी दे रहे हैं, मिलकर जाकर धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे रहे हैं, पीठ पीछे बात करते हैं तब भी धन्यवाद दे रहे हैं पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। ये इनकी कौनसी मजबूरी है, वह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस बजट को सब वर्गों ने सराहा है। सब वर्गों के लिए बजट है, सब विधान सभा क्षेत्रों के बजट है, कोई विधान सभा क्षेत्र बचा हो तो मैं कह नहीं सकता, तमाम साथियों से बात हुई ...(व्यवधान) आपकी बच गई होगी, आपने नहीं दी होगी योजना, यह आपकी कमी है। आपने नहीं दी अपनी योजना, वरना कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं बचा, हर आदमी ने सराहा है। समाचार पत्र पढ़ें, चाहे टीवी चैनलों पर कोई बैठा, चाहे उसमें सामाजिक कार्यकर्ता बैठा, राजनीतिक कार्यकर्ता बैठा, राजनीतिक विशेषज्ञ बैठा, सबने इस बजट की तारीफ की कि यह सबसे शानदार बजट था। कोविड के कारण कोई सोच नहीं सकता था कि इतना शानदार बजट आयेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शानदार बजट लाकर, विकास की राह में यह नया मील का पत्थर साबित होगा, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोविड काल में काम हुआ, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री राजकुमार गौड़)

हमेशा समीक्षा करते रहे, हर आदमी को सुना, सफाई कर्मचारी से लेकर, मैम्बर आफ पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल के सदस्यों से, एमएलए से, एमपी से बात की, उसी का यह रिजल्ट है कि आज के इस कोरोना काल में हम काफी बचे हैं। आज फिर एक बार समस्या आ रही है। हम लोगों का कर्तव्य है हम सब लोग मिलकर इसको देखें कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए और कैसे आम आदमी की मदद की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, आपने नर्सिंग कालेज खोलने की घोषणा की। आपका संकल्प है कि 15 जिलों में मेडिकल कालेज बने, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने दो वर्ष पूर्व गंगानगर में सरकारी मेडिकल कालेज बनाने की स्वीकृति दी थी, घोषणा की थी, उसका टेंडर पास हो गया है, 18 तारीख को टेंडर लग रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इसी महीने गंगानगर आकर मेडिकल कालेज की नींव रखिये, जिससे भवन निर्माण हो और गंगानगर को जो मेडिकल कालेज दिया है, वह गंगानगर की जनता हमेशा याद रखेगी।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए यहां तमाम बातें की गईं। मेरे साथी भी कहते हैं कि हमने किसानों की मदद की, किसानों की कौन मदद कर रहा है, आज सब लोग देख रहे हैं। जो तीन काले कानून बनाये हैं, मेरे एक बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे जिले के हैं, वे बोल रहे थे कि किसान बताएं कि कौनसे बिन्दु को हटाएं। यह बिन्दु आपने जो लगा दिया, उसी पर तो बिन्दी लग गई। किस बिन्दु को हटाने की बात कर रहे हैं? आप तीन काले कानून लाये, इन तीनों काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा। आज आपको चिंता नहीं है। आज गुरूर में हैं, आज आप बहुत घमंड में हैं। वे कह रहे थे कि मुझे बताएं। लगता है कि मोदीजी ने अपना अधिकार उस साथी को दे दिया। आप जाइए, अपने जिले में जाकर किसानों से बात कीजिए, किसानों से बैठकर बात करेंगे तो आपको मालूम लगेगा कि कौनसे कानून किसानों के पक्ष में है और कौनसे किसानों को नुकसान दे रहे हैं, यह समय बताएगा आपको। आज तो गरीब आदमी, किसान और मजदूर सड़कों पर बैठे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसका मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि यह हाउस बिल पास करे, हाउस एक बार फिर निवेदन कर ले प्रधान मंत्रीजी से कि इन काले कानूनों को वापस लीजिए और लोगों की जान को बचा लीजिए।

(श्री राजकुमार गौड़)

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए सरकार ने जो अलग-अलग फायदे की बातें कीं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि समय 7.00 बज रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत के मामले में सरकार ने जो निर्णय किया है कि किसानों पर बिजली का नया पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बिजली के जितने भी बिल आ रहे हैं, आज भी गरीब आदमी इनसे दु:खी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो आप सुविधा दे रहे हैं वह सुविधा आप गरीब आदमियों को भी दीजिए। जो ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां बनाई हैं, चाहे जोधपुर डिस्काम की बात करें, जयपुर डिस्काम की बात करें, अजमेर डिस्काम की बात करें, उत्पादन और प्रसारण की बात करें, इनके माध्यम से खर्चे बढ़े ही हैं। इन आफिसों पर खर्चे बढ़े ही हैं, उन खर्चों का बोझ आम आदमी पर, सामान्य आदमी पर और गरीब पर पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि एक ऐसी कमेटी बनाए, वह कमेटी निर्णय करे और पूरे राजस्थान में यह देखे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी कमेटी बनाए और पूरे राजस्थान के अलग -अलग जिलों से, अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों से बिल मंगवाकर उसकी समीक्षा करे, आखिर क्या कारण है कि हर जगह इसकी क्यों शिकायत आ रही है, इन शिकायतों को दूर करना बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने किसानों के लिए सोलर बिजली

(श्री राजकुमार गौड़)

के 50 हजार से ज्यादा कनेक्शनों की सुविधा की बात की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 और 2013 के बीच में सोलर पर काफी अनुदान था, डिग्गियों पर काफी अनुदान था, पिछली सरकार ने उन अनुदानों को काफी कम कर दिया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे वह डिग्गियों की बात हो, चाहे सोलर की बात हो, उन पर अनुदान बढ़ाया जाए, जिससे आम गरीब किसान को मदद मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। यहां कृषि मंत्रीजी बैठे हैं माननीय कटारिया साहब, 2018 में सरकार ने जाते-जाते डिग्गियां बनाने के लिए किसानों को बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के कह दिया कि डिग्गियां बना लो। आपको मालूम है कि उन डिग्गियों के पैसों का अनुदान उन किसानों को नहीं मिला है। मेरे यहां भी 182 करोड़ था 2018 में, उसमें से 42 करोड़ रुपये अभी भी देना बाकी है। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार ने अपना अनुदान का हिस्सा दे दिया लेकिन केन्द्र सरकार से जो हिस्सा आने वाला है, मेरे साथी जो यहां बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके 25 मैम्बर आफ पार्लियामेंट दिल्ली में बैठे हैं, उनको कहिये कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए डिग्गियों का जो अनुदान नहीं मिल रहा है, केन्द्र सरकार का हिस्सा नहीं आ रहा है, वे केन्द्र सरकार से हिस्सा दिलायें, जिससे हम किसानों को उनके अनुदान का पैसा दे सकें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो फीडर ठीक होना है, राजस्थान और पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार में भी सहमति बन गई है परंतु पंजाब सरकार बंदी लेना चाहती है, अगर वह बंदी लेगी तो हमारे यहां का किसान उजड़ जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से बात करें और इस तरह की व्यवस्था करें कि बीकानेर कैनाल जो लम्बे समय से साफ नहीं हुई, एक साल पहले राजस्थान सरकार ने 98 लाख रुपये पंजाब सरकार को दिये थे, पंजाब सरकार किन्हीं राजनीतिक कारणों से उसको नहीं साफ करवा पाई, तो उसको रिपेयर करने से पहले बीकानेर कैनाल को साफ कर गंग कैनाल में बीकानेर कैनाल के माध्यम से पानी दिया जाए, तो उससे किसान को फायदा होगा। आज आवश्यकता है कि पानी पूरा मिले। डैम में कम पानी की बात है, उस बात को हम समझते हैं,

(श्री राजकुमार गौड़)

परंतु आज फसल पकने वाली है, मार्च का जो महीना है उसमें कोई भी कैनाल हो, चाहे गंग कैनाल की बात हो, भाखड़ा की बात हो, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें, इनमें आवश्यकता है कि हमारी यह फसल पक जाए और हमारे प्रभारी मंत्री कल्ला साहब गंगानगर पधारे थे, आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिये थे कि हर हालत में फसल पकनी चाहिए तो मैं फिर कहना चाहूंगा सरकार को कि इस तरफ विशेष ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, कृषि संकाय खोलने की बात की गई, 600 विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की बात की गई। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा। मेरे पूर्व साथी ने बोला, मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथी कहते हैं कि बजट तो काल्पनिक है, बजट में घोषणाएं होती हैं, काम नहीं होते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज, गंगानगर की घोषणा हुई, वहां मेडिकल कालेज बनने जा रहा है। कृषि महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 13 मार्च, 2020 को की थी, उसके बाद कोविड शुरू हो गया, उसके बाद भी बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि नवम्बर माह में गंगानगर में 1962 से जो डिमांड थी कृषि महाविद्यालय की, वह 1962 की डिमांड अब जाकर नवम्बर, 2020 में पूरी हुई और 2020 में कृषि महाविद्यालय गंगानगर में शुरू हो गया, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। 60 सीटों के साथ शुरू हुआ, वाइस चांसलर ने कहा कि हम अगले साल आपको 60 सीटें और देना चाह रहे हैं, यह इस सरकार की नीति है। यह नीति है, केवल आप यह कहकर कि ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कहकर आप भ्रमित मत करिये, समाज को भ्रमित मत कीजिये, सदन को भ्रमित मत कीजिये, बाहर बैठी जनता है उसको भ्रमित करने की कोशिश नहीं करें। जनता बहुत कुछ जानती है, जनता सब बातों को समझती है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोले गये, स्कूल क्रमोन्नत किए गये, उसके लिए भी मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर के लिए मेरी डिमांड है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर बनायी जाए और उसके लिए बजट पास किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं पेट्रोल-डीजल और गैस पर बात करना चाहूंगा। मेरे साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रधान मंत्रीजी से बात कीजिये, हद

(श्री राजकुमार गौड़)

पार कर चुकी है। जब 15 पैसे गैस सिलेण्डर पर बढ़ते थे, 15 पैसे पेट्रोल, डीजल पर बढ़ते थे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातों का हल्ला मचाया करते थे। आज लोग दु:खी हैं, आज लोग परेशान हैं। गंगानगर में 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। गैस के रेट पहली बार हुए होंगे हिन्दुस्तान में आजादी के बाद कि 2 माह में 200 रुपये गैस के सिलेण्डर के बढ़ गये। इस गैस को आप उज्ज्वला कहकर कहते थे कि प्रधान मंत्रीजी ने बहुत बड़ी सुविधा दी है वह गरीब आदमी आज अपना माथा पीट रहा है। गरीब आदमी सोच रहा है कि उस सिलेण्डर का मैं क्या करूं? वह लकड़ी चुनकर लाता था, उससे भोजन तो बनाता था अपने बच्चों के लिए, आपने उसको सिलेण्डर दे दिया, आज वह खाली सिलेण्डर पड़ा है, आज कोई भी गरीब आदमी 1600 रुपये से दो सिलेण्डर नहीं भरवा सकता। सर, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी, केन्द्र सरकार से बात करें जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

(19.00 बजे)

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): पैट्रोल और डीजल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से वैट और एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है सर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखें, कौन-कौनसे जिले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगते हैं, वहां बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। गंगानगर भी उनमें से एक है। आप एक बार इसे कम करके देखिए। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। रेट घटाने से, टैक्स घटाने से लोग ज्यादा डीजल-पेट्रोल यहीं से खरीदेंगे, पंजाब और हरियाणा में भरवाने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आप कम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज सहयोग करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, हनुमानगढ़ में हमारा एक डिपो था जिसे भारत सरकार ने बंद कर दिया। अगर वह डिपो वापस शुरू हो जाए तो कम से कम 3 रुपये लीटर का हमें फायदा हो सकता है।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ई.डब्ल्यू.एस. में 10 परसेंट का रिजर्वेशन दिया मुख्य मंत्री जी ने, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद, परंतु हम चाहते हैं कि आरक्षण में दूसरे लोगों

(श्री राजकुमार गौड़)

को जो सुविधा मिलती है, चाहे वह आयु की सुविधा हो या फीस की, वह ई.डब्ल्यू.एस. के लोगों को भी दी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, प्लीज, दो पाइंट। एक मैं यह कहना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कालेज के काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 11 इंजीनियरिंग कालेज में सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके लिए बजट की सुविधा की जाए। लोगों की एक डिमाण्ड है।

विप्र समाज के लोगों की डिमाण्ड है कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। यह भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बजट भाषण की शुरुआत करने से पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेक इन इण्डिया पर जो सवाल किया था कि मेक इन इण्डिया क्या है और कहां गया, उसका जवाब देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 9 माननीय सदस्यों को बोलना है और माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि सही 8 बजे सदन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी, इसलिए आप मेहरबानी करके इधर-उधर जाने की बजाय सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में आप चर्चा कर लें। मैं आपको सही 7 मिनट में बैठा दूंगा। प्लीज सहयोग करें वरना बाकी के माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे। उनके सवाल का जवाब तो बाद में भी देते रहियेगा।

श्री छगनसिंह (आहोर): मेक इन इण्डिया आत्मनिर्भर भारत पर लागू होता है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब भारत में वस्तुएं बनेंगी और स्किल डवलपमेंट होगा। मेक इन इण्डिया हो जाएगा तो आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

मैं आपसे यह भी कहूंगा कि शेर-ओ-शायरी से प्रदेश की सियासत नहीं चलती, काम करने से चलती है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक बजट है तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं यह ऐतिहासिक बजट इतिहास बनकर न रह जाए और

(श्री छगनसिंह)

इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में की गयी गलतियां पुन: दोहरायी न जाएं। यह ऐतिहासिक बने, इसके लिए यह किस तरह से लागू हो, यह आपको कल्पना करनी है।

सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने इस बजट का पक्ष लिया है, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करके छोटी-छोटी व्यवस्थाओं पर बात करना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन योजना है, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और विशेष योग्यजन को जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन में जो बुजुर्ग होते हैं, उनके अंगूठे के निशान या रेटीना काम नहीं करते तो उनका आधार कार्ड नहीं बनता है और वह नहीं बनने से उनकी पेंशन नहीं आ रही है। जिस प्रकार से आधार कार्ड में भारत सरकार ने एक लाइबिलिटी दी हुई है, 24 अक्टूबर, 2017 को एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि - provided that if an Aadhaar card number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of subsidy, benefit or service. इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आधार कार्ड के अलावा पेंशन के लिए जो गरीब भाई हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। उनके अंगूठे के निशान और रेटीना काम नहीं कर रहे हैं तो वे तीसरा आप्शन आई-कार्ड के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि वे भी पेंशन व्यवस्था में आ जाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 8 केस हैं, जो मेरे ध्यान में आये हैं। रोडला के जीवाराम भील, जिनकी पेंशन पांच साल से बंद है। कारण मात्र यह है कि आधार कार्ड नहीं बन पाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आधार कार्ड नहीं होकर कोई तीसरा आप्शन, जैसे- आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी अन्य कार्ड में उनका नाम जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, नशा मुक्ति की बात होती है। मैं बात करूंगा एक बड़े सम्मेलन की। आसोतरा में राजपुरोहित समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। गादीपति तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में दिव्य अशीष खेताराम जी के आशीर्वाद से वेदान्ताचार्य डा. ध्यानाराम जी ने एक महासम्मेलन किया। उसमें एक प्रावधान किया कि पूरे समाज में नशा मुक्ति के लिए कहीं पर भी अफीम, बीड़ी, सिगरेट शादी, गमी में किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लाना है। पूरे समाज ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद भूरि-भूरि प्रशंसा भी हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो बड़ा निर्णय हुआ है उसमें सरकार भी सहयोग करे।

(श्री छगनसिंह)
सहयोग कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल को खेताराम जी महाराज के जन्मोत्सव पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा करें जिससे पूरी 36 कौमों में मैसेज जाए कि नशा मुक्ति के लिए जो इस समाज ने काम किया था, उसके लिए राजस्थान सरकार ने ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की है।

इसी प्रकार से सभी माननीय सदस्य चर्चा करते हैं रावणा राजपूत समाज की। रावणा राजपूत समाज रियासतकाल में दारोगा, वजीर, हुजूरी नाम से जाने जाते थे।

श्री सभापति: दो मिनट में कनक्लूड करें आप।

श्री छगनसिंह (आहोर): अभी तो दो ही मिनट हुए हैं। हुजूरी वजीर, दारोगा जैसे शब्द राजस्व रिकार्ड में आ गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गजट नोटिफिकेशन निकालकर इस समाज को भी, जो इनके दिल आहत होते हैं कि हमारे जो रियासतकाल में नाम थे, उस समय वे सम्मानजनक शब्द कहे जाते थे, लेकिन अब उन शब्दों का दुरुपयोग होने लगा है तो गजट नोटिफिकेशन द्वारा इन तीनों शब्दों को विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड में सिर्फ रावणा राजपूत समाज लिखा जाए। यह इस समाज के लिए बड़े गर्व की बात होगी और राजस्थान सरकार की भी इसमें कहीं न कहीं अच्छाई साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपीपी मोड पर दो पीएचसी हैं, वहां पर डाक्टर भी नहीं हैं और जितने भी सब-सेंटर हैं, पीपीपी मोड पर होने के कारण सरकार का उन पर ध्यान नहीं होता। कम से कम 15 -20 गांवों में पीपीपी मोड पर पीएचसी हैं, उन्होंने स्टे ले रखा है। सरकार से निवेदन करूंगा कि लड़ाई लड़कर पुन: उन्हें पीपीपी मोड से हटाकर तुरंत गवर्नमेंट में लाकर दोनों भवरानी और घाणा हास्पिटल को पीएचसी को पुन: सरकार के अधीन करें, जिससे वहां पर रहवासी करीब एक लाख जनता को सुविधा मिले।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो आहोर विधान सभा क्षेत्र में दूर-दूर तक कहीं पर भी पीएचसी नहीं है, जैसे- नोरवा में, शंखवाली में, ऊण में, पावटा में, तो उनमें से किसी एक जगह पर इस बजट में पीएचसी की घोषणा करें।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्री छगनसिंह (आहोर): सर, अभी तो दो ही मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): समाप्त ही कर रहा हूं, सर। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि आहोर उप-खण्ड में 139 गांवों का उप-खण्ड है। वहां पर मुन्सिफ कोर्ट की...

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। विराजिए। श्रीमती संतोष। अंकित नहीं होगा।

श्री छगनसिंह (आहोर): 000

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजट 2021-22 पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार के इस बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है। यह बजट केवल घोषणाओं पर आधारित लग रहा है। इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ को कुछ भी विशेष नहीं दिया गया है। सरकार बार-बार किसान हित की बात कर रही है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि मेरा गंगानगर जिला कृषि प्रधान है और मेरे क्षेत्र की मुख्य मांग है, सिंचाई के लिए पानी। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी समय पर नहीं मिले तो उसके लिए सब व्यर्थ हो जाता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों की खड़ी गेहूं व चने की फसलें सिंचाई के पानी के अभाव में सूख रही हैं। यदि सरकार किसानों के हित की बात करे तो किसानों के लिए समय पर सिंचाई पानी व बिजली, दोनों की व्यवस्था करवाये। किसान ऋण के जाल में तभी फंसता है जब उसकी खड़ी फसल पानी व बिजली के अभाव में जल रही होती है क्योंकि इस बार मावठ भी नहीं हुई है और मानसून भी अच्छा नहीं रहा है तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सरकार को सही हालात नहीं बताते हैं इसलिए किसान धरना-प्रदर्शन को मजबूर होते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों को फसल पकाव के लिए सिंचाई के पानी की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र घड़साना, रावला, नाहरावाली 365, अनूपगढ़ और रामसिंहपुर के कई किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर एक मार्च से सिंचाई विभाग के एक्स.ईएन. कार्यालय, विजयनगर के आगे धरने पर बैठे हैं। यदि समय रहते सिंचाई पानी का समाधान नहीं किया तो रावला-घड़साना आंदोलन जैसी स्थिति दोबारा होने वाली है। मेरी सरकार से मांग है कि किसान भाइयों के हित को ध्यान में

(श्रीमती संतोष)

रखते हुए सिंचाई पानी दिया जाए जिससे किसानों की फसलों का पकाव हो सके।

रोजड़ी माइनर के किसानों की बारियां भी पिट गई हैं, उनको भी सिंचाई पानी नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, एक पानी के अभाव में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी इसलिए इस ओर सरकार शीघ्र ध्यान दे।

सभापति महोदय, पिछले बजट में कस्टम हायरिंग सेंटर व नन्दीशाला खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अनूपगढ़ क्षेत्र में इनमें से कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ग्राम पंचायत 22ए के ग्राम 18ए में पशुपालन विभाग के नाम मुरब्बा नम्बर 306/447 भूमि आबंटित है, इसमें नन्दीशाला खोली जाए जिससे गोवंश का भला हो सके।

सभापति महोदय, जल संरक्षण हेतु डिग्गी निर्माण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के काश्तकारों ने डिग्गियां तो कर्जा लेकर बना ली थीं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा तय अनुदान राशि नहीं दी गई है। गंगानगर जिले की 2231 डिग्गियों का अनुदान शेष है, वह अनुदान राशि अतिशीघ्र दी जाए, जिससे किसान भाइयों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत 22 आरजेडी के आनन्दगढ़ में 33 केवी जीएसएस की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ में बिजली विभाग के एक्स.ईएन. का पद भी काफी समय से खाली है, उसको भरा जाए। मेरे क्षेत्र की काफी ढाणियां आज भी विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं, इनमें विद्युत कनेक्शन के लिए कोई कार्ययोजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है, जिससे ढाणियों में रह रहे लोगों को बिजली मिल सके। वाटर वर्क्स में विद्युत की सप्लाई दिन में दी जानी चाहिए जिससे गलियों में व्यर्थ पानी न बहे।

सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2019 से एफआईआर निर्बाध रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित किये जाने की घोषणा की गई है। मेरे क्षेत्र के पुलिस थाना रावला की एक घटना मैं सदन में बता रही हूं। एक महिला ने दिनांक 17.02.2021 को थाने में उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थानाधिकारी ने महिला को कहा कि आपका

(श्रीमती संतोष)

मुकदमा पदमपुर थाने में दर्ज होगा। पदमपुर थानाधिकारी के मोबाइल नम्बर व अपना नाम लिखकर एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी और उसे बाहर निकाल दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): फिर महिला डीवाईएसपी कार्यालय, अनूपगढ़ पहुंची परन्तु न्याय नहीं मिला। फिर वह महिला वकील के माध्यम से मुंसिफ कोर्ट, घड़साना में पेश हुई और जज साहब ने रावला थाने के पैरोकार को बुलाया व मुकदमा दर्ज करने को कहा। फिर महिला वापस रावला थाने में प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुई परन्तु फिर भी रावला थानाधिकारी ने उस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज न कर दोबारा प्रार्थना पत्र लिखवाकर मुकदमा दर्ज करवाया। महिला को एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कितने चक्कर लगवाने पड़े, यह उसको पता है, ऐसा हाल है मेरे प्रदेश का। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगी पुलिस विभाग के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को जो 24 घंटे की सख्त ड्यूटी करते हैं और जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं लेकिन चन्द अधिकारियों की वजह से विभाग बदनाम हो जाता है।

सभापति महोदय, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करती है। मेरा मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार की जड़ों तक नहीं पहुंचा जाता तब तक ऐसे मामले होते रहेंगे। ऐसी ही एक घटना मेरे जिले के पुलिस थाना जवाहरनगर की है। एक सिपाही +++ 10 लाख रुपये की घूस लेते पकड़ा गया। जयपुर एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि इससे पूर्व भी वह सिपाही 16 लाख की घूस ले चुका था। इतनी बड़ी राशि लेने की हैसियत एक सिपाही नहीं रखता क्योंकि इसमें जिले के उच्च अधिकारियों व पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों को गम्भीर मानते हुए जांच होनी चाहिए जिससे राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगे।

श्री सभापति: यह नाम अंकित नहीं करेंगे इसमें आप।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, सरकार ने किसानों को खातेदारी देने का अभियान चला रखा है लेकिन मेरे क्षेत्र की अनूपगढ़ तहसील के पटवारी, गिरदावर और टीआरए गलत रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं जिसके कारण किसानों को खातेदारी नहीं मिल पा रही है और किसानों में आक्रोश है। सरकार

(श्रीमती संतोष)

इस विषय को गंभीर मानते हुए तत्काल दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही कर किसानों को राहत दी जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अशोक डोगरा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, अनूपगढ़ शहर में आईएसडीपी, सीवरेज परियोजना 5.8.2010 को स्वीकृत की गई थी, जिसमें 7 करोड़ 61 लाख 84 हजार रुपये की थी। इसका कार्यादेश......

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज सहयोग करें। विराजिये। श्री अशोक डोगरा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): नई दिल्ली को दिया गया था।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): धन्यवाद साहब।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, पिछली बार 2020-21 का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 फरवरी को इसी सदन में पेश किया था, जिसमें मैं जिस जिले बूंदी जिले से आता हूं, वहां के लिए 5 घोषणाएं थीं, जो मैं पढ़कर सुना देता हूं, जिनमें किसी भी घोषणा में एक नया पैसा भी नहीं आया। पहली घोषणा तो यह थी पेज नम्बर 31 पर - 'वर्ष 2019-20 में चम्बल भीलवाड़ा के आरोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडोली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु घोषित की गयी डीपीआर बन गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 970 करोड़ रुपये की इस परियोजना को शुरू कर बूंदी जिले के 286 गांवों, 287 ढाणियों एवं नैनवां कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाये।' इसमें एक रुपया भी नहीं आया है, टेंडर भी नहीं हुआ है, काम होना तो बहुत दूर की बात है।

अब दूसरी बात ले लो। दूसरी घोषणा थी पीडब्ल्यूडी की। मुख्य मंत्री जी ने पेज नम्बर 36 पर यह कहा - 'बूंदी-अलोद-मेण्डी सड़क जिला बूंदी, 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी।' एक रुपया भी नहीं आया और इसी की इस साल वापस घोषणा हो गई पेज नम्बर 47 पर - 'बूंदी-दलेलपुरा-अलोद-मेण्डी सड़क बनाई जाएगी।' इसमें राशि हटा दी जो पहले 20 करोड़ थी।

अब तीसरी घोषणा बता देता हूं। इन्होंने कहा- गुरु नानक देव की 505वीं जयंती के उपलक्ष में पांच जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, अलवर,

(श्री अशोक डोगरा)

बूंदी में गुरुद्वारा प्रबन्धन समिति के सहयोग से नये उद्यान गुरुनानक जयंती पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें इतना पैसा लगेगा।' एक भी पार्क क्या, कोई जगह भी इसके लिए चिह्नित नहीं की।

चौथी घोषणा थी- 'प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में...' इसमें दो-चार जिलों का नाम है जिसमें बूंदी भी है, '22 मार्गों का पुनरुद्धार कराया जाएगा और इसके लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।' इसमें भी एक नया पैसा नहीं लगाया। मतलब यह पूरा झूठ का पुलिंदा हो गया और इसमें कहीं कोई कुछ भी काम नहीं हुआ और इस साल वापस इतनी सारी घोषणाएं कर दीं, जिनमें पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने असत्य बोलकर इस सदन का अपमान किया।

इतने से सालों में एक लाख 49 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बना दिया। दस दिनों में किसानों को सम्पूर्ण कर्जे की माफी का झांसा देकर सरकार सत्ता में आई पर किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों की बाजरे और मक्के की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी और किसान आधी रेट पर फसल बेचने को मजबूर हुए। बेरोजगारों को 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहकर मात्र एक लाख समथिंग को दे रहे हैं और बाकी सब बेरोजगार परेशान हो रहे हैं।

अब आपका राज कैसा चल रहा है, उसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक डाबी उप तहसील है, वहां 14 पंचायतें हैं और उनमें सैण्ड स्टोन निकलता है, माइनिंग एरिया है। उसके बिलकुल लगा हुआ भीलवाड़ा जिले का बिजौलिया उपखण्ड है, वहां भी पत्थर निकलता है, दोनों एरिया जुड़े हुए हैं। मेरे एरिया को बरड़ क्षेत्र कहते हैं। बरड़ क्षेत्र सहित समीप के लगे भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया खनन क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। डाबी उप तहसील के ग्राम काली घाटी, बड़पू, पराणा, बुधपुरा, गणेशपुरा, राजपुरा, भवानीपुरा, कंवरपुरा, धनेश्वर, थड़ी, छांटखेड़ा, नरौली सहित सभी स्थानों पर अवैध खनन चल रहा है। डाबी उप तहसील के समूचे खनन क्षेत्र में कहीं वन क्षेत्र में तो कहीं राजस्व की भूमि पर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन सिर्फ डाबी ही नहीं, भीलवाड़ा के बिजौलिया में भी है। इस खनन को देखकर लगता है बिलकुल ठेकेदारों को क्लीयर कह दिया कि तू बिना पर्ची काटे रायल्टी जमा कर ले और

(श्री अशोक डोगरा)

ले जा और इससे पूरी तरह से अवैध खनन करने वालों की पौ-बारह हो रही है। इस अवैध खननकर्ता को सरकारी संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते इन पर किसी भी तरह की कोई प्रभावी कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई अधिकारी कार्यवाही करने की हिम्मत ही नहीं करता। अवैध खननकर्ताओं द्वारा रात-दिन चलाई जा रही है, बड़ी-बड़ी जेसीबी लगा दी, साबल लगा दी, डम्पर लगा दिये, लोडर लगा दिये, कम्प्रेशर लगा दिये, रात-दिन काम चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके बंधी जा रही है और सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लीज धारक हैं वे परेशान हो रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा है।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा पोर्टल आपने एक साल से बंद कर रखा है। कोई गरीब आदमी, जो खाद्य सुरक्षा का लाभ लेना चाहता है, वह पोर्टल ही बंद हैं, वह क्या करेगा? स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को 40 रुपये रोज मिल रहे हैं, बच्चों का दूध आपने बंद कर ही दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): कर रहा हूं, साहब। पटवारी हड़ताल पर हैं, गिरदावरी कौन करेंगा? हमारे यहां गेहूं की फसल तैयार है, एमएसपी पर कैसे खरीदेगी, टोकन कौन काटेगा, कोई खरीदने वाला नहीं है।

मैं दो-तीन बात कहना चाहता हूं इस बजट में कि रायथल को उप तहसील घोषित की गई है, जबकि रायथल एक ऐसा गांव है, जिससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है, आय का स्रोत भी नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि या तो नमाणा को या फिर खटकड़ को उप तहसील बनायें, जिससे जनता को फायदा हो सके।

एक-दो मेरी और डिमांड थीं। शुगर मिल केशोरायपाटन, सहकारिता मंत्री जी अभी थे, यह शुगर मिल 15-20 साल पहले कांग्रेस के राज में बंद हो गई थी, वहां एक-डेढ़ महीने से लोग शुगर मिल चलाने के लिए केशोरायपाटन में धरने पर बैठे हुए हैं। यह सरकार जो किसानों की बात करती है, कोई पूछने नहीं गया उनके पास। शुगर मिल चलाने के लिए उनके पास पौने दो सौ बीघा जमीन भी है। को-आपरेटिव सर्किल में चल रही थी और जमीन पर्याप्त है और 15 करोड़ से ज्यादा वहां पैसा भी है, उससे चल सकती है। वहां के लोगों ने महाराष्ट्र और यूपी से इंजीनियरों को बुलाकर मशीन भी चैक कर ली, मशीनरी भी पर्याप्त है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, गांव में भी ऐसी चौपालें नहीं लगती होंगी, ये देखिए आप नजारा, ये राजस्थान की विधान सभा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कई माननीय सदस्य बोलने से रह जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हो क्या रहा है? इस सदन की गरिमा तार-तार हो रही है, आपके आसन पर विराजते हुए, इनको कहिए, अभी नींद निकाल-निकालकर आये हैं मंत्री महोदय और आकर इस तरह की, अभी देखो आप, 15 आदमी नहीं हैं सत्तारूढ़ दल के।

श्री सभापति: कई माननीय सदस्य बोलने से रह जाएंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनको इतनी चिंताएं हैं कि इनको नींद नहीं आती है, अब इसका हम क्या करें, बताओ आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): वसुन्धरा जी की जगह किसी और को बैठा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसके लिए जांच दल बनाइए आप, एक वह जांच करें, रात को मैं कैसे सोता हूं और ये कैसे सोते हैं जांच में सामने आ जाएगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): वहां के सात सौ, आठ सौ गांवों के किसान गन्ना बोने...

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): इनका प्रयास है, यहां भी किसी और को बैठाएंगे।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): वे गन्ना बोने के लिए तैयार हैं, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि जो केशोरायपाटन की शुगर मिल है, उसको कैसे भी करके चालू कराएं।

उसके अलावा मेरे बूंदी शहर की डिमांड थी, एक तो बूंदी शहर में नगर परिषद् एरिये में सीवरेज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी गलियां खुद गई, एक अमृत योजना की वजह से पेयजल की पाइपलाइन डल रही है, पूरा शहर खस्ता हाल में है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि बूंदी शहर को एक विशेष पैकेज दें ताकि वहां की सड़कों की हालत सुधर सके।

दूसरा, माननीय परिवहन मंत्री जी यहां बैठे हैं, ये बूंदी जिले के प्रभारी

(श्री अशोक डोगरा)

मंत्री जी भी रहे हैं। वहां के बस स्टैण्ड की इतनी बुरी हालत है कि कोई बस आती है तो ऐसी तो धूल उड़ती है और उसकी गिट्टी से किसी का भी माथा फूट जाता है, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। 10-15-20 लाख के काम हों तो मैं विधायक कोष से करवा दूं, करोड़ों रुपये की डिमांड है वहां पर।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): पहले हमारे टाइम पर तो यह था कि वह बस स्टैण्ड बाहर जाएगा, इसलिए काम नहीं हुआ। अब इन्होंने कह दिया कि बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बस स्टैण्ड में भी जल्दी से जल्दी सुधार कराने की कोशिश करें।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): एक मेरे बरड़ क्षेत्र में खातेदारी अधिकार पर बैन लगा हुआ है, इसको भी चालू कराएं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालूराम। पब्बाराम जी बैठे हैं, तो बोलिए। दो बार नाम पुकार लिया, तब भी नहीं बोल रहे हैं आप।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बजट के संवाद पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया और जिस प्रकार से शब्दों का शब्दजाल रचकर के ऐसे लगा, ऐसे हिप्नोटाइज किया सदस्यों को कि जिस प्रकार से स्वर्ग को जमीन पर उतार रहे हैं। ऐसा लगा कि सब-कुछ मिल रहा है और सभी को मिल रहा है। तीन बजट हो गये ओर तीनों बजटों के दौरान जो-जो घोषणाएं हुईं, वे धरती पर नहीं आईं। ये तीसरे में कैसे आएंगी, यह एक यक्ष प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, अभी टेल में पानी भी नहीं पहुंचता और टेल के समय में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया तो मुझे भी पता है कि समय की सीमा है, तो मैं कुछ बातें अपनी रख देता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की, ताकि उसके ऊपर विचार किया जा सके। हालांकि, बहुत-सी जगह के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं परन्तु मेरे क्षेत्र के लिए मात्र एक जल जीवन मिशन के तहत एक छोटी घोषणा हुई है, इसके अतिरिक्त कोई घोषणा नहीं हुई है। यहां पर चिकित्सा मंत्री भी विराजमान हैं, पिछले वर्ष फलौदी को जिला अस्पताल घोषित किया था। मैंने माननीय चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्य

(श्री पब्बाराम)

मंत्री जी को हार्दिक आभार व्यक्त किया था, परन्तु आज तक वहां पर पीएमओ नियुक्त नहीं हुआ है और न ही वहां पर पद भरे गये हैं और न ही किसी प्रकार का बजट आबंटन किया गया है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे पीएमओ भी नियुक्त करें और अन्य पद भी भरें और उसके भवन निर्माण के लिए जमीन अलाट करवाकर के उसके लिए बजट भी आबंटित करें। यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, फलौदी शहर के अंदर सीवरेज की समस्या बहुत विकट है और मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी इस बजट के अंदर ही सीवरेज का बजट आबंटित करें और माननीय मंत्री जी भी विराजमान हैं, मैं आशा करता हूं कि फलौदी जैसा ऐसा ऐतिहासिक शहर जहां पर कुरजां आकर के प्रवास करती हैं और जब उस गंदगी के ऊपर से जाती है तो शहर के ऊपर से कन्नी काटकर के जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि सीवरेज की व्यवस्था करवाएं।

एक शहरी जल जीवन मिशन भी आ गया है तो शहर के पानी की व्यवस्था करा दें। जल जीवन मिशन के तहत शहर के अंदर डीपीआर बनाकर के टेल तक सारे घरों के अंदर पानी अच्छी तरह से पहुंचे, यह भी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी घोषणाएं हुईं, बड़ी योजनाएं बताई गईं, जल जीवन मिशन माननीय प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत 2024 तक हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो क्षेत्र है बारूं, टेकरा, चिलडा, राबेरी..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): उसके अंदर अभी तक लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हम उस पानी के लिए थर्ड फेज की आशा नहीं कर सकते, थर्ड फेज कब आयेगा और कब वह चालू होगी। आपसे निवेदन है कि उसको मेन कैनाल से मात्र 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, मेन कैनाल से सिर्फ 5 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता है। उसको लेकर के, इनको पानी पीने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं रहती।

दूसरा, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी भी विराजमान हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, हमारे बाप के अंदर जो आपसे लगता क्षेत्र है, 2018 के अंदर 6 करोड़ रुपया जो भवन निर्माण के लिए दिया गया था, उसका कार्य शुरू हो

(श्री पब्बाराम)

गया था, परन्तु इतनी मंथर गति से चल रहा है कि आज तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ, ठेकेदार धीरे-धीरे कार्य कर रहा है, थोड़ा त्वरित गति से काम कराने का काम करें।

दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से विशेषकर यह आग्रह है कि कम से कम आपका तो पूरा राजस्थान पड़ा है, आप फलौदी से ही क्यों मेरे शिक्षकों को ले जाकर डेपुटेशन करते हैं कोलायत और बीकानेर के अंदर, यह तो कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए कि हमारे शिक्षक वापस फलौदी के अंदर भेज दीजिए, बहुत सारी रिश्तेदारियां भी हैं, ओलमा भी मिलेगा..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, बार-बार यह कहा जा रहा है कि आपको 25 सांसद दिये हैं, ये आपकी मेहरबानी से नहीं दिये हैं, इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने उनको चुनकर के भेजा है। आज इतने बरसों बाद में जब कश्मीर के अंदर तिरंगा लहरा रहा है..

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): वह उन सांसदों के कारण लहरा रहा है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा जा रहा है। वह सांसद अपना काम कर रहे हैं। जब चाइना में, वहां पर ड्रैगन जैसा तंबू उखाड़कर वापस...

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करिये आप। राठौड़ साहब। प्लीज सहयोग करिये। विराजिये आप। मेरा पुन: आपसे आग्रह है कि पांच माननीय सदस्य बोलने हैं और आठ बजे सदन की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा करूंगा। प्लीज सहयोग करें। जितना टाइम आपको दिया गया है उसमें सहयोग करें आप। जब मैंने कह दिया कि अंकित नहीं होगा तो आप कितना ही बोलें उससे कोई फायदा नहीं होना है। प्लीज सहयोग करें। श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के सारे पटवारी धरने पर बैठे हैं और राजस्थान के सारे किसान, 1 जनवरी से अभी तक किसानों के कई काम, जो भी नकल के काम, प्रमाण पत्र के काम,

(श्री कालूराम)

किसानों के कृषि कनेक्शन के काम, सारे काम अटके हुए पड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पटवारियों की हड़ताल खतम करें क्योंकि मेरे खुद के बिजली का कनेक्शन करवाना है और 31 मार्च के बाद दूसरा साल लगता है, मगर पटवारी नकल नहीं दे रहे हैं। नरेगा में काम स्वीकृत होते हैं, उसके लिए पटवारियों की नकल लगती है, नक्शा लगता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारियों की हड़ताल खतम करें। इनकी कोई ज्यादा मांग नहीं है। तीन मांगें दे रखी हैं इन्होंने, इन तीनों मांगों में एक तो 3600 की ग्रेड-पे है और 9, 18, 27 की बजाय इन्होंने 7, 14, 21, 28 की मांग रखी है, इनकी यह मांग पूरी की जाए। राजस्थान के समस्त किसान जो इनसे परेशान हो रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में पाला गिरने की वजह से हमारे क्षेत्र में किसानों की सम्पूर्ण फसलें नष्ट हो गईं, उन फसलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। फसल कट चुकी है कब गिरदावरी होगी? मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरंत ही इस हड़ताल को खतम करें और पटवारियों को काम पर लगाया जाए।

हमारे राजस्थान में कई संविदाकर्मी हैं, संविदाकर्मी को मात्र 6000 रुपये दिये जाते हैं। माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री जी विराजमान हैं, आपके एनआरएचएम में 8 साल हो गये हैं, हमारे एनआरएचएम के और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इनमें पंचायती राज के कर्मचारी हैं, आशा सुपरवाइजर हैं, इसके अलावा विद्यार्थी मित्र हैं, उनको 6-7 हजार रुपये में आप काम करवाते हैं। 6-7 हजार रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है, वह विद्यार्थी मित्र और संविदाकर्मी कैसे काम करेगा?

हमारे क्षेत्र में पेयजल के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल में पिछली घोषणा में पैरा नंबर-135 में हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 37247 करोड़ रुपये खर्च करने थे। उसमें बारां जिला सम्मिलित किया था। उसमें झालावाड़ जिला भी था। अभी झालावाड़ जिले में 37 हजार करोड़ की जगह 1000 करोड़ का काम भी नहीं हुआ है। 2021 का साल मार्च में पूरा हो जाएगा। यह सिर्फ आपकी घोषणा ही रहेगी कि इसमें आप काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च से पहले-पहले डीपीआर बनाकर जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को घर-घर पानी देने का आपने वादा किया था तो हर व्यक्ति को घर-घर पानी दें, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और मात्र 20 दिन बचे हैं, कब आप इसकी

(श्री कालूराम)
वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च से पहले-पहले इसकी भी स्वीकृति जारी करें।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री कालूराम (डग): स्वास्थ्य के विषय में माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे डग में मात्र 30 बैड का हास्पिटल है और 105 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पड़ता है, उसको ट्रोमा सेंटर किया जाए या 100 बैड दिया जाए, मंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

एक और मंत्री महोदय ने ग्रामीण बसें चालू करने के लिए हमें कहा था कि आपके ग्रामीण बसें चालू की जाएंगी। मेरे डग से इंदौर जाने की 2 बसें चलती थीं, वह दोनों बसें बंद हैं कोरोना काल से। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इंदौर की बसें चालू की जाएं क्योंकि हमारे डग से यात्री और व्यापारी इंदौर सामान लेने के लिए जाते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह भी चालू की जाए।

सिंचाई के लिए हमारे क्षेत्र में कालीसिंध और चंबल नदी चोमेला के आसपास निकली है। हमारे पेयजल के लिए गागरिन से करीब 75 किलोमीटर दूरी की लाइन डलकर 381 करोड़ की हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो गागरिन योजना शुरू की थी, पूर्ण नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे चोमेला क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाया जाए ताकि वहां पेयजल की समस्या खतम हो क्योंकि अभी अकाल का समय है, हमारे क्षेत्र में अकाल की वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और अकाल की वजह से सारी जमीनें सूखी पड़ी हैं, तो दो नदियां हमारे क्षेत्र में बहकर जा रही हैं। माननीय धारीवाल साहब हमारे नागेश्वर पधारते हैं, मंत्री महोदय, आपने तो क्षेत्र देखा है, तो आपसे रिक्वैस्ट है कि एक बांध देने की कृपा करें ताकि क्षेत्र के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी।

एक भवानीमंडी नगरपालिका है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन नहीं है, कहीं आग लगती है पूरे क्षेत्र में तो आग से फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसानों के चारा नष्ट हो जाता है तो एक आप अग्निशमन देने के लिए भी कृपा करें।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री कालूराम (डग): हो गया, साहब? खनन विभाग में कई अवैध खनन हो रहे हैं। आपने घोषणा की थी...

श्री सभापति: विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री कालूराम (डग): 000

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, बोला था।

श्री सभापति: आपने नहीं बोला तो भी मैंने मान लिया है, आप अपनी बात को चालू रखें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): इस बजट में पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है। मेरा विधान सभा क्षेत्र निराशा भरा बजट देख रहा है। क्षेत्र में अनेकों समस्याएं लंबित चल रही हैं और सबसे बड़ी समस्या है सेम की समस्या। महोदय, 40 वर्षों से सेम की समस्या चली आ रही है। पिछली भाजपा सरकार में 39 करोड़ रुपये सेम की समस्या के लिए दिये थे जिससे किसानों को राहत मिली थी लेकिन गत दो वर्षों में सेम नाले की सफाई नहीं हो पा रही। सेम का प्रकोप बढ़ रहा है, भूमि बंजर होती जा रही है, किसान परेशानियां झेल रहे हैं, भूमि सेम के कारण जलमग्न व लवणीय बंजर हो चुकी है। 30-40 वर्षों से किसान बुआई नहीं कर सके हैं। बंजर भूमि सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बंजर भूमि सुधार के लिए काश्तकारों को सहायता दें ताकि जो लवणीय भूमि है, उस पर फसल हो सके व जो कनेक्शन बड़ोप्पल में, 99 आरडी में, रावतसर में हुए हैं सेम नाले पर पिछली सरकार ने तो उसमें पूरा बजट दिया था और उसके बिल भराई हो रहे थे परंतु अब उसके बिल भरने बंद हो गये हैं, जिसके कारण से उसके कनेक्शन कट रहे हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उस सेम नाले की सफाई की जाए व सेम प्रभावित क्षेत्र में बंजर भूमि सुधार हेतु कुछ सरकार सहायता करे। सेम प्रभावित कस्बा 15-16 के.डब्ल्यू.डी., 99 आरडी, 75 आरडी, 91 आरडी, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जीवन नगर, गंदेली, दासूवाली, सरदारपुरा, खेतावाली ढाणी, भैरूश्री जाखड़ा वाली, बड़ोप्पल, दौलतावाली, ठाकरूवाला चक, 18 एसपीडी, कलालवाली ढाणी में सेम की काफी गंभीर समस्या है। सरकार ने बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किया है। अत: सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

सेमग्रस्त क्षेत्र में सरकार पूरा ध्यान दे ताकि जो भूमि सेम से खाली हुई थी, वह वापस कृषि योग्य बने, नहीं तो वहां के काश्तकार भूख के कगार पर आ जाएंगे। पिछली सरकार ने पक्के खालों के निर्माण के लिए राशि दी थी पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा प्रणाली एवं इंदिरा प्रणाली दोनों हैं। मैं दो वर्षों से मांग कर रहा हूं लेकिन बजट में कोई राशि आबंटित नहीं की गयी है, फिर भी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। साफ झूठ बोला जा रहा है। क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण नहीं हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): आरडी 84 पर, आरडी 91 पर, आरडी 99 पर खेतावाली ढाणी, आरडी 108 पर जर्जर हालत में जो पुल हैं, उन्हें दो वर्षों से ठीक करवाने की मैं मांग करता आ रहा हूं। कभी भी हादसा हो सकता है। विधान सभा में प्रश्न भी उठाया था और सरकार ने माना है कि हालत गंभीर है, परंतु सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण के लिए राशि दी जाए।

किसानों की डिग्गियों के निर्माण के लिए सरकार अनुदान राशि देती है। हनुमानगढ़ जिले में किसानों की अनुदान राशि का भुगतान काफी समय व्यतीत होने पर भी नहीं किया गया है फिर भी सरकार किसान हितैषी है, यह कैसा मजाक सरकार किसानों के साथ कर रही है। उन डिग्गियों का रुका हुआ अनुदान मिलना चाहिए और मेरा विधान सभा क्षेत्र घग्घर बहाव नदी क्षेत्र है परंतु दो-तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां काफी दूर से घूम कर आना पड़ता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अत: गुनती क्षेत्र से पीलीबंगा, लुढाना से अमरपुरा और पुनियावाला चक से खेदासरी, भैरूसरी काजवे का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इसी तरीके से मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा बहुत बड़ा शहर है, हास्पिटल की बिल्डिंग टूटी हुई है, उस हास्पिटल की बिल्डिंग की मरम्मत की जाए। वह विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां 30 बैड का अस्पताल है, उसको 60 बैड का अस्पताल कर दिया जाए तो वहां पर डाक्टरों की स्थिति ठीक रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

डाक्टरों के रहने के लिए किसी प्रकार के क्वार्टर नहीं हैं। वहां जो भूभाग पड़ा हुआ है, वहां आप क्वार्टर की स्वीकृति दें ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। जब इमरजेंसी केस आते हैं तब डाक्टरों को दूर से बुलाना पड़ता है, जिसके कारण से या तो हनुमानगढ़ जाना पड़ता है या फिर डैथ हो जाती है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि डाक्टरों के रहने के लिए व्यवस्था करें ताकि वहां सही ढंग से लोगों को इलाज मिल सके। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 24 तारीख से राजस्थान का बजट पढ़ रहा हूं, यह पूरा ही बजट निराशाजनक है। राजस्थान के विकास को पीछे धकेलने वाला बजट है। मैं बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे जिले में उदयपुर संभाग का माही का बहुत बड़ा डैम बना हुआ है लेकिन इस बजट में नहरों की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं किया गया। पीपलखूंट पंचायत समिति जो प्रतापगढ़ जिले में लगती है, वहां पर लंबे समय से दो तालाब बने हुए हैं बोरी बांध घटी, उनकी नहरें अस्त व्यस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। वहां पर बावडीखेड़ा का एक तालाब है, उसकी भी नहरें अधूरी पड़ी हुई हैं। साथ ही मोकाटोक नामक स्थान पर लंबे समय से बांध बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी बजट का उत्तर देंगे, तब उसमें इसके बजट की घोषणा करेंगे। आरएसईबी के अंतर्गत मेरे पीपलखूंट क्षेत्र में डूंगलावाणी घंटाली में एक नया पावर हाउस सेंटर खोला जाए, जीएसएस खोला जाए ताकि वहां पर लाइट की व्यवस्था सुचारु हो। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं पुलिया टूटी हुई पड़ी हैं। पीपलखूंट क्षेत्र में प्रतिपुरा और नायण के बीच में, रोहिण्या के बीच में एक पुल वसुन्धरा जी के टाइम का स्वीकृत पड़ा हुआ है। माही का बैक वाटर होने की वजह से उसका काम शुरू नहीं हो रहा है, उसका काम शुरू कराएं। पीपलखूंट हाईवे का काम शुरू कराएं। मेरे घाटोल विधान सभा क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं। परोली राठौड़ और परोली गोरधन के बीच में पुलिया टूटी हुई पड़ी हैं, उन पुलियाओं की मरम्मत की आवश्यकता है। मेरे मुखियावास उपखण्ड घाटोल विधान सभा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मैं मांग कर रहा हूं।

(श्री हरेन्द्र निनामा)

24 तारीख के बाद पूरे सदन में कोई तो मोदी जी का नाम ले रहा है, कोई राहुल जी का नाम ले रहा है, इसके अलावा कोई नाम नहीं आ रहा है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारे मेवाड़ में, वांगड में जिस तरह का विकास वसुन्धरा जी और भैरोंसिंह जी के समय में हुआ, चाहे शिक्षा का हो, सड़कों का हो, इर्रिगेशन का हो, सारा का सारा विकास हुआ। इसको लेकर वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता एक भजन गाती है, उस भजन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी का विकास किस तरह का है, यह मैं इस भजन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि, "दुनिया में डंको पर्यो है रे मोदी, अमर चाले थारो नाम। मोदी गांव-गांव में बिजली, मोदी अमर चाले थारो नाम। मोदी गांव गांव में टपरे बनाएं, मोदी अमर चाले थारो नाम। मोदी आतंकवाद को खतम किया, मोदी अमर चाले थारो नाम। मोदी अयोध्या का फैसला किया, मोदी अमर चाले थारो नाम। मोदी दुनिया में डंका पड़ा है, मोदी अमर चाले थारो नाम।" मैं एक बात के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि माही बांध से मेरे घाटोल क्षेत्र में पेयजल के लिए 500 करोड़ की योजना लागू की है, उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगसी राम कोली।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, जैसा सदस्य बोल रहे थे, सबने सुना ही नहीं। वह यह कह रहे थे की गैस सिलेंडर की रेट गलत बढ़ा दी और पूरा देश परेशान है। आपने पूरा गा करके सुना दिया, वह यही बोले हैं, पूछ लो आप उनसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, प्लीज सहयोग करें ... (व्यवधान) दो माननीय सदस्य बोलने से रह जाएंगे। श्री जगसी राम कोली।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, 24 फरवरी को राजस्थान का 2020-21 का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस बजट को देखते हुए, मैं इस राजस्थान की विधान सभा में लगातार चौथी बार आ रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के पृष्ठ संख्या 23 पर एक दोहे के द्वारा बताया है कि सपने वह नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वह हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को या तो यह किसी ने पर्ची पकड़ाई है या दिखाई है, क्योंकि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह दोहा वहां फिट

(श्री जगसी राम)

हो रहा है। सिरोही जिले में रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हमारे मंडार पुलिस थाने में 8 लाख रुपये की चोरी हुई है, एक बनास डेयरी का पेमेंट जावल में, लॉकर तोड़कर वह लेकर गया है। वहां कानून-व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। सभापति महोदय, यही नहीं, सिरोही जिले का सबसे बड़ा कस्बा शिवगंज है, शिवगंज में पूरे जोधपुर संभाग के कपड़ा व किराना के व्यापारी आते हैं। वहां 28 फरवरी को एसबीआई बैंक का लॉकर तोड़ा गया है, उस पर आज तक इस व्यवस्था के अंदर पुलिस ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। सभापति महोदय, रेवदर विधान सभा में दिनों दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, आबूरोड शहर में भी व्यापारियों की दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं।

इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र जो गुजरात से लगता हुआ है, भटाना चौकी और छापली चौकी पर जो अधिकारी लगते हैं, वहां पर लगने के लिए बोली लगती है क्योंकि राजस्थान गुजरात का माल इधर-उधर करने में जो अधिकारी सक्षम होते हैं, उनको ही वहां लगाया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहला सुख नीरोगी काया, नि:शुल्क दवा योजना को लागू किया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि सिरोही जिले में और विशेष तौर से रेवदर और आबूरोड में डाक्टरों की कमी है। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और हमारे चिकित्सा मंत्री जी जो सामने बैठे हैं, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे आग्रह किया था कि हमारे आबूरोड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जो पूरा ट्राइबल क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र हैं वहां पर डाक्टर हिंगोनिया की 24 घंटे सेवाएं रहती थीं, उनको आपने हटाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस डाक्टर को वहां पर वापस लगाया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को फायदा मिले।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सीएचसी से जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने का राजस्थान की सरकार ने जो मापदंड तय किया है, मैं समझता हूं कि सिरोही जिले में आबूरोड शहर और आबूरोड ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा पापुलेशन क्षेत्र में ओथैंटिक है, उस आबूरोड को जिला अस्पताल न बनाकर क्षेत्र की जनता के साथ कुठाराघात किया है। सभापति महोदय, रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको क्रमोन्नत किया

(श्री जगसी राम)

है, इसके लिए जमीन भी आबंटन करा दी है, उसको भी जल्दी से जल्दी चालू करावें। वहां पर भामाशाह भी भवन निर्माण की स्वीकृति देने के लिए तैयार है। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि स्टाफ की व्यवस्था भी वहां पर साथ-साथ में करें, ताकि हमेशा के लिए एक अच्छी पहल हो।

सभापति महोदय, मैं पशु चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं कि पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरिनरी सेवा उपलब्ध करवायी जाएगी। इस सेवा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छी योजना है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): रेवदर में कम्पाउंडर और स्टाफ की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नंदीशालाओं की बात जो सबने कही है, नंदीशाला के लिए या तो मुख्य मंत्री जी को घोषणा नहीं करनी थी और यदि घोषणा करनी थी तो वहां पर जिला मुख्यालय पर या पंचायत समिति स्तर पर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर किसान खेतों के चारों तरफ 24 घंटे चौकीदारी कर रहे हैं। किसान पीड़ित हैं, इसलिए सरकार नंदीशाला खोलकर किसानों को राहत प्रदान करे, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

सभापति महोदय, लाइट की जो व्यवस्था है, किसानों के लिए बहुत अच्छी की थी, सरकार ने दिन में देने की जो व्यवस्था करवायी थी, लेकिन आज की तारीख में सिरोही में रात में बिजली दी जाती है और पर्याप्त बिजली न देते हुए पांच घंटे या साढ़े पांच घंटे देते हैं, उसमें भी ज्यादा कटौती होती है, इसमें भी सुधार करने की व्यवस्था है। किसानों के लिए सिंगल फेज की व्यवस्था थी। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत चिंता कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था करवायी जाए, लेकिन जब गांवों के अंदर बिजली ही नहीं होगी तो वहां के बच्चे कहां से पढ़ेंगे? दूरदराज व एससी, एसटी के बच्चे कहां से पढ़ेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि दीनदयाल योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना लागू की थी, उस योजना को वापस चालू करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अध्ययन करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई योजना है..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, उससे प्रदेश के अंदर किसानों को फायदा हो रहा था, सरकार बदलने के बाद तुरंत प्रभाव से उनको बंद कर दिया गया है।

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा। श्री गोविन्द प्रसाद। प्लीज सहयोग करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, शायद मेरे विधान सभा क्षेत्र का आखिरी नंबर भी 200 है और बोलने में भी मेरा नाम आखिर में आया है। बड़ी खुशी की बात है।

श्री सभापति: आप पर यह कृपा माननीय राठौड़ साहब ने की है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): पूरा सदन मेरे साथ है।

श्री सभापति: सदन है या नहीं है, मैं जरूर आपके साथ हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। राजस्थान सरकार का यह तीसरा बजट है, इस तीसरे बजट में झालावाड़ जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र एम.पी. बोर्डर पर है और पूरा विधान सभा क्षेत्र एम.पी. बोर्डर की सीमा से बिलकुल सटा हुआ क्षेत्र है। वहां भाजपा की सरकार है यहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है कि वहां के आमजन और यहां के आमजन में काफी अंतर है। वहां का आमजन महसूस कर रहा है कि वहां की तकलीफें समाप्त हो गयी हैं, लेकिन यहां पर जो तकलीफें आ रही हैं, चाहे वे बिजली के क्षेत्र में हों, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हों, चाहे सड़क के क्षेत्र में हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, हर क्षेत्र में यहां आमजन को हमेशा तकलीफ रही है। ये ढाई साल गुजर चुके हैं पर मुझे पता नहीं हाड़ौती के दो-दो मंत्री होते हुए जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हाड़ौती के दो-दो मंत्री होते हुए मुझे पता नहीं कि तीसरा जो बजट राजस्थान का पेश हुआ है, यह बजट कहीं कोटा की सीमा पर जाकर रुक तो नहीं जाता है? यह झालावाड़ तक कैसे नहीं पहुंच पाता है? यह माननीय धारीवाल जी की मेहरबानी है कि यह सारा बजट कोटा को ही देते हैं और झालावाड़ को कुछ नहीं देते हैं। इस बजट में और अगले बजट में झालावाड़ के लिए कोई योजना नहीं है। कुछ योजना दी है तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर चरितार्थ वाली कहावत के बराबर है।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि झालावाड़ जिले में एक मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, चाहे वहां की जो निम्न प्रकार की जातियां हैं, चाहे तंवर समाज है, चाहे भील समाज है, चाहे लोधा समाज है, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चालू की हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थीं, वे योजनाएं बंद कर दी गयी हैं। जो चालू हैं, उनके नाम बदल दिये गये हैं। कई प्रकार की योजनाएं हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा अगले बजट में घोषणा की गई थी, जैसे नंदी गोशाला। नंदी गोशाला आज तक पंचायत समिति स्तर पर नहीं बनी है। हमारे क्षेत्र में झालावाड़ जिले में जो गोशालाएं हैं, जो रजिस्ट्रेशनशुदा हैं, उनका बजट, अगले साल का 2020 का तीन माह का बजट अभी भी अटका हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह बजट जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं।

दूसरी बात, मैं पेयजल के क्षेत्र में कहता हूं कि हमारा जिला जो झालावाड़ जिला है, उसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना, जो एमपी बोर्डर पर सटा हुआ है, नेवज नदी पर एक मोहनपुरा डैम बना हुआ है। पेयजल के क्षेत्र में महारानी साहब ने घुलंडी और कालिघाट से 72 गांव जोड़े थे, उनको तो पेयजल मिल रहा है लेकिन मेरी 65 ग्राम पंचायतें हैं पूरे विधान सभा क्षेत्र में, उनमें से 26 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं और अभी इस फरवरी के माह से वहां के हैंडपम्प और ट्यूबवैल सभी हवा फेंकने लग गये हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। मोहनपुरा डैम है, उस डैम से, वहां की सरकार से एमओयू करके पेयजल और सिंचाई हेतु ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र के आमजन को उसका सही लाभ प्राप्त हो सके।

आपने प्रत्येक थाने में स्वागत कक्ष के लिए घोषणा की थी। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8 थाने हैं, एक भी थाने में स्वागत कक्ष नहीं बना है। आपने गौरव पथ की घोषणा की थी, मात्र ढाई साल में एक गौरव पथ बना है। दो के प्रस्ताव अभी दिये हैं लेकिन अभी तक उनका क्या हुआ, यह हमें पता नहीं। आपसे निवेदन है कि वहां की टूटी-फूटी सड़कें, पुलियाएं और शिक्षा के क्षेत्र में तो एक भी स्कूल, यह तीसरा बजट होने को है, लेकिन एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ है, यह है राज्य सरकार।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

चिकित्सा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आपका यह तीसरा बजट है, एक भी पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं किया है। यह ऐसी सरकार है। हमारी बड़ी विडंबना है कि यह सारा विकास कहीं कोटा की सीमा पर दीवार बनकर इस तरफ तो नहीं रह रहा है। झालावाड़ में क्यों नहीं जा पा रहा है? बड़ी विडंबना है, हमें इस सदन में कहना पड़ रहा है, मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूं और मुझे देखने को मिल रहा है कि आज इस सदन में पक्ष और विपक्ष में जो वाद विवाद होता है।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 20.00 बजे गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ब्यावर बस आगार का सौन्दर्यीकरण

153. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बस डिपो के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाता है? यदि हां, तो ब्यावर आगार का सौन्दर्यीकरण कब तक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर के एक भामाशाह ने उक्त आगार की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण करने हेतु प्रस्ताव उक्त आगार को दिया था? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार उक्त आगार के सौन्दर्यीकरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण ब्यावर आगार के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) परिशिष्ट-1 में वर्णितानुसार भामाशाह संस्था द्वारा संशोधित मानचित्र आज दिनांक तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रस्तुत नहीं करने के कारण निगम प्रशासन द्वारा स्वीकृति देने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कोटा में चम्बल शुद्धिकरण योजना का क्रियान्वयन

159. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा शहर में चम्बल नदी के पास चम्बल रिवर फ्रन्ट बनाये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा चम्बल रिवर फ्रन्ट के बजट में बढ़ोतरी की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में चम्बल नदी को प्रदूषण रहित बनाने को कोई योजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चम्बल शुद्धिकरण योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार की कोटा शहर में चम्बल नदी के पास रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत कोटा शहर में चम्बल नदी के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। चम्बल नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दोनों तरफ के नालों को ट्रेप करते हुए गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए एस.टी.पी. प्लान्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दोनों साइडो पर घाट का निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर तथा ऐतिहासिक फसाड़ आदि का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) चम्बल रिवर फ्रंट का कार्य नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से करवाया जा रहा है। चम्बल रिवर फ्रंट योजना हेतु प्रारम्भिक लागत 800.00 करोड रुपये का आकलन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अपने बजट में 75.00 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। शेष वित्तीय प्रावधान प्रोजेक्ट एवं प्रोजेक्ट की प्रगति को देखते हुए रखा जाना प्रस्तावित है। आज भी परियोजना

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की लागत का आकलन राशि 800.00 करोड़ का है। कोई बढ़ोतरी अभी तक संभावित नहीं है। अब तक करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) हां। चम्बल रिवर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रारम्भिक कार्य एनआरसीपी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 में कार्य स्वीकृत किया गया था। योजनान्तर्गत चम्बल नदी में गिरने वाले 22 नालों को ट्रेप कर सीवर लाइन में डालने एवं इन नालों के पानी को शुद्ध करने का कार्य प्रस्तावित किया गया था।

इन सभी कार्यों को वर्ष 2013 तक पूर्ण किये जाने थे परन्तु संवेदकों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने एवं धीमी गति के कारण तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 02 अगस्त, 2016 को सभी कार्य निरस्त कर दिये गये।

अब NMCG (National Mission for Clean Ganga) योजना के अन्तर्गत शेष कार्यों की संशोधित स्वीकृति राशि रु. 258.48 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 25.02.2021 को जारी की गई है। कार्यादेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

(4) जी हां। यह सही है कि चम्बल शुद्धिकरण योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह कार्य माह जून, 2022 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जैसलमेर में नवीन राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

160. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर का क्षेत्रफल 27860 वर्ग किमी है एवं उक्त में तीन लाख गोवंश एवं बीस लाख अन्य पशुधन हैं तथा उक्त क्षेत्र में 43 राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केंद्र ही संचालित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उक्त केंद्रों तक बीमार पशुधन को औसतन दूरी 25 से 30 किमी. पैदल व अन्य साधनों से जाना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीमार पशुओं को पहुंचाने हेतु संचालित राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केंद्रों तक की जो दूरी तय करनी पड़ती है वह दूरी प्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्रों के सापेक्ष में 10 से 12 गुना अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष तौर पर उक्त क्षेत्र में

(श्री रूपाराम)

राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर बीमार पशुओं को पहुंचने हेतु औसतन दूरी अन्य विधान सभा क्षेत्रों में औसतन दूरी के बराबर ही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार निर्धारित मापदण्डों में परिवर्तन करते हुए नये मापदण्डों में क्षेत्रफल को भी समावेश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर अन्तर्गत तहसील जैसलमेर एवं तहसील फतेहगढ़ का कुल क्षेत्रफल 28874 वर्ग किमी. है।

वर्ष 2019 की पशुगणना अनुसार जिला जैसलमेर में 4.07 लाख गौवंश तथा 19.55 लाख कुल अन्य पशुधन है। पशुगणना विधान सभा क्षेत्रवार नहीं की जाती है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में 43 राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित है।

(2) जी हां। जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थितियों के कारण पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों तक बीमार पशुधन को पहुंचाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

(3) जी हां। जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थितियों के कारण पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों तक बीमार पशुधन को पहुंचाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

वर्तमान सरकार की बजट घोषणा 2019-20 अनुसार आगामी 5 वर्षों में राज्य की 1 हजार 478 ग्राम पंचायतों पर नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने हैं, जिससे प्रदेश की अधिकतर ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे।

(4) वर्तमान में प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना विचाराधीन है।

थानागाजी में संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

161. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी

(श्री कान्ति प्रसाद)
समितियां अलवर डेयरी के अंतर्गत संचालित हैं एवं उक्त में से कौन-कौनसी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त बंद समितियों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अलवर डेयरी के अन्तर्गत संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चालू व बन्द का विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्र का नाम	**कुल समिति**	**क्रियाशील दुग्ध समिति (चालू)**	**अक्रियाशील (बन्द)**
सरिस्का	31	7	24
थानागाजी	72	32	40
कुल	**103**	**39**	**64**

सूची प्रदर्श 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अलवर दुग्ध संघ द्वारा बन्द समितियों को पुन: क्रियाशील किये जाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में 17 बी.एम.सी. (क्षमता 1 हजार लीटर व कुल राशि रुपये 437.07 लाख)के स्थापित किये जाने बाबत अलवर दुग्ध संघ के कार्यालय पत्रांक 48834 दिनांक 05.11.2020 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा, जिला परिषद्, अलवर को प्रस्ताव भेजे गये है, उनके द्वारा कार्यालय क्रमांक 16750-54 दिनांक 09.11.2020 द्वारा उक्त प्रस्ताव को अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित किये गये हैं। उक्त योजनान्तर्गत बी.एम.सी. प्राप्त होने पर इन क्षेत्रों में बी.एम.सी. लगाई जाकर बन्द समितियों को पुन: कार्यशील बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। (छाया प्रतियां संलग्न-प्रदर्श-ब)

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्वचालित ट्रैक का निर्माण

162. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा स्वचालित ट्रैक का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब-कब कितने-कितने और कहां-कहां किये गये एवं प्रत्येक पर कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बनाये गये उक्त स्वचालित ट्रैक परिचालन में नहीं हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने ट्रैक हैं जो वर्तमान में परिचालन में नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद पड़े उक्त ट्रैक को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा स्वचालित ट्रैकों का निर्माण करवाया गया है। 13 परिवहन जिलों में RSRDC के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निर्मित ड्राइविंग ट्रैक पर विभाग के मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा मैन्युअल चालन परीक्षण लिया जा रहा है। निर्मित ड्राइविंग ट्रैक पर ऑटोमेशन सम्बन्धी कार्य स्मार्ट चिप कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जगतपुरा (जयपुर) में ऑटोमेशन का कार्य किया जा चुका है। दिनांक 03.02.2021 से जगतपुरा (जयपुर) में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 12 जिलों में स्मार्ट चिप कम्पनी द्वारा ऑटोमेशन कार्य पूर्ण होने पर पीपीपी मोड पर संचालन किया जा सकेगा।

(3) सरकार नवनिर्मित ड्राइविंग ट्रैकों को चालू करने का विचार रखती है। दिनांक 03.02.2021 से जगतपुरा (जयपुर) में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक पर चालन परीक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 12 जिलों यथा भरतपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, डीडवाना एवं झालावाड़ में माह अप्रैल, 2021 तक ऑटोमेशन कार्य पूर्ण होने पर पीपीपी मोड पर संचालन किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि

163. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री समाराम गरासिया)

क्या यह सही है कि विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले कार्मिकों को मानदेय 1320 रुपये दिया जाता है? क्या सरकार उक्त के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले कार्मिकों को वर्तमान में 1320/- प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। कुक-कम हैल्पर का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुक-कम हैल्पर्स के मानदेय में वृद्धि हेतु भारत सरकार को समय-समय पर लिखा गया है। भारत सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर राज्य में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

बस्सी में संचालित स्टोन क्रैशर

164. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम गढ में विशाल स्टोन क्रेशर स्टेट हाईवे संख्या 24 बस्सी-भाडोती से केवल मात्र लगभग 30 मीटर की दूरी पर ही लगा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को स्टेट हाईवे से 100-150 मीटर की दूरी पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टोन क्रेशर के पास ही एक प्राचीन मंदिर तथा रिहायशी मकान है जिन्हें उक्त क्रेशर से उत्पन्न प्रदूषण से हानि हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टोन क्रेशर के द्वारा ली जाने वाली अनापतियां अनियमित तरीके से प्राप्त की गई हैं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आज तक अनापत्ति नहीं ली गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बिना अनापत्तियां प्राप्त किये स्टोन क्रेशर लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त स्टोन क्रेशर को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम गढ़ में विशाल स्टोन क्रेशर हाईवे संख्या 24 बस्सी भाडोती से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।

(2) जिला कलक्टर, जयपुर के अनुसार वर्तमान मौका स्थिति अनुसार उक्त स्टोन क्रेशर पर स्थित सीमा की तार फेन्सिंग से 40 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का प्राचीन मन्दिर है तथा खनन लीजों की तार फेन्सिंग से बाहर स्थित खातेदारी भूमियों में छितराये रूप में रिहायशी मकान बने हुए हैं।

उक्त स्टोन क्रेशर से प्रदूषण से प्राचीन मंदिर एवं रिहायशी मकान को हानि होने के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कोई सूचना/ शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त स्टोन क्रेशर में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच हेतु दिनांक 09.02.2021 को राज्य मंडल द्वारा इकाई का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु क्रेशर इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(3) उक्त स्टोन क्रेशर इकाई द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना सम्मति (CTE) दिनांक 10.11.2009, तत्पश्चात् संचालन सम्मति (CTO) दिनांक 21.02.2011 एवं 07.02.2014 को प्राप्त की गयी है। उक्त क्रेशर द्वारा संचालन सम्मति के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा बिना अनापत्तियां प्राप्त किये स्टोन क्रेशर लगाने वालों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत निरन्तर कार्यवाही की जाती है। पूरक टिप्पणी संलग्न है।

(टिप्पणी पुस्तकालय में रखी गयी।)

बिलाड़ा में नवीन खेल स्टेडियम की स्थापना

165. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की बिलाड़ा नगरपालिका एवं गांवों में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंदिरों के पुजारियों को पेंशन का परिलाभ

161. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को वर्तमान में कितना वेतन अथवा मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त में वृद्धि करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुजारियों को विभागीय कर्मचारी मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्त किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त पुजारियों को पेंशन का लाभ दे रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पुजारियों को पेंशन का परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 390 तथा आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिर हैं। इनमें सेवा पूजा व्यवस्था हेतु नियुक्त पुजारी तीन प्रकार के हैं:-

1. वंशानुगत
2. नियमित वेतन श्रृंखला के
3. अंशकालीन

वंशानुगत पुजारियों को रियासतकालीन जागीर, भेंट से प्राप्त आय प्राप्त होती है।

नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्त राजकीय सेवा के पुजारियों को PB -1 5200-20200 ग्रेड-1750 L-2 तथा निधि पुजारियों को 5200-20200 ग्रेड पे-1700 L-1 अनुसार वेतन भत्ते दिये जाते हैं।

राजकीय मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार कुशल पुजारी को 1800/- तथा अकुशल पुजारी को 1200/- रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।

निधि मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों को 3600/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

(देवस्थान मंत्री)

वर्तमान में वेतन/मानदेय में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

(2) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों में नियुक्ति नियमित वेतन श्रृंखला के पुजारियों को राजस्थान सेवा नियमानुसार सेवानिवृत्त किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार पेंशन का लाभ दिया जाता है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त पुजारियों को नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है।

आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों के पुजारियों को Countibutory provident fund(C.P.F.) योजना का लाभ दिया जाता है।

(3) वंशानुगत पुजारी और अंशकालीन पुजारी राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिये इन्हें पेंशन परिलाभ देय नहीं हैं। प्रश्न के प्रथम भाग के बिन्दु सं. 2 जो कर्मचारी की श्रेणी में हैं, उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

देवस्थान विभाग के निधि कार्मिक भी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने से इन्हें पेंशन देय नहीं है। इन्हें नियमानुसार Countibutory provident fund(C.P.F.) का लाभ दिया जाता है।

सिरोही में माधव विश्वविद्यालय, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट को निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां

162. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माधव विश्वविद्यालय, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्राम पंचायत भारजा से प्राप्त की गई निर्माण स्वीकृतियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, भारजा के विरुद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिंडवाड़ा को 13 अक्टूबर, 2017 को दिये गये निर्देश एवं उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में जारी की गई स्वीकृतियों एवं हुए निर्माण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माधव विश्वविधालय, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्राम

(पंचायती राज मंत्री)

पंचायत भारजा से प्राप्त की गई निर्माण स्वीकृतियों का विवरण निम्न प्रकार है-

1. ग्राम पंचायत भारजा द्वारा स्वीकृति क्रमांक 432 दिनांक 06.09.2012 को मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर खसरा नंबर 146/8 व 146/01 भुजेला वाडा के 50 बीघा को 99 वर्ष की लीज के भूमि आवंटन पर कुल क्षेत्रफल 126627.9 वर्गमीटर भूमि पर चारदीवारी एवं प्रस्तावित स्वीकृत प्लान अनुसार कुल रुपये 126628 ग्राम पंचायत कोष में रसीद संख्या 194/56 से दिनांक 06.09.2012 जमा कर जारी की गई। (संलग्नः-परिशिष्ट 1, 2)
2. ग्राम पंचायत भारजा द्वारा स्वीकृति क्रंमाक पंचायत/2015-16/652 दिनांक 23.10.2015 को खसरा नंबर 146/03 भूजेला(काला मगरा) श्री राजकुमार पुत्र श्री जगमाल सिंह राजपूत के नाम पर संपरिवर्तन आबादी आवासीय भूमि में 07 मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति कुल क्षेत्रफल 13612.50 वर्गफीट पर रुपये 95288 रूपये को रसीद संख्या 01/60 दिनांक 23.10.2015 जमा कर जारी की गई। (संलग्न-परिशिष्ट 3)
3. ग्राम पंचायत भारजा द्वारा स्वीकृति क्रंमाक पंचायत/2015-16/653 दिनांक 23.10.2015 को भूमि खसरा नंबर 146/02 भूजेला(काला मगरा) श्री राजकुमार पुत्र श्री जगमाल सिंह राजपूत के नाम पर संपरिवर्तन वाणिज्यिक में 07 मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति कुल क्षेत्रफल 13612.50 वर्गफीट पर कुल रुपये 190575 रूपये को रसीद संख्या 01/61 दिनांक 23.10.2015 जमा कर जारी की गई। (संलग्नः - परिशिष्ट 4)

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत भारजा के विरुद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा को कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र दिनांक 13.10.2017 को दिये गये निर्देश एवं उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की वस्तु स्थिति इस प्रकार है:-

कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र दिनांक 13.10.2017 से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर ग्राम भूजेला में हो रहे भवन निर्माण की जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत भारजा द्वारा वाणिज्यिक

(पंचायती राज मंत्री)

संपरिवर्तन भूमि पर 07 मंजिला भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भारजा के पत्रांक क्रमशः पंचायत/2015-16/652 दिनांक 23.10.2015 व क्रमांक 653 दिनांक 23.10.2015 से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 68 के तहत जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां को राजस्थान पंचायती राज नियम 161 (2)(ख) का उल्लंघन मानते हुए निर्माण कार्य को तुरन्त रोकने एवं कार्यरत सरपंच, ग्राम पंचायत भारजा के विरुद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही को 7 दिवस में भिजवाने के निर्देश विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा को दिया जाना उल्लेखित है। (पत्र की प्रति संलग्न है)

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही के पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2020 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र के आधार पर श्रीमती मनीषा मीणा, तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 68 के तहत जारी 02 प्रशासनिक स्वीकृतियां को नियम विरुद्ध मानते हुए आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जाकर विस्तृत जांच हेतु प्रकरण अति. जिला कलेक्टर सिरोही को इस कार्यालय के आदेशांक 566-571 दिनांक 18.09.2020 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22 के उपनियम 3 अंतर्गत भेजी गई है। विस्तृत जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (आदेश प्रति संलग्न है) (संलग्नः- परिशिष्ट 5)

(3) माधव विश्वविद्यालय, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्राम पंचायत भारजा पंचायत समिति पिण्डवाड़ा द्वारा स्वीकृतियां एवं हुए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. ग्राम पंचायत भारजा के रिकार्ड अनुसार मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट गॉव लॉडो पोस्ट सुल्तानपुर, तहसील जिला सोलना (हिमाचल प्रदेश) द्वारा दिनांक 20.07.2012 को भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र मय प्लान प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2012 को प्रस्ताव संख्या 08 द्वारा 7 दिन का अन-आपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अन्दर मियाद आपत्ति प्राप्त

(पंचायती राज मंत्री)

नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2012 के प्रस्ताव सं. 15 अनुसार खसरा नम्बर 146/8 व 146/01 क्रमशः भुजेला, वाडा में आवंटन भूमि कुल 50:00 बीघा भूमि पर चारदीवारी व भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति रा.प.रा. नियम 1996 के नियम 68 (1) (IX) के अनुसार कुल भूमि 126627.9 वर्ग मीटर भूमि पर 1/- प्रति वर्ग मीटर से राशि 126628/- रसीद नं. 194/56 दिनांक 06.09.2012 पंचायत कोष में जमा कर मानव भारती विश्वविद्यालय भूजेला स्थापना हेतु चारदीवारी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति पत्र क्रमांक/2012-13/432 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया। इसी विश्वविद्यालय की समीपस्थ क्रय शुदा भूमि डॉ. राजकुमार पुत्र जगमाल सिंह भूजेला वाडा तहसील पिण्डवाड़ा सिरोही द्वारा भवन निर्माण के लिए स्वीकृति व माधव प्राइवेट आई.टी.आई. के भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत में दिनांक 15.09.2015 को प्रार्थना पत्र प्लान प्रस्तुत किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2015 को आपत्ति प्रमाण पत्र जारी व मौका निरीक्षण कमेटी गठित की गई है। दिनांक 20.10.2015 के प्रस्ताव सं0 05 अनुसार अन्दर मियाद आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण अनुशंसा अनुसार आवासीय परिवर्तन खसरा नम्बर 146/01 क्षेत्रफल 13612.5 वर्ग फीट व वाणिज्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन खसरा नम्बर 146/02 क्षेत्रफल 13612.5 वर्ग फीट पर आवास सात मंजिला एवं वाणिज्यिक सात मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायत भारजा क्रमांक/2015-16/652 दिनांक 23.10.2015 से प्रशासनिक स्वीकृति रा.प.रा. नियम 1996 के नियम 68 के तहत संपरिवर्तन आबादी आवासीय भूमि खसरा नम्बर 146/03 भूजेला (काला मगरा) में 07 मंजिला भवन निर्माण 13612.5 वर्ग फीट प्रति वर्ग फीट 1 की दर से 7 मंजिला भवन से 95288/-रुपये एवं पत्र क्रमांक/2015-16/653 दिनांक 23.10.2015 से रा.प.रा. नियम 1996 के नियम 68 के तहत संपरिवर्तन वाणिज्यक भूमि द्वारा नम्बर 146/02 भूजेला (काला मगरा) में 7 मंजिला भूमि पर भवन

(पंचायती राज मंत्री)

निर्माण क्षेत्रफल 13612.5 वर्गफीट 2/- की दर से 7 मंजिला की राशि 190575/- रुपये से जारी की गई।

2. ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति खसरा नंबर 146/8 में 42 बीघा में चार मंजिला कैंटीन भवन 1205.57 वर्गमीटर, पांच मजिला लाइब्रेरी भवन 2311.02 वर्गमीटर, पांच मंजिला एडमिन भवन 1480.80 वर्गमीटर, पांच मंजिला वर्कशाप भवन 2206.72 वर्गमीटर, दो मंजिला स्टाफ क्वार्टर ब्लॉक ए-970 वर्गमीटर, दो मंजिला स्टॉफ क्वार्टर ब्लॉक नंबर-बी 970 वर्गमीटर, तीन मंजिला आयुर्वेदिक हास्पिटल भवन 7673 वर्गमीटर में दो मंजिला पूर्ण व 1278 वर्गमीटर में तीसरी मंजिल कॉलम व लेन्टर निर्माणाधीन, छह मंजिला होम्योपैथिक भवन 1955 वर्गमीटर, सात मंजिला आयुर्वेदिक कालेज 13732 वर्गमीटर मौके पर कार्य बंद हैं। पांच मंजिला महिला छात्रावास भवन ब्लॉक-01 1312 वर्गमीटर, पांच मंजिला महिला छात्रावास भवन ब्लॉक-02 1312 वर्गमीटर, पांच मंजिला अन्तरराज्यीय छात्रावास भवन 1857 वर्गमीटर, पांच मजिला इंजीयनिरिंग भवन 6478 वर्गमीटर, पांच मंजिला कृषि भवन 6478 वर्गमीटर, पांच मंजिला आर्ट्स व कामर्स भवन 6478 वर्गमीटर, पांच मंजिला लॉ भवन 6478 वर्गमीटर, दो मंजिला स्टोर व स्टॉफ क्वार्टर 830 वर्गमीटर, एक मंजिला जल शोधन संयंत्र 36 वर्गमीटर, फॉर्मेसी भवन-01 850 वर्गमीटर, फॉर्मेसी भवन-02 5367 वर्गमीटर, नर्सिंग भवन 1789 वर्गमीटर में तीनों भवनों का कॉलम व लेन्टर व ईंट दीवार चिनाई का काम 50 प्रतिशत पूर्ण व 50 प्रतिशत अपूर्ण है। वक्त निरीक्षण काम बंद था।

चार मंजिला म्यूजियम भवन 1195 वर्गमीटर कार्य किया हुआ है लेकिन रंगरोगन व फिनिशिंग अपूर्ण है। चार मंजिला भण्डारा/न्यू ऑफिस कैंटीन भवन 2732 वर्गमीटर का निर्माण कार्य अपूर्ण हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति खसरा नंबर 146/01 भूजेला वाडा में 08 बीघा में चट्टानी पहाड़नुमा रिक्त भूमि है, जिसके चारों ओर चारदीवारी निर्मित है, जिसमें अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं है।

(पंचायती राज मंत्री)

ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित खसरा नंबर 146/3 व 146/2 का कुल 01 बीघा में पांच मंजिला आईटीआई भवन में तीन तल 6722 वर्गमीटर पूर्ण हो चुका हैं व ऊपर के दो तल 4481 वर्गमीटर में कॉलम व लेन्टर बने हुए हैं। कार्य अपूर्ण हैं और 12.12.2017 से ग्राम पंचायत के नोटिस से कार्य बंद हैं।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)

थानागाजी में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

163. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित ऐतिहासिक हवेलियों, दुर्गों एवं धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घरेलू पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 लागू कर दी गई है। इस नीति में घरेलू पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु बनाई गई ग्रामीण पर्यटन योजना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(2) विभाग द्वारा ऐतिहासिक हवेलियों, दुर्गों एवं धार्मिक पर्यटक स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थल विशेष स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य कर्मचारियों को मेडिक्लेम योजना का लाभ

164. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि के द्वारा समय-समय पर लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में विगत 2 वर्षों में किन-किन राज्य कर्मचारियों द्वारा उक्त योजनाओं में मेडिक्लेम हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा सरकार द्वारा किन-किन कर्मचारियों के आवेदनों को स्वीकार कर मेडिक्लेम दिया गया तथा किन कर्मचारियों के आवेदन किन कारणों से अस्वीकार किये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला अलवर में विगत 2 वर्षों में जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा उक्त योजनाओं में मेडिक्लेम हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर, जिन कर्मचारियों के आवेदनों को स्वीकार कर मेडिक्लेम दिया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर तथा जिन कर्मचारियों के आवेदन अस्वीकार किये गये, उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

डीजल-पेट्रोल की दरें कम करने की कार्ययोजना

165. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की दरें कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 24 जनवरी, 2021 तक कब-कब और कितना-कितना वैट बढ़ाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मध्य प्रदेश में पेट्रोल की दरें राजस्थान से अधिक हैं एवं डीजल दरें लगभग बराबर हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों

(वित्त मंत्री)

से पेट्रोल एवं डीजल की दरें राजस्थान में अधिक हैं। दिनांक 23.02.2021 की दरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार ने जनता को राहत देने हेतु हाल ही में दिनांक 28.01.2021 को अधिसूचना जारी कर डीजल एवं पेट्रोल की वैट दरों में 2 प्रतिशत की कमी की है।

(2) प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से अब तक कब-कब और कितना-कितना वैट टैक्स बढ़ाया/ घटाया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

राजकीय छात्रावासों के आवासियों को जवाहर नवोदय के समकक्ष देय सुविधाएं

166. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार राजकीय छात्रावासों में आवासियों को खाद्य सामग्री के लिये प्रतिमाह देय राशि एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं बढ़ाकर जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासियों के समकक्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय छात्रावासों पर होने वाले व्यय अन्य प्रशासनिक व कार्यालय मद से न किये जाकर खाद्य सामग्री मद में किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासियों के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजकीय छात्रावासों में मैस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (9.5 माह प्रति वर्ष) 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की गई है।

(2) जी नहीं।

बिलाड़ा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित प्रकरण

167. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हीराराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्तमान में कितने लोगों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन दी जा रही है? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कितने आवेदन लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	विशेष योग्यजन पेंशन
21,623	7,761	1,795

पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विभागीय आदेश क्रमांक 4791 एवं 5407 दिनांक 02.07.2019 द्वारा आवेदनों की जांच/सत्यापन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए Rajssp Portal पर निर्धारित समय सीमा के पश्चात् स्वतः सत्यापन एवं स्वतः स्वीकृत की व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस की कालावधि में जांच/सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु 15 दिवस की कालावधि निर्धारित है।

अतः वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जांच एवं स्वीकृति की निर्धारित समयावधि में कोई आवेदन लम्बित नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा के शाहपुरा में बाईपास का निर्माण

168. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डवलपमेंट आफ टू लेन जयपुर नेशनल हाईवे 12 से भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 79 फागी, मालपुरा, केकड़ी, मांडल डीबीएफओटी पैटर्न पर क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त परियोजना कब से प्रारम्भ हुई एवं कब तक पूर्ण होना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा बाईपास का निर्माण भी प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से भीलवाड़ा राज्य मार्ग संख्या-12, लम्बाई 212 किमी का कार्य डिजाइन, निर्माण वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण मोड (डीबीएफओटी) के अन्तर्गत है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 02.02.2012 से आरम्भ हुआ, उक्त परियोजना की 212 किमी लम्बाई में केकड़ी बाईपास सहित कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रेनवाल (लम्बाई 3.1 किमी), फागी (लम्बाई 5.47 किमी), मालपुरा (लम्बाई 7.5 किमी), कादेडा (लम्बाई 3.0 किमी), शाहपुरा (लम्बाई 8.350 किमी) बाईपासों के कार्यों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्य किया जाना सम्भव होगा।

(2) जी हां। शाहपुरा बाईपास लम्बाई 8.350 किमी की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाहपुरा बाईपास की भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेरगढ़ में घरेलू कनेक्शन देने की योजना

169. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के गरीब किसान परिवारों को सिंगल फेज कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विगत दो वर्ष में कितने कनेक्शन दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घरेलू कनेक्शन में दो से तीन पोल के कनेक्शन भी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में घरेलू कनेक्शन हेतु नवीन योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रचलित विनियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड

(ऊर्जा मंत्री)

में कृषि कार्य हेतु सिंगल फेज कनेक्शन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंगल फेज कृषि कनेक्शन दिया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

अतः विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गत दो वर्षों में कोई भी सिंगल फेज कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

(2) जी हां। दो से तीन पोल वाले घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर आदेश संख्या 756 के तहत गैर आबादी क्षेत्र में स्थापित एल.टी. लाइन से 100 मीटर तक सर्विस लाइन डालकर एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे हैं। 100 मीटर से अधिक दूरी होने पर आवश्यकतानुसार पोल लगाकर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सरकारी योजना संचालित नहीं की जा रही है। बिन्दु संख्या 2 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार मांग पत्र राशि जमा करवाने के पश्चात् प्राथमिकता अनुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चौमूं में पेयजल समस्या के समाधान की योजना

170. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चौमूं की पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा विभाग को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2020 के बाद कितने पत्र विभाग को लिखे गये? पत्रों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में विधायक द्वारा लिखे गये पत्रों में से कौन-कौनसी पेयजल समस्या का समाधान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन-सी का व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक द्वारा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को माह जनवरी, 2020 के पश्चात् लिखे गये पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) क्षेत्रीय विधायक द्वारा विभाग को उक्तानुसार लिखे गये पत्रों में उल्लेखित पेयजल सम्बन्धी विभिन्न कार्यों/योजनाओं की स्वीकृति जारी कर इन्हें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

उक्त पत्रों में उल्लेखित कार्यों/योजनाओं के विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक पूर्ण कराये गये, प्रगतिरत कार्यों तथा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन ग्रामीण जल योजनाओं के प्रस्तावों इत्यादि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत वर्ष 2019 से अब तक विभाग द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं/कार्यों की वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौमूं के 16 ग्रामों हेतु 14 जल योजनाओं के तैयार किये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति अन्तर्गत वर्तमान में विचाराधीन हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

प्रस्तावित जल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की शिवविहार-ए आवासीय योजना का नियमन

171. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवविहार-ए योजना जो जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना दक्षिण के अन्तर्गत आती है? क्या उक्त आवासीय कॉलोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) उक्त योजना के अनुमोदन हेतु उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सभी दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करा दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय कॉलोनी का नियमन किये जाने बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद चला था? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना का नियमन शिविर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक लगा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में अनुमोदित एवं गैर अनुमोदित योजनाओं के उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना शिव विहार-ए का रिकॉर्ड जमा नहीं होने से योजना का नियमन नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

इटावा (कोटा) के पशु चिकित्सालय के लिए भूमि का आबंटन

172. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय इटावा (कोटा) के लिए भूमि आबंटित किये जाने हेतु नगरपालिका इटावा जिला कोटा द्वारा सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है एवं क्या-क्या कार्यवाही किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त पशु चिकित्सालय के लिए 1.5 एकड़ (3 बीघा, 15 बिस्वा) भूमि आवंटित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय के लिए खसरा 330/2750 एवं 329 में से उक्त भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भूमि आबंटन में हो रहे विलम्ब के कारण भवन निर्माण

(श्री रामनारायण मीना)

कार्य में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक भूमि आबंटन के आदेश जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशु चिकित्सालय, इटावा (कोटा) को भूमि आबंटन किये जाने हेतु नगरपालिका इटावा के प्रस्ताव पर तथ्यों की जांच उपरान्त भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। परन्तु प्रभारी राजकीय पशु चिकित्सालय, इटावा, हल्का पटवारी इटावा एवं नगरपालिका इटावा द्वारा मौका देखकर खसरा नम्बर 329 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 330/2750 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि में से मौका स्थिति अनुसार 0.16 हैक्टेयर भूमि गैंता चौराहे से खातोली चौराहे के बीच बाईपास रोड पर प्रथम श्रेणी राजकीय पशु चिकित्सालय इटावा हेतु चिह्नित की गई है। प्रभारी पशु चिकित्सालय इटावा के आवेदनानुसार 0.16 हैक्टेयर भूमि आबंटन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 एवं 02 के उत्तर में निहित है।

आबूरोड नगरपालिका में अनियमितताओं की जांच

173. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार द्वारा नगरपालिका आबूरोड में अनियमितताओं के सम्बन्ध में 7 मार्च, 2020 को जिला कलेक्टर सिरोही से विस्तृत जांच करवाने की घोषणा की थी? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जिला कलेक्टर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में वित्तीय मामलों में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अनियमितता की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से जांच करवाये जाने की अनुशंसा की गयी, जिसके क्रम में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लिख दिया गया है। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट में जिन 6 दोषी अधिशासी अधिकारियों के नाम उल्लेखित किये गये हैं, उनमें से 4 अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री त्रिकमदान चारण, श्री विनोद बंसल एवं श्री सुनील कुमार शर्मा (जो वर्तमान मे नगरपालिका सेवा में हैं), के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

शेष रहे दो अधिकारियों में से एक श्री लाल सिंह राणावत वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है एवं दूसरे अन्य अधिकारी श्री सोहनलाल धानका, जो तत्समय उप परियोजना अधिकारी टी.ए.डी. विभाग आबूरोड में पदस्थापित थे और जिनका मूल विभाग आयोजना विभाग है, को जांच रिपोर्ट में अंकित अनियमितता के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी।)

उदयपुर में नवीन चल पशु चिकित्सालय

174. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला उदयपुर में कितने पद रिक्त हैं? सरकार उन्हें कब तक भरने का विचार रखती है? उक्त जिले में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कर्मचारियों के अभाव में कब से बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में चल पशु चिकित्सालय (मोबाइल वेटरिनरी हॉस्पिटल) संचालित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितने उक्त चिकित्सालय स्वीकृत कर संचालित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में पशुपालन विभाग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(पशुपालन मंत्री)

वर्तमान में कर्मचारियों के अभाव में कोई पशु चिकित्सा केन्द्र बन्द नहीं है।

(2) वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में पंचायत समूह स्तर पर गौवंश एवं अन्य पशुओं के इलाज के लिए जिन्हें पशु चिकित्सालय ले जाने में कठिनाई होती है, चल पशु चिकित्सालय (मोबाइल वेटरिनरी हॉस्पिटल) की व्यवस्था करने का उल्लेख है।

वर्तमान में वर्ष 2016 से प्रदेश में कुल 102 मोबाइल इकाई स्वीकृत हैं, जिनमें से 46 संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण

175. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन के मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण अब तक नहीं हुआ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**संस्था**	**संख्या**
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	03
2.	पशु चिकित्सालय	07
3.	पशु औषधालय	01
4.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	42
	कुल	**53**

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बानसूर की निम्नांकित पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु विभाग के नाम भूमि आबंटन के पट्टे प्राप्त नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं हो पाये हैं:-

क्र.सं.	**संस्था**	**संख्या**
1.	पशु चिकित्सालय	04
2.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	37
कुल		**41**

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण विभाग के नाम जमीन के पट्टे प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से कराये जाते हैं।

बाड़मेर में नन्दी गौशाला हेतु अनुदान

176. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित नंदी गौशाला के उद्घाटन पर पचास लाख का सरकार द्वारा अनुदान देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? क्या सरकार उक्त अनुदान को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। दिनांक 29.08.2019 को उक्त नंदीशाला एवं कांजी हाउस, बाड़मेर को राशि रु 50.00 लाख के अनुदान की घोषणा की गई थी। घोषणा की अनुपालना में दिनांक 03.03.2020 को नंदी गौशाला नगर परिषद् बाड़मेर को राशि रु. 50.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बाड़मेर द्वारा दिनांक 11.02.2021 को भुगतान किया जा चुका है।

बस्सी में नये दूध संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

177. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(1) जयपुर डेयरी प्रबंधन द्वारा नये दूध संग्रहण केन्द्र किस आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं? नये संग्रहण केन्द्र (डेयरी बूथ) स्वीकृत करने सम्बन्धी मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को बी.एम.सी. किस आधार पर दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितनी दूध उत्पादन सहकारी समितियां हैं? स्थानवार, समितियों के नाम तथा पदाधिकारियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये दूध संग्रह केन्द्र स्वीकृत करने के कितने आवेदन लंबित हैं? उक्त के लंबित रखने के क्या कारण हैं? बस्सी तहसील व कोटखावदा के नौ दूध संग्रहण केन्द्रों एवं तहसील कोटखावदा व चाकसू के 57 डेयरी बूथों के निरस्त करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी प्रबंधन (Management) द्वारा जिस ग्राम/ ढाणी/ चक में दुग्ध संकलन केन्द्र खोला जाना है, के कार्यक्षेत्र के निवासी दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं नियमित निवासी के प्रमाण स्वरूप वोटर आईडी की प्रतियां संलग्न कराई जाती हैं।

तत्पश्चात् सम्बन्धित जोन प्रभारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उचित निर्णय लेने हेतु सर्वे कराया जाता है। सर्वे में सर्वप्रथम संकलन केन्द्र खोलने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न सूचना एकत्रित की जाती है।

सदस्य का नाम (पिता/पति सहित)।

सदस्य का पूर्ण पता।

सदस्य के पास गाय/भैंस की संख्या एवं पशुओं की नस्ल।

सदस्य के पास कुल दूध का उत्पादन एवं उसमें से सोसायटी को दिये जाने वाले दूध की न्यूनतम एवं अधिकतम मात्रा आदि का विवरण सम्बन्धित मार्ग प्रभारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

प्रभारी उपकेन्द्र अपनी टिप्पणी कर प्रबन्धक (पीएण्डआई) को भिजवाते हैं।

(गोपालन मंत्री)

तत्पश्चात् प्रबन्धक (पीएण्डआई) द्वारा सर्वे रिपोर्ट का विश्लेषण कर अपनी राय प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ को प्रस्तुत की जाती है। प्रबन्ध संचालक द्वारा तद्नुसार अन्तिम निर्णय लिया जाता है। नये दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धित मापदण्ड/दिशा- निर्देश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आरसीडीएफ कार्यालय के पत्र क्रमांक 18658-85 दिनांक 14.08.2017 के तहत बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.) दिए जाने/ समिति चयन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार परिशिष्ट-ब पर संलग्न है:-

बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) उन सोसायटी के बीच स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन व्यय में बचत हो सके।

बी.एम.सी. उस सोसायटी पर लगाई जाती है, जहां आस-पास की सोसायटी से अधिक दूध आता है।

बी.एम.सी. स्थापित किए जाने वाली समिति वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं खर्चों को वहन करने की स्थिति में होनी चाहिए।

बी.एम.सी. स्थापित किये जाने वाली समिति सड़क मार्ग से जुड़ी होनी चाहिए ताकि टैंकर आवागमन में व्यवधान नहीं हो सके।

बी.एम.सी. की स्थापना से दुग्ध मार्गों का कैन-लेस दुग्ध संकलन किया जाना है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में 120 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां एवं 45 प्रस्तावित दुग्ध समितियां हैं, जिनका नाम, स्थानवार एवं पदाधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में 44 दुग्ध संकलन केन्द्र स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय के निर्देशानुसार एवं आचार संहिता लागू होने से वर्तमान में नये दुग्ध संकलन केन्द्र नहीं खोले जा सकते।

बस्सी तहसील के कोटखावदा के 9 दुग्ध संकलन केन्द्र जयपुर दुग्ध संघ के उपकेन्द्र चाकसू के अन्तर्गत आते हैं, जो निरस्त किये गये 57 संकलन केन्द्रों में शामिल हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

कोटखावदा व चाकसू के 57 डेयरी बूथ (दुग्ध संकलन केन्द्र, जिसमें

(गोपालन मंत्री)

बस्सी तहसील कोटखावदा के 09 दुग्ध संकलन केन्द्र सम्मिलित हैं) को नियमानुसार सर्वे में कमी रहने की शिकायत के कारण निरस्त किये गये हैं। संकलन केन्द्र के पुन: सर्वे के निर्देश दे दिये गये हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में रोडवेज बसों का संचालन

178. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार जिला टोंक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का पूर्व की भांति संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कितने ग्रामों व शहरों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में पूर्व में कितनी बसें कहां-कहां स्वीकृत थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों, कम आय एवं यात्रीभार के कारण पूर्व में संचालित जिन वाहनों को बन्द किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

निगम के सीमित संसाधनों एवं कम यात्री भार के कारण परिशिष्ट "1" में वर्णित बस सेवाओं को फिलहाल संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं है ।

(2) वर्तमान में निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 90 अप एवं 90 डाउन परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनसे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के जुड़े हुए ग्रामों एवं शहरों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में पूर्व में स्वीकृत निगम बसों की समय सारिणी/मार्गवार विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर व जैसलमेर की नवीन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

179. श्री अमीन खां (शिव): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार जिला बाड़मेर व जैसलमेर की नई ग्राम पंचायतों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 95 के अन्तर्गत राइट टू एजुकेशन के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उमावि तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उप्रावि/मावि/उमावि खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त मानदण्डानुकूल प्रस्तावों में उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित शिक्षक

180. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? केन्द्र व राज्य की राशि का पृथक-पृथक वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने जिलों में कितने-कितने आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर चलाये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई व कितने शिक्षक लाभान्वित हुए? वर्षवार, शिक्षकों की संख्या व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 से 2019 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- क पर संलग्न है।

(2) उक्त उपलब्ध करायी गई राशि का मदवार व वर्षवार व्यय विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में जिलेवार चलाये गये आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर पर हुए व्यय एवं लाभान्वित शिक्षकों की संख्या का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रणथम्भौर अभयारण्य में टेरिटोरियल क्षेत्र बढ़ाने की योजना

181. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न अभयारण्यों में टाइगर हैं? यदि हां तो कौन-कौन से अभयारण्यों में कितने-कितने नर, मादा व बच्चे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में विभिन्न अभयारण्यों में जानवरों द्वारा पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों पर हमला किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रणथम्भौर अभयारण्य में टाइगर के बढ़ते कुनबे के कारण टेरिटोरियल क्षेत्र से टाइगर बाहर निकल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त को रोकने हेतु क्या योजना बनाकर क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में मौजूद बाघों सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में विगत पांच वर्षों में वन्यजीवों द्वारा पर्यटकों पर हमले की कोई घटना नहीं हुई।

उक्त अवधि में अन्य व्यक्तियों पर हुए हमलों का संभागीय मुख्य

(राज्य मंत्री, वन)

वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी-1" से "बी-5" अनुसार है।

(3) जी हां। यह सही है कि रणथम्भौर बाघ परियोजना में बाघों के बढ़ते कुनबे के कारण बाघ, बाघ परियोजना क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। बाघ एवं वन्यजीव वन क्षेत्र से आबादी अथवा कृषि क्षेत्र में न निकलें, इस हेतु वन क्षेत्रों व टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में आवास सुधार (Habitat Improvement) आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के विस्थापन के प्रयास भी किये गये हैं ताकि बाघ व वन्यजीवों के लिए अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध हो सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

182. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक किस-किस श्रेणी के बेरोजगार युवकों को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया गया?

(2) बेरोजगार युवकों से वर्षवार कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों को भत्ता उपलब्ध करवा दिया गया तथा कितने शेष हैं एवं क्यों? जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा मुख्य मंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक श्रेणीवार किया गया भुगतान निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

क्र.सं.	श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान राशि (करोड़ रुपयों में)
1	सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग	181286	630.55
2	अनुसूचित जाति	37234	119.72
3	अनुसूचित जनजाति	30913	92.13
	कुल	**249433**	**842.40**

(2) मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 317293 आवेदन तथा 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 139385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 182201 बेरोजगार आशार्थियों तथा 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 67232 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया। योजनान्तर्गत एक वर्ष में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 1 लाख 60 हजार निर्धारित होने के कारण कुल 215390 आवेदन जांच में सही पाये जाने के उपरान्त भी लम्बित हैं। वर्षवार प्राप्त आवेदन, लाभान्वितों तथा शेष लम्बित आवेदनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)